डेल्टा से ज्यादा खतरनाक

ओमिक्रॉन

Alpha
September 2020

Beta
May 2020

Delta
October 2020

Omicron
November 2021

मूल्य 30/-

जनवरी, 2022

डायलॉग इंडिया

परिवर्तन की चाह.. संवाद की राह

सबके अपने अपने दावे

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

सबसे आगे...

VISIT…

Career Plus
EDUCATIONAL SOCIETY

SELECTION / ACHIEVEMENTS

"JAI BHIM MUKHYAMANTRI PRATIBHA VIKAS YOJNA"

Under the department for the welfare of SC/ST/OBC/EWS(Gen.)
Government of NCT Delhi

Career Plus
EDUCATIONAL SOCIETY

CHANCHAL UGC-NET	DEEPALI SSC-CGL	KANIKA DELHI POLICE	ASHWANI SSC-CHSL	RAMAN KUMAR CTET	RAVIKANT RAILWAY	PARAS ARYA SSC-CHSL	VIKASH KASHYAP MOHALLA CLINIC	RAVI SSC-CGL
RITIKA SSC-CPO	DEEPANSHU SATOHA SSC-CGL	POOJA BIRLA DELHI COURTS	PINKI KAUR SSC-CGL	HIMANSHU P SINGH SSC -CGL	KAMAL LDC-CLERK	UPASNA SSC-SI	PRIYANKA SSC-CPO	GULABH SINGH DELHI POLICE
VIKKY GAUTAM DRDO	MAHESH CTET	PRIYANKA CTET	SURABHI DELHI COURTS	NIRMALA DEVI NET	PREETI CTET	MANISH KUMAR LDA-CLERK	SANJAY KUMAR UPSSSC	VIPIN KUMAR UPSSSC
ASHOK KUMAR CTET	RINKU CTET	SANGEETA CTET	PUSHPA DEVI SSC-CHSL	AJAY CTET	KULDEEP SSC-CPO	MAHESH SSC-CHSL	MONIKA KUMARI RPF CONSTABLE	CHETAN T.O.-BPCL
MANIK UPSSSC	ANAMIKA SSC-CHSL	YOGESH KUMAR SSC -CHSL	JYOTI CTET/RAILWAY	KAVITA SSC -CHSL	NAVEEN RPF	KAMAL SSC-CHSL	DEEPAK RAILWAY	YOGITA IIT-JEE
KAJAL UGC - NET	TEENA SAGAR SSC	VANDNA SAILI CTET	AKSHIT SSC	RINKI CTET	DEEP SHIKHA CTET	VINITA UGC - NET	PUNEET KUMAR REET-TEACHER	UMESH L.L.B
DEEPALI SSC-CHSL	HEMANT K SINGH RAILWAY	HEMANT KUMAR RAILWAY	KIRAN CTET	KAVITA CTET	PAWAN KUMAR UP - PSC	ANKIT RAILWAY	NITESH KUMAR CTET	GAYATRI JUNIOR ASSISTANT
KARAN KUMAR SBI	BANTI KUMAR ASSISTANT MAINTENANCE	GURPREET SINGH CTET	SAROJ JR. ASSISTANT	SACHIN CTET-DSSSB	MAHESH KUMAR DDA PATWARI	KULDEEP UP-POLICE	SHASHI SSC - CHSL	REKHA SSC
MAMTA CTET	PRAVESH ASSISTANT TEACHER	RAHUL SSC - CHSL	ASHWANI SSC-CHSL	RUCHIKA KAKKAR Ph.D.(JNU)	AND MANY MORE.....			

विषय सूची

डायलॉग इंडिया
परिवर्तन की वाह संवाद की राह

जनवरी, 2022

डेल्टा से ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन

भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धती

संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने को तैयार है भारत - विदेश मंत्री जयशंकर

क्या हेलिकॉप्टर हादसे रोके जा सकते हैं?

कूटनीतिक हलचल

सबके अपने अपने दावे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सबसे आगे...

विधानसभा चुनाव सबके वादे सबके दावे

पंजाब चुनाव अंधेरा नहीं, रोशनी के दीप जलाये

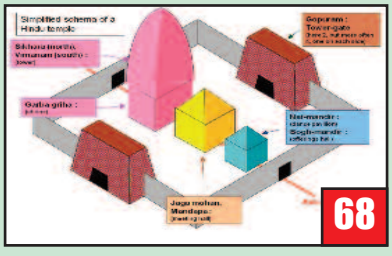

मंदिर संकुल : सनातन संस्कृति व चेतना के केंद्र

हमारे बारे में

डायलॉग इंडिया
परिवर्तन की राह संवाद की राह

वर्ष- 13 **अंक- 5**

संपादक
अनुज कुमार अग्रवाल

प्रबंध संपादक
डॉ. सारिका अग्रवाल

विशिष्ट संपादक
अमित त्यागी

विशेष संवाददाता
शरीफ भारती, आदित्य गोयल,
डॉ. यशवंत चौधरी, डॉ. अर्चना पाटिल

उप संपादक
नेहा जैन

मुख्य प्रबंधक (डिजिटल मीडिया)
सम्यक अग्रवाल

मुख्य प्रबंधक (विज्ञापन, वितरण एवं प्रसार)
विजय कुमार

जन सम्पर्क अधिकारी
पंकज कुशवाहा

ब्यूरोचीफ
उत्तर प्रदेश - एस.पी. सिंह
मध्य प्रदेश - संजीव चोकोटिया
राजस्थान - रामस्वरूप रावतसरे
बिहार - नंद शर्मा
दिल्ली - जितेन्द्र तिवारी

डिजाइन एवं ग्राफिक्स
विकास, मनीष, दीपक, रजत

मुख्य कार्यालय : 301/ए, 37-38-39
अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स
मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन : 011-27652829, 08860787583
फैक्स : 011-27654588
ई-मेल : dialogueindia@yahoo.in
dialogueindia.in@gmail.com
ई-पत्रिका : www.dialogueindia.in

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा स्टेलेंट प्रिंट एन पैक, ए-1, डीएसआईडीसी कॉम्पलैक्स, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली से मुद्रित एवं 301, 37-38-39, अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित

© सर्वाधिकार सुरक्षित

जनवरी, 2022 माह के लिए प्रकाशित

- डायलॉग इंडिया में प्रकाशित सभी लेख एवं सामग्री लेखकों के स्वयं के हैं, इससे प्रकाशक व सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

बड़ी लकीर खींचने की सोच

किसी भी राजनेता के लिए यह बहुत कठिन होता है कि वो अपने आगे बढ़ाए कदमों को वापस ले ले। किंतु प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों पर ऐसा किया। सरकार के संयम व धैर्य व बड़ी लकीर खींचने की सोच ने अंतत: किसानों की घर वापसी पर मजबूर कर दिया और बड़े नुकसान के बाद लंबे समय से तनावग्रस्त व अटका हुआ देश पटरी पर लौट आया। सभी किसान नेता व विपक्षी दल भी प्रशंसा के पात्र हैं। यह परिपक्व होते भारतीय लोकतंत्र की निशानी है। आजादी के बाद शायद यह पहली बार हुआ कि कृषि, किसान व इनके भूत, वर्तमान व भविष्य पर इतनी गहन व विस्तृत चर्चा हुई होगी। इस मंथन का परिणाम पूरे देश में कृषि व किसानों के लिए सेकड़ों योजनाओं व सुविधाओं का आगाज रहा तो सरकार सहकारिता व जैविक कृषि (शून्य लागत खेती) को मुख्यधारा में लाने पर मजबूर हुई। यह अभूतपूर्व कदम हैं और भारत की संस्कृति व आत्मा से मेल खाते हैं। सरकार व किसान संगठनों को सुनिश्चित करना होगा कि कृषि कानूनों के वापस लेने के बाद भी कृषि क्षेत्र में सुधारों की गति थमने न पाए। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी पर डबल्यूटीओ के समझौते के अनुसार 2023 के बाद नहीं दी जा सकती है, ऐसे में जल्द ही कृषि संबंधी मुद्दे फिर से मुख्यधारा में आने तय हैं। बेहतर होगा कि सरकार इस पर अभी से ही राष्ट्रव्यापी विमर्श व बहस अभी से ही प्रारंभ कर दे ताकि समय रहते एक सर्वमान्य रास्ता निकल सके और देश को फिर से गतिरोध, संघर्ष व कटुता के दौर से न गुजरना पड़े।

प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के कोरिडोर का सरकारी खर्च से निर्माण व अपने हाथों से लोकार्पण कर विध्वंस के खिलाफ रचनात्मकता की एक नई लकीर खींची है। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद इस कदम ने जहां भारत की धर्मनिरपेक्षता को पुनर्परिभाषित किया वहीं भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दर्शन की जमीन मजबूत कर दी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से पूर्व उठाए गए इस कदम से देश के बहुसंख्यक हिंदुओं में उनकी साख व छवि तो मजबूत हुई ही है साथ ही भाजपा के समर्थकों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसी बीच संघ परिवार मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी सक्रिय हो गया है। विश्लेषकों का अनुमान है कि यूपी के भाजपाई मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रिय छवि के बीच मोदी-योगी की जोड़ी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी आगामी विधानसभा चुनावों में फिर से भाजपा की प्रचंड जीत का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो सन् 2024 के लोकसभा चुनावों के सभी समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे और 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' के मुद्दे के इर्दगिर्द ही चुनाव लड़ें जाएंगे और भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। मोदी सरकार पूरे देश में ही धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने व

देशभर में प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार व विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधाएं विकसित करने में लगी है। इसका दूरगामी प्रभाव पड़ना तय है। यह भारत को फिर से वैश्विक पटल पर खड़ा करने की तैयारी है। भारत अपनों जिस ज्ञान व अध्यात्म परंपरा के कारण विश्वगुरु बना था यह उसे पुनर्जीवित करने का भगीरथ प्रयास है। जिसके कारण आम भारतीय रोमांचित है और मोदी सरकार के साथ खड़ा है। भारत के वैभव, ज्ञान व गौरव को पिछले कुछ सौ सालों में इस्लामिक व ईसाई ताकतों ने जिस प्रकार कुचला व विभाजन के साथ मिली आजादी और नेहरू - गांधी परिवार की कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा उसको छिपाने के खेल हुए उसका सच अब देश की जनता के सामने आ रहा है और वह पुन: देश के उस खोए हुए वैभव व गौरव की वापसी को आतुर है। जनता की इस आकांक्षा को समझ अब सेकूलर दलों को आधा अधूरा ही सही 'हिंदुत्व' का लबादा ओढ़ना पढ़ रहा है हालांकि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग परिभाषित करते हैं तो उनकी सोच का खोखलापन उजागर हो जाता है।

जगते, उभरते, निखरते और संवरते भारत की अंगड़ाई से पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान बुरी तरह परेशान हैं। भारत के अभूतपूर्व सैन्य आधुनिकीकरण व स्वदेशीकरण के बीच आक्रामकता ने भारत को दुनिया के सामने एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। इसके बीच जनरल विपिन रावत की कथित हैलिकॉपटर दुर्घटना में मौत अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चीन के राष्ट्रपति ली जिन पिंग की महत्वाकांक्षाओं व जीवनपर्यंत राष्ट्रपति बने रहने की जिद ने पूरे एशिया विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र को अशांत कर रखा है। वे जानबूझकर भारत के साथ सीमा विवाद बढ़ाए हुए हैं। अक्तूबर 2022 में होने वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके आजीवन राष्ट्रपति होने पर मुहर लगनी है। इसी कारण वे आक्रामक हैं व कार्यकारिणी के सदस्यों का मत अपने पक्ष में करने के लिए आक्रामक राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। इसी कारण पूरे विश्व के कूटनीतिक-सामरिक-आर्थिक समीकरण गड़बड़ाए हुए हैं। अमेरिका के नेतृत्व में पूरे विश्व में चीन से आयत कम करने व आत्मनिर्भर होने की मुहिम, चीन -अमेरिका व्यापार युद्ध का असर भी पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। बदलाव के इस दौर में रुस भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। कभी अफगानिस्तान तो कभी यूक्रेन के बहाने वो विश्व पटल पर अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश में है। पाकिस्तान के अफगान मुद्दे पर हावी होने के बीच भारत ने अफगान समस्या पर कई ठोस पहल कर अपनी स्थिति मजबूत की है। काश ये महाशक्तियां आपसी संघर्ष की जगह शांति व सहकार की बात कर कूटनीति के क्षेत्र में बड़ी लकीर खींच पाते!

इन सबके बीच जलवायु परिवर्तन व कोरोना के फिर से फैलते दंश ने पूरी दुनिया को अस्त-व्यस्त कर रखा है। सच्चाई तो यह है कि किसी भी देश की सरकार के पास इन दोनों चुनौतियों का कोई जवाब नहीं। बस अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया इन दोनो चुनौतियों के कारण अतिशय जन धन व संसाधनों की हानि झेल रही है। हर दिन तबाही, विस्थापन, मरीजों व मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कृषि चक्र बिगड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए जीवाश्म ईंधनो के प्रयोग को कम करने की कोशिश में दुनिया इलेक्ट्रिकल व्हिकल, सौर ऊर्जा व अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा श्रोत अपना रही है। कार्य संस्कृति व मानसिकता बदली जा रही है । परंतु इस खेल ने सप्लाई चेन को बिखेर दिया है। सरकारों की वित्त व्यवस्था बिगड़ गयी है तो अतिशय मुद्रा के चलन ने मुद्रास्फीति व महंगाई बढ़ा दी है। बेरोजगारों व विस्थापितो की संख्या हर दिन बढ़ रही है। आने वाले समय में कृषि उत्पादन में कमी व ग्लेशियर पिघलने से तटीय क्षेत्रों के डूबते जाने व मौसम की मार बढ़ते जाने के दुष्प्रभाव झेलने के लिए हमें कमर कसी रखनी पड़ेगी।

यह समय अस्तित्व के संघर्ष का है और दुनिया के सभी देशों चाहे अमीर हों या गरीब मिलकर एक साथ आगे आना होगा। कम संसाधनों व प्रकृति का कम से कम दोहन कर जीने की कला फिर से सबको सीखनी होगी। भारतीय सनातन संस्कृति इस मामले में सच्ची मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। दुनिया के सभी देश इसको अपनाने की दिशा में आगे बढ़े तो ही अस्तित्व बचे रहने की संभावना है। यक्ष प्रश्न यह है कि अपने अहम को त्यागकर क्या वे इस बड़ी लकीर खींचने को तैयार होंगे?

अनुज अग्रवाल
संपादक

डेल्टा से ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन

भारत में भी अब कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेज बढ़ते जा रहे हैं। अबतक 14 राज्यों में 220 ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए हैं। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार (Central Govt) ने कहा है कि कोरोना (Corona) का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) पहले के डेल्टा (Delta) के मुकाबले तीन गुना अधिक संक्रामक है और तेजी से फैल रहा है। इसे देखते हुए सभी राज्यों को अपनी तरफ से सतर्कता बरतते हुए पूरी तैयारी रखनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ने भी सलाह दी है कि ओमिक्रॉन को नियंत्रित करना जरूरी है और इसके लिए सभी उपायों पर अब विचार किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखा पत्र-नाईट कर्फ्यू लगा सकते हैं

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिखे एक पत्र में कहा है कि वे कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर सावधानी बरतें और किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें। इसमें कहा गया है कि भले ही कम मामले दर्ज किए जाएं लेकिन इन पर पूरी नजर रखनी है और स्थानीय स्तर तथा जिला स्तर पर सक्रिय कदम उठाएं जाएं।

9 बड़ी बातें

स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि किए गए उपाय स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित होने चाहिए, इसे 'दहलीज सीमा' के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना चाहिए।

केंद्र ने कहा, थ्रेसहोल्ड, पिछले एक सप्ताह में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की सकारात्मकता या ऑक्सीजन समर्थित या आईसीयू बेड पर 40 प्रतिशत अधिभोग है।

केंद्र ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 'रोकथाम के उपाय कर सकते हैं, थ्रेसहोल्ड तक पहुंचने से पहले ही प्रतिबंध लगा सकते हैं'।

ओमिक्रॉन के अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में डेल्टा संस्करण 'अभी भी मौजूद है', पत्र पढ़ा।

'अधिक दूरदर्शिता, डेटा विश्लेषण, गतिशील निर्णय लेने और सख्त और त्वरित रोकथाम कार्रवाई' का आह्वान करते हुए, पत्र में कहा गया है कि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश और जिला स्तर पर निर्णय लेना 'बहुत ही त्वरित और केंद्रित होना चाहिए और इन सीमाओं से पहले भी रोकथाम के उपाय और प्रतिबंध होने चाहिए, पहुंच गए हैं'।

परीक्षण और निगरानी विधियों के हिस्से के रूप में केंद्र ने सभी कोविड-सकारात्मक व्यक्तियों के घर-घर जाकर मामले की खोज, संपर्क, ट्रेसिंग का उल्लेख किया है।

जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए क्लस्टर संक्रमणों के नमूने तुरंत INSACOG लैब्स को भेजे जाने चाहिए।

राज्यों को 100 प्रतिशत टीकाकरण कवरेज 'तेजी से और सुनिश्चित' करने के लिए भी कहा गया है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि आपातकालीन धन का उपयोग अस्पताल के बिस्तर, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन उपकरण और दवा सहित चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किया जाए।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में ओमिक्रोन मामलों की संख्या 200 का आंकड़ा पार कर गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली ने नए संस्करण के सबसे अधिक मामले 54 दर्ज किए गए हैं। उनके बाद तेलंगाना (20 मामले), कर्नाटक (19), राजस्थान (18), केरल (15) और गुजरात (14) हैं। मंत्रालय ने कहा कि उनमें से 77 मरीज ठीक हो गए हैं।

Omicron आ गया है, तो बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। दिसंबर के शुरू में शुरुआत हुई है तो जनवरी, फरवरी, मार्च को गंभीर मानकर चलिए। इन्हीं तीन महीनों में से किसी एक महीने में पीक बनेगा।

मैं तो छह महीने से कह रहा था कि दिसंबर से मार्च के बीच तीसरी लहर को पक्का मानकर चलिए, लेकिन सभी कह रहे थे कि अब तीसरी लहर नहीं आएगी। खैर, मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि आएगी तो चौथी लहर भी, क्योंकि यह वायरस अब जाने से तो रहा। नए नए वेरिएंट इसके आते रहेंगे।

यानी 2022 का भी कबाड़ा ही समझिए। यह वायरस हड़बड़ी में बनाए गए वैक्सीनों से संभलेगा, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। फिर भी वैक्सीनों की वास्तविक प्रभावशीलता का पता

सारे देश में 'ओमिक्रॉन' का भय संचारित है

अनेक राज्यों में रात्रिकालीन कर्फ्यू शुरू हो गया है । देश में भी बूस्टर डोज की बातें हो रही हैं। अब विशेषज्ञों की राय बन रही है कि बूस्टर डोज पहली दो डोज से पृथक वैक्सीन की होनी चाहिए। इस सिलसिले में तकनीकी सलाहकार समिति ने अपना फैसला फिलहाल स्थगित रखा है क्योंकि वह और अध्ययन करना चाहती है। एक और फैसला बच्चों की वैक्सीन का है, जो अभी तक लम्बित है । यूरोप के कई देशों में 5 से 11 साल के बच्चों को टीके लगाने की शुरुआत हो गई है। भारत में जायडस कैडिला की वैक्सीन तैयार है, पर न जाने क्यों फैसला होने में देर है।

आम लोगों में डर है कि शायद एक और लहर आने वाली है। देश में वैक्सिनेशन से जुड़े तीन मसले हैं। वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। सामान्य नागरिकों की बात बाद में करें, एक डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज न लेने वालों में सबसे आगे हेल्थकेयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं। ताजा जानकारी है कि देश में 1.03 करोड़ हेल्थकेयर वर्कर्स और 1.83 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स ने वैक्सीन की पहली डोज ली थी। उसके बाद 95.21 लाख हेल्थकेयर वर्कर्स और 1.65 करोड़ ने दूसरी डोज लगवाई, यानी करीब 7 लाख हेल्थ केयर और 18 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी डोज नहीं ली। ये आंकड़े किसी को डराने के लिए पर्याप्त हैं ।

इस बार संक्रमण कितना तेज है, इसका अनुमान ब्रिटेन के अनुभव से लगाया जा सकता है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन संक्रमण के कारण मौत होने की खबर भी मिली है। वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बताया कि लंदन में अब करीब 40 प्रतिशत संक्रमण ओमिक्रॉन के हैं। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की उपस्थिति की घोषणा के तीन दिन बाद ही ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण की खबर आ गई थी।

डब्ल्यूएचओ के हाल भी अजीब है । उसे अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि नया वेरिएंट इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? उसके ताजा सूचना संस्करण में तो यह कहा गया है कि ओमिक्रॉन 'संक्रमण के खिलाफ टीके की प्रभावशीलता कम' है और यह भी कि अभी इसका संक्रमण गंभीर नहीं है। भारत में डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय निदेशक डॉ. पूनम खेत्रपाल ने कहा है कि नए वेरिएंट का मतलब यह नहीं है कि हालात और ज्यादा खराब होंगे। हां, उसे लेकर अनिश्चय ज्यादा होगा। जो पूरे देश में दिख रहा है ।

आज कई तरह के अनिश्चय जन्म ले रहे हैं। डब्ल्यूएचओ कहता है 'चूंकि पर्याप्त डेटा नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ओमिक्रॉन की तेज गति इसलिए है कि यह इम्यूनिटी को जल्दी भेद रहा है या इसमें संक्रामकता ज्यादा है या दोनों ही बातें हैं।' जो डेटा उपलब्ध है, उससे कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन जल्द ही डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ देगा, पर इस वेरिएंट की गंभीरता को साबित करने वाला डेटा भी उपलब्ध नहीं है।

वैश्विक रूप से कहें तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी और यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मिक्स एंड मैच टीकाकरण की जरूरत है। इसमें कोविड-19 से बचाव के लिए तैयार किए गए वैक्टर आधारित और एमआरएनए, दोनों तरह के टीके शामिल हैं। दूसरे शब्दों में कहें, तो मेडिकल एजेंसी ने एक ही टीके की दो खुराक लेने की जगह, दो अलग-अलग टीकों की दो खुराक लेने की सिफारिश की है। और यह सिफारिश तब की गई है जब इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट मैथ्यू स्नेप ने कहा कि मिक्स एंड मैच टीकाकरण का सकारात्मक परिणाम दिख रहा है। स्नेप इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता हैं।

इस वर्ष जून में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने शुरुआती नतीजों की सफलता के बारे में बताया था। उन्होंने पाया था कि जिन रोगियों को पहली खुराक ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की लगी और चार सप्ताह बाद दूसरी खुराक बायोएनटेक-फायजर वैक्सीन की लगी, उनमें एस्ट्राजेनेका की दो खुराक लगाने वालों की तुलना में ज्यादा एंटीबॉडी विकसित हुईं। ऐसे कई अध्ययन हुए जिनके नतीजे जुलाई के आखिर में विज्ञान जरनल नेचर में प्रकाशित भी हुए हैं। भारत की सरकार को समग्र रूप से सोचना चाहिए।

तीसरी लहर के दौरान ही चलेगा। अभी तक जो कहा गया है, वे फिलहाल दावे ही हैं। जब तक ये दावे वास्तविक परीक्षण में भी सही सिद्ध नहीं हो जाते, केवल वैक्सीनों के भरोसे ही न रहें।

इस बार सावधानी इसलिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके हवा द्वारा फैलने की बातें भी सामने आ रही हैं। उम्मीद की किरण बस एक ही है कि दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो उनमें कुछ न कुछ इम्युनिटी जरूर विकसित हुई होगी। अब वह इम्युनिटी कितने समय तक काम करेगी और नए वेरिएंट पर भी काम करेगी कि नहीं, इसका पता भी तीसरी लहर के दौरान ही चलेगा।

लेकिन खतरनाक यह है कि भारत जिस विशाल आबादी वाला देश है, उसमें अगर आधी आबादी भी संक्रमित होने से रह गई होगी, तो बची हुई आधी आबादी के बीच ज़्यादा फैलकर यह फिर से पिछली लहर जैसा ही कहर बरपा सकता है।

इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस बार अब फिर से जनता की लापरवाही और व्यवस्था की बदइंतजामी न देखनी पड़े! बाकी कोरोना ने इतना अहसास तो करा ही दिया है कि इस जीवन को जितना क्षणभंगुर समझते थे, उससे ज्यादा क्षणभंगुर है यह। कब कौन है, कौन नहीं है, कोरोना काल में कुछ नहीं कह सकते।

तो सावधानी जारी रहे और मुकाबले के लिए कमर कस लिया जाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।

-अभिरंजन कुमार

Omicron की बेकाबू रफ्तार के बीच एक और विलेन 'Delmicron' का खतरा, कई देशों में मचा रहा तबाही

Delta Variant : कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट सामने आया है। जिसका नाम डेल्मीक्रॉन है। यह डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट का कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है।

कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्मीक्रॉन सामने आया

Coronavirus Latest New Variant Delmicron : दक्षिण अफ्रीका में पिछले महीने सामने आए कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इस वेरिएंट से पहले डेल्टा (Delta Variant) तबाही मचा रहा था। लेकिन अब एक और वेरिएंट सामने आ गया है। जिसका नाम डेल्मीक्रॉन है (Coronavirus Delmicron Variant)। अमेरिका और यूरोप में बढ़ रहे कोविड-19 (Covid-19) के मामलों के पीछे इसे ही जिम्मेदार माना जा रहा है।

आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि डेल्मीक्रॉन डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का संयोजन (कॉम्बिनेशन) है। और अधिक तेजी से भी फैलता है। कोविड-19 पर महाराष्ट्र के टास्क फोर्स के सदस्य डॉ. शशांक जोशी के बताया, 'डेल्टा और ओमिक्रॉन के ट्विन स्पाइट (एक साथ तेजी से फैलने) डेल्मीक्रॉन के कारण यूरोप और अमेरिका में संक्रमण के मामलों की एक छोटी सुनामी आई है।' उन्होंने आगे कहा कि ओमिक्रॉन दुनिया के बाकी देशों में तेजी से डेल्टा वेरिएंट की जगह ले रहा है।

डेल्मीक्रॉन वेरिएंट ओमिक्रॉन से कैसे अलग है?

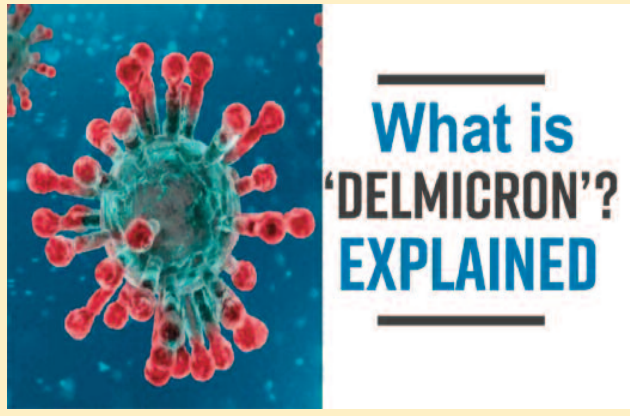

ओमिक्रॉन सार्स-CoV-2 का अत्यधिक उत्परिवर्तित B.1.1.1.529 रूप है, जो पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था। ये वेरिएंट अधिक तेजी से फैलता है और इससे संक्रमित व्यक्ति में डेल्टा के मुकाबले हल्के लक्षण दिखते हैं। इसमें मृत्यु दर डेल्टा वेरिएंट से भी कम है। जबकि डेल्मीक्रॉन, डेल्टा और ओमिक्रॉन का संयोजन है। जिसके तेजी से फैलने की आशंका है। डेल्मीक्रॉन में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों स्ट्रेन एक साथ मिलकर कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी कर रहे हैं।

भारत में कैसी है डेल्मीक्रॉन की स्थिति?

भारत में आधिकारिक तौर पर अभी तक डेल्मीक्रॉन को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में इस समय ओमिक्रॉन के कुल मामले 354 हो गए हैं (Delmicron Variant in India)। डॉ. शशांक जोशी ने कहा कि इस बात का अनुमान लगाने का अभी तक कोई तरीका नहीं है, जिससे पता चल सके कि डेल्टा और ओमिक्रॉन से बने नए वेरिएंट डेल्मीक्रॉन का क्या असर हो सकता है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने के लिए वायरस से बचाव के उपाय अपनाते रहना जरूरी है।

डेल्मीक्रॉन वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) या फिर अमेरिका के रोग नियंत्रक एंव रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 टास्क फोर्स या फिर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के लिए बनी टास्क फोर्स में भी किसी ने डेल्मीक्रॉन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है।

जान है तो जहान है , जनाब !

सतर्कता की दृष्टि मध्यप्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू हो गया है। नया वैरिएंट ओमिक्रॉन देश और विदेश में चिंता को और बढ़ा रहा है। पहले बात देश की- बीते कल देश के 7 राज्यों में ओमिक्रॉन के 96 नए केस सामने आए हैं , जिनमें अकेले तमिलनाडु में 33 और महाराष्ट्र में 23 मरीज मिले। तेलंगाना में14 , कर्नाटक में 12 गुजरात में 7 , केरल में 5 और ओडिशा में मामले सामने आए हैं। इस तरह देशभर में नए वैरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 357 हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश चुनाव को टालने की अपील भी की है। विदेश में चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड जैसे देशों ने पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है।

इस चिंता में देश का न्यायालय भी शामिल हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की 'भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कोरोना मुफ़्त टीकाकरण का जो अभियान चला, वो प्रशंसनीय है। न्यायालय उसकी प्रशंसा करती है और माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता है कि इस भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाते हुए रैली, सभाएं और होने वाले चुनाव को रोकने एवं टालने के बारे में विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है।'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश व विदेशों में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को देखते हुए प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से यूपी विधानसभा चुनाव कुछ समय के लिए टालने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए राजनीतिक दलों की भीड़ एकत्रित करने वाली चुनावी रैलियों पर

बदलनी होगी स्वास्थ्य नीति से जुड़ी सोच

भारत के लिए इस अध्ययन और अमेरिका की स्वास्थ्य नीति में बदलाव के बड़े मायने हैं। हमारे देश में 40 फीसदी बीमारियां दूषित जल पीने, साफ-सफाई के अभाव और कुपोषण से फैलती हैं, जिनमें मलेरिया, डायरिया हैजा, माहवारी संबंधी इनफेक्शन, नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं से संबंधित बीमारियां शामिल हैं।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक ताजा अध्ययन बताता है कि यदि हम पैकेज्ड खाने में 20 फीसदी और पेय पदार्थों (बेवरेज) में 40 प्रतिशत शुगर कंटेंट कम कर दें, तो दिल से संबंधित 2.48 लाख बीमारियों के मरीज को कम कर सकते हैं। इससे मधुमेह के 7.5 लाख मरीजों की संख्या कम की जा सकती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अमेरिका ऐसा करके अगले 10 साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में 4.28 अरब डॉलर बचाएगा। अमेरिकी स्वास्थ्य नीति में क्यूरेटिव के साथ प्रिवेंटिव अप्रोच भी जुड़ते जा रहे हैं। दुनिया के किसी भी देश का स्वास्थ्य क्षेत्र तीन अप्रोच पर काम करता है-प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रोमोटिव। प्रिवेंटिव का मतलब है बीमारियों की रोकथाम का अप्रोच, क्यूरेटिव का अर्थ है, यदि बीमारी हो जाए, तो उसका इलाज और प्रोमोटिव का मतलब है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है, उसे स्वस्थ बनाए रखा जाए।

भारत के लिए इस अध्ययन और अमेरिका की स्वास्थ्य नीति में बदलाव के बड़े मायने हैं। हमारे देश में 40 फीसदी बीमारियां दूषित जल पीने, साफ-सफाई के अभाव और कुपोषण से फैलती हैं, जिनमें मलेरिया, डायरिया हैजा, माहवारी संबंधी इनफेक्शन, नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं से संबंधित बीमारियां शामिल हैं। ये प्राणघातक बीमारियां हैं। 30 फीसदी बीमारियां गलत जीवन शैली के कारण होती हैं, जिनमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, तनाव, अस्थमा और मेटाबोलिक सिंड्रोम आदि शामिल हैं। जबकि शेष बची 30 फीसदी में किडनी, दिल आदि से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं। मेडिकल जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर वर्ष मलेरिया से दो लाख मौत होती है। यूनिसेफ के अनुसार, दुनिया भर में रोज करीब 800 महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मौत हो जाती है, जिनमें से 20 फीसदी महिलाएं भारत की होती हैं। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में भारत में आठ लाख बच्चों की मौत हुई, यानी हर मिनट में तीन मौत। हर साल अकेले डायरिया से 1.2 लाख बच्चे मारे जाते हैं। नवजात बच्चों की सबसे अधिक मौत भारत में होती है।

अक्सर कहा जाता है कि भारत में डॉक्टरों की संख्या कम है। जर्मनी में प्रति हजार लोगों पर 4.3, स्पेन में 3.9, अमेरिका में 2.9, ऑस्ट्रेलिया में 3.7 और ब्रिटेन में 2.9 डॉक्टर हैं। जबकि भारत में यह आंकड़ा 0.8 है। अपने यहां 11 लाख से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही, 6.3 लाख आयुष डॉक्टर भी हैं। यहां दिक्कत अप्रोच में है। यदि डॉक्टरों की संख्या 22 लाख भी होगी, तो समस्या वही रहेगी। हमारे यहां स्वास्थ्य ढांचा तीन स्तरों पर काम करता है। प्रथम स्तर पर गांव में एक उप सहायता केंद्र होता है, जहां एएनएम की ड्यूटी रहती है, जो गांव में टीकाकरण आदि का काम संभालती है।

वहां एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होता है, जहां एमबीबीएस और आयुष डॉक्टर,नर्स, खून जांच करने की प्रयोगशाला, लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट और 249 तरह की जरूरी दवाएं उपलब्ध होती हैं। ऐसे अस्पतालों में चार से छह बेड होते हैं। यहां उन 40 फीसदी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, जो गंदे पानी, साफ सफाई के अभाव व कुपोषण से फैलती हैं।

दूसरे स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा टीबी हॉस्पिटल आते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का मिनी अस्पताल होता है, जहां नौ विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। यहां पर सभी जरूरी जांच सुविधा और 369 प्रकार की जरूरी दवाएं हर समय मौजूद रहती हैं। यहां जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। जबकि तीसरे स्तर पर जिला अस्पताल आते हैं। उसके बाद मेडिकल कॉलेज हैं, जहां 556 तरह की दवाएं तथा सभी जांच सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यहां 30 फीसदी क्रॉनिक बीमारियों का इलाज संभव है।

हमारे लिए कुछ चीजों की जानकारी जरूरी है। पहली बात यह है कि हमारे यहां स्वास्थ्य सेवा के ढांचे में कोई कमी नहीं है। ऐसे में, स्वास्थ्य से जुड़े तीनों अप्रोच यहां कारगर हो सकते हैं। दरअसल बिना सही पोषण के इम्युनिटी नहीं बनेगी और बगैर इम्युनिटी के रोग से लड़ाई संभव नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्यूरेटिव अप्रोच अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि उसमें प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव अप्रोच को शामिल नहीं किया जाए।

दूसरी बात यह कि हमें प्राथमिक सेवा को दुरुस्त करना होगा। इसके लिए सूची में शामिल सभी जरूरी दवाओं व खून की जांच की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। तीसरी बात, व्यक्ति के स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा दवाओं तथा जांच पर खर्च होता है। यदि सरकार दवा कंपनी से सीधे दवा खरीदे, तो वह सस्ती मिल जाएगी। इससे दवा कंपनियों को कोई नुकसान नहीं है। तमिलनाडु की सरकार सीधे दवा कंपनियों से दवा खरीदती है। चौथी बात, मोटापा, उच्च रक्तचाप और तनाव का मुख्य कारण जंक फूड व खराब जीवन शैली है।

इस मामले में यदि हम प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव अप्रोच पर काम करें, तो मानव संसाधन, बजट और काम के घंटे बचा सकते हैं। पांचवीं बात यह कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त रहने से ही स्वास्थ्य सेवा ठीक रहेगी। स्वास्थ्य सेवा के शीर्ष केंद्र अगर मधुमेह और बुखार से ही लड़ते रहेंगे, तो हम स्वास्थ्य शोध के क्षेत्र में नया क्या करेंगे ? छठी बात यह कि बीमारी पर केंद्रित होने के बजाय हमें लोगों के

स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। और आखिरी बात यह कि हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में सांस्कृतिक तत्वों को भी समझना होगा। जैसे हमारी भोजन संबंधी संस्कृति में कार्बोहाइड्रेट ओर वसा को वरीयता दी जाती है। त्योहारों पर अधिक मीठा व वसायुक्त खाने का चलन इसी का परिणाम है।

- अश्विनी शर्मा

सरकार के साथ आप भी सचेत हों

भारत सहित पूरी दुनिया के लिए कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन चिंता का सबब बनता जा रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने देश में कोविड की तीसरी लहर की संभावना को भी तेज कर दिया है। देश में 15 से18 साल की आयु के बच्चों के लिए देश में वैक्सीनेशन 3 जनवरी2022 से शुरु होने जा रहा है । देश में बूस्टर डोज की शुरुआत 10 जनवरी से होगी, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के लोगों और हेल्थ कर्मियों को बूस्टर डोजदिया जायेगा ।

ओमिक्रॉन को लेकर सरकारी आंकडे चौकानें वाले हैं । ओमिक्रॉन के लगभग 50 प्रतिशत मामले ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया था। आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित 183 लोगों में से 87 यानी करीब 50 प्रतिशत लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि कोविड के इस नए रूप को रोकने के लिए सिर्फ वैक्सीन ही पर्याप्त नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने विशेष सम्बोधन में कहा है कि देश 141 करोड़ वैक्सीन डोज का अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है । उन्होंने कहा कि देश में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। 1 लाख 40 हजार आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है, परन्तु निगरानी बढ़ाने के साथ साथ मास्क का प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भारत में पाए गए 183 ओमिक्रॉन मामलों का विश्लेषण जारी किया । इन मामलों में से 96 की टीकाकरण की स्थिति की जानकारी थी। जिनमें से 87 वे लोग ओमिक्रॉन की चपेट में आए जिन्हें टीके की दोनो डोज दी जा चुकी थी। इनमें से तीन ऐसे लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए जिन्हें बूस्टर डोज भी दिया गया था। इनमें से 73 ऐसे लोग थे जिनके वैक्सीनेशन की जानकारी नहीं थी जबकि 16 टीकाकरण के पात्र नहीं थे। वहीं 18 लोग जो ओमिक्रॉन से ग्रसित हुए उनका यात्रा का इतिहास भी नहीं मिला। 165 लोगों में से27 प्रतिशत का विदेशी यात्रा का इतिहास नहीं था जो समुदायिक संक्रमण की ओर संकेत देता है।

उधर आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि क्लीनिकल सिम्टम्प्स वाले विश्लेषण से पता चलता है कि ओमिक्रॉन के 70 प्रतिशत रोगी एसिम्प्टोमैटिक है। भारत में अभी तक पाए गए ओमिक्रॉन के मामलों मे लगभग एक तिहाई मामले हल्के लक्षण वाले मिले जबकि बाकी में किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखे।

नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने चेतावनी देते हुए कहा कि घरों के अंदर ओमिक्रॉन संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि बिना मास्क पहन कर बाहर जाता है और वह बाहर से संक्रमण लाकर घर के लोगों को संक्रमित कर सकता है। पॉल ने कहा कि संक्रमण से बचने के लिए हमें जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाना होगा। लगातार मास्क का प्रयोग करें, हाथों को साफ रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचे।

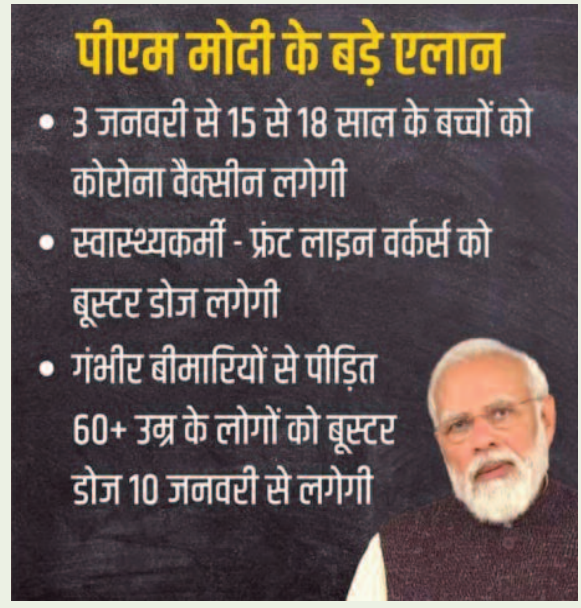
पीएम मोदी के बड़े एलान
• 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी
• स्वास्थ्यकर्मी - फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगेगी
• गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60+ उम्र के लोगों को बूस्टर डोज 10 जनवरी से लगेगी

प्रधान मंत्री श्री मोदी ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी की हैं । उन्होंने कहा कि हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इस प्रकार सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 10 जनवरी 2022 से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एहतियाती खुराक (बूस्टर डोज) की शुरुआत होगी 760 वर्ष से ऊपर की आयु के कॉ-मॉरबिडिटी वाले नागरिकों को, डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की बूस्टर डोज का विकल्प उनके लिए भी उपलब्ध होगा।

रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि औसतन न्यायालय के समक्ष लगभग 400 -500 मुकदमे सूचीबद्ध होते हैं। जिसके कारण अधिक संख्या में अधिवक्ता उपस्थित होते हैं और उनके बीच किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती। लोग आपस में सटकर खड़े होते हैं। जबकि कोरोना के नए वैरिएंट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और तीसरी लहर आने की आशंका है।

देश के कुछ हिस्सों अलग ङ्कअलग संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल रैली, सभाएं आदि करके लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं। इन रैलियों- सभाओं में किसी भी प्रकार से कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना संभव नहीं है। यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से कहीं अधिक भयावह होगा। ऐसी स्थिति इस प्रकार की रैली, सभाएं आदि जिनमें भीड़ एकत्रित हो, उन पर तत्काल रोक लगाना ही उपाय दिखता है। चुनाव में उतरी या उतरने को आमादा पार्टियों को अपना प्रचार व प्रसार रैली एवं सभा में भीड़ न जुटाकर इस दुष्काल में जन जीवन सुरक्षा के प्रयास में लगना चाहिए। जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेंगी।

सबसे पहले हर नागरिक को स्वयं सचेत होना होगा। फिर राज्य, केंद्र सरकार को अपने दायित्व के लिए मुस्तैद होना होगा। दूसरी लहर के अनुभव बेहद कटु हैं, फिर वो सब न लौटे 7 जान है, तो जहान है।

-राकेश दुबे

भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव

मौलिक भारत विचार श्रृंख्ला-5

भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धती

अजय सिंह 'एकल'

आयुर्वेद जो अथर्ववेद का एक उपवेद है में ईश्वर से प्रार्थना की गई है जिसका पहला सूक्त है 'पश्येमशरद:शतम' इसका अर्थ है हम सौ शरदों को देखें अर्थात सौ वर्षों तक हमारी नेत्र इन्द्रिय स्वस्थ रहे। दूसरा सूक्त है 'जीवेमशरद:शतम' अर्थात हम सौ वर्षों तक जीवित रहे और केवल जीवित ही न रहे तो हमारी ज्ञानेन्द्रियमन, बुद्धि, नेत्र इत्यादि सब स्वस्थ रहे। इसी प्रकार मनुष्यों के जीवन में सोलह प्रकार के सुखों की कल्पना की गई है जिसमे 'पहला सुख निरोगी काया' को ही बताया गया है। पश्चिम के विद्वानों ने भी कहा है धन दौलत, स्वास्थ और चरित्र में सबसे महत्व पूर्ण मनुष्य का चरित्र है, फिर स्वास्थ और सबसे बाद में धन दौलत का स्थान है। लेकिनइस भौतिक संसार में हम मनुष्यों ने गलत समझ के कारण धन दौलत कमाने को ही सबसे ज्यादा महत्व दे रहे है। हम दौलत कमाने के चक्कर में अपना स्वास्थ खराब कर लेते है और फिर स्वास्थ को ठीक करने में कमाई हुई धन दौलत खर्च कर देते है, नतीजा हम अच्छे स्वास्थ और कमाई हुई दौलत दोनों से हाथ धो बैठते है। हमे पता है की स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रह सकता है। ऐसा दिमाग जो क्रियाशील हो, सृजनात्मक हो और मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य 'सर्वेभवन्तुसुखिन:' अर्थात सभी सुखी होवें, सभी रोगमुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बनें और कोई भी दु:ख का भागी न बने के ध्येय पर आगे बढ़ सके । देश के नागरिकों का स्वस्थ और सुखी होना ही देश के सुख और समृद्धि का मार्ग है ।

यहां यह समझना आवश्यक है की स्वस्थ होने का मतलब शरीर में केवल बीमारियां न होना नहीं है बल्कि हमेंबीमारियां न होने पाए इसके लिए हमें सुरक्षात्मक तरीकों को अपना कर बीमारियों को दूर रखना है। नियमित प्राणायाम, योग, उचित खान पान की आदतें तथा सही जीवन चर्या का पालन करने पर यह संभव है। कहा जाता है की यदि आप भोजन दवा की तरह नहीं खा रहे है तो आपको दवा भोजन की तरह खाना पड़ेगा। अर्थात भोजन केवल स्वाद के लिए न होकर सुपाच्य, संतुलित और सीमित मात्रा में हो तो यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।

क्यों होती है बीमारियांआयुर्वेद में बताया गया है की ज्यादातर बीमारियां शरीर में वातपित्त और कफ के असंतुलन के कारण होती है। अत: इनके संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक जानकारी रखना और उचित खान पान से इसमें संतुलन बनाए रखना स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है । बीमारियां होने का दूसरा कारण है मन में नकारात्मक स्वसंवादों के निरंतर चलते रहने के कारण होने वाला असंतुलित व्यवहार । नकारात्मक स्व संवाद से मन के रोग जैसे क्रोध, अहंकार, नफरत इत्यादि का जन्म होता है और यह शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा करते है । उदाहरण के लिए गुस्सा करने से दिल और दिमाग खतरनाक अवस्था तक दुष्प्रभावित होते हैं। दिमाग में खून की

नलियां सिकुड़ने से हाई ब्लड प्रेशर के कारण दिल पर दबाव बढ़ जाता है। यह दिल की मांसपेशियां और खून की धमनियोंको नुकसान करते हुए दिल की कार्य प्रणाली तक को प्रभावित कर सकती है। इसी प्रकार ईर्ष्या, भय,चिंता तनाव और द्वेष आदि से पीड़ित मनुष्य का पाचन ठीक नहीं होता है। और यह पेट के रोगों को जन्म देता है। जिद पर अड़े रहने की आदत से भी पेट के रोग उत्पन्न होते है। अहंकार घुटनों की तकलीफे और कपट गले और फेफड़े के रोग पैदा करता है। अत: शरीर को निरोग रखने में जितना महत्व भोजन का है उतना ही महत्व सकारात्मक सोच और जीवन शैली का भी है। दोनों के बीच उचित सामंजस्य शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। हमारे शरीर में 70-72% जल होता है और 70 प्रतिशत से ज्यादा बीमारियां दूषित जल पीने से होती है । केंद्र सरकार ने इसके लिए भी एक अभियान शुरू किया 'हर घर में नल और नल में जल' बस इसमे थोड़ा प्रयास करके नल में जल पीने योग्य हो इसकी व्यवस्था हो जाने से एक बड़ी समस्या का समाधान निकल जाएगा। और व्यक्तिगत और सामुदायिक बीमारियों से निजात मिलने में सहायता मिलेगी।

स्वस्थ रहने के लिए जितना आवश्यक व्यक्तिगत सफाई के नियमों का पालन करना है उतना ही आवश्यक है की हम अपने आस पास की सफाई और पर्यावरण का ध्यान रखे । इस विषय पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 2014 में पहली बार देश को संबोधित करते हुए समाज का ध्यान आकर्षित किया था। नगर और गांव में साफ सफाई रहे इसके लिएस्वछता अभियान चला कर लोगों को जागृति किया था। साथ ही गांव में हर घर में शौचालय बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। देश भर में करोड़ों शौचालय इस अभियान के अंतर्गत बनवाए गए। हालांकि इनका पूरा इस्तेमाल हो रहा है यह संदेहास्पद है तो भी स्वछता अभियान के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे है।

एक बार बीमार हो जाने के बाद दवा ही इलाज है। सकारात्मक सोच और अनुशासित जीवन जीने से इसमें शीघ्र लाभ भी होता है और दुबारा बीमार पड़ने की संभावनाएं भी कम हो जाती है। उम्रबढ़ने के साथ बीमारियां होना स्वाभाविक है इन्हें रोकना संभव नहीं किन्तु पहले से तैयारी इसके दुष्प्रभावओं को कम कर सकती है । खान-पान पर नियंत्रण, शारीरिक श्रम और सकारात्मक सोच के अलावा अपने को परिवार और समाज के लिए उपयोगी बनाए रखना तथा व्यस्त-मस्त रहना इसमें सहायक है । अगर अब तक काम में व्यस्तता के कारण आप ने कोई शौक नहीं पाला या इसे पूरा करने का समय नहीं निकाल पाए तो अब पूरा कीजिए । यह शौक खेलने का नाचने गाने का लिखने -पढ़ने, बागवानी, खेती अथवा फोटोग्राफी इत्यादि का हो सकता है । लेकिन शौक जरूर रखे और यथा संभव पूरा करने में समय और संसाधन लगाइए। यह स्वस्थ बने रहने में निश्चित ही मदद करेगा ।

हमारे देश में चिकित्सा व्यवस्था सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है। दूर दराज के इलाकों में प्राथमिक, माध्यमिक एवं चिकित्सा व्यवस्था मूलत: सरकार के पास है । जबकि शहरी इलाकोंमें इलाज के लिए एम्स जैसे सरकारी और अपोलो जैसे निजी क्षेत्रों के अस्पतालों की विश्व स्तरीय सुविधायें उपलब्ध है। लेकिन भारत की बड़ी आबादी के लिहाज से ये सुविधायें पर्याप्त नहीं है। देश में एक लाख मरीजों की देखभाल के लिए मात्र 45 डाक्टर है जबकि आदर्श स्थिती 85 डाक्टरो की है। ऐसे ही नर्से 225 के मुकाबले केवल 75 है अत: इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इन कमियों को ध्यान में रख कर केंद्र और प्रदेश की सरकारेतैयारियां कर रही है। केवल उत्तर प्रदेश में 2019 में जहां केवल 10 मेडिकल कालेज थे 2024 तक 15 नए मेडिकल कालेज खोले जाने की योजना है। ऐसे प्रयास अन्य प्रदेशों की सरकारों द्वारा किया जाना अपेक्षित है । केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में किए जाने वाले बजट खर्च जो अभी निर्धारित है वह अपर्याप्त है अत: इसे बढ़ाने के लिए विचार किया जाए । केंद्र सरकार अभी जी डी पी का 1.3% चिकित्सा के लिए बजट कर रही है इसे 2.5% तक किए जाने की जरूरत है। ताकि सभी नागरिकों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा मुहैया करवाई जा सके ।

पिछले दो वर्षों में वैश्विक महामारी करोना की वजह से जो हालात पैदा हुए है इससे निपटने के लिए देश की चिकित्सा व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत और विस्तृत किए जाने की भी महती आवश्यकता है। पिछले दशकों में शुरू हुए अर्बनहेल्थ मिशन तथा रुरलहेल्थ मिशन अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाए हैं । जिसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार है। इसके लिए समुचित व्यवस्था करके अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और भ्रष्ट एवं कामचोर अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करने से बात बनेगी।एक और समस्या देश में चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं के मानकीकरण की है जिस पर नियामक संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए। तमाम कानूनों और प्रतिबंधों के बावजूद ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डाक्टरों का बोल बाला है। चिकित्सा की समुचित सुविधाएं न होने के कारण और जानकारी के अभाव में अनेक ग्रामीण नागरिक इनके शिकार हो जाते है। इस के लिए सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं की मदद से

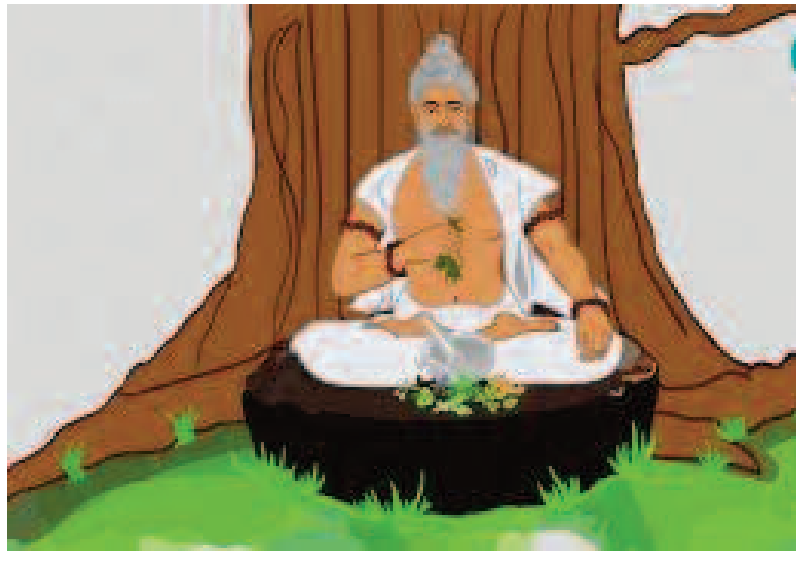

जागरूकता अभियान चला कर इसे रोकने की आवश्यकता है ।

चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं है । दूसरे अनेक देशों के मुकाबले भारत में चिकित्सा खर्च कम है और विश्व स्तरीय सुविधाये निजी क्षेत्र में उपलब्ध होने के कारण पड़ोस के ऐशीयाई देशों, खाड़ी देशों तथा कुछ यूरोप के देशों के मरीजों के इलाज के लिए भारत एक पसंदीदा स्थान बन गया है। इसे और विस्तृत तथा सुविधा युक्त किए जाने से देश में चिकित्सा सेवा क्षेत्र से आय में बढ़ोतरी भी होगी और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। साथ ही इसमें रोजगार बढ़ेगा। योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा की सुविधाये बढ़ने से देश में चिकित्सा पर्यटन बढ़ेगा और इन पद्धतियों के विशेषज्ञ अपनी सेवाओं से मानवता की सेवा और व्यापार दोनों कर सकेंगे।

दवाओं के व्यापार में लूट का खेल एमआर पी के माध्यम से संगठित तरीके से देश में चल रहा है । जिसके आधार पर मुनाफे के लिए मरीजों से दवा का अनाप-शनाप दाम वसूला जा रहा है। यह सब अधिकारियों की मिली भगत से उनकी नाक के नीचे हो रहा है। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।यद्यपि देश मे दवाओं के दाम तय करने के लिए एनपीपीएयाने राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है, लेकिन यह केवल 384 दवाओं के दाम तय करता है।इसमें सभी आवश्यक दवाओं शामिल करना चाहिए। कानूनी रूप से इससे बचने के लिए दवा कंपनियां दवाओं के तरह तरह के कांबिनेशन बना लेती हैं, जिन्हें एफडीसीअर्थात फिक्स्डडोजकांबिनेशन बोलते हैं, उनपर भी पूरी लगाम लगनी चाहिए। एफडीसी द्वारा दवा कंपनियां एनपीपीए द्वारा तय दामों की सीमा से बाहर हो जाती है और उसे महंगे दाम पर बेचना आसान हो जाता हैं। हालांकि सरकार ऐसे एफडीसी को प्रतिबंधित करती रहती, फिर भी ये धंधा धड़ल्ले से जारी है, जिसे हर हाल में रोकना होगा। देश में दवाओं का सालाना कारोबार करीब सवा लाख करोड़ का है जिसमें पचास फीसदी हिस्सेदारी एफडीसी की है। सरकार ने उचित मूल्य पर दवा उपलब्ध करवाने के लिए जन औषधि केंद्रों की शुरुवात की है । लेकिन इनकी संख्या पर्याप्त न होने और जानकारी के अभाव में यह सीमित सेवा ही दे पा रही है। अत: जन औषधि केंद्रों की जानकारी मुहैया करवाना और इनकी संख्या बढ़ाने के साथ इन केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि जन साधारण को दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके । डाक्टरों को स्पष्ट आदेश होने के बावजूद डाक्टर मूल रसायन या 'सॉल्ट' का नाम लिखने के बजाय दवाइयों का ब्रांड का नाम लिखना ही पसंद करते है। इस कानून का भी सख्ती से पालन करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास आवश्यक हैं।करोना काल में अनेक ऐसे भी वाकये हुए है जहां मरीजों को दवा के प्रिंटेड दाम से कई गुणा ज्यादा मूल्य देना पड़ा है।इससे आम जनता को जहां परेशानी हुई वही चिकित्सा से जुड़े लोगों की छवि भी खराब हुई और लोगों का व्यवस्था से विश्वास उठा है। सख्त कानून बना कर इस तरह की कोशिशों को हर हाल में रोका जाना आवश्यक है।

यह संतोष का विषय है की केंद्र सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल और इस कार्यकाल में चिकित्सा क्षेत्र में अनेक योजनाओं की शुरुवात की है। कुछ प्रमुख योजनाएं जैसे प्रधान मंत्री बीमा योजना, पी एम आयुष्मान भारत हेल्थइंफ्रास्ट्रक्चर मिशन,आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, स्वास्थ पहचान पत्र इत्यादि के शुरू होने से चिकित्सा क्षेत्र का पूरा चेहरा बदलने वाला है। यह योजनाएं पूरी होने पर नागरिकों को उनका संवैधानिक हक भी दिलाएंगी और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देश की पहचान से विकसित देश की पहचान बनाने में मदद करेंगी।

अनेक वर्षों से भारत देश की पहचान एक नौजवान देश की रही है क्योंकि 50% आबादी 25 साल से कम और 65% आबादी 35 वर्षों से कम लोगों की है लेकिन अगले 20-25 वर्षों में यह स्थिति बदल जाएगी और तब 60 वर्ष के लोगों की संख्या 50% या इससे अधिक होने से चिकित्सा आवश्यकताये भी बदल जाएंगी । इसलिए यह आवश्यक है की देश का हेल्थइंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा और मजबूत हो ताकि भविष्य की जरूरतें पूरी हो सके। यह एक लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है अत: अभी से इस पर काम करना समय की मांग है। भविष्य में करोना जैसी महामारी और ऐसी दूसरी आपदाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए समय रहते इन चुनौतिओ का सामना करने की तैयारी करने में ही देश और जनता की भलाई है।

अमृत महोत्सव वर्ष में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर काम शुरू हो और अगले कुछ वर्षों में चिकित्सा संबंधी जन आकांक्षाएंपूरी करने की व्यवस्था बन सके तो सही मायने में अमृतमहोत्सव वर्ष की सार्थकता होगी। स्वस्थ नागरिक ही देश को समृद्ध और शक्तिशाली बना सकते है और अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचा सकते है। ■

हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहितम्।
मानं च तच्च यत्रोक्तं आयुर्वेदः स उच्यते॥

आयुर्वेद

आयुर्वेद वह विज्ञान है जो जीवन के लिए हितकारी और अहितकारी, पथ्य और अपथ्य, जीवन जीने की शैली, रोगों से बचाव के तरीके और रोगों के उपचार के उपायों का ज्ञान कराता है।

संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने को तैयार है भारत - विदेश मंत्री जयशंकर

भारत ने पांच मध्य एशियाई देशों से कहा कि वह उनके साथ अपने सहयोग को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है और यह उनकी विकास यात्रा में दृढ़ भागीदार होगा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यह संदेश तीसरे भारत-मध्य एशिया डायलाग में दिया, जिसमें कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान के उनके समकक्षों ने भाग लिया। जयशंकर ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, हम अपने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति से बहुत खुश हैं। लेकिन हम जानते हैं कि क्षमता बहुत अधिक है। आज हममें से प्रत्येक को अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

सतत विकास लक्ष्य की दिशा में हमें काम करना चाहिए। साथ में हम इसे बेहतर कर सकते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत आपका दृढ़ भागीदार होगा। विदेश मंत्री ने तेजी से बदलती वैश्विक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की और दोनों पक्षों द्वारा विविध क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तारित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, हमारे पास पहले से ही सहयोग का एक अच्छा इतिहास है। लेकिन आज आपको मेरा संदेश, इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार रहना है।

पांचों देशों का शीर्ष नेतृत्व हो सकता है गणतंत्र दिवस पर अतिथि

पांच देशों के शीर्ष नेतृत्व के 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने की उम्मीद है। तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव ने डायलाग को जनवरी में आगामी मध्य एशिया-भारत शिखर सम्मेलन की तैयारी बताया।

भारत के साथ साझेदारी को बताया अहम

कजाखस्तान के विदेश मंत्री मुख्तार तिलेबर्दी ने साझा प्राथमिकताओं और दोतरफा साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने की प्रतिबद्धता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी गतिशील रूप से बढ़ रही है, जिसमें सहयोग के नए क्षेत्र शामिल हैं। किर्गिजस्तान के विदेश मंत्री रुस्लान कजाकबाएव ने इस क्षेत्र के साथ भारत के अच्छे संबंधों का उल्लेख करते हुए उसे सभी मध्य एशियाई देशों के लिए एक रणनीतिक भागीदार बताया।

सहयोग के विस्तार के नए अवसर पैदा करती है

ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन ने कहा कि उनका देश भारत-मध्य एशिया डायलाग को पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी के विकास और मजबूती के लिए महत्वपूर्ण मानता है। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया के क्षेत्रीय एकीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति क्षेत्र और भारत के बीच सहयोग के विस्तार के नए अवसर पैदा करती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत एक शक्तिशाली औद्योगिक आधार, विज्ञान और तकनीकी क्षमता के साथ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उजबेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुलअजीज कामिलोव ने कहा कि मध्य और दक्षिण एशिया के बीच अंतर-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डायलाग एक प्रभावी माध्यम है।

चार विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता

भारत-मध्य एशिया डायलाग से इतर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान के समकक्षों के साथ सुरक्षा, ऊर्जा, संपर्क, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय बातचीत भी की। पिछले कुछ वर्षों से भारत ऊर्जा के क्षेत्र में समृद्ध इन मध्य एशियाई देशों के साथ समग्र सहयोग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि उनके साथ बातचीत अच्छी रही।

अफगान की ओर मैत्री एवं मदद के भारतीय कदम

जब दुश्मनी निश्चित हो जाए तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए-इस एक पंक्ति में फलसफा है, कूटनीति है, अहिंसा है, मानवीयता है एवं जीवन का सत्य है और यही भारतीयता भी है। इसी भारतीयता का एक अनूठा उदाहरण तमाम विपरीत स्थितियों के बावजूद अफगानिस्तान की मदद करके भारत ने प्रस्तुत किया है। भारत ने फिर से सहयोग, संवेदना एवं मानवीय सोच से कदम बढ़ाया है। संकट से जूझ रहे अफगान नागरिकों के लिए यहां से भारी मात्रा में जीवनरक्षक दवाओं की खेप भेजी गई है। जो विमान काबुल से भारतीय और अफगान नागरिकों को लेकर यहां आया था, उसी के जरिए यह खेप भेजी गई। यह भारत का सराहनीय कदम है, मानवीयता से जुड़ा है।

समस्या जब बहुत चिन्तनीय बन जाती है तो उसे बड़ी गंभीरता एवं चातुर्य से नया मोड़ देना होता है। भारत ने ऐसा ही किया गया है। जबसे अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता कायम हुई है, तबसे वहां भारत की गतिविधियां लगभग रुकी हुई थीं। वहां भारत के द्वारा चल रहे विकास के आयाम भी अवरुद्ध हो गये थे। तालिबानी मानसिकता एवं भारत विरोधी गतिविधियों के कारण शुरू में तो भारत लंबे समय तक यही तय नहीं कर पा रहा था कि वह तालिबान को मान्यता दे या न दे, क्योंकि पूरी दुनिया में तालिबान को एक दहशतगर्द, आतंकवादी एवं हिंसक संगठन माना जाता है और इस तरह किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कब्जा करके सत्ता बनाने वाली शक्तियों को मान्यता देना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध माना जाता है। इन स्थितियों के कारण भारत द्वंद्व में रहा। समस्याएं अनेक रही हैं, चीन और रूस ने तालिबान की सत्ता को समर्थन देना भी एक समस्या रही है। भारत के सामने एक समस्या यह भी थी कि उसे अमेरिका का रुख भी देखना था। अमेरिका को पसंद नहीं कि कोई देश अफगानिस्तान की मदद करता। जब उसकी सेना वहां से हटी, तभी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। इसलिए दुनिया के वे सभी देश तालिबान के विरोध में खड़े थे, जो अमेरिका के मित्र थे। लेकिन इन सब समस्याओं एवं स्थितियों के बावजूद भारत का एक स्वतंत्र वजूद भी रहा है, उसकी सोच राजनीति के साथ-साथ मानवीय एवं उदारवादी रही है। शायद यही वजह है कि भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की जनता की खैर-खबर लेना जरूरी समझा है।

आज अफगानिस्तान के सम्मुख संकट इसलिए उत्पन्न हुआ कि वहां सब कुछ बनने लगा पर राष्ट्रीय चरित्र नहीं बना और बिन चरित्र सब सून। तभी आतंकवाद जैसी स्थितियों के लिये उसका इस्तेमाल बेधड़क होने लगा, अहिंसा और शांति चरित्र के बिना ठहरती नहीं, क्योंकि यह उपदेश की नहीं, जीने की चीज है। उसे इस तरह जीने के लिये भारत ने वातावरण दिया, लेकिन उनका पडौसी पाकिस्तान इस वातावरण को पनपने नहीं दिया। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी है और पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान के भारत से रिश्ते हमेशा तनाव भरे ही रहते हैं। ऐसे में अगर अफगानिस्तान का झुकाव भी उसकी तरफ रहेगा, तो भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसलिए भारत ने शुरू से अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखा है। तालिबान के कब्जे से पहले वहां भारत ने अनेक विकास परियोजनाओं में भारी धन लगा रखा है। तालिबान के आने के बाद उन परियोजनाओं पर प्रश्नचिह्न लग गया था।

जगजाहिर है कि अफगानिस्तान तालीबानी बर्बरता एवं पाकिस्तानी कुचेष्टाओं के चलते इस वक्त भयानक संकटों का सामना कर रहा है। देश में भुखमरी के हालात हैं, आम जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विकास की जगह आतंकवाद मुख्य मुद्दा बना हुआ है। लाखों लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। सत्ता को लेकर तालिबान के उग्र तेवर एवं भीतर ही भीतर वहां के राजनीतिक गुटों में तना-तनी का माहौल है। देश के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान का दखल मुश्किलों को और बढ़ा रहा है, अधिक चिन्ता की बात तो यह है कि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग आतंकवाद के लिये हो रहा है। एक विकास की ओर अग्रसर शांत देश के लिये ये स्थितियां एवं रोजाना हो रहे आतंकी हमलों में निर्दोष नागरिकों का मारा जाना, भूख-अभाव का बढ़ना, चिन्ताजनक है। भारत यदि इन चिन्ताओं को दूर करने के लिये आगे आया है तो यह एक सराहनीय कदम है।

इस तरह भारत ने अफगानिस्तान को जीवनरक्षक दवाओं की खेप भेज कर न सिर्फ दुनिया के सामने अपना मानवीय पक्ष स्पष्ट किया है, बल्कि अफगानिस्तान के लोगों का दिल जीतने का भी प्रयास किया है और कूटनीतिक दृष्टि से भी बड़ा कदम उठाया है। चीन और अमेरिका दोनों को इससे स्पष्ट संकेत मिल गया है। भारत अभी अफगानिस्तान को पचास हजार टन अनाज और दवाओं की कुछ और खेप भेजने वाला है। यह खेप पाकिस्तान के रास्ते जानी है। पाकिस्तान ने इसके लिए रास्ता दे दिया है, उस पर दोनों तरफ के अधिकारी अंतिम बातचीत के दौर में हैं। तालिबानी हमले की वजह से अफगानिस्तान में बड़ी तबाही मची है, वहां के पारंपरिक कामकाज भी लगभग ठप हैं। ऐसे में वहां के लोगों के लिए भोजन और दवाओं की किल्लत झेलनी पड़ रही है। भारत से पहुंची यह मदद वहां के लोगों के लिए बड़ी राहत पहुंचाएगी। इससे वहां की जनता में भारत के प्रति मानवीय सोच पनपेगी। भारत चाहता है कि अफगानी लोग अहिंसा, शांति, मानवीयता एवं आतंकमुक्ति का जीवन जीये। न अहिंसा आसमान से उतरती है, न शांति धरती से उगती है। इसके लिए पूरे राष्ट्र का एक चरित्र बनाना जरूरी होता है, भारत ऐसी ही कोशिश कर रहा है। वही सोने का पात्र होता है, जिसमें अहिंसा रूपी शेरनी का दूध ठहरता है। वही उर्वरा धरती होती है, जहां शांति का कल्पवृक्ष फलता है। ऐसी संभावनाओं को तलाशते हुए ही भारत सहयोग के लिये आगे आया है।

भारत ने तो अफगानिस्तान का लम्बे समय तक सहयोग किया है। वहां के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो भारत वहां का विकास चाहता है, शांति चाहता है, उन्नत चरित्र गढ़ना चाहता है, वहां उन्नत जीवनशैली चाहता है, हर इंसान को साधन-सुविधाएं, शिक्षा-चिकित्सा देना चाहता है, उस देश का भी भारत के साथ प्रगाढ़ मैत्री संबंध है, इन सुखद स्थितियों के बीच उस जमीन का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिये हो, यह कैसे औचित्यपूर्ण हो सकता है? यह तो विरोधाभासी स्थिति है। भारत तो वहां लंबे समय से विकास की बहुआयामी एवं विकासमूलक योजनाओं में सहयोग के लिये तत्पर है। वहां संसद भवन के निर्माण, सड़कों का नेटवर्क खड़ा करने से लेकर बांध, पुलों के निर्माण तक में भारत ने मदद की है। लेकिन अब मुश्किल तालिबान सत्ता को मान्यता देने को लेकर बनी हुई है। दो दशक पहले भी भारत ने तालिबान की सत्ता को मान्यता नहीं दी थी। जाहिर है, इसमें बड़ी अड़चन खुद तालिबान ही है। जब तक तालिबान अपनी आदिम एवं आतंकी सोच नहीं छोड़ता, मानवाधिकारों का सम्मान करना नहीं सीखता, तब तक कौन उसकी मदद के लिए आगे आएगा? अब यह तालिबान पर निर्भर है कि वह गतदिनों दिल्ली में हुए क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद को किस तरह लेता है और कैसे सकारात्मक कदम बढ़ाता है। लेकिन उसकी मानसिकता बदलने तक भारत इंतजार नहीं कर सकता है, इसलिये उसने अफगानी लोगों के सहयोग के लिये अपने कदम बढ़ा दिये हैं, जो सराहनीय है, मानवीय सोच से जुड़े हैं, निश्चित ही इन सहयोगी कदमों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

(ललित गर्ग)

वेद प्रताप
वैदिक

मध्य एशिया में भारत को मिले नए दोस्त

मध्य एशिया के पांचों गणतंत्रों और भारत के रिश्ते अब मजबूत हो रहे हैं। इसका जबरदस्त असर भारत की विदेश नीति और इस क्षेत्र के सभी देशों की समृद्धि पर होगा। पिछले सप्ताह मध्य एशिया के पांचों राष्ट्रों- कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्री एक साथ दिल्ली आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ संवाद किया। पिछले महीने ही इन देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी दिल्ली आए थे। इन देशों के साथ पहले भी दो बार भारत का संवाद हो चुका है।

रूस का था कब्जा

इन पांचों राष्ट्रों के सर्वोच्च नेता भी हमारे गणतंत्र दिवस पर पहली बार एक साथ भारत आएंगे। 2015 में यह भी पहली बार हुआ था कि भारत से कोई प्रधानमंत्री इन पांचों देशों में एक साथ गए हों। लेकिन इन देशों के साथ भारत के संबंध जितने मजबूत होने चाहिए थे, उतने नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि लगभग 30 साल पहले तक ये राष्ट्र रूस के कब्जे में थे। तब इनके साथ रिश्ते मॉस्को से संचालित होते थे। इनके बारे में यह धारणा भी बनी रही कि ये कहीं दूर बसे हुए देश हैं। इनकी गिनती भारत के पड़ोसियों में नहीं होती थी, लेकिन इतिहास बताता है कि ये देश और भारत सदियों से एक-दूसरे के पड़ोसी रहे हैं और पड़ोसी से भी ज्यादा एक बड़े परिवार की तरह रहे हैं।

ताजिकिस्तान में चीन ने बनाया खुफिया सैन्य अड्डा, तालिबान पर नजर, मध्य एशिया में बढ़ा दखल

ये पांचों देश यूं तो मुस्लिम-बहुल हैं, लेकिन कट्टरपंथी नहीं हैं। इन पर सोवियत संघ का साम्यवादी प्रभाव काफी गहरा है। इसलिए भारत के प्रति इन राष्ट्रों में एक आकर्षण है। इसी का प्रमाण है, पिछले सप्ताह पाकिस्तान में आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) का सम्मेलन! 57 इस्लामी देशों के इस संगठन के सम्मेलन में कई मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री गए, लेकिन इन पांचों मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्री इस्लामाबाद जाने की बजाय नई दिल्ली आए। उस सम्मेलन में अफगानिस्तान के बारे में विचार-विमर्श हुआ।

भारत ने अफगान-संकट पर पिछले महीने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का जो सम्मेलन किया, उसमें उसने पाकिस्तान और चीन को भी बुलाया था, लेकिन दोनों ने भारतीय पहल का बहिष्कार किया। वैसे, हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने सम्मेलन में भारत को आमंत्रित नहीं किया, जबकि मुस्लिम आबादी के लिहाज से भारत दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रों में माना जाता है। अगर भारत को आमंत्रित नहीं किया गया तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और चीन जैसे देशों को क्यों बुलाया गया? भारत ने अफगानिस्तान में जितने बड़े और विविध निर्माण-कार्य किए हैं, कितने देशों ने किए हैं?

भारत और पाकिस्तान में आयोजित इन दोनों सम्मेलनों में सबसे बड़ा मुद्दा तो अफगानिस्तान ही था। भारत ने पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में लगभग 3 बिलियन डॉलर खर्च करके संसद से सड़क तक क्या-क्या नहीं बनाया है। उसने लगभग 200 किलोमीटर की सड़क जरंज से दिलाराम तक बनाकर अफगानिस्तान के लिए फारस की खाड़ी तक पहुंचने का सीधा रास्ता बना दिया है। समुद्र तक पहुंचने के पाकिस्तान पर उसकी निर्भरता का यह विकल्प है। अगर अब तक चाहबहार-परियोजना कारगर हो जाती तो भारत और मध्य एशिया के बीच सीधा रास्ता बन जाता, जिसका लाभ अफगानिस्तान को तो मिलता ही।

अफगानिस्तान के सवाल पर पांचों देशों ने वही राय रखी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने प्रस्ताव में रखी है। यानी काबुल की सरकार सर्वसमावेशी हो। वह आतंकी गतिविधियों और अफीम की तस्करी से मुक्त रहे और अफगान जनता की जरूरतों को पूरा किया जाए। भारत ने 50 हजार टन अनाज और लगभग डेढ़ हजार टन दवाएं भी काबुल भिजवा दी हैं। इस्लामी देशों ने निजी तौर पर थोड़ी-बहुत मदद की घोषणा जरूर की है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 57 देशों के प्रतिनिधियों ने अफगान जनता की जीवन-रक्षा के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। अगर विदेशी बैंकों में रोके गए 10 बिलियन डॉलर ही अफगान जनता की सेवा में लगा दिए जाएं तो उसे मौजूदा संकट से राहत मिल सकती है।

मोदी ने यूं ही नहीं की कट्टरपंथ की बात, SCO बैठक में पाकिस्तान को दिखाया आईना

वहीं, दिल्ली में हुए इस सम्मेलन में सभी देश इस बात पर सहमत थे कि यदि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच व्यापार, उद्योग-धंधे और आवागमन को बढ़ाना है तो 'उत्तर-दक्षिण यातायात गलियारे' की योजना को जल्दी से जल्दी साकार करना होगा। इन देशों ने ईरान के चाहबहार बंदरगाह को विकसित करने पर भी जोर दिया ताकि भारत के साथ पांचों देशों को यातायात की सीधी सुविधा मिल जाए। भारत ने इन सभी राष्ट्रों के

लिए एक बिलियन डॉलर का फंड भी बनाने की बात कही है ताकि उनके यहां कई सुविधाएं तैयार हो सकें। इस समय इन पांचों देशों के साथ भारत का व्यापार मुश्किल से दो बिलियन डॉलर है जबकि चीन का व्यापार सौ बिलियन डॉलर का।

चीन के शिन्च्यांग प्रांत और मध्य एशिया के बीच सीधा थल-मार्ग और पाकिस्तान के जरिए भी चीन की मध्य एशिया तक पहुंच बनी हुई है। चीन अपने 'प्राचीन रेशम पथ' की रणनीति को फिर से चला रहा है। वह इन राष्ट्रों को करोड़ों डॉलर उधार देकर उन्हें अपने प्रभाव-क्षेत्र में लाना चाहता है। रूस को इससे कोई खास एतराज नहीं है। वह इस बात से संतुष्ट है कि कम से कम यह चीनी रणनीति अमेरिकियों को मध्य एशिया में हावी नहीं होने देगी। मध्य एशिया का यह पूरा क्षेत्र लगभग 100 साल तक ब्रिटिश साम्राज्य और रूस के बीच महाशक्ति-अखाड़ा बना रहा है।

खनिजों का अखंड भंडार

भारत को मध्य एशिया के प्रति वह रवैया नहीं रखना है, जो ब्रिटिश राज का था। भारत का उद्देश्य है कि संपूर्ण मध्य एशियाई राष्ट्रों का विकास हो और उसका लाभ दक्षिण एशिया के देशों को भी मिले। मध्य एशिया के इन राष्ट्रों में गैस, तेल, तांबा, लोहा, कोयला, यूरेनियम के भंडार अछूते पड़े हुए हैं। मध्य एशिया का क्षेत्र भारत से सवा गुना बड़ा है और उसकी जनसंख्या 8 करोड़ भी नहीं है। आप पांच-पांच सौ किलोमीटर चले जाइए, आपको एक भी आदमी दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि इन देशों में भारत अपने विशेषज्ञों को लगाए और निवेश करे तो यहां के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकता है। साथ ही, सारा दक्षिण और मध्य एशिया अगले दस वर्षों में यूरोप से भी अधिक समृद्ध हो सकता है।

भारत और मध्य एशिया के सांस्कृतिक संबंध भी सदियों से काफी मजबूत रहे हैं। अंग्रेज तो यही प्रचार करते रहे कि मध्य एशिया के आर्यों ने ही वहां से आकर भारत को बसाया है। इन देशों में मुझे पिछले 50-55 वर्षों में कई बार जाने का मौका मिला। इन देशों में आर्य, जैन और बौद्ध संस्कृतियों के अवशेष देखकर कोई भी चमत्कृत हो सकता है। इनकी भाषा और विश्व-दृष्टि पर संस्कृत का प्रभाव देखने लायक है। भारत चाहे तो इन राष्ट्रों के साथ दोस्ती करके अपने प्राचीन वैभव को फिर से प्राप्त कर सकता है।

भारत-रूस करें चीन को अलग-थलग

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की हालिया भारत यात्रा चीन के लिए एक संदेश होनी चाहिए। उस चीन के लिए जो भारत की सरहदों पर बार-बार अतिक्रमण की कोशिश करने से बाज ही नहीं आ रहा है। पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों के दरम्यान अनेक अहम मसलों पर समझौते हुए। लेकिन, अगर साफ तौर पर या संकेतों में ही चीन को यह बता दिया जाता कि भारत-रूस हरेक संकट में एक-दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, तो बेहतर होता।

देखिए कि जब से दुनिया कोविड के शिकंजे में आई है तब से पुतिन सिर्फ दो ही देशों में गए हैं। पहले वे अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन से मिलने जेनेवा गए थे। उसके बाद वे भारत आए। इसी उदाहरण से समझा जा सकता है कि वे और उनका देश भारत को कितना महत्व देता है। इसलिए पुतिन की इस यात्रा को सामान्य या सांकेतिक यात्रा की श्रेणी में रखना तो भूल ही होगी। दरअसल भारत-रूस के बीच मौजूदा संबंधों में आई गर्मजोशी की जमीन तैयार करने में दोनों देशों के विदेश मंत्री क्रमश: एस.जयशंकर और सर्गेई लावरोव ने अहम रोल अदा किया है। दोनों देशों की यह चाहत है कि इनके बीच आपस में आगामी 2025 तक 30 अरब डॉलर का कारोबार और 50 अरब पूरा डॉलर के निवेश का लक्ष्य हो जाए।कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सामरिक भागीदारी में कोई बदलाव नहीं आया है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच सहयोग रहा है।

हालांकि कुछ जानकार मान रहे थे कि भारत-चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में हुई झड़प के बाद रूस की तटस्थ नीति के चलते दोनों देशों के संबंध अब पहले की तरह तो नहीं रहेंगे। कहने वाले कह रहे थे कि कईयों को गिला यह था कि झड़प के बाद भी रूस की भारत के हक में ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई थी। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई भयंकर झड़प पर रूस ने कहा था कि वो भारत-चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण चिंता में है, लेकिन उसे उम्मीद है कि दोनों पड़ोसी देश इस विवाद को आपस में सुलझा सकते हैं। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारतीय सेना के कर्नल सहित 20 जवान मारे गए थे। चीन की सीमा पर यह पांच दशकों के बाद सबसे बड़ा सैन्य टकराव था, जिसने दोनों देशों के बीच पहले से ही अस्थिर सीमा गतिरोध को और बढ़ा दिया था। तब से भारत-चीन संबंध सामान्य नहीं हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से कहा गया था, 'निश्चित रूप से हम चीनी-भारतीय सीमा पर बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हम मानते हैं कि दोनों देश भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम हैं।' उस हिंसक झड़प में चीन को भी भारी नुकसान हुआ था जग हंसाई हुई थी सो अलग। रूस को अपना पुराना और भरोसे का मित्र मानते हुए भारत उससे कुछ अतिरिक्त की उम्मीद कर रहा था। भारत की

जनता की दिली इच्छा थी कि रूस उसी तरह से भारत के साथ खड़ा हो जैसे वह 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग के समय में खड़ा हुआ था। तब वह सोवियत संघ था। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की प्रतिक्रिया से वे लोग निराश ही हुए थे जिन्होंने भारत-सोवियत संघ मैत्री का दौर देखा था। तब सोवियत संघ भारत के भरोसे के मित्र के रूप में सामने आता था। भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग के समय सोवियत संघ ने भारत का हरसंभव साथ दिया था। यह बात भी सच है कि इन पचास सालों के दौरान दुनिया बहुत बदली है, पर इतनी भी नहीं बदली जितना कि रूस बदला। कायदे से उसे पूर्वी लद्दाख में झड़प के समय भारत के हक में खुलकर आगे आना चाहिए था। लेकिन, उसने औपचारिक किस्म का एक संतुलित बयान देकर अपनी जान छुड़ा ली थी।

फिर कुछ हलकों में यह भी कहा जा रहा था कि आतंकवाद से लड़ने के मामले में भी भारत को रूस का अपेक्षित साथ नहीं मिला। ब्रिक्स देशों के मंच पर भी नहीं। सारी दुनिया

चीन में रियल एस्टेट का संकट बढ़ा

Evergrande के बाद Kaisa ने किया डिफॉल्ट

Evergrande ने तो बॉन्ड पेमेंट में डिफाल्ट किया ही है, अब एक और कंपनी Kaisa ने भी डिफॉल्ट किया है। इसके बाद हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज ने Kaisa Group Holdings के शेयरों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है।

चीन की दो कंपनियों का डिफॉल्ट इससे दुनिया भर में बढ़ी चिंता

चीन के रियल एस्टेट बाजार (Real estate crisis China) का संकट बढ़ता जा रहा है। वहां की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी Evergrande ने तो बॉन्ड पेमेंट में डिफॉल्ट किया ही है, अब एक और कंपनी Kaisa ने भी डिफॉल्ट किया है। इसके बाद हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज ने Kaisa Group Holdings के शेयरों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी है। इसकी वजह से दुनियाभर के शेयर बाजार निवेशकों में चिंता बढ़ी है।

ऐसा माना जा रहा है कि 6.5 फीसदी रेट वाले बॉन्ड का पेमेंट न करने का मतलब यह है कि Kaisa तकनीकी रूप से डिफॉल्ट की श्रेणी में चली गई है। यह कंपनी Evergrande को पिछले महीने करीब 8.25 करोड़ डॉलर के ब्याज का भुगतान करना था, लेकिन वह विफल रही। इससे इस बात की आशंका है कि कंपनी अपने पूरे 19 अरब डॉलर के इंटरनेशनल बॉन्ड के लिए आगे चलकर डिफॉल्ट कर सकती है। ऐसा हुआ तो चीन की पूरी इकोनॉमी के लिए यह बड़ा झटका होगा और इसका पूरी दुनिया पर कुछ न कुछ असर होगा।

अब अपेक्षाकृत छोटी कंपनी Kaisa के कर्ज चुकाने में विफलता से ऐसा लगता है कि चीन के प्रॉपर्टी बाजार में नकदी का संकट बढ़ता जा रहा है। Evergrande को पिछले महीने करीब 8.25 करोड़ डॉलर के ब्याज का भुगतान करना था, लेकिन वह विफल रही। इससे इस बात की आशंका है कि कंपनी अपने पूरे 19 अरब डॉलर के इंटरनेशनल बॉन्ड के लिए आगे चलकर डिफॉल्ट कर सकती है। ऐसा हुआ तो चीन की पूरी इकोनॉमी के लिए यह बड़ा झटका होगा और इसका पूरी दुनिया पर कुछ न कुछ असर होगा।

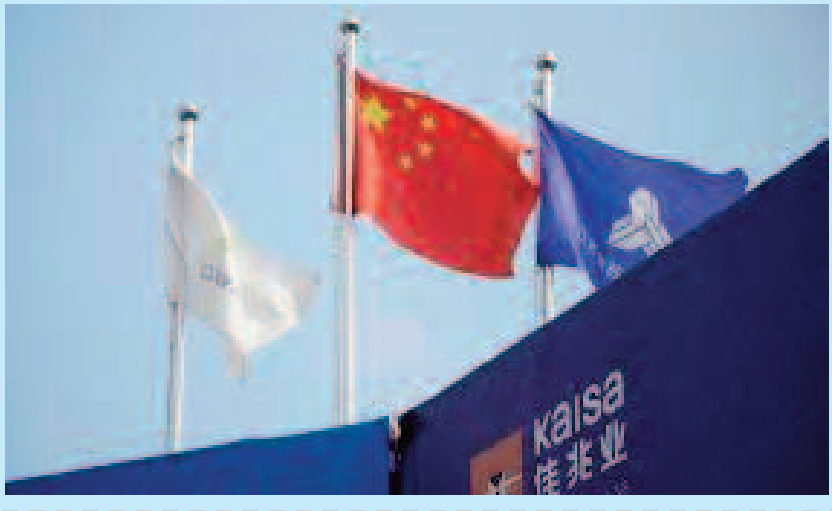

अब अपेक्षाकृत छोटी कंपनी Kaisa के कर्ज चुकाने में विफलता से ऐसा लगता है कि चीन के प्रॉपर्टी बाजार में नकदी का संकट बढ़ता जा रहा है। Evergrande के बाद विदेशी बाजार से बॉन्ड के द्वारा कर्ज जुटाने वाली सबसे बड़ी चीनी कंपनी है।

क्या है आशंका

खबर के अनुसार Kaisa करीब 40 करोड़ डॉलर के विदेशी कर्ज ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आशंका यह है कि आगे अपने करीब 12 अरब डॉलर के पूरे विदेशी बॉन्ड के लिए डिफॉल्ट कर सकती है।

Evergrande भी मुश्किल में

इसके पहले ऐसी खबर आई थी कि चीन के दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी Evergrande के कई विदेशी बॉन्ड होल्डर को 30 दिन का ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद भी कूपन पेमेंट यानी ब्याज भुगतान नहीं मिला। इससे ऐसा लग रहा है कि नकदी की तंगी से जूझ रहा यह समूह औपचारिक रूप से डिफॉल्ट होने के करीब है।

Evergrande को पिछले महीने करीब 8.25 करोड़ डॉलर के ब्याज का भुगतान करना था, लेकिन वह विफल रही। इससे इस बात की आशंका है कि कंपनी अपने पूरे 19 अरब डॉलर के इंटरनेशनल बॉन्ड के लिए आगे चलकर डिफॉल्ट कर सकती है। ऐसा हुआ तो चीन की पूरी इकोनॉमी के लिए यह बड़ा झटका होगा और इसका पूरी दुनिया पर कुछ न कुछ असर होगा।

अब अपेक्षाकृत छोटी कंपनी Kaisa के कर्ज चुकाने में विफलता से ऐसा लगता है कि चीन के प्रॉपर्टी बाजार में नकदी का संकट बढ़ता जा रहा है।

म्यांमारः भारत का मध्यम मार्ग

यह खुशी की बात है कि भारत सरकार अब म्यांमार (बर्मा) के बारे में सही और स्पष्ट रवैया अपना रही है। जिस दिन म्यांमार की नेता आंग सान सू ची को चार साल की सजा घोषित हुई थी, उसी समय मैंने लिखा था कि भारत सरकार की चुप्पी ठीक नहीं है। जब भी पड़ौसी देशों में लोकतंत्र का हनन हुआ है, भारत कभी चुप नहीं रहा है। चाहे वह पूर्वी पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो या मालदीव हो। लेकिन अब हमारे विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला ने स्वयं म्यांमार जाकर उसके फौजी शासकों, सू ची के पार्टी नेताओं और कई देशों के राजदूतों से खुला संवाद किया है। श्रृंगला ने साहसिक पहल की और फौजी शासकों से कहा कि वे जेल जाकर सू ची से मिलना चाहते हैं। फौजियों ने उसकी अनुमति उन्हें नहीं दी लेकिन इससे यह तो प्रकट हो ही गया कि भारत म्यांमार की घटनाओं के प्रति तटस्थ या उदासीन नहीं है। श्रृंगला ने फौजी शासकों को स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने इस पड़ौसी देश के लोकतंत्र के बारे में पूरी तरह से चिंतित है। 'एसियान' संगठन का म्यांमार सदस्य है लेकिन उसने आजकल म्यांमार का बहिष्कार कर रखा है लेकिन भारत उसके प्रति इतना सख्त रवैया नहीं अपना सकता। उसके दो कारण हैं। पहला

तो यह कि भारत के नगा और मणिपुर के बागियों को नियंत्रित करने में बर्मी फौज भारत की सक्रिय मदद करती है और दूसरा चीन वहां हर कीमत पर अपना वर्चस्व बढ़ाने पर आमादा है। संयुक्तराष्ट्र संघ में म्यांमार के फौजियों की काफी लानत-मलामत हो रही है लेकिन भारत ने म्यांमार पर मध्यम मार्ग अपना रखा है। वह फौज के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा है लेकिन उस पर अपना कूटनीतिक दबाव बराबर बना रहा है ताकि बर्मा में लोकतंत्र की वापसी हो सके। भारत ने पहले भी सू ची और फौज के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। म्यांमार में स्थित महाशक्तियों के राजदूतों ने भी श्रृंगला को सचेत करना उचित समझा। यह सच है कि 'एसियान' और संयुक्तराष्ट्र संघ में म्यांमार के खिलाफ सिर्फ प्रस्ताव पारित कर देने से खास कुछ होनेवाला नहीं है। भारत का मध्यम मार्ग ही इस समय व्यावहारिक और उचित है।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है और चीन का उसे खुला समर्थन मिलता है। चीन भी तो ब्रिक्स का सदस्य ही है। इसके बावजूद रूस ने कभी चीन को इस बिन्दु पर सलाह नहीं दी कि वह पाकिस्तान से दूरियां बनाएं। ब्रिक्स, यानी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संघ। इस में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। आतंकवाद के मसले पर सभी ब्रिक्स देशों को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ समवेत स्वर से बोलना चाहिए था। लेकिन, यह अबतक तो कभी नहीं हुआ। चीन ब्रिक्स आंदोलन को लगातार कमजोर करता रहा है। चीन भारत के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा है। चीन के इस रवैये पर रूस चुप ही रहता है। भारत रूस से यह उम्मीद तो नही करता कि वह चीन से अपने सभी संबंध तोड़ ले। पर इतनी अपेक्षा तो कर सकता है कि वह सही मसले पर बोले। सत्य का साथ दे। भारत- रूस का दायित्व है कि वे धूर्त चीन पर लगाम लगाने के लिए रणनीति बनाएं। यह सारी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिये जरूरी है।

बहरहाल, चालू साल 2021 भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस साल 1971 की ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के पांच दशक और हमारी सामरिक भागीदारी के दो दशक पूरे हो रहे हैं। पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार में 17 फीसद की गिरावट हुई थी, परन्तु इस साल पहले 9 महीनों में व्यापार में 38 फीसदकी बढ़ोतरी देखी गई है। दोनों देश स्वाभाविक रूप से सहयोगी हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर साथ ङ्कसाथ काम कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र, अंतरिक्ष सहित उच्च तकनीक के क्षेत्र शामिल हैं। यहां तक तो सब ठीक है।

भारत-रूस संबंध सारी दुनिया के लिए उदाहरण होने चाहिए। दोनों देशों को विश्व शांति और बंधुत्व के लिए सदैव प्रयासरत रहना होगा। अगर वे सिर्फ आपसी व्यापार में वृद्धि की ही बातें करेंगे और तब नेपथ्य में चले जाएंगे और जब दोनों पर संकट होगा तो फिर इस तरह की दोस्ती का मतलब ही क्या रहेगा?

आर.के. सिन्हा
(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तभकार और पूर्व सांसद हैं)

भूटान समेत अन्य पड़ोसियों के क्षेत्र हड़प रहा है चीन

डोकलाम में 2017 की तनातनी के बाद चीन ने भूटान समेत अपने अन्य पड़ोसियों के क्षेत्रों पर कब्जा जमाना जारी रखा है। ऐसा वह भविष्य में सैन्य बढ़त लेने के लिए कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2017 के बाद से ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सीमा और उसके बाहर भी चीन का विस्तार करने को लेकर मुखर रहे हैं। चीन का ध्यान तिब्बत और भूटान की सीमाओं पर केंद्रित है ताकि दक्षिण एशिया में

क्या है यूक्रेन विवाद?

रूस और अमेरिका के बीच तनी तलवारें

नाटो सैन्य गठबंधन के नेता, अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने की योजना बना रहा है। हालांकि रूस ने इस तरह की किसी भी योजना से इनकार किया है। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था तभी से उसके और यूक्रेन के बीच तनाव बना हुआ है।

सोवियत रूस के दो अलग हुए भाई रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) अपनी सीमाओं पर सेनाओं की बड़े पैमाने पर तैनाती को लेकर आमने-सामने हैं। नाटो (NATO) सैन्य गठबंधन के नेता, अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने की योजना बना रहा है। हालांकि रूस ने इस तरह की किसी भी योजना से इनकार किया है। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था तभी से उसके और यूक्रेन के बीच तनाव बना हुआ है।

बताया जा रहा है कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हाल ही में हुई एक बैठक में अमेरिका के विदेश सचिव एंटोनी ब्लिंकेन ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के सामने दोहराया था कि अमेरिका ने रूस को यूक्रेन के साथ पश्चिमी सीमा से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का आह्वान किया है।

अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, ब्लिंकेन ने साफ कर दिया है कि अगर रूस अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी तैयार हैं और रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ब्लिंकेन की बातों से यह साफ नहीं था कि कीमत चुकाने से उनका क्या मतलब था। उनका मतलब किसी तरह की सैन्य प्रतिक्रिया से था या कुछ और।

यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 90 हजार से ज्यादा सैनिक सीमा पर जुटे हैं और उनके साथ बख्तरबंद गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां भी मौजूद हैं। इसी को लेकर यूक्रेन और नाटो गठबंधन चिंतित है कि रूस किसी तरह के आक्रमण की कोई योजना तो नहीं बना रहा है।

उधर रूस का कहना है कि यूक्रेन ने 1 लाख 20 हजार सैनिकों को सीमा पर तैनात कर रखा है और वह पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र को दोबारा हासिल करने में लगा हुआ है। यूक्रेन ने इस आरोप को गलत ठहराया है।

क्या यह अचानक पैदा हुआ तनाव है?

रूस और यूक्रेन के बीच मतभेद नस्लीय दावे के रूप में सामने आया है। वहीं विशेषज्ञ इस विवाद को भू राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। यूक्रेन ना तो यूरोप यूनियन और न ही नाटो का हिस्सा है फिर भी उसकी पश्चिमी यूरोप और नाटों के साथ बढ़ती निकटता ने रूस के माथे पर शिकन ला दी है। और वह इसे अमेरिकी नेतृत्व में उसके प्रभावी क्षेत्र में सीधे हस्तक्षेप के रूप में देख रहा है।

2014 में रूस ने क्रीमिया पर तब कब्जा किया जब यूक्रेन की जनता यूरोपीय संघ के साथ गहरे आर्थिक संबंधों पर जोर दे रही थी। इस दिशा में उठाए गए कदम को यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने रद्द कर दिया था, जो भारी विरोध के चलते देश से भाग गए थे। एक महीने बाद मार्च, 2014 को रूस की सेना क्रीमिया में पहुंच गई और उस पर कब्जा कर लिया,और एक विवादित जनमत संग्रह के तहत यह दिखाया गया कि क्रीमिया की जनता ने रूस का समर्थन किया है। कब्जे के चलते यूक्रेन ने पश्चिमी ताकतों और अमेरिका से रूस के खिलाफ कदम उठाने के लिए मदद मांगी, यह बात रूस को नागवार गुजरी थी।

यूक्रेन की नाटो से कितनी निकटता?

यूक्रेन ने इस मामले के चलते यूरोपीय संघ और नाटो से प्रतिबंध पैकेज तैयार करने और रूस के आक्रामक रवैये के खिलाफ सहयोग की गुजारिश की है। हालांकि रूस नाटो के दिए किसी भी झटके का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पुतिन ने मास्को में कहा था कि नाटो की यूक्रेन में किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि वह पश्चिमी देशों से भरोसेमंद और दीर्घ अवधि सुरक्षा की गारंटी चाहेंगे और नाटो पूर्व की ओर अपने कदम बढ़ाने से खुद को रोकेगा। पुतिन ने कहा कि वो अमेरिका और उसके सहयोगियों से इस बारे में बात करेंगे जिसमें उन समझौतों पर जोर दिया जाएगा जो नाटो को पूर्व की ओर अपने कदम को बढ़ाने से रोक सके। जिससे रूस को अपने क्षेत्र में किसी की हस्तक्षेप की धमकी मिलती है।

2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के साथ रूस और यूक्रेन में शांति कायम रखने को लेकर एक समझौता हुआ था जिसे मिन्स्क समझौता कहा गया था जो अभी भी जैसे तैसे कायम है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह यूक्रेन के प्रतिकूल था।

अमेरिका की प्रतिक्रिया

अमेरिकी विदेश सचिव ब्लिंकेन ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा था कि रूस के यूक्रेन पर हमले की योजना के उनके पास पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने स्टॉकोम में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि रूस भले ही युक्रेन पर हमले से इनकार करे, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि वह (पुतिन) कम वक्त में ऐसा करने की क्षमता रखते हैं।

ब्लिंकेन ने कहा कि हमने साफ कर दिया है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो दृढ़ता से जवाब देंगे जिसमें आर्थिक प्रभाव भी शामिल होगा। अमेरिकी राजनयिक और सैन्य संस्थानों ने हालांकि यह साफ नहीं किया है कि प्रतिक्रिया किस तरह की होगी, बस ब्लिंकेन ने यह कहा कि इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे।

वहीं अमेरिकी सैन्य चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख मार्क मिले ने कहा कि इस तरह से अमेरिका और नाटो देशों के सुरक्षा हित दांव पर लगे हैं, रूस ने ऐसे देश पर सैन्य कार्रवाई की थी जो 1991 से स्वतंत्र था। वहीं रूस का मानना है कि नाटो ने तनाव कम करने और खतरनाक घटनाओं से बचने की हमारे प्रस्तावों की रचनात्मक जांच से इनकार कर दिया है। वहीं गठबंधन का सैन्य ढांचा रूस की सीमाओं के करीब आ रहा है।

इसी बीच रूस और अमेरिका अपने अपने देशों में राजनयिकों के निष्कासन में लगे हुए हैं, रूस ने जहां रूसी विदेश मंत्रालय से अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को 31 जनवरी तक देश छोड़ने को कहा है। यह उन लोगों के लिए है जो तीन साल से मास्को में तैनात थे। वहीं अमेरिका में 27 रूसी राजनयिक और उनके परिवार 30 जनवरी तक अमेरिका छोड़ देंगे।

इसके साथ ही क्रीमिया पर कब्जे के बाद से रूस पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसके अलावा यूक्रेन को सैन्य हथियारों की मंजूरी के साथ साथ अमेरिका ने एक अरब डॉलर की रक्षात्मक सहायता भी प्रदान की है।

तनाव कम करने के लिए कोई प्रयास किए गए

ऐसा कहा जा रहा है कि ब्लिंकेन और लावरोव की बैठक के बाद जल्दी ही पुतिन और जो बाइडेन संपर्क कर सकते हैं। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा था कि संपर्क होना बहुत जरूरी है, हमारी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेनस्की ने भी रूस के साथ बातचीत पर जोर दिया है।

भारत की बढ़त को थामा जा सके।

खासकर तिब्बत की सीमा से लगे इलाकों पर स्वतंत्र सैटेलाइट तस्वीरें ये साबित करती है कि चीन चालाकी से भारत और भूटान से लगी सीमाओं पर विवादित क्षेत्र में गांवों का निर्माण कर रहा है ताकि भविष्य में इनपर अपना दावा पुख्ता कर सके।

हाल ही में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव वू यिंगजी ने ऐसे ही एक गांव ग्यालफुग का दौरा किया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर बसाया गया है। ये गांव 1980 से किए जा रहे चीन के दावे वाले 232 वर्ग मील क्षेत्र में बसाया गया है जबकि अंतरराष्ट्रीय रूप से ये उत्तरी भूटान के हुंसे जिले का अंग है।

चीन 1990 के दशक से भूटान को ये प्रस्ताव दे रहा है कि यदि भूटान अपने हिस्से वाले डोकलाम, चारितांग, सिनचुलंग्पा, ड्रामना, शाखतो और साकतेंग क्षेत्रों के 269 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को दे देता है तो चीन 495 वर्ग किलोमीटर के अपने दावे वाले क्षेत्र पर दावा करना बंद कर देगा और भूटान को भारी वित्तीय मदद भी देगा। हालांकि भूटान ने इस पैकेज डील को ठुकरा दिया।

लोकतंत्र सम्मेलन पर बोला चीन, हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा अमेरिका

चीन ने शनिवार को अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह लोकतंत्र का इस्तेमाल मतभेद बढ़ाने और देशों को एक-दूसरे से लड़ाने के 'सामूहिक विनाश' के हथियार के रूप में कर रहा है। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन की आलोचना करते हुए ये बात कही।

चीन का दावा है कि इस सम्मेलन का आयोजन चीन को अलग-थलग करने के उद्देश्य से किया गया है। ऑनलाइन तरीके से आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के 100 से अधिक देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। शुक्रवार को समाप्त हुए इस सम्मेलन में विश्व नेताओं ने चुनावों की पवित्रता और मानवाधिकारों की रक्षा करने तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। ■

विनीत
नारायण

क्या हेलिकॉप्टर हादसे रोके जा सकते हैं?

देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत व अन्य सैनिकों की शहादत से पूरा देश सदमे में है। कुन्नुर में हुआ यह दर्दनाक हादसा पहला नहीं है। भारत के इतिहास में ऐसे दर्जनों हादसे हुए हैं जिनमें देश के सैनिक, नेता व अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों ने अपनी जान गवाई है। सवाल यह है कि क्या हम इन हादसों से कुछ सबक ले पाए हैं? जिस एमआई सीरिज के रूसी हेलिकॉप्टर में जनरल रावत सवार थे वो एक बेहद भरोसेमंद हेलिकॉप्टर माना जाता है। दुर्घटना का कारण क्या था यह तो जांच के बाद ही सामने आए। परंतु जिस तरह हम अन्य विषयों में तकनीक की मदद से तरक्की कर रहे हैं उसी तरह वीआईपी हेलिकॉप्टर यात्रा में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे ?

इस हादसे के कारण पर तमाम तरह के कयास लाए जा रहे हैं। पिछले कुछ हादसों की सूची को देखें तो ऐसा भी माना जा रहा है कि वीआईपी उड़ानों में, खराब मौसम के चलते, पाइलट के मना करने पर भी वीआईपी द्वारा उड़ान भरने का दबाव डाला जाता रहा है। फिर वो चाहे 2001 का कानपुर का हादसा हो, जिसमें माधवराव सिंधिया ने अपनी जान गवाईं थी या फिर 2011 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुआ हादसा जिसमें मुख्य मंत्री खंडू की मौत हुई थी। जानकारों की मानें तो रूस में बने इस अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर को यदि खतरा हो सकता था तो वो केवल खराब मौसम का ही। गौरतलब है कि वीआईपी उड़ानों में इस हेलिकॉप्टर को केवल अनुभवी पाइलट ही उड़ाते हैं और ऐसा ही इस उड़ान के लिए भी किया गया।

वीआईपी यात्राओं के लिए विभिन्न हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल वायुसेना व नागरिक उड्डयन दोनों में होता है। परंतु भारत में अभी तक इन उड़ानों के लिए 'विजूअल फ्लाइट रूल्ज' (वीएफआर) ही लागू किए जाते हैं। वीएफआर नियम और कानून के तहत विमान उड़ाने वाले पाइलट को कॉक्पिट से बाहर के मौसम की स्थिति साफ-साफ दिखाई देनी चाहिए जिससे कि वह विमान के बीच आने वाले अवरोध, विमान की ऊंचाई आदि का पता चलता है। इन नियम को लागू करने वाले नियंत्रक नियम लागू करते समय इन बातों को सुनिश्चित करते हैं कि विमान की उड़ान के लिए मौसम की स्थिति, विजिबिलिटी, विमान की बादलों से दूरी आदि उड़ान के लिए अनुरूप हैं। मौसम के मुताबिक इन सभी परिस्थितियों के अनुसार विमान की उड़ान जिस इलाके में होनी है वह उस इलाके के अधिकार क्षेत्र के मुताबिक बदलती रहती है। कुछ देशों में तो वीएफआर की अनुमति रात के समय में भी दी जाती है। परंतु ऐसा केवल प्रतिबंधात्मक शर्तों के साथ ही होता है।

वीएफआर पाइलट को इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि उसका विमान न तो किसी अन्य विमान के रास्ते में आ रहा है और न ही उसके विमान के सामने कोई अवरोध हैं। यदि उसे ऐसा कुछ दिखाई देता है तो अपने विमान को इन सबसे बचा कर उड़ाना केवल पाइलट की जिम्मेदारी होती है। ज़्यादातर वीएफआर पाइलट 'एयर ट्रैफिक कंट्रोल' या एटीसी से निर्धारित रूट पर नहीं उड़ते। लेकिन एटीसी को वीएफआर विमान को अन्य विमानों के मार्ग से अलग करने के लिए वायुसीमा अनुसार, विमान में एक ट्रान्सपोंडर का होना अनिवार्य होता है। ट्रान्सपोंडर की मदद से रेडार पर इस विमान को एटीसी द्वारा देखा जा सकता है। यदि वीएफआर विमान के लिए मौसम व अन्य परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं तो वह विमान 'इंस्ट्रुमेंट फ़्लाइट रूल्ज' (आईएफआर) के तहत उड़ान भरेगा। आईएफआर की उड़ान ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है।

जिन इलाकों में मौसम अचानक बिगड़ जाता है वहां पर उड़ान भरने के लिए पाइलट को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। अन्य देशों में जिन पाइलट्स के पास केवल वीएफआर की उड़ानों की योग्यता होती है उन्हें बदलते मौसम वाले क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाती।

जनरल रावत के हेलिकॉप्टर को वायुसेना के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान उड़ा रहे थे। वे सुलुर में 109 हेलिकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर भी थे। उन्हें इस तरह की उड़ानों का अच्छा-ख़ासा अनुभव था। विषम परिस्थितियों में उन्होंने इस तरह के हेलिकॉप्टर को कई बार सुरक्षित उड़ाया। हेलिकॉप्टर को ख़राब मौसम का सामना करना पड़ा या उसमें कुछ तकनीकी ख़राबी हुई इसका पता तो जांच के बाद ही लगेगा। लेकिन आमतौर पर ऐसे में जांच आयोग पाइलट की गलती बता देते हैं। लेकिन जानकारों की माने तो इस हादसे में पाइलट की

अमेरिका के षड्यंत्र और भारत की कूटनीति

1. यह पूर्णत: स्पष्ट हो चुका है कि कोरोना वायरस अमेरिका का एक षड्यंत्र है जो चीन से व्यापार युद्ध जीतने के लिए अमेरिका ने छोड़ा था। अमेरिका का साथ देने वाले देशों को लगा था कि चूंकि डेल्टा वेरिएंट के कारण जिस प्रकार दुनिया के व्यापार समीकरण बिगड़े और चीन को अतिशय नुकसान हुआ व पूरी दुनिया में बीमारों व मृतकों के ढेर लग गए, उससे अमेरिका का उद्देश्य पूरा हो गया और यह खेल अब और आगे नहीं बढ़ेगा। किंतु जब कोरोना का नया वेरिएंट ऑमिक्रॉन सामने आया तो अमेरिका का साथ देने वाले देश दहल गए। इसी पर भारत के सीडीएस बिपिन रावत ने टिप्पणी की थी-

सीडीएस जनरल रावत की चेतावनी- जैविक युद्ध में बदल सकती है कोरोना महामारी

कोरोना महामारी व उसके नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने चेतावनी दी थी कि यह महामारी जैविक युद्ध में बदल सकती है।

जनरल रावत ने कहा था कि ऐसे हालात में विश्व के सभी देशों को इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

क्या यह महामारी एक नए प्रकार के युद्ध का स्वरूप ले रही है। हम लोगों को खुद को मजबूत कर इससे निपटना होगा ताकि ये वायरस और बीमारियां हमारे देश को प्रभावित न कर सकें। उन्होंने कहा कि अब कोरोना का ओमिक्रोन वेरिएंट सामने आया है। अगर यह अन्य रूपों में बदलता है तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी कोरोना के नए वेरिएंट के उभरने और संक्रमण बढ़ने को लेकर चेतावनी दी।

2. चीन द्वारा भी बार बार यह कहा गया कि

US behind Corona?

China is pushing a new theory about the origins of the coronavirus: It is an American disease that might have been introduced by members of the United States Army who visited Wuhan in October.

3. डायलॉग इंडिया में भी अपने शोध आलेख में यही निष्कर्ष निकाले थे।

कोरोना वायरस - विश्व की सरकार के लिए अमेरिका व ₹-20 देशों का जैविक हथियार ? - अनुज अग्रवाल

http://dialogueindia.in/कोरोना-वायरस-विश्व-की-सरक/

4. अमेरिका को संतुलित रखते हुए भारत चीन के साथ अपने व्यापार को पिछले वर्ष में बढ़ाता रहा और उसने रूस के साथ भी रक्षा समझौते को हाल ही में दस साल और बढ़ाया है। अमेरिका इसके खिलाफ था।

भारत के द्वारा रूस से एस 400 मिसाइल सिस्टम खरीदने से अमेरिका को लगी मिर्ची

भारत के द्वारा रूस से एस-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे जाने से अमेरिका का दोगला चरित्र सामने आ गया है। भारत से अपनी दोस्ती की बात करने वाला अमेरिका अब चाहता है कि भारत रूस से यह सिस्टम न खरीदे। अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ने नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि जो भी देश एस-400 का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, उन्हें लेकर हमारी नीतियां सार्वजनिक रही हैं। हमें लगता है कि ये खतरनाक है और ये किसी के भी सुरक्षा हितों में नहीं है।

5. चीन के साथ टेंशन का ट्रेड पर असर नहीं

भारत और चीन के बीच आपसी कारोबार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एक जनवरी से 30 नवंबर 2021 के बीच दोनों देशों में कुल 8.57 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जो पिछले पूरे साल के मुकाबले 46.4% ज्यादा है। अहम बात यह है कि इन 11 महीने में भारत ने चीन से 6.59 लाख करोड़ रु. का सामान खरीदा, जो पिछले साल के मुकाबले 49% ज्यादा है।

वहीं, चीन ने भारत से कुल 1.98 लाख करोड़ रु. का सामान खरीदा, जो पिछले साल के मुकाबले 38.5% ज्यादा है।

अमेरिका बिपिन रावत के जैविक युद्ध वाले बयान और रूस से एस-400 मिसाइल सिस्टम व चीन से बढ़ते भारत के व्यापार से नाराज है। वह चाहता है कि भारत पूरी तरह अमेरिका के पाले में आ जाए। जबकि मोदी सरकार चीन, रूस और अमेरिका सहित सभी देशों से संतुलित संबंध बनाए रखने की नीति पर अडिग है। इसीलिए आशंका यह भी हैं कि जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत एक हादसा न हो ।

- अनुज अग्रवाल

गलती नहीं लगती।

ऐसे हादसों में जांच को कई पहलुओं से गुजरना पड़ता है। इनमें तकनीकी खराबी, पाइलट की गलती, मौसम और हादसे की जगह की स्थिति महत्वपूर्ण होती हैं। इन सभी विषयों की गहराई से जांच होती है तभी किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। जांच का केवल एक ही मकसद होता है, आगे से ऐसे हादसे फिर न हों।

जब भी कोई हादसा होता है तो तमाम टीवी चैनलों पर स्वघोषित विशेषज्ञों की भरमार हो जाती है जो इस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। परंतु कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि भारत में अन्य देशों की तरह वीआईपी हेलिकॉप्टर उड़ानों के लिए वीएफआर को लागू क्यों किया जा रहा? भारत के नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) और वायुसेना को इस बात पर भी गौर करना चाहिए। कब तक हम ऐसे और हादसों के साक्षी बनेंगे?

यह हादसा पिछले हादसों से अलग नहीं है। बल्कि उन्हीं हादसों की सूची में एक बढ़ता हुआ अंक है। बरसों से वीएफआर के नियम, जिन्हें केवल हवाई अड्डों के नियंत्रण वाली सीमा में ही प्रयोग में लाया जाता है, के द्वारा ही हवाई अड्डों के बाहर व अन्य स्थानों में प्रयोग में लाया जा रहा है। जबकी होना यह चाहिए कि डीजीसीए और वायुसेना के साझे प्रयास से वीएफआर की समीक्षा होनी चाहिए और ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ■

आर.के. सिन्हा

जनरल रावत से कांपते थे चीन-पाक

एक बेहद दुखद हेलिकॉप्टर हादसे में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत के निधन से सारे देश का शोक में डूबना लाजिमी है। जनरल रावत के अलावा 12 अन्य लोगों की मौत हो गई है। देश को आगामी 16 दिसंबर को पाकिस्तान से 1971 की जंग में विजय के पचास साल के अवसर पर जश्न मनाना था और शहीदों को याद करना था। जाहिर है, उन सब कार्यक्रमों पर भी जनरल रावत के न रहने से गहरा असर पड़ेगा। जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस बनाया गया था। वे इससे पहले भारतीय सेना के प्रमुख भी रहे थे। उन्हें थल सेना और जल सेना के कामकाज की भी गहन समझ थी। वे तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बैठाने का काम शानदार तरीके से कर रहे थे।

जनरल रावत चीन के मामलों के गहन विशेषज्ञ थे और चीन और पाकिस्तान के साथ सरहद पर चल रही तनातनी पर सरकार को लगातार सलाह देते थे। उनका मानना था कि देश किसी भी परिस्थिति में दबेगा नहीं। वह शत्रुओं की ईंट का जवाब पत्थर से देगा। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर जनरल रावत ने कहा था कि 'लद्दाख में चीनी सेना के अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्प भी है । लेकिन, यह तभी अपनाया जाएगा जब सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वार्ता विफल रहेगी।' रावत के बयान से आम हिन्दुस्तानी आश्वस्त हुआ था कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। वह एक सधा हुआ संतुलित बयान था।

पर जनरल रावत देश को कभी अंधेरे में नहीं रखते थे। उन्होंने चीन को भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा बताया था। कुछ समय पहले ही जनरल रावत ने कहा था, भारत के लिए चीन सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बन गया है और हजारों की संख्या में सैनिक और हथियार, जो देश ने हिमालयी सीमा को सुरक्षित करने के लिए पिछले साल भेजे थे, लंबे समय तक बेस पर वापस नहीं लौट सकेंगे। जनरल रावत ने चीन को लेकर कुछ ऐसा कहा कि चीन को बहुत बुरा लगा। तिलमिलाए चीन रावत के बयान पर कहा, भारतीय अधिकारी बिना किसी कारण के तथाकथित 'चीनी सैन्य खतरे' पर अटकलें लगाते हैं, जो दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन का गंभीर उल्लंघन है कि चीन और भारत एक दूसरे के लिए खतरा नहीं हैं।

चीन भले ही कुछ भी कहता रहे अपने पक्ष में, पर यह बात साफ है कि भारत के सामने असली चुनौती चीन की ही है। जब से जनरल रावत ने सीडीएस का कामराज संभाला था, वे तब से सेना के तीनों अंगों को तैयार कर रहे थे कि अगर भारत को चीन-पाकिस्तान का एक साथ जंग के मैदान में सामना करना पड़े तो भी भारत पीछे न रहे। उनकी इस सोच के चलते भारतीय फौज भी अपने को लगातार तैयार कर रही थी। ये सब सैन्य तैयारियां चीन-पाकिस्तान देख रहे थे। उन्हें जनरल रावत के एग्रेसिव सोच का पता चल चुका था। दरअसल चीन को लेकर जो राय जनरल रावत व्यक्त कर रहे थे वही पूर्व रक्षामंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस कई साल पहले कर चुके थे। उन्होंने चीन को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। पोखरण-2 परमाणु परीक्षण के बाद तत्कालीन एनडीए सरकार के रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडीस ने दावा किया था कि भारत का चीन दुश्मन नंबर वन है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना था कि जॉर्ज साहब ने यह बयान रक्षा मंत्री रहने के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर दिया होगा। जॉर्ज के अलावा पूर्व रक्षामंत्री मुलायम सिंह यादव भी मानते थे कि भारत का पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है। साल 2017 में डोकलाम विवाद के बाद लोकसभा में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। केंद्र सरकार को आगाह करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

बहरहाल, रक्षा मामलों के कुछ जानकार मानते भी हैं कि अगर अब कभी भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ,तो पाकिस्तान भी मैदान में खुलकर आएगा चीन के हक में। इसी के साथ अगर पाकिस्तान का भारत के साथ युद्ध हुआ तो चीन भी पाकिस्तान के हक में लड़ेगा। रक्षा मामलों के जानकार और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तो सार्वजनिक रूप से यह कहते रहे हैं कि अगर भारत-चीन युद्ध छिड़ता है तो पाकिस्तान शांत नहीं बैठेगा। वह भी चीन के हक में लड़ेगा।

बेशक, चीन और पाकिस्तान के तेवर देखते हुए भारतीय सुरक्षा बलों को जमीनी और समुद्री सीमाओं पर पूरे साल सतर्क रहना पड़ रहा है। भारतीय सेनाएं इस जिम्मेदारी को जनरल रावत की सरपरस्ती में बखूबी निभा रही थीं। जनरल रावत के आकस्मिक निधन के बाद भी भारत की चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तनाव खत्म नहीं होने वाला। यह तो मानकर ही चलिए। मतलब भारत अपने दो शत्रु देशों का सरहद पर एक साथ प्रतिदिन ही सामना करता रहेगा। जब तक उन्हें एक बार अच्छी तरह से ठंढा न कर दे दृ ये साबित कर चुके हैं कि ये बाज नहीं आएंगे। इनसे मैत्रीपूर्ण संबंधों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो भारत को अपने इन पड़ोसी मुल्कों की नापाक हरकतों का मुकाबला करने के लिए हर वक्त चौकस रहना ही होगा। जनरल रावत के स्थान पर बनने वाले देश के नए सीडीए के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वे अपने पूर्ववर्ती यानी जनरल रावत के समय सेना को मजबूत करने के कार्यों को जारी रखें। यही उस महान योद्धा के प्रति देश की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वे देवभूमि उत्तराखंड के गौरव और देश के योद्धा थे। कृतज्ञ भारत उन्हें सदैव याद रखेगा।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तभकार और पूर्व सांसद हैं।)

इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वालों की बढ़ रही संख्या

● शंकर शरण

वसीम रिजवी के इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाने के बाद इस बात का कहीं न कहीं बल मिल रहा है कि अब ये फैसला करने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इससे पहले इंडोनेशिया के संस्थापक की पुत्री सुकमावती सुकर्णोपुत्री ने भी ऐसा ही किया था।

शंकर शरण। बीते दिनों वसीम रिजवी ने सनातन धर्म ग्रहण कर लिया। इसके पहले इंडोनेशिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति की पुत्री सुकमावती सुकर्णोपुत्री ने इस्लाम छोड़ विधिवत हिंदू धर्म स्वीकार किया था। मुस्लिम देशों में इस्लाम छोड़ने, उस पर विश्वास न रखने और इस्लामी मान्यताएं ठुकराने वाले मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सुकर्णोपुत्री जैसी बड़ी हस्ती द्वारा इस्लाम छोड़ने पर दुनिया के इस्लामी नेताओं से कोई धमकी न आना भी एक संकेत है।

कुछ समय पहले कनाडियन-अफ्रीकी मौलवी बिलाल फिलिप्स ने 'इस्लाम छोड़ने की सुनामी' आने की आशंका जताई थी। प्रसिद्ध अरब विशेषज्ञ डा. डैनियल पाइप्स का अवलोकन भी ध्यातव्य है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़े पाइप्स कई दशकों से अरब मामलों के अध्ययनकर्ता हैं। उनका भी मानना है कि मुस्लिम जगत में अपने मजहब से दूर होना 'जंगल की आग' सरीखा फैल रहा है। इस्लाम छोड़ने वाले ठसक से यह बता भी रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। अभी तुर्की मूल की लाले गुल ने एक संस्मरण पुस्तक, 'मैं जीना चाहती हूं' लिख कर अपनी घोषणा की। वह पुस्तक तुर्की में सर्वाधिक बिक रही है। यह अब अनेक मुस्लिम देशों में हो रहा है।

दुनिया में इस्लामी संगठनों, सत्ताओं के काम, बयान ही सुर्खियों में रहते हैं। उसके विपरीत प्रक्रिया अपेक्षाकृत चर्चाहीन रहती है, पर अब यह बदल रहा है। इस्लामिक स्टेट, तालिबान आदि के कारनामों ने मुसलमानों के एक वर्ग में राजनीतिक इस्लाम पर बुनियादी संदेह भी पैदा किया है। यह मुख्यत: चार रूपों में व्यक्त हो रहा है। कठोर इस्लामी कायदे छोड़ना, सभी मजहबी कायदों से छुट्टी करना, नास्तिक हो जाना और दूसरे धर्म अपना लेना। चारों रूप कई मुस्लिम देशों में बढ़ रहे हैं, किंतु अलग-अलग मुस्लिम देश में किसी खास चीज की प्रमुखता भी दिख रही है। जैसे तुर्की में नास्तिकता बढ़ रही है।

सऊदी अरब में इस्लाम छोड़ने वाले बढ़ रहे हैं। ईरान में मतांतरण हो रहा है। मिस्र में कठोर इस्लामी कायदे छोड़े जा रहे हैं। यह सब स्वत: हो रहा है। इसमें किसी बाहरी कारक का जिक्र नहीं आया। यानी मुसलमान स्वयं अपनी नियति तय करने की ओर बढ़ रहे हैं। मुल्ला-मौलवियों को सब कुछ तय करने देने की परंपरा तोड़ रहे हैं। मिस्र में उग्रवादी इस्लामी संगठनों के लोगों को नीची नजरों से देखा जाने लगा है। कभी-कभार सड़कों पर उनकी पिटाई भी हो जाती है। स्त्रियां अपने हिजाब फेंक कर विरोध दर्शाती हैं। इस्लाम के आलोचक लेखकों, पत्रकारों की संख्या और लोकप्रियता बढ़ी है। तुर्की युवाओं में गैर-इस्लामी तौर-तरीके लोकप्रिय हो रहे हैं। वे इस्लामी विश्वासों के विपरीत विचार अपना रहे हैं। धर्म-विश्वास ही नहीं, संस्कृति, आपसी संबंध, पोशाक, खान-पान आदि में भी गैर-इस्लामी व्यवहार अधिक प्रचलित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट ने भी नोट किया कि मदरसों के छात्र ज्ञान, स्वानुभूति और आध्यात्मिक भाव-चिंतन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अर्थात मुल्ला-मौलवियों के मूल दावों को ही खारिज कर रहे हैं। विन-गैलप संस्था द्वारा किए सर्वेक्षण में 73 प्रतिशत तुर्क लोगों ने अपने को 'गैर-मजहबी' बताया। किसी मुस्लिम देश में अपने मजहब से उदासीन लोगों की यह सबसे बड़ी संख्या है। विन-गैलप के सर्वेक्षण में पांच प्रतिशत सऊदी नागरिकों ने अपने को 'पक्का नास्तिक' कहा। अमेरिका में भी इतने ही लोग अपने को पक्का नास्तिक कहते हैं। यह भी नोट करें कि सऊदी सरकार नास्तिकता रोकने के लिए आतंकवाद-विरोधी कानून का प्रयोग कर रही है। इसी से पूरी स्थिति का अनुमान हो जाता है। दूसरी ओर वही सरकार शिक्षा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था में गैर-इस्लामी चीजें मंजूर कर रही है।

गैर-मुसलमानों के लिए निषिद्ध कुछ क्षेत्र अब सबके लिए खोले जा रहे हैं। साफ है वहां इस्लामी मत का निर्विवाद एकाधिकार अब पहले जैसा नहीं रह गया। यदि नागरिकों को स्वतंत्रता मिले तो स्थिति कुछ भी हो सकती है।

ईरान में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ रहा है। ईरानी सरकार में मंत्री महमूद अलावी ने सार्वजनिक रूप से माना कि कई मुस्लिम क्रिश्चियन बने हैं। मंत्रियों की टिप्पणियां इक्की-दुक्की घटनाओं पर शायद ही होती हों।

इस्लाम से दूरी बना रहे मुसलमान केवल मजहब ही नहीं, बल्कि परिवार, सामाजिक संबंध, राजनीति आदि में भी इस्लामवादियों के विपरीत रुख ले रहे हैं। वे स्वतंत्रतापूर्वक सोच-विचार कर रहे हैं और मजहबी निर्देशों के अनुसार चलने से इन्कार कर रहे हैं। इजरायल से अनेक मुस्लिम देशों के संबंध बढ़ना भी एक तथ्य है। इस्लाम छोड़ने वाले मुसलमान यूरोप, अमेरिका में भी हैं। प्यू रिसर्च के एक आकलन के अनुसार अमेरिका में सालाना एक लाख मुसलमान इस्लाम छोड़ते हैं। फ्रांस में सालाना 15 हजार मुसलमान दूसरे धर्म अपनाते हैं। यह उन देशों में कुल मुस्लिम जनसंख्या के हिसाब से मामूली है, किंतु रुझान के रूप में वहां भी मौजूद है।

एक बिल्कुल नई बात यह कि अब इस्लाम छोड़ने वाले संगठित होकर या अकेले अपनी बातों का प्रचार भी कर रहे हैं। इस्लामी मतवाद के तत्वों का खंडन, विश्लेषण आदि करके मुस्लिम जगत में फैला रहे हैं। इस्लाम छोड़ने वाले नए लोगों को सहयोग, सहायता, बल पहुंचा रहे हैं। कई पूर्व-मुस्लिम यू-ट्यूब, वेबसाइट, पुस्तकों आदि द्वारा यह कर रहे हैं। उन्हें सुनने, पढ़ने वालों की संख्या काफी है। ऐसे लिखने-बोलने वाले पूर्व-मुस्लिमों के विरुद्ध धमकियों, हिंसा आदि का दबाव और भय, दोनों कम हो रहा है। यह स्वाभाविक है। जब निर्भीक लोगों की संख्या बढ़ती है, तब धमकी देने वालों का मनोबल कमजोर होता ही है। फिर बड़े-बड़े मौलवी-मौलाना पूर्व-मुसलमानों के सवालों, दलीलों पर निरुत्तर रहते हैं। धमकियों और फटकार के सिवाय उनके पास कोई उत्तर नहीं।

डा. डैनियल पाइप्स ध्यान दिलाते हैं कि अरब से ही नई-नई प्रवृत्तियां, मान्यताएं, व्यवहार आदि पूरे विश्व के मुस्लिमों के बीच फैलते रहे हैं। जैसे खास वेश-भूषा, वहाबीवाद, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट आदि सभी प्रमुख आंदोलन या तरीके वहीं से दुनिया के मुसलमानों में फैले। संभव है कि कुछ समय बाद इस्लाम से उदासीनता और इस्लाम छोड़ने की हवा नाइजीरिया, बांग्लादेश, मलेशिया आदि देशों में भी दिखने लगे। भारतीय मुसलमानों में भी सकारात्मक बदलाव संभव है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अधिक और अग्रणी बौद्धिक मुसलमान भारत से ही हुए हैं।

(लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

कूटनीतिक हलचल

रूस पीठ पर वार करता है

1965 का धोखा हम कैसे भूल सकते हैं। अब एक बार फिर शतरंज की बाजी मेज पर सज चुकी है।

जिनपिंग आ रहे हैं भारत और इस मीटिंग की संरचना रूस ने की है। कहने को भारत और चीन के बीच शुरू हुए छद्म युद्ध को समाप्त करने के लिए इस मीटिंग को रखा गया है पर चीन पीठ पर वार करने के लिए जाना जाता है। 1962 का युद्ध और उसका परिणाम इसका जीता जागता उदाहरण है जिसकी टीस आज भी यदा कदा हमारी छाती को छलनी करती रहती है।

अभी हाल ही में पिछले साल जब कैलाश रेंज पर हमारा कब्जा हो गया था तो चीन ने आगे बढ़ कर बातचीत की आफर की थी और सिर्फ फिंगर आठ से फिंगर चार तक फौजें हटाने के बदले संपूर्ण कैलाश रेंज से हमारी फोजों की वापसी करवा ली थी। और जब बात लदाख की आई तो चीन साफ मुकर गया था।

लगता है अब भी कुछ इसी तरह का धोखा देना चाह रहा है चीन। चीन इस समय बहुत बुरी तरह से आहत है। प्रकृति ने और कोरोना ने उसकी कमर बुरी तरह से तोड़ रखी है ऊपर से चीन में भावी निवेश बिल्कुल बन्द हो गया है। पूर्व का हो चुका निवेश भी वहां से निकल कर मोदी की PLI स्कीम के अंतर्गत भारत की और रुख कर रहा है। लगभग 1000 चीनी फैक्टरियां भारत की और रुख कर चुकी हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल, सिंथेटिक फैब्रिक्स, बैटरीज, आई टी, सोलर इक्विपमेंट्स आदि की फैक्ट्रियां भारत शिफ्ट हो रही हैं।

चीन आर्थिक तौर पर टूट रहा है। चीनी बैंक फेल हो रहे हैं। एवर्ग्रन्डे जैसी बड़ी कम्पनी जिसमें चीन के 75 लाख से ज्यादा लोगों का निवेश है उसका दीवाला निकल गया है। 3400 बिलियन फॉरेन रिजर्व वाले चीन की अकेली इस कम्पनी पर ही 2100 बिलियन डालर का कर्ज है जिसको चीन चाह कर भी नहीं बचा सकता।

कोरोना के बाद चीन के संसार भर के प्रोजेक्ट्स और निवेश अधर में लटक गये है। संक्षेप में कहें तो चीन किसी भी हालत में भारत के साथ युद्ध में उलझ कर अपने को खत्म नहीं करना चाहता और इसी लिए चीन ने अपने आर्थिक मित्र रूस से भारत को मनाने के लिए यह पैंतरा चला है।

इस समय युद्ध भारत के लिए भी घातक है। भारतीय अर्थ व्यवस्था इस समय ट्रांस्फोर्मिंग मोड में है। भारत ने PLI में बड़े बड़े पैकेज घोषित किये हुए हैं। उनसे पीछे हटने का मतलब है सदा के लिए विदेशी निवेशको का विश्वास खोना।

सारांश में यह चीन भारत वार्ता दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी और उपयुक्त है। बस हमें चीन की चालबाजी वाली नीति और रूस के गुप्त एजेंडे का ध्यान रखना होगा।

■ ■ ■ ■

ओलाफ शोलजे ओ मैटिक अब जर्मनी के एंजिला मर्केल के बदले नए चांसलर बने हैं। मतलब चीन की जर्मनी में स्थापित यार की विदाई हो गयी है। वैसे मर्केल क्यों चीन से ख़ौफ खाती थी इसका मुझे आजतक न तो ज्ञान हुआ और न ही आजतक इसकी मुझे समझ आई है। चीन के हर अच्छे बुरे फैसले को मर्केल मानती आई थी और कई बार तो भारत को भी जर्मनी ने चीन के कहने पर कई मामलों में घेरने की कोशिश की थी।

चीन जिस तरह से मर्केल के जमाने में जर्मनी को अपनी जेब में रखा समझता था उसी तरह की सोच के साथ चीन ने जर्मनी के नए चांसलर को भी वन चाइना पालिसी पर धमकाने की कोशिश की। पर अब ओलाफ शोलजे ओ मैटिक ने तो चीन के साथ वो खेल कर दिखाया जो आजतक साफ साफ न तो अमेरिका कर सका और न ही भारत।

भारत और अमेरिका दोनों सामरिक दृष्टि से ताइवान को अलग राष्ट्र मानते हैं पर राजनीतिक तौर पर आजतक अमेरिका भी खुल्लम खुल्ला चीन की वन चाइना पालिसी का उल्लंघन नहीं कर पाया पर जर्मनी के चांसलर ने तो इसे अपनी संसद में आए एक प्रस्ताव को पास करा कर चीन को बता दिया है कि अब जर्मनी ताइवान के साथ आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक तीनो रिश्ते रखेगा और अगर यह चीन को बुरा लगता है तो लगे, जर्मनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

■ ■ ■ ■

दोगला दोगला ही होता है और इसका सबसे

डेटा सुरक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़ा नया कानूनी ढांचा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में प्रौद्योगिकी और इंटरनेट को लेकर एक नया एवं आधुनिक कानूनी ढांचा आएगा और डेटा सुरक्षा विधेयक इस दिशा में पहला कदम है। चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार और सार्वजनिक सेवाओं का `तेजी से डिजिटलीकरण होगा और जल्द ही शुरू होने वाली डिजिटल इंडिया-2 योजना पिछले कुछ वर्षों में हासिल हुए लाभ का फायदा उठाने की कोशिश करेगी।

मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इंटरनेट और प्रौद्योगिकी खुले, सुरक्षित और जवाबदेह बने , क्योंकि अगले कुछ वर्षों में 1.2 अरब भारतीय इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेंगे। चंद्रशेखर ने आधार 2.0 वर्कशॉप के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, `देश में प्रौद्योगिकी और इंटरनेट को लेकर एक नया आधुनिक कानूनी ढांचा आएगा। डेटा सुरक्षा विधेयक इस दिशा में पहला कदम है जिसे आप जल्द ही अगले कुछ महीनों में देखेंगे। यह भी संचालन के पूरे वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।' इस सप्ताह की शुरुआत में संसद की एक समिति ने कई विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच डेटा सुरक्षा विधेयक पर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। यह रिपोर्ट 29 नवंबर से शुरू होने वाले आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश की जाएगी। करीब दो साल के विचार-विमर्श के बाद निजी डेटा सुरक्षा विधेयक से संबंधित संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट को सोमवार को अंगीकार कर लिया गया। इसमें उस प्रावधान को बरकरार रखा गया है, जो सरकार को अपनी जांच एजेंसियों को इस प्रस्तावित कानून के दायरे से मुक्त रखने का अधिकार देता है।

लोगों के निजी डेटा की सुरक्षा और डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना के मकसद से यह विधेयक 2019 में लाया गया था। इसके बाद विपक्षी दलों के सदस्यों की मांग पर इस विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श और आवश्यक सुझावों के लिए समिति के पास भेजा गया था। निजी डेटा सुरक्षा विधेयक के मुताबिक, केंद्र सरकार राष्ट्रीय हित की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और देश की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा के लिए अपनी एजेंसियों को इस प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से छूट दे सकती है। इस बीच, ऐसा समझा जाता है कि समिति ने सिफारिश की है कि मध्यस्थ के तौर पर काम न करने वाले सभी सोशल मीडिया मंचों को प्रकाशकों के तौर पर देखा जाना चाहिए और उन्हें उनके मंचों पर डाली जाने वाली सामग्री के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि भारत में किसी भी सोशल मीडिया मंच को भारत में तब तक काम करने की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि प्रौद्योगिकी को संभालने वाली मूल कंपनी देश में अपना एक कार्यालय स्थापित नहीं करे।

बड़ा उदाहरण अमेरिका है।

जो लोग मुझे नियमित पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अमेरिका पहले युद्ध उन्माद फैलाता है। साथ देने का वायदा करता है ऐसा करने में अपने पास से फंडिंग करता है उसके बाद अपने हथियार बेचता है। और फिर जब लगता है कि अब यह देश और ज्यादा हथियार नहीं खरीद सकता तो चुपके से पीछे से खिसक लेता है।

आज तक मिडिल ईस्ट में यही किया। पाकिस्तान को तो इसी नीति से लगभग तबाह ही कर दिया। पूरी तरह निचोड़ने के बाद फेंक दिया।

अब यही भारत के साथ और ताइवान के साथ करने की लगातार कोशिश कर रहा है। भारत के पास तो मोदी है सो भारत अभी बचा हुआ है पर ताइवान, ताइवान को अभी 111 देशों की हुई डेमोक्रेसी समिट में भाग लेने के लिए बुलाया गया। जब ताइवान का मिनिस्टर इस मीटिंग में एड्रेस कर रहा था तो उसके पीछे लगे मैप पर ताइवान को चीन से अलग देश के रूप में दिखाया गया था। बस USA के प्रोग्राम कंट्रोलर ने ताइवानी मिनिस्टर की वीडियो ही गायब कर दी और सिर्फ ऑडियो चालू रही। डिप्लोमेटिक हल्के में इसे किसी देश की बहुत बड़ी बेइज्जती माना जा सकता है पर ताइवान चीन और अमेरिका दोनों से बहुत छोटा देश है अत: वो इस अपमान के घूंट को पी कर भी चुप रह गया।

मेरा यहां इस दोगले अमेरिका से प्रश्न है कि अगर वो वन चाइना पालिसी को मानता है तो उसने चीन को छोड़ कर ताइवान को अलग से न्योता ही क्यों दिया और अगर वह ताइवान को चीन से अलग मानता है तो उसने भाषण देते हुए ताइवानी मिनिस्टर का वीडियो क्यों रोका जिसमें ताइवान को चीन से अलग दिखाया गया था।

यह सब सिर्फ इसलिए था कि अमेरिका चीन से डरता है और सीधे सीधे चीन से न लड़ना चाहता है और न ही उसे नाराज करना चाहता है पर चीन को बर्बाद जरूर करना चाहता है जिसके लिए कभी भारत, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी जापान और कभी ताइवान को आगे करता है और इन सभी देशों को भर भर के अपने हथियार बेचना चाहता है। इसी कड़ी में उसने आस्ट्रेलिया, जापान, भारत को बिल्लियन्स ऑफ बिल्लियन्स के हथियार बेच दिए हैं।

सो दुनिया के लोगों इस दोगले अमेरिका से सावधान। यह सांप है जितना मर्जी दूध पिला लो न जाने यह कब डस ले।

■ ■ ■ ■

अमेरिका एक ऐसा देश जो अपने फायदे के लिए पूरे विश्व में किसी को भी धोखा दे सकता है।

अब यूक्रेन वाला मामला ही ले लो। बार

नकली विज्ञान ने हमसे 400 प्रकार के टमाटर छीन कर हमें एक अंडे के आकार का टमाटर जो बिल्कुल गुणहीन है चिपका दिया

आजकल आपने देखा होगा कि बाजार में मिलने वाले अधिकतर फल और सब्जियों में स्वाद बिल्कुल नहीं होता । लेकिन दिखने में वह एकदम लाजवाब होगी जैसे कि जामुन, टमाटर । हाइब्रिड बीज से तैयार होने वाली जामुन इतनी मोटी मोटी, गोलमटोल होती हैं कि देखते ही खाने के लिये मुहं में पानी आ जाता है । और देशी जामुन बेचारी देखने में बिल्कुल पतली सी । एक कोने में दुबक कर पड़ी रहती कि कोई हम गरीब का भी मोल डाल दे । लेकिन जब आप hybird जामुन को खायो तो स्वाद बिल्कुल फीका फीका सा बेस्वाद सा होता है। हाइब्रिड मोटी मोटी जामुन गले में एक अजीब तरह की खुश्की करती है । खाने के बाद आपको पानी पीना पड़ता है । दूसरी और देशी जामुन मुहं में रखते सार ही रस घोल देती है ।आनंद आ जाता है कोई गले में खुशजी नहीं होती । देशी जामुन जिनकी किस्मत और समझ अच्छी हो कभी कभार मिल जाती है ।

आज का दूसरा मुद्दा है टमाटर । अंग्रेजी टमाटर देखने में अंडे जैसे लगते हैं इसलिये मैं इनको अंडे वाले टमाटर कहता हूं । यह अंडे वाले टमाटर खाने में देशी टमाटरों (जोकि बिल्कुल गोल होते हैं) के मुकाबले बिल्कुल असरदार और स्वादिष्ट नही होते । देशी टमाटर जहां एक पड़ेगा और सब्जी में रस घोल देगा ।अंडे वाले हाइब्रिड टमाटर तीन पड़ेंगे और सब्जी की ऐसी तैसी कर देंगे वो अलग ।

पिछली एक पोस्ट जो बताती थी कि कैसे हाइब्रिड गेंहू में कैसे ग्लूटामेट की मात्रा अधिक होती है जिससे आजकल तथाकथित विकसित देश अमेरिका जिसकी 25% जनसंख्या मुधमेह नामक रोग से ग्रसित है । दूसरी और देशी गेहूं जैसे शरबती में ग्लूटामेट की मात्रा संतुलित मात्रा में होती है ।

यह लेख लिखने का उद्देश्य है कि आप भी ना केवल जैविक बल्कि भगवान की बनाये हुए फल सब्जियां अनाज ही खरीदें क्योंकि इंसान गलती कर सकता है भगवान नहीं । कुदरती बीजों द्वारा उत्पन्न फल सब्जियां ही आपके स्वास्थ्य के लिये उत्तम हैं ।

जिस दिन आपकी सब्जी में आंवले का उपयोग होना शुरू हो गया उस दिन से आधा मेडिकल माफिया जो आपको दिन रात लुटता रहता वह भाग जाएगा। सनातन भारत में सब्जी में खट्टापन लाने के लिये टमाटर के स्थान पर आंवले का प्रयोग होता था । इसलिये सनातन हिंदुओ की हड्डियां महर्षि दधीचि की तरह कठोर होती थीं, इतनी मजबूत होती थी कि महाराणा प्रताप का महावजनी भाला उठा सकतीं थी। आज तमाम तरह के कैल्शियम विटामिन्स खाने के बाद भी जवानी में ही हड्डियां कीर्तन करने लगती हैं । जिस मौसम में देशी टमाटर मिले तो ठीक लेकिन अंडे जैसे आकार के

अंग्रेजी टमाटर खाने के स्थान पर आंवले का प्रयोग आपकी सब्जी को स्वादिष्ट भी बनाएगा और आपको मेडिकल माफिया के मकड़जाल से भी बाहर निकालेगा । आंवला ही एक ऐसा फल है जिसमे सब तरह के रस होते है । जैसे आंवला , खट्टा भी है मीठा भी कड़वा भी है नमकीन भी । आंवले का सनातन संस्कृति में महत्तम इतना है कि दीपावली के कुछ दिन बाद आंवला नवमी मनाई जाती है । आपको करना केवल इतना है कि साबुत या कटा हुआ आंवला, बिना बच्चों और आधुनिक सदस्यों को बताए सब्जी में डाल देना है । अगर आंवला साबुत डाला है तो सब्जी बनने के बाद उसको ऐसे ही खा सकतें है । जब आंवला नहीं मिलता तो आंवले को सुखा कर पीस कर इसका प्रयोग उचित है ।

मेडिकल माफिया को भगाएं आंवला अपनाएं ।

हमारी संस्कृति में गेहूं कहां है ।
लोक गीतों में बाजरा है जैसे
'बाजरे दा सिट्टा वे मैं तली ते मरोडिया , तुरिया जांदा माहिया असा गली विचों मोडिया'

विजयादशमी त्यौहार पर हम जौं बीजते हैं गेहूं नहीं, पिंड हमेशा जौं के आटे के बनते हैं गेहुं के नहीं।

दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन चावल फेंकती थी, वह भी बिना पोलिश हुए गेहुं नहीं ।

फिर यह गेहूं हमारे भोजन में कैसे घुस गया। शोध का विषय है । क्या यह तो नहीं कि गेहुं food माफिया, मेडिकल माफिया को सूट करता है बाजरा या जौं नहीं। क्या 1960 की कृत्रिम गेहुं की कमी दिखाकर भारत की कृषि व्यवस्था और भोजन व्यवस्था जानबूझकर तब्दील की गई । क्योंकि 1960 के लगभग ही कृषि और अनाज में सरकारी दखल बढ़ता गया । 1960 के लगभग ही FCI आया, Agricultural को समाप्त करने के लिये Agricultural Development यूनिवर्सिटी खोली गई । जिसमें घटिया बीज तैयार किये गये जो जहर के बिना बढ़ते ही नहीं थे । 1960 के दशक में APMC Act आया जिससे मण्डियों के माध्यम से कृषि को कंट्रोल कर लिया गया । हरित क्रांति भी उस गेहूं की कमी का आधार बनाकर रची गई जिसका उपभोग भारतीय समाज बहुत कम करता था ।

ध्यानार्थ IMA चिकित्सा के क्षेत्र में Allopathy का योगदान न के बराबर है। देखिये कैसे ये दूसरों के ज्ञान पर जबरदस्ती हक जमाये बैठा है। फिर किस आधार पर अंग्रेजी चिकित्सा इन पर अपना हक जमाता है?

चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान

1. सर्जिकल प्रोसीजर (300 प्रकार की) आचार्य सुश्रुत, आयुर्वेद।
2. Surgical Instruments - Acharya sushruta,
3. अष्टविध शस्त्रकर्म (Excision, incision, scraping, puncturing, Probing, extraction, drainage, Suturing) - सुश्रुत , आयुर्वेद
3. Bandage (15 types) - Ayurveda
4. Craniotomy - Ayurveda
5. त्रिविध कर्म (pre, para, post operative) - Ayurved
6. अग्नि कर्म (Cautery) - Ayurveda
7. Plastic Surgery - Ayurveda

8. Ear lob कर्ण संधान विधि(15) - आयुर्वेद
9. संधिमुक्त (dislocation)- ayurveda
10. नेत्र चिकित्सा -सुश्रुत
11. कर्ण रोग-सुश्रुत
12. नासा रोग-सुश्रुत
13. मुख रोग -सुश्रुत
14. दंत रोग-सुश्रुत
15. जिह्वा रोग-सुश्रुत
16. Rhinoplasty - Sushruta
17. Suture Material - Sushruta
18. Dissection of cadavers - Sushruta

अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति का खुद का अपना क्या है कोई बताएगा ?

सभी बड़े ब्रांड की कंपनियों के द्वारा हानिकारक केमिकल बेकरी उत्पादों जैसे बिस्किट, ब्रेड आदि और आइस क्रीम में डालें जातें हैं ताकि यह लंबे समय तक खराब ना हों । अमूमन जल्द खराब होनी Icecreame इसलिये चार छह महीने काट जातीं हैं । इसलिए आपने Notice किया होगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स की Ice Cream खाने के तुरंत बाद आपको प्यास लगती है और यह Ice Cream आपके गले में एक अजीब तरह की खराश उत्पन्न कर देती है । जबकि घर में बनी हुई Ice Cream और किसी Local दुकानदार की Ice Cream जो समाज द्वारा Certified होती है उसको खाकर आपका गला सूखता नहीं । इसी तरह बिस्कुट के स्थान पर स्थानीय बेकरी में आप नान खताई तैयार करवा सकतें हैं । ब्रेड के स्थान पर बड़ा पाव जो आपकी आंखों के सामने बनता था वह प्रयोग कर सकतें हैं । बड़े बड़े ब्रांड के पास पैकिंग और एडवरटाइजिंग के अलावा आपको देनें के लिये जहर के अतिरिक्त और कुछ नहीं । इनके दिखावे पर मत जाएं ।

भांग

भांग का पौधा वह ब्रह्मास्त्र है जो प्लास्टिक और अरब देशों का कचूमर निकाल सकता है। अमेरिका और कनाडा में इसकी खेती को कानूनन मान्यता दे दी गई है । उत्तराखण्ड में भी इसकी खेती अब गैर कानूनी नहीं रही। भांग के पौधे से 1200 से ऊपर उत्पाद बन सकतें है म जिनमे प्लास्टिक, कपड़ा, पैकिंग मटेरियल, चूने और भांग के मिश्रण से Concreate जैसा मजबूत Material, गाड़ियों के लिये तेल, आयुर्वेदिक दवाएं आदि बनाई जा सकती हैं। 1950 के दशक तक इसकी खेती कानूनन थी जो बाद में नशा माफिया, मेडिकल माफिया, पेट्रोलियम माफिया से रिश्वत खाकर सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। भांग का पौधा बहुत तेजी से उगता है । 6 महीने में इसकी फसल आ जाती है । भांग एक ऐसा पौधा है जो विश्व को क्रूड ऑयल के दुष्चक्र से निकाल सकता है । उत्तराखंड, अमेरिका, कनाडा की तरह भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी कानूनी मान्यता दे देनी चाहिये। अगर एक बार ऐसा हो गया तो किसानों, उपभोक्ताओं और प्रकृति की दशा काफी हद तक सुधर जाएगी। इसके गैर नशीले पौधे के बीज अभी अमेरिका आदि से आयात होतें है। सरकार को इसके इन बीजों के उत्पादन पर ध्यान देना चाहिये। पंजाब, हरियाणा की कैंसर कारक फसलों का उत्पादन करने वाली धरती के लिये भांग की खेती एक अच्छा विकल्प होगी।

बार अमेरिका के बयान आ रहे थे कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो हम यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे और उसका उसी तरह से साथ देंगे जैसे वो उनका नाटो का सदस्य हो। इतनी सपोर्ट पाकर यूक्रेन ने भी चौड़े हो कर रूस को कह दिया कि अगर रूस ने हमपर युद्ध छेड़ा तो रूस अपने सैनिको को ताबूत में भरकर ले जाने को तैयार रहे।

पर अचानक कल रूस के साथ बातचीत में अमेरिका ने खुलासा किया कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका सिर्फ रूस पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएगा पर उसका इस युद्ध में कूदने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। अब यूक्रेन उसी तरह ठगा से महसूस कर रहा है जैसे आर्मेनिया अजरबैजान के साथ युद्ध में रूस द्वारा ठफा हुआ महसूस कर रहा था।

अमेरिका की पालिसी है कि पहले इतना भड़का दो फिर ऐन समय पर पीछे से खिसक लो।

ठीक इसी तरह की पालिसी से उन्होंने पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान में उलझाए रखा और पाकिस्तान को तो बकरा बना कर रूस तक को तोड़ दिया और भारत को भी पाकिस्तान के साथ कई जंगों में उलझा कर भारतीय अर्थव्यवस्था को पनपने ही न दिया। पाकिस्तान को तो खैर तबाह ही कर दिया। भारत के अंदर भी आम जनता में विभिन्न ह्रह्र के द्वारा इतने नफरत के बीज बो दिए ताकि भारतीय नेतृत्व इसी उग्रवाद में उलझा रहे। कहीं मुस्लिम उग्रवाद, कहीं खालिस्तान उग्रवाद, कहीं अल्फा उग्रवाद, कहीं बोडो उग्रवाद यानी अल कायदा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, बब्बर खालसा समेत 35 से अधिक आतंकवादी संगठनों को फंडिंग कर भारतीय सरकर को अंदर से और चीन तथा पाकिस्तान को हवा देकर बाहर से तोड़ने के प्रयास जारी रखें।

चीन अमेरिका का दुश्मन नम्बर एक चीन हैं क्योंकि वो अमेरिका को न सिर्फ आर्थिक रूप से पछाड़ चुका है बल्कि उसे अब लगभग हर क्षेत्र में चुनोती दे रहा है। अमेरिका को पता है कि अगर चीन को अभी न रोका गया तो चीन हर हालत में बहुत जल्द निकट भविष्य में अमेरिका की ही तबाह कर देगा। पर अमेरिका यह भी समझता है कि वो सीधे सीधे चीन से पंगा नहीं ले सकता। बस इसलिए कभी भारत, कभी ताइवान, कभी जापान, कभी आस्ट्रेलिया को चीन के खिलाफ उकसाता रहता है।

उधर चीन को भी पता है कि अगर उसने भारत को अभी न रोका तो भारत ही इसकी तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा है और उसके विश्व विजय अभियान के सपने को कभी पूरा न होने देगा। मोदी के आने से पहले चीन ने भारत की कांग्रेसी सरकार को खरीद रखा था और भारत को अपनी जेब में पड़ा समझ रहा था। वैसे भी वो धीरे धीरे भारत पर आर्थिक तौर पर कब्जा कर रहा था पर मोदी ने आकर चीन का सारा खेल बिगाड़ दिया। तब चीन ने भारत को तोड़ने के लिए बॉर्डर पर आ कर धमकाया पर मोदी ने सेना के सामने सेना और हथियारों के सामने हथियारों का मिरर डिप्लॉयमेंट करके चीन को भी हतप्रभ कर दिया।

तो दोस्तों मोदी के रहते हम अपने देश को बाहरी आक्रमण से तो सेफ मान सकते हैं पर अंदरूनी आक्रमण को हम सब को मिलकर ही सम्भालना होगा।

■ ■ ■ ■

चीन का कहना है कि भारत के राफेल विमान चीनी सीमा के अंदर

महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी

देश में सेमीकंडक्टर्स (Semiconductors) और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसे मिशन मोड में चलाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की जाएगी।

हाइलाइट्स

सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए 76,000 करोड़ की योजना को मंजूरी

देश में चिप्स का एक कंप्लीट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा

डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स की स्थापना

इसे मिशन मोड में चलाने के लिए होगी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना

देश में सेमीकंडक्टर चिप्स (Semiconductor Chips) की कमी दूर करने के लिए मोदी सरकार 76,000 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत अगले 6 साल में देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का एक कंप्लीट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स की स्थापना शामिल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बाद में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विस्तार से इस योजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके तहत देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग और कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 76 हजार करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपये का इनसेंटिव दिया जाएगा। इसे मिशन मोड में चलाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की जाएगी।

क्या है सरकार की योजना

मोदी सरकार भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहती है। सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई पीएलआई (Production Linked Incentive) स्कीम्स लाई है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी से देश में मैन्युफैक्चरिंग बेस मजबूत होगा। सरकार का लक्ष्य डिस्प्ले के लिए 1 से 2 फैब यूनिट स्थापित करने का है। डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स के लिए 10-10 यूनिट लगाने का प्लान है।

फैब यूनिट में चिप बनाने वाली कंपनियों की जरूरत के हिसाब से वैफर (Wafer) को डिजाइन किया जाता है और बनाया जाता है। इसके बाद सैमसंग, एनएक्सपी और क्वालकॉम जैसी चिप बनाने वाली कंपनियां इसका पैकेज, टेस्ट और बिक्री करती हैं। करीब एक साल पहले सरकार से देश में सेमीकंडक्टर फैब यूनिट बनाने के लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगे थे। सरकार ने तब 40 फीसदी कैपिटल सब्सिडी की भी पेशकश की थी लेकिन कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।

चिप की कमी

देश और दुनिया में पिछले कुछ समय से चिप की कमी से कई इंडस्ट्रीज का प्रॉडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। माना जा रहा है कि यह संकट अगले साल और गहरा सकता है। जानकारों के मुताबिक ग्लोबल चिप सप्लाई शॉर्टेज से कम से कम 169 इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई हैं। 2022 तक इसका कोई समाधान नजर नहीं आता है। चिप संकट ने पहले ही अमेरिका जैसी प्रमुख इकॉनमी को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। सेमीकंडक्टर्स को अरबों प्रॉडक्ट्स का दिल माना जाता है। इनमें स्मार्टफोन्स, डेटा सेंटर्स, कम्प्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डेवाइसेज, वीकल्स, हाउसहोल्ड अप्लायंसेज, लाइफ सेविंग फार्मास्यूटिकल डेवाइसेज, एग्री टेक, एटीएम और कई तरह के उत्पादों में इस्तेमाल होता है।

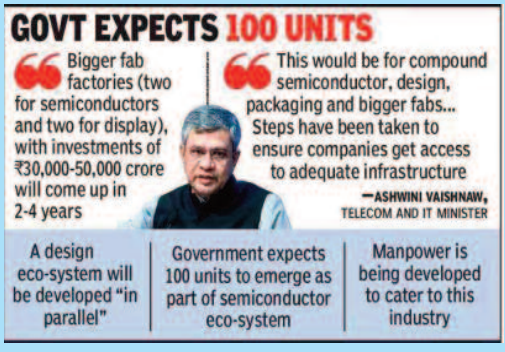

घुस आये। इसका जवाब भारतीय सेना के प्रवक्ता ने ऐसे दिया कि यह कहना कि भारतीय विमान चीन की सीमा नें घुस आए बिल्कुल गलत है। भारतीय विमान चीन की सीमा में घुसे ही नहीं। जिसे चीन अपनी सीमा कह रहा है वो भारतीय सीमा ही है जिसका चीन ने 1962 से जबरन कब्जा किया हुआ है।

हमें अपनी सीमा में विमान उड़ाने पर चीन ऐतराज करने वाला कौन होता है।

अग्नि प्राइम नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण हो चुका है।

क्या है अग्नि प्राइम NG

1. यह एक कंटेनर बेस्ड मिसाइल है जिसे कंटेनर में फिट करके कहीं पर भी लाया ले जाया जा सकता है या फिर स्थापित किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लो दुश्मन के जासूस अपनी सेना को इसकी सटीक तैनाती की जगह बता देते हैं कि इसे दिल्ली में रखा गया है तो इससे पहले की दुश्मन इसपर अटैक करके इसे नष्ट करे इसकी स्थिति को मिनटों में बदला जा सकता है। वैसे भी चूंकि यह कंटेनर में फिट होति है इसलिए यह हमेशा दुश्मन की नजरों से ओझल रहती है। क्योंकि दुश्मन को यह पता नहीं लग पाता कि किस कंटेनर में सामान रखा हुआ है और किस कंटेनर में मिसाइल फिट है।

2. यह मन्यु वेरेबल maneuverable है। मतलब जब इसे किसी चीज को नष्ट करने के लिए इसे छोड़ा जाता है और दुश्मन के राडार इसे डिडेक्ट कर के इसको नष्ट करने के लिए अपने एयर डिफेन्स सिस्टम से कोई मिसाइल छोड़ देते हैं तो यह अपने आप उसे सेंस करके अपना रास्ता बदल कर उस मिसाइल को चकमा दे सकती है।

3. इसकी रेंज कहने को तो 2000 किलोमीटर है पर असली रेंज 3000 किलोमीटर तक बताई

जा रही है।

4. यह न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी न्यूक्लियर हथियार भी ले जाने में सक्षम है।

यह एक ऐसी मिसाइल है जिसे किसी भी समय पूरे देश के किसी भी कोने में मात्र चंद घंटों में स्थापित किया जा सकता है।

इस सबका मतलब बस इतना है कि भारत अपनी मिसाइलों की अलग अलग रेंज से चीन के शरीर में इतने छेद कर देगा कि चीन को समझ ही न आएगा ।

■ ■ ■ ■

तब्लीगी जमात

यह ऐसी जमात है जो देती तो दीन और मजहब की तालीम है पर इनका असली मकसद आतंकवादी पैदा करना होता है।

इसको सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाले देश सऊदी ने ही अब इस पर बैन लगा दिया। न सिर्फ इन पर बैन लगाया है बल्कि इसके साथ सम्बन्ध रखने वालों को भी सजा देने के प्रावधान है।

अब सऊदी ने ऐसा क्यों किया इस पर अलग से एक पोस्ट विस्तार से लिखूंगा। यहां यह बताना जरूरी है कि इस जमात के दिये गए उपदेशों से कैसे हमारे देश की फिजा में जहर घुल रहा है। आपको दो वर्ष पहले CAA कानून पास होने के बाद शाहीन बाग की घटना याद होगी। तब दिल्ली के छह और अलीगढ़ की रूने कैसे इनका सड़कों पर आ कर साथ दिया था।

जामिया के छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ था ! अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश विद्रोही भाषण एवं नारे लगाए गए थे।

तो क्या यहां के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं या देश विद्रोही लोगों के एजेंडे को चलाने।

नागरिकता संशोधन बिल पास होने से क्या जामिया के छात्रों की फीस महंगी हो गयी थी ?

उनके कॉलेज की सीट कम हो गई थीं ?

उनका होस्टल छिन गया था ?

उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान उतपन्न किया गया था?

ऐसा क्या हुआ कि उनके पेट में दर्द हो गया ?

क्यों पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर आए जामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र ?

क्यों हिंसक हुए छात्र ?

इनकी क्या पहचान थी?

क्या यह किसी ऐसे वर्ग से ताल्लुक रखते हैं जो देशद्रोही है?

इन प्रश्नों के जबाब मिलने ही चाहिये।

शिक्षा संस्थानों को गुन्डो का अड्डा नही बनने दिया जा सकता। ऐसे छात्रों को पढ़ाई नहीं गोली की जरूरत है।

आप सब पाकिस्तान को ही देखो। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ तैयार किया आज वो पाकिस्तान में ही उधम मचा रहे हैं और पाकिस्तान की सरकारों से अपने मन मतलब की शर्तें मनवा रहे हैं।

इन संकेतों को सऊदी ने पहचाना और इससे पहले कि उनके यहां भी इस तह की जमात बलशाली होकर उन्हें घुटने पर लाये उन्होंने उन पर प्रतिबंध लगा दिया।

भारत में भी ऐसे प्रतिबन्ध लगाए जा सकते है। पर मोदी सरकार के विरुद्ध उनके अपने ही समुदाय के लोग खड़े हो जाते हैं। कभी वो जाट होते हैं कभी वो सिख होते हैं कभी वो यादव होते हैं कभी वो बंगाली होते हैं कभी वो संख्या अनगिनत है। यहां बिखराव है वहां एकता है।

देर सबेर यह बात हर भारतवासी को समझ तो आएगी पर जितनी ज्यादा देर होगी समस्या भी उतनी बड़ी होती जाएगी और उससे निपटने में खून भी उतना ही ज्यादा बहेगा।

■ ■ ■ ■

50 किलोमीटर दूर से ही अब नेस्तनाबूद करेगी भारतीय नौसेना चीन के किसी भी युद्धपोत को।

जी हां

अस्ल में चीन की नोसेना भारत की नोसेना से संख्या बल में आठ से दस गुना ज्यादा ताकतवर है। समुद्र में पनडुब्बी आदि को नष्ट करने के लिए तारपीडो की आवश्यकता पड़ती है। पर दुनियाभर में किसी भी देश के पास 35 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से मार कर सकने वाली तारपीडो नहीं है। अब ऐसे ने किसी भी पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए किसी भी नोसैनिक को उसके बहुत करीब जाना पड़ता था ताकि वो दुश्मन पर वार कर सके। यह दूरी 10 से 20 किलोनीटर के अंदर होती थी। किसी पर इतने करीब जा कर वार करने से वो खुद भी वो दुश्मन की जद में आ जाता था। ऐसे में शिकारी खुद शिकार हो सकता था।

बस DRDO ने इसी का तोड़ निकाला है और अब 650 किलोनीटर दूर से ही चीन के किसी भी युद्धपोत का तारपीडो द्वारा सफाया किया जा सजता है। यह हथियार मिसाइल और टारपीडो का मिश्रित रूप है जिसमें एक टारपीडो को एक मिसाइल 600 किलोमीटर तक लेकर जाती है और फिर वो तरोईडो को ट्रिगर कर देती है और आगे का काम फिर टारपीडो करती है। इसे सुपरसोनिक एंटी सबमरीन टॉरपीडो कहते हैं। और DRDO ने दो दिन पहले ही इसका परीक्षण किया है।

■ ■ ■ ■

DRDO की ब्रेक फेल।

जी हां पिछले एक पखवाड़े में 25 से ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण करने के बाद भी DRDO ने अगले 15 दिनों में तीन और मिसाइलों के परीक्षण का NOTAM जारी कर दिया है।

उधर राजनाथ सिंह ने भी DRDO को हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इस मिसाइल का आने वाले दस पन्द्रह वर्ष तक कोई तोड़ पैदा नहीं होने वाला क्योंकि अभी तक विश्व के किसी भी देश ने इसका ठीक से टेस्ट तक नही किया। रूस अमेरिका और चीन इसको बना लेने के दावे तो कर रहे हैं पर अभी तक इसका सफल परीक्षण सिर्फ रूस और भारत ही कर सके हैं। भारत ने सिर्फ एक बार इसका सफल परीक्षण किया और

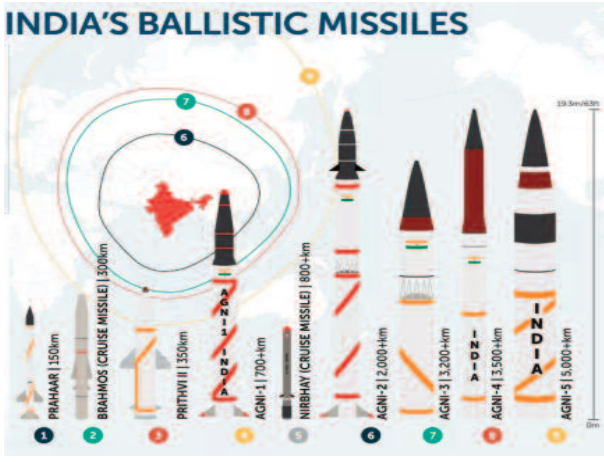

इसे करने के बाद इस प्रोग्राम को ठंडे बस्ते नें डाल दिया था जिसे राजनाथ सिंह ने जनरल रावत की शहादत के बाद DRDO को एक बार फिर इसे पिटारे से बाहर निकालने के DRDO को आदेश दे दिए हैं।

अब रुस्तम 2 और हाइपरसोनिक मिसाइल चीन के जनरलों की रात की नींद गायब करेंगी। पाकिस्तानी जनरलों की टांगे तो भारत द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक करने से ही कांप गयी थी और इस बात का खुलासा खुद एक पाकिस्तानी मंत्री ने पाकिस्तानी असेंबली में किया था।

■ ■ ■ ■

2030 तक भारत का टारगेट है कि भारतीय पूरी ऑटो इंडस्ट्री 100% इलेक्ट्रिक हो जाये। अगर हम इस टारगेट को पाने में सक्षम हो जाते हैं तो हमें बहुत बड़ी मात्रा नें बैटरीज की जरूरत पड़ेगी। अभी तक दुनिया भर में जो कारें इलेक्ट्रिक पर चल रही हैं उनमें लिथुमाईन बैटरीज का इस्तेमाल हो रहा है।

यहां यह बताना जरूरी है कि दुनिया भर के रेयर अर्थ की 90% भाग पर चीन का कब्जा है जिसके बिना लिथुमाईन बैटरी बनाना नामुमकिन है। आज की स्थिति देखगें तो चीन लिथो माईन बैटरी की दुनिया भर की जरूरत का 95% से भी ज्यादा भाग पूरा करता है। ऐसे में भारत अगर अपनी पूरी ऑटो इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है तो चीन जब चाहे भारत को घुटनों पर ला सकता है। ऐसे में भारत को पूरी तरह भारत में बनी बैटरी चाहिए जिसका रॉ मटेरियल भी भारत में ही उपलब्ध हो। ऐसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के कई IITians यंग उधमी अपना अपना स्टार्टअप लेकर आगे आये हैं जिनमें प्रमुख बेंगलोर के LOG 9 एल्युमीनियम एयर बैटरी और भुवनेश्वर की NEXUS है। इनका फोकस था लिथुमिन बैटरी के मुकाबले निम्न बिंदुओं पर बेहतर बैटरी का उत्पादन करना।

फास्ट चार्जिंग
लांग रेंज
कॉस्ट एफिशिएंसी
लाइफ
बायो ग्रेडेबल

इन सभी पॉइंट्स पर सफलता प्राप्त करते हुए भुवनेश्वर वाले स्टार्टअप ने अपने आविष्कार का पेटेंट भी करवा लिया है। इस तरह की बैटरी में किसानों द्वारा जला देने वाली पराली का भी इस्तेमाल होगा जिससे 7 बिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। इससे किसानों द्वारा जला देने वाली पराली के दाम भी किसानों को मिलेंगे।

■ ■ ■ ■

हर बार जब भारतीय मूल का व्यक्ति एक वैश्विक सीईओ बनता है, हम या तो सेल्फ लोथिंग पर काम करते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि, अब हम अमेरिकी कॉर्पोरेट को नियंत्रित करते हैं और व्यक्ति भारतीय हित पर ध्यान केंद्रित करेगा! तथ्य यह है कि पेप्सी से गूगल से माइक्रोसॉफ्ट से ट्विटर तक – सीईओ का पहला KRA उनके संबंधित कॉर्पोरेट हित और बदसूरत सत्य है, वे केवल भारतीय मूल के हैं! भारतीय नहीं!

भारतीय नागरिकता किसी के पास नहीं है! उन्होंने वापस आत्मसमर्पण कर दिया!

तो, बड़े होकर भारत में लोगों पर गर्व महसूस करें या जो भारतीय पासपोर्ट ले जाते हैं!

भारतीय अन्य देशों में स्थित भारतीय मूल के सीईओ पर गर्व करना पसंद करते हैं!

लेकिन, एक ही जनजाति भारत में लोगों द्वारा सबसे अधिक घृणा की जाती है!
Ambani, Adani, Tata, Birla .. !!

उन्होंने भारत में रहकर भारतीय उत्पाद, भारतीय लोगों के लिए कंपनियां बनाई, आम आदमी के लिए विशाल शेयरधारक धन बनाया, डिजिटल स्पेस, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, ओ एंड जी, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, कपड़े, दूरसंचार में क्रांति ला दी, डिजिटल स्पेस, में क्रांति ला दी पी, ताकि, बिना सिर के मुर्गियां उन्हें दुरुपयोग कर सकें, निःशुल्क लागत, रक्षा रीढ़, शिपिंग, आदि। आदि !!

तथ्य है, हम भारतीय सिर्फ भावनात्मक मूर्खों के गुंडे हैं!! उससे ज्यादा कुछ नहीं!!

अंबानी-अडानी ने देश के लिए अधिक धन और नौकरियां पैदा की हैं

- 20 नडेला
- 200 Pichai's

और

- 1000 पराग ..
- 10 गुना से गुणा, फिर भी अम्बानी-अडानी

INDIANS IN GLOBAL TECH COS' CORNER OFFICES

Indian-Origin CEO	Listed Tech Co	Market Cap ($ bn)
Satya Nadella	Microsoft	2,527
Sundar Pichai	Alphabet	1,924
Shantanu Narayen	Adobe	325
Arvind Krishna	IBM	106
Sanjay Mehrotra	Micron Technology	95
Nikesh Arora	Palo Alto Networks	54
Rangarajan Raghuram	VMware	51
Jayshree Ullal	Arista Networks	38.7
Parag Agrawal	Twitter	38.5
George Kurien	NetApp	20
Revathi Advaithi	Flex	8
Anjali Sud	Vimeo	3

को भारत में नफरत ही मिलती है.. *

- हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो मस्तिष्क-ड्रेन के बारे में चिंता करता है और राष्ट्र में धन निर्माताओं का दुरुपयोग करता है।
- यह अब अमेरिका और चीन नहीं है। भारत 70 से अधिक यूनिकॉर्न 1 बिलियन डॉलर से अधिक के मूल्यांकन वाली स्टार्टअप कंपनी के साथ दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्ट-अप इको-सिस्टम बन रहा है। स्टार्टअप, 2021 में 40 लेकिन लोगों को अडानी के भारत में सबसे अमीर व्यक्ति बनने से दिक्कत है। टाटा समूह के 7,50,000 कर्मचारी हैं.।
- एल एंड टी 3,38,000 लोगों को रोजगार देता है।
- इन्फोसिस में 2,60,000 कर्मचारी हैं।
- महिंद्रा में 2,60,000 कर्मचारी हैं।
- रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2,36,000 लोग हैं।
- विप्रो में 2,10,000 कर्मचारी हैं।
- एचसीएल में 1,67,000 कर्मचारी हैं।
- एचडीएफसी बैंक में 1,20,000 कर्मचारी हैं।
- आईसीआईसीआई बैंक में 97,000 कर्मचारी हैं।
- टीवीएस समूह में 60,000 कर्मचारी हैं।
- बस ये दस कॉर्पोरेट एक साथ लगभग 25 लाख भारतीयों को रोजगार देते हैं और उन्हें बहुत सम्मानजनक वेतन देते हैं। ये 25 लाख कॉर्पोरेट नौकरियां कुल केंद्र सरकार के आधे से भी ज्यादा हैं। नौकरियां (48.34 लाख)। कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में कुल सरकारी नौकरियां भी 5 गुना है।
- सरकार। एक करोड़ से अधिक लोगों (1%) को नौकरियां प्रदान करता है और निजी और संगठित क्षेत्र 6-8त्न प्रदान करता है और बाकी 92त्न असंगठित क्षेत्र में नौकरी करता है।
- निजी क्षेत्र का सम्मान करें।
- करोडपति और अरबपतियों को पूजते हैं।
- नौकरी बनाने वालों के लिए जयकार करें।
- वे लाखों भारतीयों के लिए आजीविका का निर्माण कर रहे हैं।
- भारत में 3 पीढ़ियों की आर्थिक क्षमता को बर्बाद करने वाले असफल समाजवादी और कम्युनिस्ट राजनेताओं की बात न सुनें।
- यदि आप भविष्य की पीढ़ियों के लिए उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं, तो भारत को 1000 नए निगमों की आवश्यकता है, जो 1000 उच्च वेतन देने वाली नौकरियां बनाते हैं।

भारतीय होने पर गर्व करें .. अंदर और बाहर।

■ ■ ■ ■

नितिन गडकरी जी का मैं जबरदस्त फैन हूं। पर नितिन जी ने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को अपनी सभी पेट्रोल और डीसल से चलने वाली गाड़ियों में फ्लेक्स इंजन जो कि एथेनॉल कम्पेटिबल हों बनाने का हुक्म दे दिया है।

यह मैं मानता हूं कि एथेनॉल किफायती और पॉल्युशन फ्री फ्यूल है पर इसको बनाने के लिए हमें कृषि उत्पादों जैसे गन्ने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर गाड़ियां एथेनॉल से चलने लगीं तो एथेनॉल की बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत भी पड़ेगी। यह जरूरत इतनी बड़ी होगी कि सारी कृषि योग्य भूमि पर गन्ने की खेती की जाए तो भी शायद पूरी न हो सके।

निश्चित ही ऐसे में हम एक और बड़े डिजास्टर की और अग्रसर हो जाएंगे। किसान भाई गेंहू, चावल, दालों जैसे उत्पादों की बजाए गन्ने की खेती करने लगेंगे।

अगर बहुत आसान अल्टरनेटिव ढूंढना है तो हमें हर हालत में मेटल एयर बैटरी की तरफ ही जाना चाहिए क्योंकि इस टेक्निक में किसी भी अडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पडेगी। हां इसके बाद हम इससे बेहतर ऑप्शन्स को खुले मन से चुन भी सकते हैं और उनपर रिसर्च भी कर सकते हैं।

नितिन जी आप से बड़ा एन्ट्रप्रेयनोर मैने आजतक नहीं देखा पर मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे है वो भी जड़रहित नहीं हैं। आशा है आप संज्ञान लेंगे।

गडकरी जी ने क्लेरिफाई किया है कि एथेनॉल को हम ओनली फ्यूल बनाने नहीं जा रहे हैं बल्कि एथेनॉल का यूज पहले से ही मौजूद करोड़ों वाहनों और आगे आने वाले कुछ प्रतिशत वाहनों में किया जाएगा ताकि जो ब्लैकमेलिंग OPEC देशों ने शुरू की है उसका इलाज किया जा सके।

मोदी जी इन OPEC देशों का हमेशा के लिए ताजीब बंधवा रहे हैं। एक और पहले से मौजूद वाहनों में डीजल और पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ सभी विकल्पों पर जबरदस्त तेजी से काम किया जा रहा है। अपने वक्तव्य में उन्होंने मेटल एयर बैटरी ओर ग्रीन हाइड्रोजन का खुल कर समर्थन भी किया है और वायदा भी किया है कि अगले कुछ दिनों में ही फ्यूल पालिसी पर वो हस्ताक्षर करने जा रहे हैं।

मेरे दोस्तों और पाठकों को अच्छे से याद होगा कि अपनी पोस्ट में अभी के लिए मैने भी इन्हीं दो फ्यूल्स का समर्थन किया था।

अब चूंकि यह बात यहां तक तो मान ली गयी है तो मैं आगे का रोडमैप भी तय करना चाहूंगा। मेरी दृष्टि में हमें इसके बाद या इसके साथ साथ नैनो डायमंड बैटरी और सुपर कपैसिटर पर भी ध्यान देना होगा। यह भविष्य के एक मात्र फ्यूल होने वाले हैं। सुपर कपैसिटर बैटरी की लाइफ 100 वर्ष और नोनो बैटरी की लाइफ 25000 वर्ष है। अगर अमेरिका की बड़ी बड़ी कम्पनियों के CEO भारतीय हो सकते हैं तो हम खुद के लिए ये सब क्यों नहीं डेवेलोप कर सकते हैं। इस बार हम करेंगे दुनिया को लीड। ■

सबके अपने अपने दावे

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

सबसे आगे...

आगामी पांच विधानसभा चुनावों में प्रत्येक प्रदेश के अलग अलग चुनावी मुद्दे नजर आ रहे हैं हैं किन्तु सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सभी प्रदेशों में जनता के दिमाग के किसी कोने में जगह बना चुका है। जो भी दल इस इस नब्ज को पकड़कर जनता से जुड़े मुद्दों का हल उन्हे देता जायेगा, जनता उसे हाथों हाथ लेती चली जाएगी। अयोध्या की दीपावली से भव्य राम मंदिर निर्माण तक लोगों ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान देखा है। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के भव्य लोकार्पण के द्वारा इसको मजबूती मिली है। बनारस की दिव्यता और भव्यता अब देखते ही बनती है। यह सब वह संदर्भ हैं जो 2014 के बाद से राजनीतिक विमर्श की दिशा बदल चुके हैं। सनातन चेतना जागृत होने से हिन्दू वोट बैंक निर्णायक स्थिति में आ गया दिखता है। भाजपा के साथ अन्य विपक्षी दल भी अब इसको समझने लगे हैं कि चुनाव जीतने के लिए हिन्दू वोट बैंक आवश्यक है इसलिए केजरीवाल का हनुमान चालीसा पढ़ना, अयोध्या जाना, राहुल और प्रियंका का मंदिर जाना, अखिलेश यादव का संतो से मिलना इस बात का प्रमाण है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अब चुनावी वोट बैंक बन चुका है। अब धीरे धीरे जाति और धर्म की राजनीति सांस्कृतिक विषयों की तरफ मुड़ने लगी है। जैसे बिहार में अब सुशासन और विकास की राजनीति आगे चल रही है। वहां सामाजिक समीकरण और वोट बैंक की राजनीति दवाब की मुद्रा में है। उपचुनाव में कोविड 19 के प्रभाव, प्रतिकूल राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों के बावजूद एनडीए ने सफलता प्राप्त की। नितीश कुमार की साख उनके काम के कारण बरकरार बनी हुयी है। दिल्ली में केजरीवाल भी तीन बार से जीतकर अपनी साख बनाए हुये हैं। बंगाल विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी जीत के बाद ममता बनर्जी का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि उनको लगता है कि वह राष्ट्रिय पटल पर राजनीति कर सकती हैं। इसी सिलसिले में वह मुंबई गईं और वहां राकांपा के शीर्ष नेता शरद पवार और शिवसेना के नेताओं से उन्होने मुलाकात की। इसी दौरान उन्होने राहुल पर कटाक्ष करते हुये कहा कि अब कोई यूपीए नहीं बचा है। इसका अर्थ साफ है कि अब वह विपक्ष का नेतृत्व करना चाहती हैं। वह अब अन्य राज्यों के क्षेत्रीय दलों से संपर्क कर अपने साथ लाने का उपक्रम कर रही हैं। मेघालय में हाल ही में 12 कांग्रेसी विधायक तृणमूल में शामिल हुये हैं। इसके साथ ही गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार में भी तृणमूल में कुछ नेता आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों में जीतकर अखिलेश यादव ममता बनर्जी को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों की दृष्टि से भी एक बड़ा राज्य है इसलिए प्रियंका गांधी 2024 की तैयारी अभी से कर रही हैं। वह नहीं चाहती हैं कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व को उत्तर प्रदेश से कोई चुनौती मिले। इसलिए कांग्रेस बहुत तेजी के साथ अपना जमीनी कैडर बना रही है। महिलाओं को 40 प्रतिशत भागीदारी की बात कहकर वह महिला वोटों को आकर्षित कर रही हैं। यही कारण है कि कुछ माह पहले अखिलेश यादव भाजपा से बढ़त बनाते दिख रहे थे किन्तु अब नए चुनाव सर्वे भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की बढ़त दिखा रहे हैं। भाजपा की सत्ता विरोधी हवा को सपा भुनाने में असफल होती दिख रही है। इसकी वजह सपा की अनेक स्थानों पर सांगठनिक कमजोरियां एवं जिलों को लखनऊ से समझने की भूल है। स्थानीय कद्दावर नेताओं के स्थान पर लखनऊ केन्द्रित नेताओं के आधार पर जिलों को समझने की भूल सपा का बड़ा नुकसान करने जा रही है। इन सबके बीच भाजपा की बढ़त की वजह उसके द्वारा निरंतर किए जा रहे कार्य हैं। 2014 के बाद से ही भाजपा अपने अजेंडे पर कार्य कर रही है। राम मंदिर और 370 के द्वारा वह संदेश दे चुकी है कि उसके जिन कार्यों को विपक्षी असंभव बताते थे वह उसने पूरे कर दिये हैं। इन सबके बीच सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को प्रतिबंधित कर दिया है। अरब देशों में काफी मात्रा में नौकरी कम होने से भारतीय वापस आ रहे हैं। भारत में भी कट्टरता फैलाने में इस जमात का हाथ रहा है। पूरे विश्व की तेल पर कम होती निर्भरता एवं अन्तराष्ट्रिय समुदाय के दवाब कारण हुये इस निर्णय से भारतीय मुस्लिमों की स्थिति सुधरेगी। उसका झुकाव अरब देशों से कम होकर भारत में रोजगार की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। इसके कारण मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग पसमांदा मुस्लिमों की स्थिति अशराफ मुस्लिमों के सामने बेहतर होने की यह शुरुआत होने जा रही है। धार्मिक कट्टरता में कमी आने पर आपसी सामंजस्य भी बढ़ने जा रहा है। अन्तराष्ट्रिय स्तर पर कम होते रोजगार के दुष्प्रभाव के बीच भारत की आत्मनिर्भरता ही उसे वैश्विक परिदृश्य में स्थापित रख सकती है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसकी धुरी बनता दिख रहा है।

● अमित त्यागी

एक तरफ काशी विश्वनाथ में लोकार्पण और दूसरी तरफ सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगना, यह दो ऐसी खबरें हैं जिनका विश्लेषण बेहद महत्वपूर्ण है। तबलीगी जमात के कारण ही भारत में कट्टरता बढ़ी थी। सऊदी अरब से आने वाले धन के कारण पिछले चार दशक में भारत में मुसलमानों का एक खास उच्च वर्ग इस धन के द्वारा अपना अजेंडा चला रहा था। इस अजेंडे के कारण ही भारत में रहने वाले पिछड़े मुसलमान पसमांदा को भी शक की निगाह से देखा जाने लगा था। अब चूंकि तबलीगी जमात पर अरब में प्रतिबंध लग चुका है इसलिए भारत में अब नया मुस्लिम विमर्श खड़ा होगा। सोशल मीडिया के दौर में अब कट्टरता से ज्यादा वास्तविक ज्ञान पर चर्चा आरंभ हो सकती है। ऐसा माना जा सकता है कि कट्टर इस्लाम तभी तक प्रभावी रह सकता है जब तक समाज में चैतन्यता नहीं होती है। जैसे ही समाज जागृत हो जाता है, वह सारगर्भित विषयों को स्वीकार करने लगता है। तेल पर निर्भरता कम होने के कारण अब नया वैश्विक परिदृश्य बैटरी चालित वाहनों का होगा। इसमे एक नया विकल्प बायो डीजल जैसे कृषि उत्पादित ईंधन का होगा। यानि कि अब खाड़ी देशों पर तेल की निर्भरता कम होगी और कृषि आधारित ईंधन व्यवस्था नया स्वरूप लेगी। आने वाले भविष्य में ऑटो मोबाइल क्षेत्र में यह एक बड़ा बदलाव

होगा। बाहर के देशों से वापस भारत लौंटे भारतीयों के लिए कृषि क्षेत्र में समाहित होना एक बड़ा विकल्प बनेगा। वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम के अनुसार 2025 तक वैश्विक स्तर पर 60 प्रतिशत नौकरी कम हो जाएंगी। लगभग 100 करोड़ लोगों को स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। ऐसे में परंपरागत उद्योग धंधे, सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय कुटीर उद्योग सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने जा रहे हैं। कोरोना काल का दौर अभी आगे भी चलते रहने वाला है ऐसे में जमीनी नब्ज को पकड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। अब राजनीति सिर्फ वर्तमान को ध्यान में रख कर नहीं की जा सकती है बल्कि भविष्य के अनुसार भी नीतिगत निर्णय आवश्यक हो गए हैं। जनता की नब्ज पकड्ने में मोदी माहिर खिलाड़ी दिख रहे हैं। एक तरफ वह वैश्विक परिदृश्य से सामंजस्य बैठाये हुये हैं तो दूसरी तरफ वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिये अपने वोट बैंक को साधे हुये हैं। ट्रम्प की हार के बाद मोदी की स्थिति चीन के समक्ष कमजोर हो गयी थी किन्तु कृषि कानून की वापसी कर उन्होने अपने विरोधियों को पूरी तरह साध दिया है। अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तियां भारत के आंतरिक गतिरोध को भुनाने की स्थिति में नहीं है। मोदी ने नयी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया है। कृषि कानून आंदोलन के समय मोदी को अपने साथियों से भी उतना सहयोग नही मिल रहा था जितना अपेक्षित था। उच्चतम न्यायालय के बार बार कहने के बाद भी गृह मंत्रालय आंदोलनकारियों पर कार्यवाही नहीं कर रहा था। मोदी और योगी के बीच मतभेद की खबरें भी खूब प्रचारित हुयी थीं। इसके बाद जब योगी के कंधे पर हाथ रखकर मोदी का फोटो आया तो अंदर और बाहर के सब विरोधी एक झटके में शांत हो गए।

इसके साथ ही मोदी ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स की देखरेख अब अपने हाथ में ले ली है। सेंट्रल विस्टा का बड़ा प्रोजेक्ट कई माह एडवांस चल रहा है। बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स के उदघाटन की तारीख तय कर दी गई है, ताकि मंत्रालय सही से काम करते रहें। इन सबके बीच जब काशी विश्वनाथ परियोजना का लोकार्पण हुआ तो वहां मोदी ने टिप्पणी की कि जब जब कोई औरंगजेब आया तब तब शिवाजी उठ खड़े हुये। ऐसा कहकर उन्होने भारतीय मूल की चेतना और विदेशी आक्रांताओं का अंतर स्पष्ट किया। अब विपक्षियों को यह नहीं सूझ रहा है कि वह हिन्दू समाज को गौरवान्वित करने वाले इन प्रयासों का क्या जवाब दें? यदि वह मोदी की बात का समर्थन करते हैं तो उनसे मुस्लिम नाराज होता है और यदि विरोध करते हैं तो हिन्दू समाज नाराज होता है। चूंकि, यह बात तो स्पष्ट है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत के लोगों पर घोर अत्याचार किए हैं। तलवार के दम पर इस्लाम फैलाया है। इसलिए आम जनमानस की इसी धारणा को मोदी के शब्द बल देते हैं और वह मोदी से जुड़ जाता है। लगभग आठ सदी तक न जाने कितने मंदिर तोड़े गये। लूट की गयी। यहां तक कि बाबर के समय राम जन्मभूमि के मंदिर को भी तोड़कर मस्जिद बना दी गयी। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ एवं मथुरा के मंदिर को तोड़कर भी वहां मस्जिद बना दी गयी। मुगल शासन के दौरान ही अंग्रेज भारत में व्यापार करने के बहाने से आए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में बहुत लूटपाट की। अपने फायदे के लिए हिन्दू मुस्लिम झगड़े करवाएं और भारत की मूल आत्मा को निरंतर आहत करते रहे।

वर्षो से आहत हिन्दू भावनाएं भुनाते मोदी

आदिकाल से मानव के जीवन में धर्म का महत्व रहा है। एक तरफ सनातन धर्म सभी धर्मों और उनकी पूजा पद्धति को स्वीकार करता है वहीं इस्लाम और ईसाइयत ने अपने धर्मों के प्रचार के लिए शक्ति का सहारा लिया। हिंसा की। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए। सनातन धर्मियों ने अन्य धर्मों को कभी विधर्मी नहीं माना। उनको स्वीकार किया। जब अन्य धर्म वाले शरण के लिए आए तो उनको भी स्वीकार किया। इनमे ईसाई, फारसी और यहूदी लोग प्रमुख थे। जबकि इस्लाम भारत में तलवार की नोक पर आया। इन आक्रमणकारियों ने भारत में बड़ी संख्या में मंदिरों, मठों, बौद्ध विहारों को निशाना बनाया। इनके ऐसे रवैये के कारण ही हिंदुओं ने इनको अपना शत्रु माना और उनसे निरंतर संघर्ष किया। इस्लामी हमलावरों के द्वारा जो धार्मिक आस्था के चिन्ह तोड़े गये उसके कारण ही हिन्दू मुस्लिम की खाई बड़ी हुयी। चूंकि, मुस्लिम समाज के द्वारा इन आक्रांताओं का विरोध नहीं किया गया इसलिए हिन्दू समाज निरंतर आहत होता रहा। अंग्रेजों ने अपना हित साधने के लिए इस खाई को और चौड़ा तो किया किन्तु हिन्दू समाज की भावनाओं को समझकर भूल सुधार का कोई कार्य नहीं किया। इसी खाई के कारण भारत का विभाजन हुआ। अफगानिस्तान, म्यांमार जैसे देश भारत से पहले ही अलग हो चुके थे। कुल मिलाकर सनातन धर्म पर हमला ही नहीं हुआ बल्कि भौगोलिक हमले भी निरंतर चलते रहे। भारत के अंदर इसके कारण एक घुटन का वातावरण बनने लगा। हिन्दू समाज के अंदर एक गुस्सा पनपने लगा। सबसे पहले जनसंघ हिंदुओं के लिए आगे आई इसके बाद भाजपा ने इसका स्वरूप ले लिया। वामपंथी दलों और कांग्रेस के सेकुलर कार्ड से उपजे इस गुस्से को जैसे ही नरेंद्र मोदी

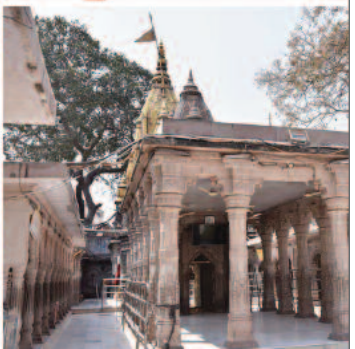

देश की आध्यात्मिक चेतना का कॉरिडोर

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपने आततायी अतीत को सुधारने का संकल्प है। यानि सदियों की आध्यात्मिक विरासत का कायाकल्प। इस कॉरिडोर के बहाने इतिहास ने नई करवट ली है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक हजार साल के अन्याय का प्रतिकार बिना किसी ध्वन्स के हुआ है।सिर्फ सृजन के जरिए। इसका स्वागत होना चाहिए। ये कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ मंदिर के मुक्ति का उत्सव है। काशी मुक्ति का शस्र है। मुक्ति की कामना में लोग यहां खिंचे चले आते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इसी मुक्ति कामी चेतना ने काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हजार साल पुराने गौरव को लौटाया है।

एक हजार साल से काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वंस का जो दंश भोग रहा था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने उससे मुक्ति दिलायी है। ग्यारहवीं शताब्दी तक इस मंदिर की शक्ल ऐसी ही थी, जैसी आज बनायी गयी है।काशी विश्वनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि मंदिरों का संकुल था। मंदिर परिसर के चारों तरफ कॉरिडोर की शक्ल में कक्ष थे, जहां संस्कृत, तंत्र और आध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी यहीं टिक कर धर्म और दर्शन की शिक्षा लेते थे। सत्रहवीं शताब्दी में औरंगजेब ने इस मंदिर संकुल को तोड़ने का आदेश इसलिए दिया कि उसका बागी भाई दारा शिकोह यहां संस्कृत पढ़ता था। दारा शिकोह ने औरंगजेब और इस्लाम से बगावत की थी। इसलिए औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया। फारसी में लिखे इस फरमान में दर्ज था कि `वहां मूर्ख पंडित, रद्दी किताबों से दुष्ट विद्या पढ़ाते हैं।'

औरंगजेब ने मंदिर तुड़वा कर एक मस्जिद भी तामीर करा दी। जिसे बाद में ज्ञानवापी मस्जिद कहा गया। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुंआ। उसके बाद कई चरणों में काशीवासियों, होल्कर और सिन्धिया सरदारों की मदद से मंदिर बनता बिगड़ता रहा। लेकिन उसकी वह भव्यता नहीं लौटी। औरंगजेब के जाने बाद मंदिर के पुनर्निर्माण का संघर्ष जारी रहा। 1752 से लेकर 1780 तक मराठा सरदार दत्ता जी सिन्धिया और मल्हारराव होल्कर ने मंदिर की मुक्ति के प्रयास किए। पर 1777 और 80 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होल्कर को सफलता मिली। अहिल्याबाई ने मंदिर तो बनवा दिया पर वह उसका पुराना वैभव और गौरव नहीं लौटा पाईं। 1836 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखर को स्वर्ण मंडित कराया। पर भगवान शंकर मंदिरों के `थर्मस फ़्लास्क' में सांस लेते रहे। संकुल के दूसरे मंदिरों पर पुजारियों का कब्जा हो गया और धीरे-धीरे मंदिर परिसर ऐसी बस्ती में बदल गया जिसके घरों में प्राचीन मंदिर कैद हो गए। कॉरिडोर को बनवा कर प्रधानमंत्री ने अहिल्या बाई के सपनों को भी विस्तार दिया है। परिसर के प्राचीन मंदिर जो चुरा कर घरों में कैद कर लिए गए थे उन्हें मुक्त कराया।

इतिहास के अपने प्रस्थान बिन्दु होते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का यह तीसरा प्रस्थान बिन्दु है। जब भी इतिहास में इसका जिक्र आएगा, मंदिर का पुनरुद्धार करने वाली अहिल्या बाई होल्कर, इसके शिखर को स्वर्ण मंडित करने वाले महाराजा रणजीत सिंह और मंदिर को उसकी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आभा लौटाने वाले नरेन्द्र मोदी का नाम सामने होगा।

आज जिस काशी विश्वनाथ मंदिर संकुल या कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। वह एक हजार साल से विध्वंस की विभीषिका झेल रहा था। शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति से पहले काशी की उत्पत्ति हुई थी। शिव आदिदेवता हैं और यह शिव की नगरी है। कह सकते हैं कि हिन्दू धर्म की जड़ें अयोध्या, मथुरा से ज़्यादा काशी विश्वनाथ में गहरी हैं। राम का व्यक्तित्व मर्यादित है। कृष्ण का उन्मुक्त और शिव असीमित व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वे आदि हैं और अंत भी। बाकी सब देव हैं। वे महादेव। इसलिए काशी विश्वनाथ से जनमानस का जुड़ाव ज़्यादा है।

सबसे पहले इस मंदिर के टूटने का उल्लेख 1034 में मिलता है। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 1194 में मोहम्मद गोरी ने इसे लूटने के बाद तोड़ा। स्थानीय लोगों ने इसे फिर बनवाया। 1447 में जौनपुर के सुल्तान ने इसे फिर से तोड़ा। अकबर की सर्वसमावेशी नीति के चलते टोडरमल ने 1585 में फिर इसका जीर्णोद्धार करवाया। टूटने बनने का सिलसिला जारी रहा। इस बार काशी विश्वनाथ के खलनायक शाहजहां थे। 1632 में शाहजहां ने इसे तोड़ने का आदेश देकर सेना भेज दी। संघर्ष हुआ। काशी के लोगों की एकजुटता के आगे मुगल सेना को वापस लौटना पड़ा। हालांकि इस संघर्ष में काशी के 63 मंदिर शहीद हुए।काशी विश्वनाथ मंदिर से औरंगजेब के गुस्से की एक वजह यह थी कि यह परिसर संस्कृत शिक्षा का बड़ा केन्द्र था और दाराशिकोह यहां संस्कृत पढ़ता था। साकी मुस्तइद खां की किताब `मासिर-ए-आलमगीरी' के मुताबिक 16 जिलकदा हिजरी-1079 यानी 18 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी कर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। इस बार एक दीवार को छोड़कर जो आज भी मौजूद है, समूचा मंदिर गिरा दिया गया। 15 रब-उल-आखिर यानी 2 सितम्बर 1669 को बादशाह को खबर दी गयी कि मंदिर न सिर्फ गिरा दिया गया है, बल्कि उसकी जगह मस्जिद की तामीर करा दी गयी है। पर साथ ही परिसर के हिस्से में पंडितों ने मंदिर का अस्तित्व बनाए रखा। लेकिन मंदिर उपेक्षित रहा मस्जिद बड़ी और मंदिर छोटा था।

परम्परा और इतिहास में यह मंदिर कालजयी सांस्कृतिक परंपराओं और उच्चतम आध्यात्मिक मूल्यों का जीवंत प्रतीक रहा है। यही समृद्ध परम्परा यहां देश भर के संतों को खींच कर लाती रही। जैन आए हुद् आए, आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि दयानंद सरस्वती, गुरुनानक सब यहां आए। सबकी आंखें यहीं खुलीं।

फरवरी 1916 में महात्मा गांधी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थापना सम्मेलन में गए। बीएचयू में अपने संबोधन से एक दिन पहले गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर गए। मंदिर की गंदगी ने उन्हें उद्वेलित किया। मंदिर की दशा की दिलचस्प तुलना उन्होंने भारतीय समाज से की। बीएचयू के अपने संबोधन में उन्होंने कहा, `इस महान मंदिर में कोई अजनबी आए, तो हिंदुओं के बारे में उसकी क्या सोच होगी और तब जो वह हमारी निंदा करेगा, क्या वह जायज नहीं होगी ?, क्या इस मंदिर की हालत हमारे चरित्र को प्रतिबिंबित नहीं करती ? एक हिंदू होने के नाते, मैं जो महसूस करता हूं वही कह रहा हूं। अगर हमारे मंदिरों की हालत आदर्श नहीं है, तो फिर अपने स्वशासन के मॉडल को हम कैसे गलतियों से बचा पाएंगे ? जब अपनी खुशी से या बाध्य होकर अंग्रेज इस देश से चले जाएंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि हमारे मंदिर एकाएक पवित्रता, स्वच्छता और शांति के प्रतिरूप बन जाएंगे ?'

महात्मा गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर चिंता जताते हुए जिन तत्वों की जरूरत मंदिर के लिए बताई और स्वच्छता, पवित्रता व शान्ति का केन्द्र बनाने का जो सपना देखा था, वो उनके जन्म के 150 साल में पूरा हुआ है। उन्हें इससे बेहतर ढंग से कैसे याद किया जा सकता है! काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमारी धार्मिक परम्परा की प्रतिकृति है। इस देश के महापुरुषों के सपनों का स्मारक है। ये स्वप्न इस देश की महान आध्यात्मिक परंपरा की जमीन पर देखे गए। इनका इस भव्य रूप में साकार होना कल्पना से भी परे है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इस देश की आध्यात्मिक चेतना का कॉरिडोर बन गया है। अपनी पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ।

(सौजन्य -अमर उजाला)

हिन्दू, हिन्दुत्व व हिंदुत्ववाद की व्याख्या

पिछले एक माह से परम ज्ञानी,आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी विवेकानन्दजी, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु सरीखे विद्वानों के पितामह स्वरूप चिर युवा महान दार्शनिक श्रीयुत राहुल जी (नकली गांधी व जबरदस्ती हिन्दू ही नहीं दत्तात्रेय गोत्रीय ब्रह्मन भी) के वक्तव्यों को सुन सुन कर कान तो पक ही रहे हैं और जब उनके सत्संग में बैठे युवा से बुजुर्गतम सत्संगी तालियां बजाते हैं तो जी करता है। अपना कपार फोर कर दिमाग की सहनशक्ति की शक्ति का अन्त्य परीक्षण (post mortem) करवा ही लूं।

अब उनके दो वक्तव्य सुनिए-

पहला- मैं हिंदू हूं,परंतु हिंदुत्ववादी नहीं हूं!

दूसरा-हिंदू आगे से वार करता है और हिंदुत्ववादी पीठे से वार करता है!

अब इस 'महोखा' (एक चिड़िया, जिसे आदि मूर्खों के लिए विशेषण के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है) की बातों पर मैं ये लेख नहीं लिख रहा हूं बल्कि ये लेख उन कांग्रेसी भकचोन्हर सत्संगियों के लिए है जो ये जानते हुए भी कि ये आउल जी चरम महोखा हैं ताली पीट कर इस का मनोबल बढ़ाते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी को नेस्तनाबूद करने में अपना महती योगदान देते हैं।

वस्तुतः हिंदू और हिंदुत्व का अन्योन्याश्रय (symbiotic) सम्बन्ध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आखिर कैसे ? और क्यों ?

उदाहरणार्थ-

1. अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो क्रिश्चियनवादी भी होऊंगा, क्योंकि मैं क्रिश्चियन तभी होऊंगा जब क्रिश्चियन धर्म में एक उम्र होने पर मेरा बपतिस्मा होगा, मुझे बाइबल से प्रार्थना करना होगा,चर्च जाना होगा,शादी विवाह,मरण मरण, दैनिन्दिन (day to day) कार्य बाइबल के अनुसार करना होगा। अर्थात मुझे क्रिश्चियन बनने से पहले ही क्रिश्चियनवादी बनना होगा।

2. अगर मैं मुस्लिम हूं तो यहां भी आपके मुस्लिम के रूप में पहली मान्यता ये होगी कि आपका 'खतना' (लिंग के अग्रभाग के चमड़े को एक उम्र विशेष पर शल्य क्रिया से काट दिया जाय और यह कार्य कोई शल्य चिकित्सक नहीं वरन अनपढ़ मुल्ला मौलवी करते है) कर दिया जाय। अगर मैं मुस्लिम हूं तो मुझे तथाकथित तौर पर कुरआन की आयतों, हदीसों का अनुसरण करना लाजमी होगा और ये मानना होगा कि इस ब्रह्मांड का मालिक सिर्फ अल्लाह है और जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर, परमेश्वर को मानता है वो काफिर है और उसको जीने का अधिकार नहीं है। तो मान्यवर ये इस्लामवाद और यहां भी पहले आपको इस्लामवादी होना पड़ेगा फिर आप मुस्लिम हो पाएंगे। यही है इस्लामवाद।

अब आते हैं हिन्दू, हिन्दुत्व व हिंदुत्ववाद पर!

हिन्दू कौन है ?

पहला यक्ष प्रश्न तो यही है। तो इसके उत्तर में किसी विशेष मीमांसा की आवश्यकता नहीं है।सीधे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो मैं कहूंगा पूरे ब्रह्मांड में जो भी व्यक्ति अपना रोजमर्रा कार्य, उत्सव, शादी, ब्याह, श्राद्ध, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि को सम्पन्न करने के लिए वेद वर्णित प्रक्रिया की अनुपालना करता है वो हिन्दू है। हिन्दू होने के प्रमाण के लिए इससे अधिक की आश्यकता नहीं है। वेदों में भी धर्म की व्याख्या यही है कि धर्म शब्द का प्रादुर्भाव संस्कृत के 'धृ' धातु से हुआ है जिसका अर्थ है- धारयति अर्थात आप जो धारण करते हैं वही धर्म है। सनातन हिन्दू धर्म में आपके दैनिन्दिन अचार,विचार,व्यवहार ही धर्म है।

हिन्दुत्व क्या है?

जिस प्रकार क्रिश्चियन धर्म में आप असल में तब समाहित होते हैं जब आपको बपतिस्मा से (Baptised) अभिमंत्रित किया जाता है,इस्लाम में शामिल होने की पहली सीढ़ी है लिंग का खतना (surgery of upper skin of penis)। इस्लाम में महिलाओं का भी खतना प्रचलित है।

इसी प्रकार वेदों के अनुसार आप सनातनी तब होंगे जब आपका यज्ञोंपवीत अर्थात जनेऊ होगा जिसे 'द्विज' अर्थात दूसरे जन्म की संज्ञा दी गयी है। तो 'ये है हिन्दुत्व'। हां कुछ धर्म के ठेकेदारों व जनाधारविहीन लोगों ने हिंदुओं की एक बड़ी जनसंख्या के यज्ञोंपवीत का मार्ग अपने निजी स्वार्थवश अवरुद्ध कर दिया।

हिंदुत्ववाद व हिंदुत्ववादी क्या और कौन हैं?

तो सहज व सरल शब्दों में हिन्दुत्व की व्याख्या मैंने कर दिया है। अब बात करते हैं हिंदुत्ववाद की। प्रत्येक वो हिंदू जो अपने प्रत्येक कार्य का वैदिक रीति नीति के अनुसार निर्वहन करता है तो वह हिन्दुत्व का पालन करता है।अब इसे आप हिंदुत्ववाद कहें या आप उस व्यक्ति को हिंदुत्ववादी कहें यह आप पर निर्भर करता है।

हिन्दू धर्म

बहुत सारे विदेशी या तथाकथित देसी इतिहासकार, मीमांसा मर्मज्ञ 'हिन्दू एक धर्म है' मानने को तैयार नहीं हैं। तर्क में कहते हैं कि फारस के विद्वानों ने सिंधु नदी के पूर्व रहने वालों को हिन्दू कहा क्योंकि, उनके यहां वर्णमाला में 'स' शब्द नहीं था और उसका स्थानापन्न शब्द 'ह' था। तो प्रश्न उठता है कि 'फारस' के स्थान पर 'फारह' क्यों न हुआ ? 'इस्लाम' की जगह 'इह्लाम' क्यों न हुआ ? तत्कालीन 'शाह' या 'सुल्तान' की जगह 'हाह' या 'हुलतान' क्यों न हुआ ?

अतः ये देसी विदेशी इतिहासकार सैकड़ों वर्षों से हिन्दू, हिन्दुत्व व हिंदुत्ववाद की अवधारणा पर प्रहार करते आ रहे हैं और बाकी रही सही कसर हमारे पप्पू, सोनिया जैसे छद्म हिन्दू,लेपट लिबरल पत्रकार, सिकुलर, फिकुलर जैसे अब्राहमिक धर्मों के जारज (वर्णसंकर) वंशज पूरी कर देते हैं।

आज मैंने ये सहज व्याख्या किया है ताकि नकली हिन्दू दार्शनिक स्वामी राहुल व उनके सत्संगी अनुयायियों के समझ में हिन्दुत्व सहजता से भर जाए।

- सन्तोष पांडे

औरंगजेब ने यहां तलवार के दम पर सभ्यता बदलने की कोशिश की : मोदी

पीएम मोदी ने काशी की धरती से कहा, आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। यहां काशी में तो माता अन्नपूर्णा खुद विराजती हैं। मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा, एक शताब्दी के इंतजार के बाद अब फिर से काशी में स्थापित की जा चुकी है।

वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद कहा, काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन से भारत को निर्णायक दिशा मिलेगी, उज्ज्वल भविष्य का सूत्रपात होगा। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने पहले काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर गंगा नदी में डुबकी लगाई।

इसके बाद पवित्र गंगाजल से काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया. करीब पांच लाख वर्ग फीट में फैली काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के पहले चरण की शुरुआत के साथ ही पीएम मोदी ने कहा, आताताियों ने वाराणसी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए. यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं।

मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जनता को भगवान बताते हुए उनसे तीन चीजों की मांग की। उन्होंने कहा, `गुलामी के लंबे कालखंड ने हम भारतीयों का आत्मविश्वास ऐसा तोड़ा कि हम अपने ही सृजन पर विश्वास खो बैठे। आज हजारों वर्ष पुरानी इस काशी से, मैं हर देशवासी का आह्वान करता हूं- पूरे आत्मविश्वास से सृजन करिए, इनोवेट कीजिए, इनोवेटिव तरीके से करिए। मेरे लिए जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप है, हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है, इसलिए मैं कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए तीन संकल्प चाहता हूं- स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। आज हमें संकल्प लेना है, वो है आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने प्रयास बढ़ाने का। ये आजादी का अमृतकाल है। हम आजादी के 75वें साल में हैं। जब भारत सौ साल की आजादी का समारोह बनाएगा, तब का भारत कैसा होगा, इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा।

पीएम मोदी ने काशी की धरती से कहा, आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। यहां काशी में तो माता अन्नपूर्णा खुद विराजती हैं। मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा, एक शताब्दी के इंतजार के बाद अब फिर से काशी में स्थापित की जा चुकी है।

पीएम मोदी ने काशी का उल्लेख करते हुए कहा, `काशी अहिंसा, तप की प्रतिमूर्ति चार जैन तीर्थंकरों की धरती है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से लेकर वल्लभाचार्य, रमानन्द जी के ज्ञान तक, चैतन्य महाप्रभु,समर्थगुरु रामदास से लेकर स्वामी विवेकानंद,मदनमोहन मालवीय तक, कितने ही ऋषियों,आचार्यों का संबंध काशी की पवित्र धरती से रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण यहां पड़े थे। रानीलक्ष्मी बाई से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक, कितने ही सेनानियों की कर्मभूमि-जन्मभूमि काशी रही है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद,पंडित रविशंकर, और बिस्मिल्लाह खान जैसी प्रतिभाएं, इस स्मरण को कहां तक ले जाया जाए।

पीएम मोदी ने कहा, `आताताियों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए! औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की! लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं! अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का अहसास करा देते हैं।

पीएम मोदी ने उन कारिगरों का भी अभिवादन किया जो कॉरिडोर के निर्माण में लगे रहे। पीएम ने कहा, `हमारे कारीगर, हमारे सिविल इंजीनयरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग, वो परिवार जिनके यहां घर थे सभी का मैं अभिनंदन करता हूं. इन सबके साथ यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन-रात एक कर दिया।'

पीएम मोदी ने कहा, `मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई-बहन का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के विपरीत काल में भी, उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इन श्रमिक साथियों से मिलने का, उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है। काशी तो काशी है! काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हों, उस काशी को भला कौन रोक सकता है?'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल तीन हजार वर्ग फीट में था, वो अब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50 से 75 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं. यानि पहले मां गंगा का दर्शन-स्नान, और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम आ सकेंगे।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है, हमारे भारत की सनातन संस्कृति का! ये प्रतीक है, हमारी आध्यात्मिक आत्मा का! ये प्रतीक है, भारत की प्राचीनता का, परम्पराओं का! भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का।

आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के दर्शन नहीं करेंगे. आपको यहां अपने अतीत के गौरव का अहसास भी होगा. कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही हैं, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा, अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल कालभैरव जी के दर्शन करके भी आ रहा हूं, देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारी अंतर-आत्मा को जागृत कर देती है।

काशी : गंगा तेरा पानी अमृत

काशी विश्वनाथ मंदिर कोरिडोर बन जाने से विदेशों में रहने वाले भारतीय और देश में रहने वाले कुछ लोग बहुत उत्साहित हैं। वे मानते हैं कि इस निर्माण से मोदी जी ने मुसलमान आक्रांताओं से हिसाब चुकता कर दिया। नए कोरिडोर का भव्य द्वार और तंग गलियों को तोड़कर बना विशाल प्रांगण अब पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक व सुविधाजनक हो गया है। वे इस प्रोजेक्ट को मोदी जी की ऐतिहासिक उपलब्धि मान रहे हैं ।

वहीं काशीवासी गंगा मैया की दशा नहीं सुधारने से बहुत आहत हैं। जिस तरह गंगा मैया में मलबा पाटकर गंगा के घाटों का विस्तार काशी कोरिडोर परियोजना में किया गया है उससे गंगा के अस्तित्व को ही ख़तरा उत्पन्न हो गया है। हजारों करोड़ रुपया 'नमामी गंगे' के नाम पर खर्च करके भी गंगा आज भी मैली है। मल-मूत्र से युक्त 'अस्सी नाला' आज भी गंगा में बदबदा कर गिर रहा है। लोगों का कहना है कि मोदी जी के डुबकी लगा लेने से गंगा निर्मल नहीं हो गयी। पिछली भाजपा सरकार में गंगा शुद्धि के लिये मंत्री बनी उमा भारती ने कहा था कि 'अगर मैं गंगा की धारा को अविरल और इसे प्रदूषण मुक्त नहीं कर पायी तो जल समाधि के लूंगी।' आज वे कहां हैं ?

पिछले दो दशकों में गंगा की देखरेख की बात तो हुई, लेकिन कर कोई कुछ खास नहीं पाया। यह बात अलग है कि इतना बड़ा अभियान शुरू करने से पहले जिस तरह के सोच-विचार और शोध की जरूरत पड़ती है, उसे तो कभी किया ही नहीं जा सका। विज्ञान और टैक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जितनी ज्यादा चर्चा होती रही, उसे ऐसे काम में बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। जबकि जो कुछ भी हुआ, वो ऊपरी तौर पर और फौरीतौर पर हुआ। नारेबाजी ज्यादा हुई और काम कम हुआ। इससे यह पता चलता है कि देश की धमनियां मानी जाने वाली गंगा-यमुना जैसे जीवनदायक संसाधनों की हम किस हद तक उपेक्षा कर रहे हैं। इससे हमारे नजरिये का भी पता चलता है।

यहां यह दर्ज कराना महत्वपूर्ण होगा कि बिना यमुना का पुनरोद्धार करे गंगा का पुनरोद्धार नहीं होगा। क्योंकि अंततोगत्वा: प्रयाग पहुंचकर यमुना का जल गंगा में ही तो गिरने वाला है। इसलिए अगर हम अपना लक्ष्य ऐसा बनाए, जो सुसाध्य हो, तो बड़ी आसनी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यमुना शुद्धीकरण को ही गंगा शुद्धि अभियान का प्रस्थान बिंदु माना जाए। यहां से होने वाली शुरुआत देश के जल संसाधनों के पुनर्नियोजन में बड़ी भूमिका निभा सकती है। अब देश के सामने समस्या यह है कि एक हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी यमुना के शुद्धीकरण के लिए कोई व्यवस्थित योजना हमारे सामने नहीं है। मतलब साफ है कि यमुना के लिए हमें गंभीरता से सोच विचार के बाद एक विश्वसनीय योजना चाहिए। ऐसी योजना बनाने के लिए मंत्रालयों के अधिकारियों को गंगा और यमुना को प्रदूषित करने वाले कारणों और उनके निदान के अनुभवजन्य समाधानों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान की छोड़ो कम से कम तथ्यों की जानकारी तो होनी चाहिए। समस्या जटिल तो है ही लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर दे दें। अगर यह दावा किया जा रहा है कि आज हमारे पास संसाधनों का इतना टोटा नहीं है कि हम अपने न्यूनतम कार्यक्रम के लिए संसाधनों का प्रबंध न कर सकें, तो गंगा-यमुना के पुनरोद्धार के लिए किसी भी अड़चन का बहाना नहीं बनाया जा सकता।

एक ओर गंगोत्री के पास विकास के नाम पर हिमालय का जिस तरह नृशंस विनाश हुआ है, जिस तरह वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया गया है, जिस तरह डाइनामाइट लगाकर पर्वतों को तोड़ा गया है और बड़े-बड़े निर्माण किये गये हैं, उससे नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र लगातार संकुचित होता गया। इसलिए स्रोत से ही नदियों में जल की भारी कमी हो चुकी है। नदियों में जल की मांग करने से पहले हमें हिमालय को फिर से हराभरा बनाना होगा।

काशी का एक विहंगम दृश्य

वहीं दूसरी ओर मैदान में आते ही गंगा कई राज्यों के शहरीकरण की चपेट में आ जाती है। जो इसके जल को बेदर्दी से प्रयोग ही नहीं करते, बल्कि भारी क्रूरता से इसमें पूरे नगर का रासायनिक व सीवर जल प्रवाहित करते हैं। इस सबके बावजूद गंगा इन राज्यों को इनके नैतिक और कानूनी अधिकार से अधिक जल प्रदान कर उन्हें जीवनदान कर रही है। पर काशी तक आते-आते उसकी कमर टूट जाती है। गंगा में प्रदूषण का काफी बड़ा हिस्सा केवल कानपुर व काशी वासियों की देन है। जब तक

गंगा जल के प्रयोग में कंजूसी नहीं बरती जायेगी और जब तक उसमें गिरने वाली गन्दगी को रोका नहीं जायेगा, तब तक उसमें निर्मल जल प्रवाहित नहीं होगा।

आज हर सरकार की विश्वसनीयता, चाहें वो केन्द्र की हो या प्रान्तों की, जनता की निगाह में काफी गिर चुकी है। अगर यही हाल रहे तो हालत और भी बिगड़ जायेगी। देश और प्रान्त की सरकारों को अपनी पूरी सोच और समझ बदलनी पड़ेगी। देशभर में जिस भी अधिकारी, विशेषज्ञ, प्रोफेशनल या स्वयंसेवी संगठन ने जिस क्षेत्र में भी अनुकरणीय कार्य किया हो, उसकी सूचना जनता के बीच, सरकारी पहल पर, बार-बार, प्रसारित की जाए। इससे देश के बाकी हिस्सों को भी प्रेरणा और ज्ञान मिलेगा। फिर सात्विक शक्तियां बढेंगी और लुटेरे अपने बिलों में जा छुपेंगे। अगर राजनेताओं को जनता के बढ़ते आक्रोश को समय रहते शांत करना है तो ऐसी पहल यथाशीघ्र करनी चाहिए।

वैसे सारा दोष प्रशासन का ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता का भी है। यहां की जनता जाति और धर्म के खेमों में बंटकर इतनी अदूरदृष्टि वाली हो गयी है कि उसे फौरी फायदा तो दिखाई देता है, पर दूरगामी फायदे या नुकसान को वह नहीं देख पाती। इसलिए सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। पर पिछले चुनाव प्रचार में जिस तरह उन्होंने मतदाताओं को उत्साहित किया, अगर इसी तरह अपने प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी और जनता के प्रति जबावदेह बनाते, विकास योजनाओं को वास्तविकता के धरातल पर परखने के बाद ही लागू होने के लिए अनुमति देते और प्रदेश के युवाओं को दलाली से बचकर शासन को जबावदेह बनाने के लिए सक्रिय करते, तो जरूर इस धारा को मोड़ा जा सकता। पर उसके लिए प्रबल इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। जिसके बिना न प्रदेश आगे बढ़ता है और ना बन सकेगा गंगा का पानी अमृत।

विनीत नारायण

के रूप में चेहरा मिला तो 2014 में भारत के लोगों ने उन्हे अपना नेता चुन लिया। इसके बाद लगातार मोदी के नेतृत्व को प्रदेशों में स्वीकार किया गया। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी के मुख्यमंत्री बनते ही सनातन चेतना जागृत होने की शुरुआत हो गयी। इसके बाद राम मंदिर और अब काशी विश्वनाथ कॉरीडोर के द्वारा इस चेतना को बल मिला जिसका प्रभाव जनता में देखा जा रहा है। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ तो 2022 के चुनाव परिणाम तय करेंगे किन्तु अब एक बात तो तय है कि हिन्दू एक वोट बैंक के रूप में उभर चुका है।

आज अगर भाजपा हिंदुओं की अस्मिता और गौरव के लिए कार्य कर रही है तो इसके पीछे उसका अपना राजनीतिक डीएनए है। एक ओर अन्य दल सिर्फ चुनाव के समय हिंदुओं की बात करते हैं तो दूसरी ओर भाजपा निरंतर हिन्दू वोट बैंक संबन्धित कार्य कर रही है। इसलिए हिन्दू भाजपा का वोट बैंक बन गया है। यदि अन्य दल भी हिन्दू के लिए निरंतर काम करना शुरू कर दें तो हिन्दू वोट बैंक को उन पर भी भरोसा हो जाएगा। वह भाजपा को छोडकर उनके साथ हो जाएंगे। जैसे भाजपा के ऊपर राम मंदिर का आरोप लगता है तो क्यों नहीं सपा श्रीकृष्ण मंदिर का बीड़ा उठा लेती है। इसके द्वारा एक झटके में वह भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। पर ऐसा करने से सपा बचती दिखती है। इन सबके बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह यादव की फोटो वाइरल होती है तो उसके अपने अपने कयास लगाए जाते हैं। इसके पहले सैफई में हुयी शादी में नरेंद्र मोदी स्वयं शिरकत कर चुके हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की शादी में स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हो चुके हैं। मुलायम सिंह यादव तो लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे चुके हैं। यानि कि सपा, भाजपा और संघ के बीच अंदर ही अंदर एक सामंजस्य है, यह तो दिखाई देने लगा है। ऐसे में अगर सपा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर का विषय उठा ले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव कई बार अपने कार्यकाल में हिन्दू तीर्थ स्थानों पर किए गये कार्यों का उल्लेख कर चुके हैं। राहुल गांधी पहले ही कभी जनेऊ पहन चुके हैं तो कभी खुद को कश्मीरी ब्राह्मण बता चुके हैं। ममता बनर्जी चंडी पाठ कर चुकी हैं तो अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ चुके हैं। चूंकि, भाजपा का डीएनए हिंदुवादी है इसलिए ये लोग पिछड़ जाते हैं। जिस दिन ये दल हिंदुवादी डीएनए आत्मसात कर लेंगे, उसी दिन भाजपा को बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। चूंकि अब ऐसा लगता है कि जैसे हिन्दू समाज मुखर हो चुका है। उसे यह स्वीकार नहीं है कि उसे मुस्लिम समाज से अलग नजरिये से देखा जाए। इसलिए हिन्दू समाज सेकुलर और राष्ट्रवाद की ऐसी परिभाषाएं स्वीकार नहीं कर रहा है जिसमे उसपे अत्याचार हों और वह मौन रहे।

मुस्लिम वोट बैंक को झगड़ते सभी विपक्षी दल

उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश

भारतीय मुसलमानों में ड़र पैदा कर भुनाती राजनीतिक शक्तियाँ

राष्ट्रवाद का नाम आते ही क्यों मुस्लिम समाज बिदक जाता है? क्यों मुस्लिम समाज को बार बार यह कहना पड़ता है कि भारत उनका भी देश है ? क्यों मुस्लिम समाज को पाकिस्तान समर्थक न होने के तर्क देने पड़ते हैं ? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर विमर्श एवं गहन चिंतन की आवश्यकता है। इसको समझने के लिए 1940-1947 के बीच के दौर को समझते हैं। यह वह दौर था जब जिन्ना और नेहरू के बीच सत्ता प्राप्ति का टकराव शुरू हो चुका था। जिन्ना किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। नेहरू को अपने आगे न झुकता देख उन्होने पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया था। उनके पाकिस्तान प्रेम ने मुस्लिमों के अंदर अलग देश की भावना बलवती करनी शुरू कर दी। उस समय देश में लगभग 10 करोड़ के आस पास मुस्लिम थे। उनमे से ज़्यादातर ने जिन्ना के साथ जाने का मन बनाया था। जिस भूभाग को पाकिस्तान के रूप में चिन्हित किया गया वह भारत का पूर्वी और पश्चिमी भाग था। दक्षिण के राज्यों से यह दोनों भूभाग काफी दूर थे। अब ऐसा नहीं है कि दक्षिण के राज्यों के मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे या पाकिस्तान समर्थक नहीं थे। चालीस के दशक में उन्होने भी पाकिस्तान के समर्थन में जिन्ना का साथ दिया। तत्कालीन दस करोड़ मुसलमानों में से एक तिहाई लोग भारत में रह गए और बाकी दो तिहाई पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत में बचे 3.5 करोड़ मुसलमानों में से काफी ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे किन्तु दक्षिण के सुदूर राज्यों से होने के कारण वह पाकिस्तान नहीं जा सके। या यूं भी कह सकते हैं कि जो लोग 1947 के प्रारम्भ में पाकिस्तान समर्थक थे वह लोग अगस्त 1947 में बंटवारे के बाद भारत में रह तो गए किन्तु उनकी विचारधारा और भावनाएं पाकिस्तान से मिली रहीं।

अब इनको हिंदुस्तानी होने की परिकल्पना वैधानिक रूप से तो सही हो सकती है किन्तु प्रयोगिक तौर पर इसको स्वीकार करना मुश्किल लगता है। बिहार, मुंबई, उड़ीसा, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था इसलिए ऐसे राज्यों में इस तरह के मुस्लिमों की संख्या काफी बड़ी मात्रा में थी। यहां रहे मुस्लिमों के अंदर नेहरू, मौलाना आजाद एवं गांधी जी के प्रति अपेक्षा का भाव रहा कि वह उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। चूंकि, वह लोग अंदर से पाकिस्तान जाने का मन बना चुके थे किन्तु जा नहीं पाये। इसलिए यह अपेक्षा स्वाभाविक भी थी। इनके अंदर डर भी था कि भारत के हिन्दू इनका क्या हाल करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद इन अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार भी दिये गये ताकि उनके हितों की रक्षा भी हो सके। अब यहां से वामपंथी विचारधारा ने काम करना शुरू किया। मुस्लिमों के अंदर के डर को इस विचारधारा ने बहुत ढंग से भुनाया। एक तरफ हिंदुओं में इन मुसलमानों को पाकिस्तानी कहकर प्रचारित किया तो दूसरी तरफ मुसलमानों को डर दिखाकर उनका तुष्टीकरण किया। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक का निर्माण कर लिया गया। इसके साथ ही हिंदुओं में दलित और आदिवासियों पर भी वामपंथी विचारधारा ने अपने डोरे डाले। भारत के जिन आदिवासी इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। वहां के संसाधनों की लूट के विदेशी षड्यंत्र का साथ देने के लिए वामपंथी गरीबों के हितैषी बन कर पूंजीवाद को फायदा पहुचाने लगे। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार, अंबेडकर के नाम पर अलग विचारधारा, कबीर पंथ एवं ऐसे ही अनेक पंथ के जरिये सनातन को कमजोर करने की साजिशें बढ़ने लगीं।

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व उस समय स्वयं सत्ता में रहने के लिए वामपंथी विचारधारा को समर्थन देता रहा। नेहरू ने परिवारवाद को आगे बढ़ाने के क्रम में लाल बहादुर शास्त्री के स्थान पर इन्दिरा गांधी को अपना उत्तराधिकारी चुना। 1967 तक कांग्रेस ने जब तक अपने दम पर सरकारें बनाई तब तक वामपंथी उनसे दूर दूर दिखे किन्तु जैसे ही 1969 में इन्दिरा कांग्रेस विभाजित होकर अलग हुयी तब इन्दिरा गांधी को वामपंथियों का प्रत्यक्ष सहयोग लेना पड़ गया। तब मुस्लिम वर्ग को कांग्रेस के खेल समझ में आने लगे। जो मुस्लिम वर्ग परंपरागत रूप से कांग्रेस का मतदाता था उसने अन्य विकल्प तलाशने शुरू कर दिये। इसके बाद अल्पसंख्यकों को बताया जाने लगा कि तुम्हारे और हिन्दुओं के हितों में अंतर है। जिन्ना के दौर की रूढ़िवादी सोच को मुस्लिम समाज में भरा जाने लगा। इसको समझने के लिए सच्चर कमिटी की रिपोर्ट को समझना पर्याप्त है। एक तरफ मुसलमानों के अंदर असुरक्षा और दूसरी तरह हिन्दुओं में जातिगत विभाजन वामपंथी विचारधारा का भारत को सबसे बड़ा योगदान है। कांग्रेस ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बौद्धिक वामपंथियों को खूब छात्रवृत्ति दीं। विदेश यात्राएं करवाईं। तत्कालीन सोवियत संघ को भारत में जिंदा रखा। इसके बदले सोवियत संघ से अच्छी ख़ासी धनराशि भारत के वामपंथियों को लगातार मिलती रही। कांग्रेस और वामपंथी राजनीतिक रूप से तो आपस में विरोधी दिखे किन्तु वैचारिक रूप से एक दूसरे के पूरक ही रहे।

-अमित त्यागी
(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं।)

सरकार द्वारा जिस तरह से कुछ त्वरित विकास कार्य हुये हैं उसे लोगों ने सराहा है। मोदी की सक्रियता और योगी की दृढ़ इच्छाशक्ति उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह माफिया, गुंडे, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही हुयी है उससे लोगों में एक आशा का भाव जाग गया दिखता है। गुंडा प्रवृत्ति के लोगों पर ऐसी कार्यवाही पहले किसी प्रदेश में इस तीव्र गति से हुयी हो

ऐसा कहीं नहीं दिखता है। अब इसी उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, एआईएमआईएम और कांग्रेस चुनाव मैदान में हैं। खास बात यह है कि यह चारों दल बहुसंख्यक हिन्दू वोट बैंक से ज़्यादा मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट बैंक पर ध्यान दे रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं जैसे राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर, राशिद अलवी द्वारा मुस्लिम वोट बैंक पर नजर के कारण ही हिन्दुत्व विरोधी बयान आते रहते हैं। दूर से देखने पर यह कांग्रेस का भटकाव दिखता है जबकि ऐसा नहीं है। चूंकि, कांग्रेस के पास अब सिर्फ एक मात्र सहारा मुस्लिम वोट बैंक बचा है और वह भी उसके हाथ से क्षेत्रीय दलों द्वारा खिसक रहा है इसलिए उसके आगे ऐसा करना एक मजबूरी है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के ऐसे बयान ही मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पूंजी हैं। मुस्लिम वोट बैंक के कारण जब ओमप्रकाश राजभर को लगा कि मुस्लिम ओवेसि के साथ जा सकता है तो वह उसके साथ हो लिए। बाद में चुनावी मौसम को पहचानने के बाद जब लगा कि मुस्लिम सपा के साथ है तो वह उधर हो लिए। अल्पसंख्यक वोटों को अपनी तरफ मोड़ने के क्रम में एक और कांग्रेस हिन्दुत्व पर चोट कर वोट चाह रही है तो दूसरी तरह सपा और राजभर जिन्ना को पटेल-गांधी के समकक्ष खड़ा करके मुसलमानों को खुश करना चाह रहे हैं। इन सबसे आहत हिन्दू वोट बैंक स्वत- भाजपा का वोट बैंक बन जाता है।

इस तरह कांग्रेस से न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिन्दू भी खिसक रहा है। केरल में हुये विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मुस्लिम वोट न के बराबर मिला। केरल एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस को सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है। अब यदि कांग्रेस का वही हाल उत्तर प्रदेश में भी होता है तो कांग्रेस के लिए अपनी मौजूदा सात सीटें बचाना भी आसान नहीं होगा। अब ऐसा तो कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी। यही वजह है कि कांग्रेस के बड़े नेता हिन्दुत्व के विरोधी बयानों की ओवर एक्टिंग ज़्यादा करते दिखते हैं। चूंकि, हिन्दू वोट बैंक अब लगभग एकजुट सा दिखने लगा है इसलिए भाजपा के अतिरिक्त सभी दल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाएं हैं। सलमान खुर्शीद द्वारा तो हिन्दुत्व की तुलना बोको हरम एवं आईएस से की जाती है। यह वही सलमान खुर्शीद हैं जो 2001 में वाजपेयी सरकार द्वारा सिमी पर बैन लगाने के बाद उनके उच्चतम न्यायालय में वकील थे। उस समय वह तत्कालीन कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भी थे। सिमी एक ऐसा संगठन था जिसने खुलेआम घोषणा कर रखी थी कि वह हथियारों के बल पर भारत में इस्लाम का शासन स्थापित करेगा। सीएए और एनआरसी की चर्चा के बीच वहां के डीजीपी ने केरल उच्च न्यायालय में कहा था कि सिमी के लोगों ने ही पीएफआई बनाया था। यह वही पीएफआई है जो सीएए के आंदोलन को फंड कर रहा था। अब यदि चुनावी झुकाव की बात करें तो सीएए के बाद मुस्लिम एक मुश्त होकर वोट कर रहा है। बंगाल में उसका झुकाव तृणमूल कांग्रेस की तरफ हुआ। केरल में माकपा के पक्ष में वोट हुआ। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो बंगाल चुनाव के बाद स्पष्ट कहा कि माकपा के वोटों का ध्रुवीकरण तृणमूल कांग्रेस की तरफ हुआ है।

पसमांदा आंदोलन से बदलता मुस्लिम विमर्श

मुस्लिम विमर्श में कुछ भ्रामक धारणाएं हैं। पहली यह है कि मुस्लिम एक समरूप समाज है। दूसरी यह है कि मुस्लिम समाज में जाति संरचनाएं और ऊंचनीच का विभेद नहीं होता है। तीसरी यह कि इस्लाम में असमानता या उत्पीड़न नहीं है। चौथी सबसे अहम धारणा यह है कि मुस्लिम एकजुट होकर वोट करते हैं। पसमांदा आंदोलन इन सभी धारणा को ध्वस्त करता हुआ स्पष्टीकरण देता है। स्वतन्त्रता पूर्व हिन्दू समाज के दलित और पिछड़े वर्ग से बड़े पैमाने पर मतांतरण करवाए गये। इन मतांतरण के लिए हिन्दू धर्म की कुरीतियां ही जिम्मेदार थीं। इस दौरान काफी लोग मुस्लिम बनें। पसमांदा आंदोलन ऐसे ही लोगों का सशक्त आंदोलन है। यह मुस्लिम विमर्श की कई मान्यताओं को चुनौती देता है। इसकी शुरुआत स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धान्त के विरोध करने वाले अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा मोमिन कॉन्फ्रेंस बनाकर की गयी थी। अंसारी 1946 में पसमांदा समाज से आने वाले पहले मंत्री भी बने। वर्तमान में पसमांदा समाज की उत्तर प्रदेश इकाई का कहना है कि तथाकथित सेकुलर दलों ने मुस्लिम समाज को खूब ठगा है। मुस्लिम समाज का लगभग 80 प्रतिशत पसमांदा मुस्लिम है। लेकिन मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम समाज के नाम पर जो विमर्श चलाया है वह उच्चवर्गीय मुस्लिमों या यूं कहें कि अशरफ मुस्लिमों का विमर्श है। यह लोग आरएसएस का भूत दिखाकर मुस्लिमों को ठगने का काम करते हैं। ये लोग जमीन पर काम नहीं करते हैं। 2012 में सरकार बनने के पहले सपा ने सच्चर कमिटी की रिपोर्ट को खूब जोर शोर से उठाया था किन्तु सत्ता में आने के बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया।

2007 में मौलाना आलम फलाही ने अपनी किताब 'हिंदुस्तान में जांत पांत और मुसलमान' में लिखा कि 'मुस्लिम समाज में समानता एक मिथक है'। भारत में दो तरह के मुसलमान हैं। एक वे हैं जो अरब, तुर्की या ईरान मूल के हैं। इन्हे अशराफ या शरीफ मुसलमान कहा जाता है।

भारत को सीरिया बनने नहीं देना है मोदी जी

इस्लामिक हिंसा और तुष्टीकरण के खिलाफ देश की जनता ने मिस्टर मोदी आप को चुना है। दलित और मुस्लिम पॉकेट का ईगो मसाज करने के लिए नहीं। आलू, प्याज का भाव जनता देख लेगी। सरकार का काम है कड़े फैसले ले कर देश का भूगोल और पर्यावरण ठीक करने का। जनसंख्या नियंत्रण और घुसपैठियों की समस्या हल हो गई तो बेरोजगारी और मंहगाई की समस्या चुटकी बजाते ही हल हो जाएगी। तो मिस्टर मोदी इन हिंसक और कायर लोगों से डरना, घुटना टेकना बंद कीजिए। पूरी सख्ती से इन फैसलों पर अमल करने का यही बेहतर समय है। सिविल पुलिस की जगह अर्ध सैनिक बलों को तैनात कर हिंसक लोगों को उन की औकात में रखिए। कभी यह बयान, कभी वह बयान दे कर दो कदम आगे, चार कदम पीछे चलने की डिप्लोमेसी से बाज आइए। संसद में अगर छाती ठोंक कर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम एन आर सी लाएंगे! तो इसे पूरे देश ने सुना है। यह सही फैसला है। इस पर दृढ़ता से कायम रहने की जरूरत है। बयान बहादुरी कर इस से पलटना भाजपा के लिए तो शोकगीत का सबब होगा ही, समूचे देश को सीरिया बनाने की राह पर भी ढकेल देना होगा। नाकारा, हिंसक और नपुंसक विपक्ष की फालतू के घेराव में फंसना और फैसला पलटना गुड बात नहीं है। क्यों कि अभी नहीं, तो कभी नहीं। मोदी सरकार को इस बाबत चीन से सबक सीखने की सख्त जरूरत है। जैसे चीन इस समय 30 लाख उइगर मुसलमानों को नजरबंद कर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। भारत को भी उसी सख्ती से घुसपैठियों को पूरी सख्ती से देश से बाहर खदेड़ देने की जरूरत है। इन के साथ किसी भी तरह की उदारता बरतने की कोई जरूरत नहीं है। चीन की ही एक पुरानी कहावत है कि इतने उदार भी न बनिए कि अपनी बीवी किसी को गिफ्ट कर दीजिए। इसी तर्ज पर मुझे यह कहने की अनुमति दीजिए कि अपनी उदारता और सदाशयता में यह भारत देश घुसपैठियों को गिफ्ट मत कीजिए। यह देश की अस्मिता, स्वाभिमान और सुरक्षा का विषय है। इस पर किसी भी तरह का कोई समझौता देश को घुसपैठियों के हाथ बेच देना है।

एन पी आर और एन आर सी से डरने और बहस करने वाले कौन लोग थे भला ? जाहिर है यह घुसपैठिए हैं या उन के पैरोकार हैं। मुस्लिम वोट के दुकानदार हैं। मोदी सरकार अगर देश की हिफाजत और भविष्य बेहतर चाहती है तो सरकार गंवा कर भी उसे एन पी आर, एन आर सी, जनसंख्या नियंत्रण और कॉमन सिविल कोड को पूरी सख्ती से लागू करना चाहिए। हिंदू, मुसलमान का भेदभाव किए बिना ही घुसपैठियों को पूरी ताकत से किसी भी कीमत पर देश से बाहर खदेड़ना बहुत जरूरी है। नहीं अभी पूरी दुनिया पर कभी राज करने वाला ब्रिटेन जैसे इस समय अपना अस्तित्व बचाने के लिए लचर और लाचार हो चुका है, सोवियत संघ टूट चुका है। भारत भी उसी राह पर जाने के लिए अभिशप्त हो चुका है। जैसे 370 से मुक्ति भाजपा और मोदी सरकार ही दिला सकती थी, इस अभिशाप से, घुसपैठियों से मोदी और भाजपा सरकार ही मुक्ति दिलवा सकती है। बिना इमरजेंसी लगाए, हर उस लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल कर मोदी सरकार को घुटने टेकने के बजाय कड़ा मुकाबला करना चाहिए। इस नपुंसक और हिंसक विपक्ष के सामने मोदी सरकार को घुटने टेकने से बचना चाहिए। अगर विपक्ष शासित प्रदेश सरकारें असहयोग करती हैं तो उन्हें उन के हाल पर छोड़ भाजपा शासित प्रदेशों में पूरी सख्ती से लागू करना चाहिए। नहीं भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी को देश कभी माफ नहीं करेगा। देश की जनता ने अगर 303 सीटें दे कर इतने भारी बहुमत से सरकार में भेजा है तो हिंसक और नपुंसक विपक्ष और घुसपैठियों के आगे डर कर घुटने टेकने के लिए नहीं भेजा है। भेजा है भारत को सीरिया बनने से रोकने के लिए।

-दयानन्द पांडे

दूसरे वे देसी मुसलमान जो यहां से ही धर्म परिवर्तन करके बने हैं। तमाम अशराफ शेष पसमांदा मुस्लिमों को अपना गुलाम मानते हैं। नस्लवाद के कारण मुस्लिम समाज में जातीयता भी बरकरार है। इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी दलित और ओबीसी मुस्लिमों में हिन्दू धर्म की जातीय संरचनाएं कम नहीं हुयी हैं। सिर्फ भारत में ऐसा हो ऐसा भी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पाकिस्तान में भी यही हालात हैं। वहां एक मुस्लिम लोहार को इसलिए 80 गोलियां मार दी गईं क्योंकि उसने अपने से ऊंची जाति की मुस्लिम लड़की से निकाह कर लिया था। पसमांदा लोग कबीरदास को अपना मसीहा मानते हैं। कबीरदास ने मुस्लिम समाज में व्याप्त जातिवाद और ऊंच नीच के खिलाफ आवाज उठाई थी और उलेमा का विरोध किया था। उनकी आवाज दबाने के लिए अशरफ उलमा ने 'कुफ्र का फतवा' जारी किया था। इसके साथ ही पसमांदा मुस्लिमों का यह भी आरोप है कि कांग्रेस के मौलाना आजाद ने स्वतन्त्रता के बाद सभी अशरफों को गोल टोपी पहनाकर शासन और प्रशासन में घुसा दिया। इस कारण से पसमांदा मुसलमान लगातार पिछड़ता चला गया। पसमांदा मुसलमानो के अनुसार मदरसे

परिवारवाद और सामंतवाद के स्तम्भ हैं जिन पर यूजीसी जैसी संस्था बनाकर नियंत्रण करना चाहिए।

सेकुलर देश में धार्मिक अल्पसंख्यक क्यों?

पसमांदा मुसलमानों के अनुसार सेकुलर देश में धार्मिक अल्पसंख्यक का कोई महत्व नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। भारत में मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान और अन्य देशों से ज़्यादा है इसलिए मुस्लिम यहां अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं। अशराफ मुसलमान, मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड का सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं जबकि वे धोबी, नट, बकसू, हलालखोर, जैसे अनेकों पसमांदा मुस्लिमों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। यह अशराफ मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय हेतु आवाज नहीं उठाते हैं जबकि हिन्दू समाज के लिए यह लोग बेहद चिंतित रहते हैं। इस तरह से देखा जाये तो पसमांदा आंदोलन राष्ट्रवादी सोच वाले मुसलमानों का आंदोलन है। पसमांदा की रगों में हिन्दू समाज का खून दौड़ता है। अभी तक की विडम्बना यह रही है कि अशराफ मुसलमानों ने पसमांदा लोगों के हकों से ज़्यादा अपनी सुरक्षा का ध्यान दिया। अपने हित देखें। इसी कारण अब मुस्लिम विमर्श बदल रहा है। पसमांदा लोगों के लिए जिन्ना नायक नहीं हैं। उनकी यही सोच अब भारतीय राजनीति में गंभीर परिवर्तन लाने जा रही है। इसके साथ ही मुसलमानों में धर्म परिवर्तन की लहर भी देखी जा रही है। अभी कुछ समय पहले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने हिन्दू धर्म अपना लिया। इन्डोनेशिया के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति की पुत्री सुकमावती सुकर्णोपुत्री ने भी इस्लाम छोडकर सनातन धर्म ग्रहण किया है। भारत में भी लाखों ऐसे मुस्लिम हैं जो हिन्दू धर्म में वापसी के लिए तैयार बैठे हैं।

मुस्लिम देशों में इस्लाम छोड़ने, उस पर विश्वास न रखने वाले और इस्लामी मान्यताओं को ठुकराने वाले मुसलमानों की संख्या काफी ज़्यादा बढ़ रही है। सुकर्णोपुत्री जैसे बड़े नाम के द्वारा इस्लाम छोड़ने पर उन्हे कोई भी कट्टरपंथी धमकी न मिलना एक बड़ा संदेश दे रहा है। कुछ समय पहले कनाडियन अफ्रीकी मौलवी बिलाल फिलिप्स ने 'इस्लाम छोडने की सुनामी' आने की आशंका जताई थी। हार्वर्ड से पढे अरब देशों के विशेषज्ञ डॉ डेनियल पाइप्स के अनुसार मुस्लिम जगत में अपने धर्म से अलग होना 'जंगल की आग' की तरह फैल रहा है। इस्लाम छोडने वाले गर्व से इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। तुर्की मूल की लाले गुल ने एक किताब लिखकर बाकायदा इसकी घोषणा की। इस किताब का नाम है 'मैं जीना चाहती हूं'। यह पुस्तक तुर्की में बहुत ज़्यादा बिक रही है। तुर्की में नास्तिकता लगातार बढ़ती चली जा रही है। सऊदी अरब में इस्लाम छोड़ने वाले बढ़ रहे हैं। ईरान में मतांतरण हो रहा है। मिस्त्र में कठोर इस्लामी कायदे छोड़े जा रहे हैं। यह सब कोई करवा नहीं रहा है बल्कि यह स्वत: हो रहा है। इसका अर्थ साफ है कि मुसलमान स्वयं अपनी नियति तय करने की ओर बढ़ चुके हैं। वह मुल्ला मौलवियों की सब कुछ तय करने की प्रथाएं तोड़ रहे हैं। मिस्त्र में तो उग्रवादी इस्लामी संगठनों को नीची नजरों से देखा जाना शुरू हो चुका है। यहां तक की कभी कभी सड़कों पर उनकी पिटाई भी हो जाती है। स्त्रियां अपने हिजाब फेंक कर अपना विरोध जता रही हैं। तुर्की में गैर इस्लामी तौर तरीके बेहद लोकप्रिय होते जा रहे हैं। विन – गैलप नामक एक संस्था के सर्वेक्षण में 73 प्रतिशत तुर्की लोगों ने स्वयं को गैर इस्लामिक बताया है। किसी मुस्लिम देश में इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों का गैर मजहबी होना एक बड़ा विषय है। सऊदी अरब में नास्तिकता रोकने के लिए सरकार आतंकवाद विरोधी कानून का प्रयोग कर रही है। यह उद्धारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तर पर एक नयी रूपरेखा का संदेश दे रहे हैं।

इसके साथ ही ईरान में इसाइयत का प्रभाव बढ़ रहा है। वहां के मुसलमान सिर्फ मजहब नहीं बल्कि परिवार, सामाजिक संबंध, राजनीति आदि में इस्लामवादियों से विपरीत रुख ले रहे हैं। इसी प्रकार इस्लाम छोडने वाले लोग यूरोप और अमेरिका में भी हैं। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल से बहुत से मुस्लिम देशों के संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। एक आंकलन के अनुसार अमेरिका सालाना एक लाख लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। फ्रांस में सालाना 15 लाख लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह संख्या हालांकि बेहद कम है किन्तु यह एक रुझान तो दिखा ही रहा है। पर इन सबसे महत्वपूर्ण अरब देशों के रुझान है जो पूरे विश्व को प्रभावित करते रहे हैं। एक खास किस्म की वेषभूषा, खान पान, वहाबीवाद, अलकायदा, इस्लामी एस्टेट जैसे प्रमुख आंदोलन अरब से ही दुनिया के अन्य देशों में फैले हैं। अब ऐसा आंकलन किया जा रहा है कि इस्लाम की उदासीनता और इस्लाम छोडने की हवा नाइजीरिया, बांग्लादेश और मलेशिया में फैल सकती है। इन सबका प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर भी पड़ेगा। पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि भारत का मुसलमान बौद्धिक स्तर पर अग्रणी है। भारत के अंदर मुसलमानो का एक बड़ा वर्ग अपना डीएनए भारतीय होने की बात मानता है। ज़्यादातर दबी जुबान से यह मानने लगे हैं कि हमारे पूर्वज हिन्दू थे। अब वह वापस हिन्दू धर्म में वापस लौटते हैं या नहीं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस तथ्य को स्वीकार करना है। ऐसा करने से भारतीय मुसलमान इस्लाम और इस्लामी लुटेरों के अंतर को समझ पाएगा। वह महमूद गजनवी और औरंगजेब के कृत्यों को न्यायोचित तो नहीं ठहराएगा। और यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जिसमे धर्म कोई भी हो किन्तु भारत की संस्कृति और मूल भावना को सभी के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। ■

काशी का गौरवशाली इतिहास

प्रो. राकेश उपाध्याय

बाबा विश्वनाथ के नवीन प्रांगण को देखकर फारसी भाषा में लिखे गए कुल्लियात-ए-बरहमन नामक औरंगजेब कालीन दस्तावेज में दर्ज एक बूढ़े ब्राह्मण से जुड़ी घटना फिर से कागजों से बाहर झांकने लगी है। संभवत: इसका प्रामाणिक उल्लेख काशी का इतिहास नामक ग्रंथ में अथवा कुबेर शुकुल द्वारा लिखित वाराणसी इतिहास-वैभव में मिलता है।

कथा के अनुसार, ईस्वी सन् 1669 में अप्रैल महीने की 18 तारीक को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को जमींदोज करने का फरमान जारी किया। इसके पहले अविमुक्तेश्वर काशीविश्वनाथ मंदिर तोड़ने की शुरूआत मुहम्मद गोरी ने की थी। ई. सन् 1194 में पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुहम्मद गोरी के आदेश पर विश्वनाथ जी के मंदिर समेत एक हजार से ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त करते हुए पूरे उत्तर भारत को बरबाद कर रख दिया। लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। यही समय था कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद आपसी कटुता में खुद के साथ देश की राजनीति का सारा दांव मुस्लिम हमलावरों के सामने हार चुके थे। इस्लाम की खूनी तलवार ई. सन 1002-1024 के दरम्यान सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से कई बार लूटमारकर ध्वस्त कर चुकी थी। सौराष्ट्र, गुजरात में यह खूनी खेल पूरा कर चुकने के करीब 170 साल बाद गंगा के मैदान में चारों ओर रक्त ही रक्त फैल गया था। जिंदा रहने की एक आस बची, और कुछ भी तो नहीं बचा।

फिर तो आने वाली हर सदी में मानो एक खेल हो गया। गणराज्य बार बार इस्लाम की खूनी तलवार से भिड़ते रहे। कटते रहे, लड़ते रहे लेकिन गिरकर भी फिर फिर उठने की जिजीविषा खत्म नहीं हुई। यही कारण है कि

काशी में विश्वनाथ जी मौका देखते ही फिर से मौके पर अपनी जगह बना लेते थे, टूटने और बनने का सिलसिला हर सदी और दशक में चलने लगा। दिल्ली और आगरे में इंतजामों से इस्लाम की सियासी तलवार को जब भी फुरसत मिलती, वह फिर से विश्वनाथ मंदिर समेत हर मंदिर को जमींदोज करने में कसर नहीं छोड़ते। कुतुबुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान, फिर खिलजी, उसके बाद फिरोज तुगलक (1351-1388), उसके बाद शरकी बादशाहों ने, फिर सिकन्दर लोदी (ई.1494) आदि ने वाराणसी समेत उत्तर भारत को तहस-नहस कर सारे बड़े केंद्रों को बरबाद कर डाला।

वो बार-बार तोड़ते जाते थे लेकिन हार न मानने वाला समाज और उसका नेतृत्व हर बार मौका देखते ही विश्वनाथ मंदिर को मिट्टी से उठाकर फिर से उसका ध्वज आसमान तक तान देते थे। अस्तित्व बचाने के इस विकट संघर्ष में अकबर का समय ही अपवाद था। अकबर के समय ईस्वी सन 1580-85 के आस-पास राजा मान सिंह और राजा टोडरमल ने विश्वनाथ मंदिर का भव्यतम मंदिर शिखर फिर से वहीं पर खड़ा कर दिया, जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद है। मस्जिद के पीछे के मंदिर के खंडहर मानसिंह और टोडरमल के बनाए मंदिर के प्राचीन अवशेष हैं। लेकिन यह शिखर भी लंबे समय तक मुस्लिम सूबेदारों को सहन नहीं हुआ। औरगंजेब के समय 18 अप्रैल 1669 ई. सन में मुगलिया स्टेट यानी सरकार के द्वारा दिया गया ये छठवां आदेश था कि विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिया जाए।

और सूबेदार ने बेहद तेजी दिखाते हुए ध्वस्तीकरण का सारा काम फरमान के मुताबिक पूरा कर दिया। हजारों निरपराध हिन्दुओं का कत्लेआम करते हुए सूबेदार ने माधवराव का धौरहरा, काशी विश्वनाथ समेत बिन्दु माधव का धौरहरा और हरतीरथ में एक अन्य भव्य मंदिर तोड़कर आलमगीर के नाम से तीन-तीन मस्जिदों का निर्माण पूरा कर दिया। इस काम की पूरी विस्तृत खबर सूबेदार ने जहांपनाह की खिदमत में लिखकर भेज दी। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को दरबार में पूरी सूचना मिली कि सरकार के आदेशानुसार, उसके अमलों ने विश्वनाथ मंदिर समेत पूरा शहर ही नेस्तनाबूद कर दिया है।

खबर सुनकर औरंगजेब खुशी से फूला न समाया। उस समय औरंगजेब के दरबार में एक बूढ़े 80-90 साल के ब्राह्मण जिनका असल नाम चंद्रभानु था और उन्हें जहांगीर, शाहजहां के समय से दरबार में फारसी शेरो शायरी और साहित्य आदि के सिलसिले में रखा गया था। औरंगजेब के समय भी वह दरबार में फारसी खतो-किताबत में जुटे रहते थे किन्तु धरम के पक्के थे। 90 साल की उम्र थी, मौत का कोई भय भी नहीं था। दरबार के कितने ही हाकिम उन्हें मुसलमान बना पाने में नाकाम थे, इसीलिए औरंगजेब हमेशा उन्हें चिढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ व्यंग्य बोलता था।

काशी विश्वनाथ की जगह मस्जिद तामीर की खबर पाते ही इन्हीं बरहमन से औरंगजेब ने उछलते हुए पूछा-'अरे बरहमन, तुम्हारे काशी विश्वनाथ की जगह अब मस्जिदे आलमगीर बन चुकी है। अपने विश्वनाथ के बारे में अब तुम्हारा क्या ख्याल है?' उस बूढ़े ब्राह्मण ने बेधड़क उत्तर दिया-'जहांपनाह शेर हाजिर है, आपका हुक्म हो तो अर्ज कर दूं।' औरंगजेब का हुक्म मिलते ही बरहमन फारसी भाषा में ही भरे दरबार में गरज उठे-

बेबीन करामातेबुतखान-ए-मरा ऐ शेख,
कि चूं खराबशवद खान-ए-खुदा गरदद।
(कुल्लियात-ए-बरहमन से उद्धृत) अर्थात, ऐ शेख, हमारे विश्वनाथ का यह कौतुक तो देखिए कि उनके हट जाने पर ही आपके खुदा की वहां तक पहुंच हो पाई। जहांपनाह ये समझ लें कि उस जमीन पर विश्वनाथ के मौजूद रहते पहुंचने की हिम्मत खुदा में है ही नहीं।

बरहमन की बात सुनते ही औरगंजेब गुस्से में दांत पीसने लगा। उसके कारिंदे बरहमन को घूरने लगे। कितनों की मुट्ठियां म्यान के हत्थे से टकरा उठीं कि अब नहीं तब बादशाह का आदेश हो।

बरहमन को लेकिन मौत का भय नहीं था। बोलते रहे कि-एक दिन आएगा और देख लीजिएगा कि विश्वनाथ फिर से अपनी जगह आ विराजेंगे और आपके खुदा उनकी ओर देखकर शरम से मुंह चुराते घूमेंगे। और जो तोड़ना है तो तोड़ते रहिए। मुझ बूढ़े को चिढ़ाना बंद कर दीजिए। क्योंकि आपके बापजान शाहजहां साहेब भी अक्सर मुझे ऐसे ही चिढ़ाते थे, लेकिन उनका क्या हुआ? आपसे बेहतर कौन जानता है। तब भी मैंने उनसे कहा था - मरा दिलेस्त बकुफ्रआश्ना कि सदबारश, बकाबा बर्दम व बाजश बरहमन आबुर्दम।। (कुल्लियात-ए-बरहमन)

यानि कि मेरा दिल मेरे हिन्दू धर्म में इतना डूबा हुआ है कि यदि सौ बार काबा जाऊं तो भी वहां से ब्राह्मण रहकर ही लौटूंगा। मुझे मुसलमान बनाकर काबा भेजने की कोशिश मत करिए। काबा जाऊंगा तो भी जाने कब लौटकर विश्वनाथ की शरण में ही चला जाऊंगा।

फिर क्या था। औरंगजेब दांत पीसता हुआ भरे दरबार से उठकर चला गया। चाहता तो एक

90 साल के बूढ़े बरहमन की गर्दन धड़ से उड़वा सकता था लेकिन संभवत: उसे अहसास हो गया था कि तलवार की धारों और अत्याचारों से यह धर्म झुकने वाला नहीं। जिस विश्वनाथ को मानने वाले ऐसे निडर आस्था से भरे लोग हैं तो फिर इस सनातन हिन्दू धर्म और इनके भगवान विश्वनाथ को तलवार की धार से मिटा पाना किसी भी भांति संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलश में गंगाजल भरकर भगवान विश्वनाथ के भव्य प्रांगण की ओर बढ़ते सबने देखा। सबका मनआंगन आनन्द से भर उठा।

गर्भगृह में पंडितों ने उन्हें इस महानतम ऐतिहासिक कार्य के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने भी विनत भाव से बाबा भोलेनाथ की ओर संकेत कर दिया। सब यही विश्वनाथ जी कर और करवा रहे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है।

प्रधानमंत्री जी का यह विचार सुनते ही मुझे महाभारत का एक बहुत ही महत्व का आख्यान याद आ गया। यह आख्यान भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ से ही जुड़ा बताया जाता है। द्रोण पर्व में इसका वर्णन आता है।

दरअसल, द्रोणाचार्य के मारे जाने के बाद आगबबूला द्रोणपुत्र महारथी अश्वत्थामा आपे में नहीं रहे। वह पाण्डवों की सेना पर वज्र बनकर बरस पड़े। उन्होंने ऐसे दिव्य आग्नेय अस्त्र अर्जुन और उनकी सेना पर फेंके जो कि अकाट्य थे, और किसी का भी जान बचा पाना मुश्किल था। अर्जुन ने किसी तरह से उस हमले में अपनी और सेना के प्रमुख योद्धाओं की जान बचाई।

रात में अर्जुन जब अगले दिन के युद्ध की योजना बना रहे थे तो उन्हें बार बार दिन के युद्ध की स्मृति हो आती। वह हैरान व परेशान थे कि आखिर उनकी जान कैसे बच गई क्योंकि हमला भयानक और खतरनाक था। वह सोच में पड़े थे कि तभी महर्षि वेदव्यास मिलने आ पहुंचे। अर्जुन ने तब अश्वत्थामा के शस्त्र प्रयोग के बारे में महर्षि को जानकारी देते हुए एक आश्चर्यजनक अनुभव साझा किया।

अर्जुन ने भगवान वेदव्यास को बताया कि –गुरुदेव जब मैं युद्धभूमि में चारों ओर से घिर गया था तब मैंने देखा कि एक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष मेरे आगे आगे हाथ में जलता हुआ त्रिशूल लेकर चल रहा है।

अर्जुन जैसे कोई स्वप्न सुना रहा था कि मैं जिस दिशा में कौरवों को रोकने बढ़ता कि वह ज्योतिर्मय पुरुष पहले ही मैदान साफ कर देता था। उसके पैर पृथ्वी पर नहीं थे, उसका त्रिशूल उनसे कभी अलग नहीं होता था, उनके एक त्रिशूल से हजारों त्रिशूल निकलकर शत्रू सेना पर कहर ढा रहे थे।

हे व्यासजी सच कहता हूं कि लोगों को लग रहा था कि मैं शत्रुओं को मार रहा हूं लेकिन असल में तो मैं अवाक् होकर उस ज्योतिर्मय सूर्य से भी ज्यादा प्रखर उस पुरुष को ही देख

रहा था, मैं तो केवल उनके पीछे पीछे चल रहा था, वह आगे आगे चलकर मेरे सारे शत्रुओं का सर्वनाश कर रहे थे। उन्होंने ही मुझे अश्वत्थामा के शस्त्रों से बचा लिया। वह कौन थे, मैं नहीं जान सका।

हे भगवान व्यास जी, मुझे बताइए कि आखिर वह महापुरुष कौन थे? कहां से आए थे, क्यों आए थे? जैसे मेरे धनुष और बाणों की दिशा वही तय कर रहे थे, अरे वही तो सब कर रहे थे, वो कौन थे।

अर्जुन ने जो कहा, उसे व्यासमुनि ने द्रोण पर्व में ज्यों का त्यों दर्ज किया था।

अग्रतो लक्षये यान्तं पुरुषं पावकप्रभम्।...ज्वलन्तं शूलमुद्यम्य यां दिशं प्रतिपद्यते। तस्यां दिशि विदीर्यन्ते शत्रवो मे महामुने।..

अर्थात..मेरे आगे आगे वह अग्नि जैसे विराट पुरुष चल रहे थे...जिनका जलता त्रिशूल जिधर जाता, उधर ही शत्रूसेना साफ हो जाती थी...

को वै स पुरुषोत्तमः। शूलपाणिर्मया दृष्टस्तेजसा सूर्यसंनिभः। न पदभ्यां स्पृशते भूमिं न च शूलं विमुक्तिं...।।

आखिर वह महापुरुष कौन थे। हे व्यासजी, मैंने उस अग्निमय महापुरुष के हाथ में में जलता त्रिशूल देखा था, उनके पैर भूमि पर नहीं थे, त्रिशूल से हजारों त्रिशूल निकलकर शत्रुओं को समाप्त कर रहे थे...वह मेरे आगे थे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, सब कुछ वही कर रहे थे, आखिर वो कौन थे।

भगवान वेदव्यास ने बड़े भाव से हैरान हुए अर्जुन को देखा, मन ही मन बुदबुदाने लगे, अरे तुमने नहीं पहचाना, वही तो विश्वनाथ थे। कुछ देर तक अर्जुन की आंखों में झांककर फिर व्यासजी बोलने लगे कि अर्जुन, रणभूमि में जो तुम्हारे आगे आगे चलकर शत्रुओं का नाश कर रहे थे, वह साक्षात हर हर महादेव थे...। वह वही विश्वेश्वर महादेव थे...। वह साक्षात वही शंकर थे जो श्मशानभूमि काशीपुरी में निवास करते हैं...।

महादेवं हरं स्थाणु वरदं...। विश्वेश्वरम् विश्वनरं कर्मणामीश्वरं प्रभुम...। स महादेवः पूज्यमानो महेश्वरः...। दृष्टवानसि शंकरम्..।..एष चैव श्मशानेषु देवो वसति नित्यशः।।

हरहर महादेव हैं वो, विश्वेश्वर विश्वनाथ, सब कर्मों के ईश्वर मेरे प्रभु वही महादेव, सब देवों के देव, पूज्य वही महेश्वर जिन्हें यह संसार शंकर के नाम से देखता और जानता है, वही जो काशीपुरी के महाश्मशान में निवास करते हैं।...अर्जुन समझ लो कि कौन तुम्हारे साथ युद्धभूमि में खड़ा था।

भगवान वेदव्यास ने अर्जुन को बताया कि तुम्हारी विजय के लिए भोलेनाथ साक्षात रणभूमि में उतर पड़े हैं। इस संग्राम में जो तुम्हारे सामने शत्रुओं का कोई वश नहीं चल पा रहा है तो ये पिनाकधारी भगवान महादेव ही तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं।

एष देवो महादेवो योऽसौ पार्थ तवाग्रतः।

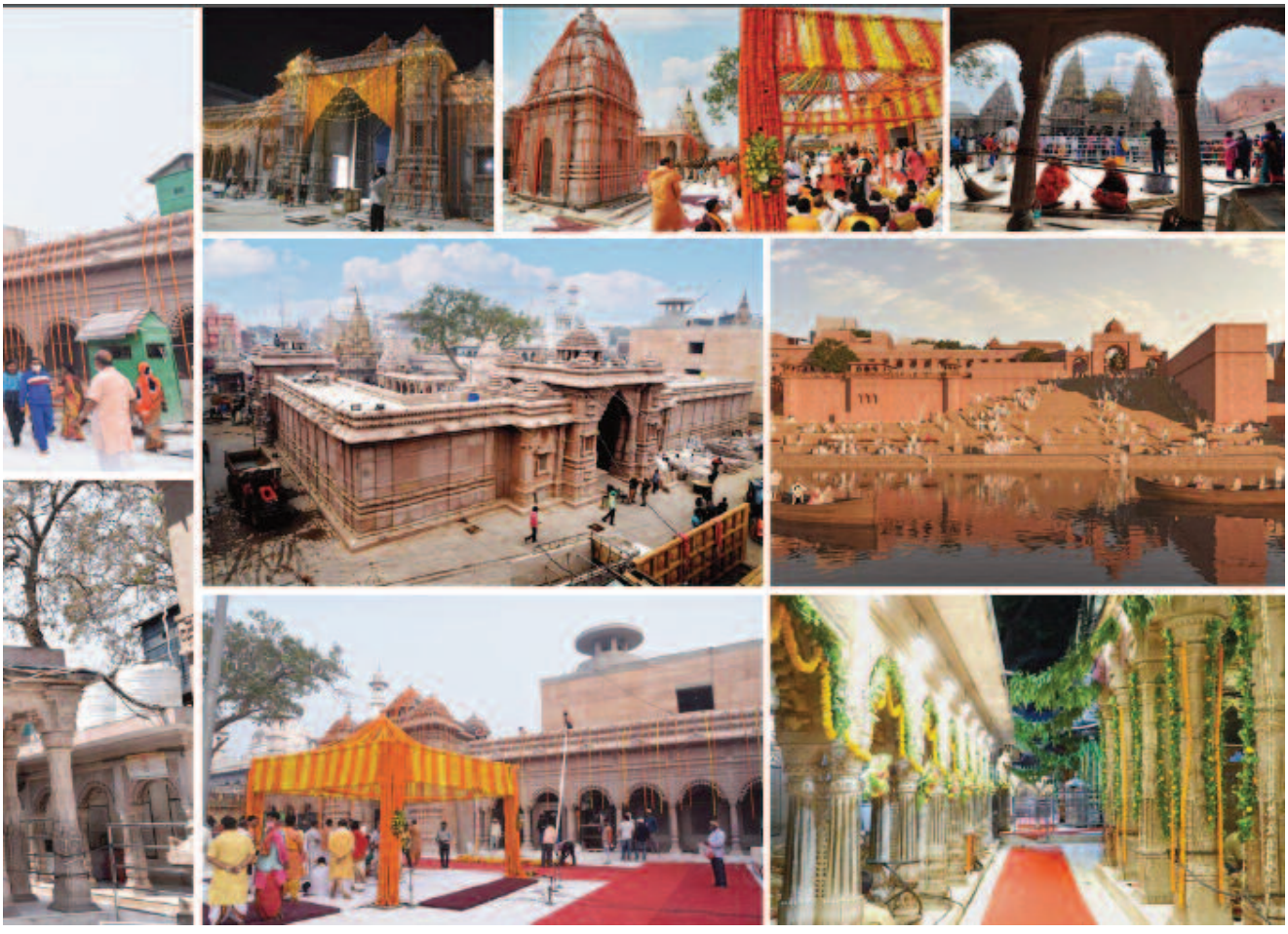

संग्रामे शात्रवान् निघ्नंस्त्वया दृष्ट: पिनाकधृक।

अरे, वह महादेव तेरे आगे आगे चल रहे हैं अर्जुन। वही पिनाक धनुष को धारण करने वाले, संग्राम में सारे शत्रुओं का विनाश करने वाले, उन्हीं महादेव की अर्चना करो अर्जुन।

काशी विश्वेश्वर महादेव विश्वनाथ की महिमा का यह संकेत भगवान वेदव्यास ने महाभारत के द्रोणपर्व में संकेतों में किया है। वेदव्यास ने अर्जुन को कहा कि जहां धर्म है वहीं महादेव हैं, श्रीकृष्ण तो है हीं, जो साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम निर्भीक होकर रणभूमि में पराक्रम करो।

गच्छ युद्धयस्व कौन्तेय न तवास्ति पराजय:। यस्य मन्त्री च गोप्ता च पार्श्वस्थो हि जनार्दन:।।।

जाओ कुन्तीपुत्र, जाकर युद्ध करो, अब तुम्हारी पराजय नहीं हो सकेगी क्योंकि साक्षात श्रीकृष्ण तुम्हारे साथ विराजमान है...और महादेव शिव तुम्हारे आगे आगे चल ही रहे हैं जो चराचर जगत के कारण और स्वामी हैं...। चराचरस्य जगत: प्रभु: स भगवान हर:।। नमस्कुरुष्व कौन्तेय तस्मै शान्ताय वै सदा..।

स्पष्ट है कि काशी विश्वनाथ जब चाहते हैं, अपनी इच्छा से हर खेल पलट देते है। जैसे कि वह स्वयं अर्जुन के आगे आगे चलकर महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे। अब किसी को अगर यही गलतफहमी है कि काशी विश्वनाथ केवल जीवन के अन्तकाल में ही याद किए जाते हैं तो उसे तत्काल अपनी बुद्धि दुरुस्त कर लेनी चाहिए। और जिन्होंने हिन्दू और हिन्दुत्व के वामपाठ को ही हिन्दू धर्म और हिन्दुत्व का पैमाना मान रखा है, उन्हें क्या कहें? कहीं सचमुच ही तो शिव ने पहले ही बुद्धि विपरीतकर युद्ध एकतरफा तो नहीं कर दिया है? खैर, रणनीति ही महत्वपूर्ण होती है, वही पार लगाती है या फिर डुबा डालती है।

किन्तु यहां सवाल चुनावी रण में राजनीतिक लिहाज से सफलता के स्वप्न देखते हुए कुछ भी अंटशंट बकने का नहीं है, सवाल है कि सांस्कृतिक विषयों को राजनीतिक विषवमन से अलग क्यों नहीं रखा जा सकता? सदबुद्धि और विवेक क्यों इसी वक्त हमारे नेताओं का साथ छोड़कर दूर चला जाता है? जाहिर तौर पर ऐसे तत्वों को शिव के सम्मुख जाकर अपने पिताई और खुद की गलतबयानी और तीर्थ की अवहेलना पर पश्चाताप अवश्य प्रकट करना चाहिए ताकि सम्मानजनक हार मिल सके। गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए।

लेकिन क्या शिव मानेंगे और क्षमा प्रदान करेंगे? यह तो शिव ही जाने और सचमुच शिव ही जानते हैं क्योंकि वह तो सबके नाथ और विश्वनाथ हैं। कर्मों के अनुसार वह जीव के साथ रहते या उसका साथ छोड़ते हैं। और क्षमायाचना करने का समय भी तो अब कहां शेष है? चुनाव तो सर्वोपरि है ना।

जो भी हो, संकेत समझिए कि ज्योतिर्मय शिव तो अपने जलते त्रिशूल को लेकर आगे आगे चलने का संकेत दे रहे हैं। 2022, 2024, 2027 और 2029 का अब सवाल ही कहां है। इससे भी बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है जिसमें उत्तर बनकर एक बीज पड़ा है।

यह तो अपने मन-आंगन में 2047 में स्वतंत्रता के 100 सालों की तस्वीर लेकर उग रहा और निरंतर बढ़ रहा यह भारत है। जितने घाव विगत एक हजार साल में शरीर पर लगे हैं, सबका परिमार्जन करते हुए सभी कुटिल चालों को ध्वस्त करने के लिए अग्निपथ पर निकल पड़ा यह भारत है।

किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए। आज से ठीक एक हजार साल पहले 1002 से 1024 तक आतंकी हमलावरों की जिहादी रक्तरंजित तलवार सोमनाथ से लेकर विश्वनाथ तक कहर ढा रही थी, तब शिव शांत भाव से सब सह रहे थे। लेकिन अब इतिहास की धारा उलट चुकी है, 2019 से 2021 के दो सालों में ही शिव भी काशी से कश्मीर तक कुछ करवट ले चुके हैं और कुछ अभी लेने वाले हैं। जाहिर है, इसके नतीजे कुछ ही वर्षों में काल के भाल पर भारत के उज्जवलतम रूप के साक्षी बनेंगे।

जबतक शिव की आंखें बंद और ध्यानमग्न थीं, जिसे जो करना व कहना था वो कर और कह रहा था, किन्तु अब आंखे खुल चुकी हैं, अब जो होगा, होने जा रहा है, समय चक्र ने ऐसी तस्वीर न देखी होगी। 13 दिसंबर 2021 की तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है। ■

विवाह की उम्र बढ़ने से खुलती खिड़कियां

● ललित गर्ग

मोदी ने 2020 के स्वतंत्रता दिवस सम्बोधन में घोषणा की थी कि देश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 किया जाएगा। वे जो कहते हैं, उसे साकार भी करते हैं, यही कारण है कि करीब एक वर्ष बाद ही प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा को क्रियान्वित कर दिखाया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। निश्चित ही इस नयी व्यवस्था के बनने से नारी जीवन में एक नया उजाला होगा। इस तरह की विसंगतियों एवं असमानताओं को दूर करने के लिये सोच के दरवाजे पर कई बार दस्तक हुई, जब-जब दरवाजा खोला गया, दस्तक देने वाला वहां से लौटता दिखाई दिया। लेकिन मोदी ने दस्तक भी दी और इसे साकार भी किया है, जिसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि इससे नारी तेजी से विकास करते हुए अपने जीवन में पसरी अनेक विसंगतियों को दूर होते हुए देख सकेंगी। लेकिन कानून बनाने का फायदा तभी है, जब उसे संपूर्णता में लागू किया जाये। परिवार व समाज को बेटियों के व्यापक हित के लिए ज्यादा ईमानदारी एवं संवेदना से सोचना अपेक्षित है। अब भारत में पुरुष और महिला, दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 21 हो जाएगी, जो एक आदर्श एवं समतामूलक समाज की संरचना को आकार देगी।

लड़कियों के विवाह की उम्र का प्रश्न केवल संतुलित समाज व्यवस्था से ही नहीं जुड़ा है बल्कि यह उनके स्वास्थ्य, सोच, सुरक्षा, विकास से भी जुड़ा है। हर देश, समाज एवं वर्ग विकसित होना चाहता है। विकास की दौड़ में महिलाएं भी पीछे क्यों रहे? यह प्रश्न अर्थहीन नहीं है, पर इसके समाधान में अनेक बिन्दुओं को सामने रखकर मोदी ने चिन्तन किया और एक नवनीत समाज एवं राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ने तब कहा था, 'सरकार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी सही उम्र में शादी हो।' इसके लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। टास्क फोर्स ने पुरजोर तरीके से कहा था कि पहली गर्भावस्था के समय किसी महिला की आयु कम-से-कम 21 साल होनी चाहिए। सही समय पर विवाह होने पर परिवारों की वित्तीय, सामाजिक और स्वास्थ्य की स्थिति मजबूत होती है। परिपक्व उम्र में शादी होने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने और आजीविका चुनने का मौका मिलता है। वे एक परिवार के कुशल संचालन में भी दक्ष हो जाती है। जगजाहिर है कि बड़ी संख्या में लड़कियों की पढ़ाई, रोजगार, परिवार संचालन की जिम्मेदारी कम उम्र में शादी की वजह से बाधित होती रही है। अपने मौलिक गुणों से सम्पन्न लड़कियों जिस किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो वह कल-कल करती नदी की तरह निर्मल व पवित्र रहती हुई न केवल स्वयं विस्तार पाती है बल्कि जहां-जहां से वह गुजरती है विविध रूपों में उपयोगी बनती जाती है। उपयोगी बनने की एक उम्र सीमा होती है।

मोदी सरकार विवाह की उम्र सीमा बढ़ाने के बाद अब बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन पेश करेगी और इसके परिणामस्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन लाएगी। दिसम्बर 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता वाली केन्द्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सिफारिशें सौंपी थीं। इस टास्क फोर्स का गठन मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यता, पोषण में सुधार से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इन्हीं सिफारिशों के आधार पर ही लड़कियों के विवाह उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होने के अनेक फायदे हैं, सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लड़कियों का आत्मविश्वास एवं मनोबल बढ़ेगा। वे अपने कैरियर एवं जीवन के लिये प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम होंगी।

नारी को अब उन्हें अपने पेरों पर खड़े होकर स्वयं को निर्मित करते हुए समाज एवं राष्ट्र के विकास में भी योगदान देना है। इसके लिये जरूरी है कि वे कच्ची उम्र में विवाह के बंधन एवं परम्परा से मुक्ति पाये। कानून के बन जाने पर भी वे इन परम्पराओं एवं बंधनों से मुक्त हो जायेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज भी देश एवं दुनिया में नारी के सम्मान एवं अधिकार के लिये बने कानूनों की धज्जियां उड़ते हुए देखी जाती है।

समाज का एक बड़ा तबका आज भी नारी को दोयम दर्जा का ही मानता है। ऐसी पुरानपंथी सोच वालों का सोचना है कि लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, इसलिए दुल्हन को दूल्हे से कम उम्र की होना चाहिए। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने समय-समय पर लड़कियों की शादी की उम्र पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताई हैं। वर्ष 1929 के बाद शारदा एक्ट में संशोधन करते हुए 1978 में महिलाओं के विवाह की आयु सीमा बढ़ाकर 15 से 18 साल की गई थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मातृत्व मृत्यु दर गर्भावस्था पर उसके संक्रमित कारणों के चलते हर वर्ष एक लाख महिलाओं की मातृत्व के कारण मौत हो जाती है। मातृत्व मृत्यु दर का बड़ा कारण कम उम्र में शादियां होना ही है। इसलिये समूची दुनिया में लड़कियों की उम्र बढ़ाने पर व्यावक स्तर पर चर्चा होती रही है, परिवर्तन भी किये जा रहे हैं। चीन में शादी की न्यूनतम उम्र पुरुषों के लिए 22 साल और महिलाओं के लिए 20 साल तय की गई है। पाकिस्तान और कई अन्य मुस्लिम देशों में पुरुषों के लिए शादी की उम्र 18 साल और महिलाओं के लिए 16 साल है। ईरान में लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 13 साल है, लेकिन अदालत और लड़की के पिता की अनुमति हो तो 9 वर्ष में भी लड़कियों की शादी कर दी जाती है। इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष तय है लेकिन अगर मां-बाप की इजाजत हो तो शादी 15 वर्ष की उम्र में भी हो सकती है। यहां तक कि अमेरिका में भी कोई उच्च सीमा नहीं है। वहां साल 2000 से 2015 के बीच अवयस्कों के दो लाख से ज्यादा वैध विवाह दर्ज हुए थे। लेकिन वह अलग तरह के सामाजिक ढांचे वाला अमीर शिक्षित देश है, जबकि भारत में सामाजिक ढांचा दूसरी तरह का है, यहां कानून बनाकर और उसे ढंग से लागू करके ही आदर्श समानता, सह-जीवन एवं विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे महिलाओं के लिए शिक्षा और कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर भी बन रहे हैं। इसलिए महिला मृत्यु दर में कमी लाना और पोषण के स्तरों में सुधार लाना जरूरी है। समय की दस्तक को सुनते हुए मां बनने वाली लड़की की उम्र से जुड़े पूरे मुद्दे को संवेदनशील नजरिये के साथ देखना जरूरी है। स्वस्थ एवं समतामूलक समाज की संरचना का दिल और दिमाग में उठ रहे इस नये सपने को आकार देने में सभी सहभागी बने, ताकि नारी जीवन-निर्माण का नया दौर शुरु हो सके। ■

विधानसभा चुनाव

सबके वादे सबके दावे

उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के आगामी चुनावों में विरोध और समर्थन का कोई बड़ा राष्ट्रिय मुद्दा नहीं बचा है। तीनों राज्यों में स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समीकरण और राजनीतिक प्रबंधन की अब परीक्षा है। जनवरी का महीना सत्ता और विपक्ष, दोनों के लिए पत्ते फेंटने वाला महीना है जहां विभिन्न दलों के प्रत्याशी एक दूसरे के खेमे में जाते नजर आएंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस अगर अपनी आंतरिक कलह से बाहर आ सकी तो वह बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं जबकि उत्तर प्रदेश में चुनाव अब सीधे सपा और भाजपा के मध्य निर्धारित हो चुका लगता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी पहले से बेहतर करती दिख रही है और कांग्रेस के लिए यह नुकसान करने वाला समीकरण है। आम आदमी पार्टी से उत्तर प्रदेश में इस बार बेहतर की उम्मीद बनी थी किन्तु अब वह कांग्रेस से पिछड़ती नजर आ रही है।

● अमित त्यागी

2022 के चुनाव अब संतुलन की स्थिति में आ गए दिखते हैं। किसी बड़े राष्ट्रिय विषय का प्रभाव इस समय नहीं दिख रहा है। अब पिछले पांच साल के कार्यों की जो धारणा जनता के मानस पर अंकित हुयी है वह ही अपना प्रभाव दिखाने जा रही है। जैसे पंजाब की बात करें तो अकाली दल ने कृषि कानून के विषय पर भाजपा का साथ छोड़ा था जबकि कृषि कानून बनते समय वह भाजपा के समर्थन में थी। अब कृषि कानून वापस हो गए हैं किन्तु अकाली अब भी भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं है। इसका अर्थ साफ है कि कृषि कानून और अकाली के गठबंधन तोड़ने में कोई समानता नहीं थी। भाजपा अब कैप्टन के साथ खड़ी है। यह गठबंधन बेहतर करता तो दिख रहा है किन्तु सत्ता में आता फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन पंजाब में बेहतर होने जा रहा है। कांग्रेस से कटा वोट आम आदमी पार्टी की तरफ स्थानांतरित हो रहा है। आम आदमी पार्टी का किरदार पंजाब में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में और बसपा उत्तर प्रदेश में कुछ एक जैसे किरदार में आ गयी है। दोनों ही दल कम सीटें जीतने के बावजूद महत्वपूर्ण रहने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मोदी ने योगी के कंधे पर हाथ रख दिया है। अगर ऐसा है तो यह भाजपा के लिए फायदे का संकेत है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी को भाजपा ने लाने में देर कर दी, इसके बावजूद वह डैमेज कंट्रोल में लगे हुये हैं। कम समय में पुष्कर धामी ने भाजपा के सभी खेमों के साथ सामंजस्य बैठा लिया है।

अब ऐसे हालात हैं कि पुष्कर धामी के युवा नेतृत्व और बूथ तक फैले भाजपा के मजबूत संगठन के सामने कांग्रेस किसी एक नेता का नाम आगे करके चुनाव में उतरने का जोखिम नहीं उठा सकती और ये बात 73 वर्ष की उम्र पार कर चुके हरीश रावत जानते हुए भी समझना नहीं चाहते दिखते हैं। दिल्ली बैठक से लौटकर हरीश रावत ने उत्तराखंड में जिस प्रकार से अपना स्वागत करवाया उससे भी कांग्रेस आलाकमान की त्योरी चढ़ी हुई है। बताया जाता है कि कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत से इस बात की नाराजगी भी जाहिर कर दी है। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस में आज सबसे बड़े कद के नेता है। किंतु इसके पीछे एक सच्चाई कुछ और भी है। हरीश रावत की कार्यशैली के चलते 2016 में कांग्रेस में हुई बड़ी बगावत और लगभग सारे बड़े नेताओं के भाजपा में जाने के बाद बचे द्वितीय पंक्ति के नेताओं के बीच उनका कद स्वाभाविक रूप से बड़ा होना ही था। उनका मीडिया मैनेजमेंट भी जबरदस्त है। अपने मजबूत संपर्क कौशल के बूते उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर यह माहौल बना रखा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत ही कांग्रेस का पर्याय है। इसी के बूते वे अपने राजनैतिक आधार को बचाये रखने की संभवत: निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल जब राज्य चुनाव के मुहाने पर है, ऐसे समय में कांग्रेस में जारी यह घमासान निश्चित रूप से कांग्रेस की संभावनाओं को दिन प्रतिदिन कमजोर कर रहा है। वहीं पुष्कर धामी के नेतृत्व में भाजपा के लिये स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही हैं। जहां तक सरकार बनने का समीकरण है तो कांग्रेस और भाजपा, दोनों में से किसी भी दल को सत्ता में आने के लिए अभी भी निरंतर मेहनत की आवश्यकता है।

अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां सपा और भाजपा ही चुनाव मैदान में प्रबल दावेदार दिख रहे हैं। अखिलेश यादव की मेहनत और पकड़ चुनाव में दिख रही है। मुस्लिम मतदाता इस बार उनके साथ एकमुश्त होकर वोट करता दिख रहा है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसका सीधा लक्ष्य भाजपा के विरोध में वोट का है। जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है। मुस्लिम समाज में अशराफ (उच्च वर्ग) और पसमांदा (पिछड़े और दलित) दो वर्ग हैं। अखिलेश यादव के साथ थिंक टैंक में अशराफ वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। यह वह वर्ग है जो पाकिस्तान के साथ बंटवारे का पक्षधर था। इन्ही लोगों की संगत में मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए जिन्ना वाला बयान दिया गया जिसका 80 प्रतिशत वाले पसमांदा समाज पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पसमांदा समाज सरकारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाला वर्ग है। उसमे योगी का उतना मुखर विरोध नहीं दिखता है जितना कि अशराफ में। हालांकि, अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका जुड़ा हुआ है किन्तु बस यही बड़ा अंतर चुनावी परिणाम को प्रभावित करने वाला कारक भी बन सकता है। इससे अलग अगर भाजपा की दृष्टि से देखें तो काशी विश्वनाथ और श्री राम मंदिर का विषय उसके वोट बैंक को प्रभावित कर रहा है। काशी के लोग भी कॉरीडोर की भव्यता और दिव्यता से प्रभावित दिखते हैं। विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है और अचानक से धार्मिक पर्यटन वहां बढ़ गया है। कुछ ऐसा ही अयोध्या में भी है।

चूंकि, चुनाव में सिर्फ आस्था का विषय ही चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता है। महंगाई, बेरोजगारी और उद्योग धंधे की मंदी भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं, ऐसे में इन विषयों पर भी भाजपा को काम करना होगा। सपा के द्वारा इन विषयों को अब अच्छी तरह उठाया जा रहा है। हालांकि, कानून व्यवस्था का विषय अब

कनपुरिया धन्नासेठ

कनपुरिया धन्नासेठ के यहां छापेमारी में लगभग 270 करोड़ रुपए की नगदी तथा लगभग सौ करोड़ का सोना चांदी बरामद हो चुका है। छापेमारी अभी जारी है। बरामदगी अभी और भारी होना निश्चित है।

तीन दिन पहले शुरू हुई इस छापेमारी और बरामदगी के तत्काल बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की सामने आयी थी। उसने कहा था कि यह कार्रवाई चुनावों के समय की जा रही राजनीतिक साजिश/स्टंट मात्र है।

फिर दूसरी प्रतिक्रिया यह सामने आयी थी कि इस आदमी का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध ही नहीं, कोई लेनादेना ही नहीं।

फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अचानक चीखने चिल्लाने लगे कि इस धन्नासेठ का तो भाजपा से लेनादेना है। वो भाजपा का आदमी है।

अब चौथी स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में जबरदस्त सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है।

लगभग साढ़े तीन, चार सौ करोड़ की अबतक हुई इस बरामदगी का असली मालिक कौन है.? यह सच बहुत जल्दी सामने आ ही जाएगा।

लेकिन एक ही मुद्दे पर तीन तरह की विरोधाभासी बयानबाजी समाजवादी खेमे की भयंकर बौखलाहट का संकेत दे रही है। इस बौखलाहट का कारण क्या है?

जिस पीयूष जैन के यर से अरबों की बरामदगी हुई है। वो जांच एजेंसियों को यह भी नहीं बता पा रहा है कि इतना रुपया उसके पास कहां से आया है.?

अपने पास से बरामद अरबों रुपये का स्त्रोत वो अपने बाप दादों से मिले सोने की बिक्री को बता रहा है। यह अलग बात है कि जितना नगद रुपया उसके पास से बरामद हुआ है उतने रुपये के लिए कम से कम 600 किलो सोना बेचना पड़ेगा।

इतना सोना उसने कब कहां और किसे बेचा.?

इस सवाल का भी कोई जवाब वो नहीं दे पा रहा है।

उसकी व्यवसायिक जिंदगी भी बेहद सामान्य और घटिया स्तर के जालसाज की सी दिख रही है। कन्नौज स्थित उसके घर की जो फुटेज दिखी है वो भी उसकी सामान्य जीवनशैली की ही गवाही दे रही है। चलता भी वो स्कूटर से ही है। जिसके बाप दादे 600 किलो से ज्यादा सोना छोड़कर मरे हों, वो व्यक्ति कितना ही सादगी पसंद क्यों ना हो, लेकिन कम से कम स्कूटर पर तो नहीं ही चलेगा।

अभी तक की जो और जैसी कहानी सामने आयी है, उस कहानी से तो यही संकेत मिल रहा है कि कानपुर स्थित उसका आलीशान मकान और कोल्ड स्टोरेज भी किसी 'बड़े' बेईमान की बेनामी सम्पत्ति ही है।

पीयूष जैन उन संपत्तियों का मुखौटा मात्र है। हालांकि जांच एजेंसियों ने बीती रात उसे गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है।

अगले एक दो दिन में वो सच भी उगल ही देगा।

बौखलाहट का कारण कहीं यही तो नहीं?

साढ़े तीन, चार सौ करोड़ की रकम चुनावी मौसम में पकड़ जाने के बाद उस रकम के असली मालिक का नाम सामने आने की चिंता किसी कहर से कम नहीं है।

तीन दिन के लिए क्वारन्टीन हुए अखिलेश यादव की क्वारन्टीन अवधि भी 6 दिन लंबी हो चुकी है।

अभी और कितनी लंबी होगी, इसकी कोई सूचना किसी के पास नहीं है।

- सतीश चन्द्र मिश्रा

भी सपा और भाजपा सरकार का मूलभूत अंतर दिखा रहा है। आम जनता सपा सरकार की गुंडई को याद करके उसकी तरफ जाते जाते रुक जाती है। इन सबके बीच सपा के लैपटॉप के बाद भाजपा के टैब्लेट भी बांटे जा रहे हैं। सारे दल अपने अपने वादे कर रहे हैं। राजनीतिक पंडित अपने अपने दावे कर रहे हैं। पर जनता की नब्ज किसने पकड़ रखी है और कौन बेहतर समीकरण साधने की कला रखता है 2022 के परिणाम तो इसके आधार पर ही तय होंगे।

क्या फिर कमल खिला सकता है योगी पर मोदी का हाथ?

मोदी और योगी के मध्य अंतर्द्वंद और शीत युद्ध की खबरें निरंतर आ रही थीं। कृषि आंदोलन के समय इसको और हवा देते हुये विपक्षियों का जोश बढ़ गया था। मोदी अपनी सरकार के अपने ही वरिष्ठ मंत्रियों से भी स्वयं को घिरा महसूस करने लगे थे। इसके बाद मोदी का योगी के कंधे पर हाथ वाला फोटो और तीन कृषि कानून वापसी का प्रकरण हुआ।

लोहिया के सिद्धांतों कों कब की तिलांजलि दे चुके कांग्रेसी, सपाई

लोहिया का कहना था कि एक सच्चे समाजवादी को कांग्रेस और वामपंथियों से बराबर दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वो कभी भी खुद को मार्क्सवादी कहलाना पसंद नहीं करते थे। लोहिया के अनुसार कम्युनिस्ट अंधों की तरह हर समस्या का हल रूसी पृष्ठभूमि में ढूंढते है अन्यत्र उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता जबकि भारत की समस्याओं का हल केवल भारत के पास ही है। लोहिया ने अपनी पुस्तक भारत माता-धरती माता के पहले अध्याय में ही पृष्ठ 10 पर लिखा है कि 'आनंद, प्रेम और शांति का आव्हान तो रामायण में है ही पर हिंदुस्तान की एकता जैसा लक्ष्य भी स्पष्ट है। राम भारत के उत्तर-दक्षिण की एकता के परिचायक थे और कृष्ण पूर्व-पश्चिम एकता के'। लोहिया जैसा व्यक्तित्व नास्तिक होते हुए भी रामायण और महाभारत के सभी चरित्रों पर विश्वास करते हैं वो कम्युनिष्टों की तरह रामायण और महाभारत के अस्तित्व पर शक नहीं करते थे। लोहिया राम, कृष्ण और शिव का भारत के समाज और राजनीति पर चिंतन करते हैं और इसके पक्ष में उन्होने सैकड़ों लेख भी लिखे। उन लेखों के सार कुछ यूं हैं कि राम त्रेता के मीठे, शान्त और सुसंस्कृत युग का देव हैं। कृष्ण पके, जटिल, तीखे और प्रखर बुद्धि युग का देव हैं। राम गम्य हैं। कृष्ण अगम्य हैं। कृष्ण ने इतनी अधिक मेहनत की, कि उसके वंशज उसे अपना अंतिम आदर्श बनाने से घबड़ाते हैं। यदि बनाते भी हैं तो उसके मित्रभेद और कूटनीति की नकल करते हैं, उसका अथक निस्व उनके लिए असाध्य रहता है। वो तो यहां तक लिखते हैं कि राम, कृष्ण और शिव हिन्दुस्तान की उन तीन चीजों में हैं 'मैं उनको आदमी कहूं या देवता।' इसके तो ख़ास मतलब नहीं होंगे जिनका असर हिन्दुस्तान के दिमाग पर ऐतिहासिक लोगों से भी ज्यादा है ।

धर्म की विजय के लिये अधर्म से अधर्म करने को तैयार रहने का प्रतीक कृष्ण है। मैं यही तो किस्से नहीं बतलाऊंगा, पर आप खुद याद कर सकते हो कि कब सूरज को छुपा दिया जब कि वह सचमुच नहीं छुपा था। कब एक जुमले के आधे हिस्से को जरा जोर से बोलकर और दूसरे हिस्से को धीमे बोल कर कृष्ण अर्धसत्य बोल गये। इस तरह की चालबाजियां तो कृष्ण हमेशा ही किया करते थे। पर वह राष्ट्ररक्षा के लिये और धर्मार्थ होती थीं। इसके विपरीत राम मर्यादित अवतार थे। ताकत के ऊपर सीमा जिसे वे उलांघ नहीं सकते थे। कृष्ण बिना मर्यादा के अवतार थे किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कृष्ण झूंठ बोलते थे और जो कोई झूठ बोले। धोखा करे, वही कृष्ण हो सकता है। राम और कृष्ण का चरित्र इतना व्यापक है कि लोहिया ने हमेशा अपने समाजवाद में उसका जिक्र किया। पर उनके नाम पर चलने वाली समाजवादी पार्टी ने लोहिया के नाम का सिर्फ इस्तेमाल किया। उनके पदचिन्हों को छोड़ दिया। उनकी परम्पराएं तोड़ दी। परिवारवाद को बढ़ावा दिया। ऐसा समाजवाद तो मैंने लोहिया की किसी किताब में नहीं पढ़ा। अगर देखा जाये तो चित्रकूट में रामायण मेला लोहिया की संकल्पना थी। मौजूदा समाजवादी पार्टी लोहिया के सप्त-क्रांति और चौखम्बा नीति से न तो परिचित है और न उसकी चर्चा करती है ना ही उनकी दृष्टि लोहिया की तरह विशाल है। लोहिया के चिंतन में राष्ट्रीयता सर्वोपरि है। कम्युनिस्ट और समाजवादी दोनों ही कांग्रेस के पिछलग्गू बने घूमते हैं जिसका लोहिया ने हमेशा विरोध किया। सच्चे समाजवादी को तो कम्युनिष्टों और कांग्रेसियों को अपने मंच से दूर ही रखना चाहिए। पर क्या ऐसा हो रहा है ? बिलकुल नहीं। ये तो सत्ता प्राप्त करने के लिये बेमेल गठबंधन कर रहे हैं। वामपंथी विचारधारा के पोषक बन रहे हैं और लगातार समाजवाद के साथ साथ लोहिया की आत्मा को छलनी कर रहे हैं।

-डॉ स्वप्निल यादव
(लेखक लोहियावादी विचारक हैं।)

धीरे धीरे मोदी और योगी में सामंजस्य दिखाई देने लगा। अचानक से योगी, मोदी के बाद भाजपा के दूसरे सबसे बड़े नेता दिखने लगे। मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं इसलिए पूर्वांक्ल का पिछड़ा वोट और केशव मौर्या के माध्यम से दलित वोट साधने का स्वप्न भाजपा ने पाल लिया। अब यह स्वप्न साकार होगा या सिर्फ स्वप्न ही रह जाएगा यह तो 2022 के चुनाव परिणाम तय करेंगे। बहरहाल, जिस तरह पूर्वांक्ल और बुंदेलखंड में अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ दिख रही है वह अगर वोट में तब्दील होती है तो सपा का प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। जहां तक दलित वोट की बात है तो आजादी के बाद से दलित वोटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा था। किसी अन्य दल की तरफ जाने के बारे में दलित सोंच भी नहीं सकता था। इसके बाद इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी की सरकार बनी तो सहानुभूति लहर में सब वोट बैंक सिर्फ राजीव के पक्ष में नजर आया। राजीव गांधी के प्रमुख सिपहसालार वी पी सिंह ने बोफोर्स दलाली के मुद्दे पर बगावत कर दी। अपना नया दल जनता दल नाम से बना लिया। अपने लिए वोट बैंक की तलाश कर रहे वीपी सिंह ने सबसे पहले

मणिपुर विधानसभा चुनावः

क्या 2017 का करिश्मा 2022 में भी दोहरा पाएगी भाजपा ?

म्यांमार की सीमा पर बसा मणिपुर भारत का एक संवेदनशील राज्य है। यहां विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। दो-ढाई महीने बाद चुनाव होने हैं। मणिपुर में भाजपा की सरकार है और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार बचाने की है। 2022 में उसने 40 सीटों पर जीत का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पाना आसान नहीं है।

2017 में भाजपा को 60 में 21 सीटें मिलीं थीं और उसे गठबंधन सरकार के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस बार वह अकेले बहुमत का आंकड़ा पार करना चाहती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही भाजपा ने एक तेज-तर्रार महिला नेता-ए-शारदा देवी को प्रदेश की कमान सौंपी है। भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से है। मणिपुर एक छोटा राज्य है। यहां एक विधानसभा क्षेत्र में औसतन करीब 30 हजार वोटर ही होते हैं। इसलिए यहां की चुनावी रणनीति अन्य राज्यों से अलग है।

2017 में भाजपा ने किया था करिश्मा

पूर्वोत्तर के मणिपुर में भाजपा ने 2017 में चमत्कार किया था। पिछले दो चुनावों में जिस दल का खाता तक नहीं खुला उसने 2017 में सीधे सरकार ही बना ली थी। भाजपा ने ये चमत्कार किया था कांग्रेस के एक पुराने नेता एन बीरेन सिंह के दम पर। वे चुनाव से चार महीना पहले (2016) कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में शामिल हुए थे। उस समय अमित शाह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने बीरेन सिंह के साथ मिल बेजान भाजपा को मणिपुर में एक मुख्य प्रतिदंवद्वी के रूप में खड़ा कर दिया। एन विरेन सिंह ने अपने जनाधार का इस्तेमाल कर भाजपा को मजबूत बनाया। 2017 के चुनाव में 21 सीटें जीत तक भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गयी। 28 सीटें जीत कर भी कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी। एन बीरेन सिंह ने क्षेत्रीय दलों के साथ मिल कर सरकार बना ली। भाजपा ने केवल चार महीने की मेहनत में करिश्मा कर दिया। उसने 15 साल से कायम कांग्रेस की सत्ता उखाड़ फेंकी।

दल-बदल का बोलबाला

मणिपुर की राजनीति में विचारवाद से अधिक अवसरवाद प्रभावी रहा है। दल-बदल यहां एक सामान्य प्रवृति है। इसकी वजह से राजनीतिक हालात के बदलते देर नहीं लगती। 2017 में भाजपा ने (21) नेशनल पीपल्स पार्टी (4), नगा पीपल्स फ्रंट (4), लोजपा (1) और दो अन्य विधायकों के सहयोग से सरकार बनायी थी। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने थे। जून 2020 में छह विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। सरकार अल्पमत में आ गयी। तब कांग्रेस ने बीरेन सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। कांग्रेस के 28 विधायक जीते थे लेकिन तब 24 ही बचे थे। सदन की सदस्य संख्या 60 के बदले 53 रह गयी थी। अगस्त 2020 में मतविभाजन हुआ। कांग्रेस के 8 सदस्य सदन से गैरहाजिर हो गये। मतविभाजन हुआ तो भाजपा सरकार के पक्ष में 28 वोट पड़े। कांग्रेस के केवल 16 विधायक सदन में मौजूद थे जिसकी वजह से वीरेन सरकार ने विश्वास मत आसानी से जीत लिया। यानी कांग्रेस के विधायकों ने गैरहाजिर हो कर भाजपा सरकार को गिरने से बचा लिया था।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं भाजपा नेता

भाजपा ने जून 2021 में ए शारदा देवी को प्रदेश अध्यक्ष बना कर बहुत बड़ा दांव खेला था। मणिपुर के सामाजिक जीवन में महिलाओं का अहम स्थान है। राजधानी इम्फाल में एक ऐसा बाजार है जहां की चार हजार से अधिक दुकानें सिर्फ महिलाएं ही चलाती हैं। ग्रामीण जीवन में भी महिलाएं घर-गृहस्थी का मुख्य आधार हैं। शरदा देवी ने अध्यक्ष बनते ही राज्य के कोने-कोने में यात्रा कर भाजपा की पहुंच को बढ़ाया है। उनके अध्यक्ष बनने के एक महीने बाद ही मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष गोबिनदास कोंथोजम पार्टी छोड़ कर भाजपा में शामिल हो गये। कांग्रेस के कई विधायक भी भाजपा में शामिल हुए। भाजपा अन्य दलों के मजबूत नेताओं को जोड़ कर अपना विस्तार कर रही है। अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक सबसे अधिक भाजपा के टिकट की मांग है। अधिकतर नेता भाजपा से टिकट पाने के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं। दूसरी प्राथमिकता नेशनल पीपल्स पार्टी है। इसका भी प्रभाव हाल के दिनों में बढ़ा है। पर्वतीय इलाकों में नगा पीपल्स फ्रंट का जनाधार है। यहां एनपीएफ के टिकट के लिए मारामारी है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो वह पिछले कुछ समय में और कमजोर हुई है। मजबूत और प्रभावशाली नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। अब उसे नये चेहरों के दम पर चुनाव में उतरना होगा। तृणमूल कांग्रेस ने भी इस बार मणिपुर में जोरशोर से चुनाव लड़ने की तैयारी की है। 2012 में वह यहां 7 सीट जीत चुकी है। 2017 में उसे एक सीट मिली थी। तृणमूल के लड़ने से यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है।

मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू करके आरक्षण की शुरुआत की। इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुये एवं हिंसा के साथ कई लोगों की जाने चली गईं। इसके बाद वीपी सिंह ने अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में 1990 में संशोधन किया। इस संसोधन के बाद यह व्यवस्था आरंभ हो गयी कि आरक्षित जातियों द्वारा शिकायत करने मात्र से ही गिरफ्तारी हो

गोवा की सियासत में हुआ दिलचस्प चुनावी मुकाबला

गोवा के राजनीतिक परिदृश्य में तृणमूल कांग्रेस के पदार्पण और दो क्षेत्रीय दलों द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करने से मुकाबला रोचक हो गया है जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी दल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 'रिवॉल्यूशनरी गोअन्स' और 'गोएन्चो आवाज' वो दो क्षेत्रीय दल हैं जो पहली बार चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। इनके अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) तथा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी (एमजीपी) भी सत्ता की दौड़ में शामिल हैं।

भाजपा 2012 से सत्ता में है और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। भाजपा को लगता है कि चुनावी रण में जितनी ज्यादा पार्टियां होंगी, उसके लिए उतना अच्छा होगा क्योंकि इससे विपक्ष को मिलने वाले वोट बंटेंगे। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने हाल में कहा था कि उसकी योजना गोवा की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की है।

कांग्रेस के पूर्व विधायक लुईजिन्हो फालेयरो कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। एमजीपी के पूर्व विधायक लावु ममलाकर भी ममता की पार्टी में सदस्य बन चुके हैं, लेकिन इसके बाद किसी अन्य स्थानीय प्रभावशाली नेता ने ऐसा नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल नीत आम आदमी पार्टी (आप) ने 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे थे लेकिन उसका खाता तक नहीं खुला। इस बार भी 'आप' ने आगामी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस सत्ता में लौटने को आतुर है और ऐसा लगता है कि वह समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए राजी नहीं है।

गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने हाल में इस बाबत पूछे जाने पर कहा था, 'यह निर्णय लेना मेरा काम नहीं है। इस पर हाईकमान फैसला लेगा।' वर्ष 2017 में कांग्रेस ने 40 सदस्यीय विधानसभा में सबसे ज्यादा 17 सीटें हासिल की थीं और भाजपा को 13 सीटें मिली थीं। हालांकि, भाजपा ने क्षेत्रीय दलों के समर्थन से मनोहर परिकर के नेतृत्व में सरकार बना ली थी।

जीएफपी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की पहल की थी और उसका भी कहना है कि इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी गोवा में अस्तित्व है और चर्चिल अलेमाओ उसके एकमात्र विधायक हैं। कुछ दिन पहले शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा था कि उनकी पार्टी गोवा में अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव में 22 से 25 सीटों पर लड़ेगी। पार्टी ने एमजीपी के साथ मिलकर 2017 का चुनाव लड़ा था लेकिन कोई सीट नहीं जीत पायी थी। कुछ नेताओं का मानना है कि विपक्षी दलों को एक साथ आकर भाजपा को हराने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन भाजपा कड़ी टक्कर देने को तैयार नजर आती है। भाजपा ने घोषणा की है कि वह मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और इसके लिए सभी 40 सीटों पर तैयारी की जा रही है।

जाएगी। कोई भी जांच एवं अन्य प्रक्रियाएं गिरफ्तारी के बाद शुरू होंगी। यह भारत में सवर्ण और दलित के बीच तलवारें खिंचने की शुरुआत थी। आज 2022 आते आते वह खाई और बढ़ गयी है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उभरने की कोशिश कर रही कांग्रेस अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगत रही है।

नब्बे के दशक में मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू करने एवं अधिनियम में संशोधन के जरिये वीपी सिंह दलित वोटों को तत्कालीन जनता दल का वोट बैंक बनाना चाह रहे थे। चूंकि उस दौरान राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के द्वारा हथियाए जाने के कारण हिन्दू भाजपा की तरफ खिंच रहा था और शाहबानों प्रकरण के बाद मुस्लिम कांग्रेस का स्थायी वोट बैंक था इसलिए वीपी सिंह के द्वारा राजनीति कठिन थी। दलित कार्ड के द्वारा उन्होने भाजपा और कांग्रेस दोनों के हिस्से से कुछ वोट बैंक चुराने का कयास लगाया था। अपने लिए नए सामाजिक समीकरण बनाने के क्रम में उन्होने पहले संसद के केन्द्रीय कक्ष में बाबा साहब की प्रतिमा लगवाई और बाद में उन्हे मरणोंपरांत भारत रत्न दिया। यह सब इतनी तेजी के साथ घटित हुआ कि कांग्रेस को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसका दलित जनाधार एक झटके में उसके हाथ से फिसल गया। वह न तो वीपी सिंह का समर्थन कर पा रही थी और न ही उसका विरोध। समर्थन और विरोध दोनों से राजनैतिक नुकसान तय था। यह उसी तरह का घटनाक्रम था जैसे वर्तमान में काशी विश्वनाथ गलियारे का सपा न विरोध कर पा रही है और न ही समर्थन। उस समय वीपी सिंह ने पहले बोफोर्स और बाद में दलित वोट बैंक के जरिये कांग्रेस को इतने बड़े झटके दिये कि राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस तिलमिला कर रह गयी। बाद में कांग्रेस द्वारा वीपी सिंह सरकार के एक मंत्री चन्द्रशेखर को तोड़ लिया गया और उनको समर्थन देकर भारत का प्रधानमंत्री बनवाया गया। इसके बाद धीरे धीरे वीपी सिंह का और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का राजनैतिक पतन हो गया। ■

लोहिया, गोवा की राजनीति एवं 1962 का भारत चीन युद्ध

प्रधानमंत्री अभी गोवा के चुनावी दौरे पर गए थे। गोवा में भाजपा की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। मोदी द्वारा वहां लोहिया का नाम लिया गया। इतिहास में दर्ज है कि सर्वप्रथम 18 जून 1946 को गोवा की साम्राज्यवादी पुर्तगाल सरकार को लोहिया की जनसभा से चुनौती मिली थी। उसे बाधित किया गया तथा लोहिया को नजरबंद कर दिया। यह चार सदियों की गुलामी के युग के में गोवा का प्रथम स्वाधीनता संघर्ष था। मगर उस दौर के नेहरू समर्थक कांग्रेसी इस गोवा संघर्ष के प्रारम्भ की आलोचना करते रहे। 'लोहिया एक जीवनी' में लेखक-द्वय अरविंद मोहन तथा ओम प्रकाश दीपक ने कहा था - 'नेहरू ने फरवरी 1947 को कहा था कि गोवा की आजादी का प्रश्न गौण है।' बल्कि बताया था 'गुलाम गोवा केवल एक फुंसी है जिसे कभी भी मसला जा सकता है।' मगर विपरीत विचार था महात्मा गांधीजी का। बापू ने मुक्तकंठ से लोहिया की सराहना की। इतना ही नहीं, 14 अगस्त 1946 को अपनी पत्रिका 'हरिजन' में महात्मा गांधी ने लिखा, 'लोहियाजी को बधाई दी जानी चाहिए।' गांधीजी ने गोवा की प्रजा पर पुर्तगाली सरकार के दमन की कड़े शब्दों में आलोचना की और पुर्तगाली प्रशासन द्वारा डॉ. लोहिया की गिरफ्तारी पर सख्त बयान दिया। गांधीजी ने नेहरू से कहा कि वह गोवा में डॉ. लोहिया की रिहाई सुनिश्चित करें। नेहरू ने इस मामले में हस्तक्षेप करने में अपनी असमर्थता जताई। गांधीजी ने कहा कि डॉ. लोहिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, 'बल्कि भारत की आत्मा गोवा की जेल में है।' उसके बाद गांधीजी ने भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल को पत्र लिखकर कहा कि वह डॉ. लोहिया की रिहाई के लिए पुर्तगाल की सरकार पर दबाव डालें। गांधीजी ने वायसराय और गोवा के चर्च से इस बारे में बार-बार अनुरोध किया। उनके प्रयास सफल हुए और 9 अक्टूबर 1946 को डॉ. लोहिया रिहा कर दिए गए।

नेहरू ने डॉ. लोहिया के संघर्ष को अनावश्यक तथा आतिशी कदम बताया था। पर लाहौर जेल की कठोर यातना का भोगी यह गांधीवादी यातना से क्यों पीछे हटता? फिर पंजिम में जो हुआ वह सर्व विदित है। बापू के समर्थन के बावजूद कुछ कांग्रेसियों ने डॉ. लोहिया के कदम को नापसंद किया लेकिन भारत के आधुनिक इतिहास का दुखद अध्याय यही है कि गोवा की मुक्ति को लेकर डॉ. लोहिया के जनसंघर्ष के पंद्रह वर्ष बाद देश के चेहरे पर मुहासे जैसा गोवा पूरा फोड़ा बन गया। गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल सिल्वा ने 11 दिसंबर 1961 को भारतीय मुक्ति सेना के मुखिया जनरल कुन्हीरामन पी. कैंडेथ के समक्ष आत्मसमर्पण किया और हिन्दुस्तान का आखिरी यूरोपीय उपनिवेश मुक्त हो गया। यहां गमनीय बात है कि नेहरू का तर्क था कि गोवा, दमन द्वीव, दादरा नगर हवेली आदि पुर्तगाली उपनिवेश की जनता को खुद तानाशाह डा. एन्वोनिओ ओलिव सालाजार के विरुद्ध स्वतंत्र होने का संघर्ष चलाना चाहिये। अर्थात यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के तुष्टिकरण की यह बात थी। जैसे भारत से कोई सरोकार नहीं है। पुर्तगाल स्वयं अधिनायकवादी गणराज्य था। ब्रिटेन और फ्रांस की भांति लोकतांत्रिक नहीं जो गुलाम भारत तथा पाण्डिचेरी के संघर्ष को समझकर उन्हें आजादी दे देता। दमन पुर्तगाली साम्राज्य की नीति रही। फिर नेहरू लगातार कहते रहे कि वे सैन्यबल से गोवा को मुक्त नहीं करायेंगे।

तो दिसम्बर 1961 को नेहरू क्यों पलटे? तब भारतीय सेना ने गोवा में घुसकर पुर्तगाली गर्वनर-जनरल से आत्म समर्पण करा दिया। क्या कारण था? मूल बात यह थी कि तब (1962 फरवरी) तीसरी लोकसभा का आम चुनाव था। उत्तर मुम्बई सीट से नेहरू के रक्षामंत्री और कम्युनिस्ट चीन के यार रहे वीके कृष्णमेनन की पराजय तय थी गांधीवादी निर्दलीय प्रत्याशी आचार्य जेबी कृपलानी की विजय निश्चित थी। अपनी तथा अपने कम्युनिस्ट-समर्थक रक्षामंत्री मेनन को बचाने हेतु गोवा में नेहरू ने अपनी सर्वविदित, बारंबार कही गयी बात को झुठलाकर, बहुघोषित अहिंसक सत्याग्रह का मार्ग छोड़कर, सेना को चुनाव के ठीक डेढ माह पूर्व गोवा कूच करा दिया। उस जनावेश में मेनन जीत गये। मगर कीमत नेहरू ने चुकाई कि इसी मेनन का दावा झूठा पड़ा कि सीमा पर खतरा अमेरिका-समर्थित पाकिस्तान से है, न कि कम्युनिस्ट चीन से। फिर चीन ने भारत को (अक्टूबर 1962) हराया और मेनन को निर्वाचित होने के छह माह के अंदर काबीना से त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन तब तक पूर्वोत्तर और लद्दाख के बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा हो गया था। आज भी है। इस बारे में भी डा. लोहिया चेतावनी दे चुके थे।

-के. विक्रम राव

बैंकों की इस हड़ताल के बाद क्या ?

● राकेश दुबे

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लगभग नौ लाख कर्मचारी निजीकरण के विरोध में दो दिन की हड़ताल कर चुके हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार जल्द ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन पेश कर सकती है। इसके अलावा, बैंकों के निजीकरण के लिए बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन के जरिये सरकारी बैंकों में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत किए जाने की सभावना भी दिख रही है। इस हड़ताल और उसके कारणों से बैंकों का कामकाज बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। यह हड़ताल नौ बैंक संघों के मंच 'यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन' (यूएफबीयू) के आह्वान पर हुई थी। कर्मचारी चालू वित्त वर्ष में दो और सरकारी बैंकों के निजीकरण के सरकारी फैसले के भी खिलाफ हैं। बैंकिंग क्षेत्र और विशेष रूप से सरकारी बैंकों में हड़ताल और उसके कारण से चिंता बढ़ रही है।

वैसे तो केंद्र सरकार ने 2017 के बाद से ही बैंकों के एकीकरण की योजना पर भी काम शुरू कर दिया था। 2017 में देश में 27 पीएसबी थे, पर 1 अप्रैल 2020 से देश में सिर्फ 12 पीएसबी बचे हैं। सरकार की योजना यह संख्या और कम करने की है। अब यह जरूरी है कि भारतीय बैंकों को बचाया व बढ़ाया जाए और इसके लिए उनको भी अपने काम में सुधार के फैसले लेने पड़ेंगे।

आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल कर्ज का 35 प्रतिशत जोखिम में है और बैंकों के पास सिर्फ 8 प्रतिशत नुकसान को अवशोषित करने की क्षमता है। यह सबसे बड़ी समस्या है, इससे बैंक तभी उबरेंगे, जब ग्राहकों को बेहतर सेवा देंगे। भारतीय बैंकों को बेहतर परिश्रम व सतर्कता का परिचय देना चाहिए। खराब ऋण समय के साथ उच्च एनपीए की ओर ले जाते हैं, इसलिए धन की पेशकश करते समय उनको सतर्कता रखनी होगी। बैंकों को उन भारतीय कंपनियों को कर्ज देते समय सतर्क रहना चाहिए, जिन्होंने विदेश में भारी कर्ज लिया है।

बैंकिंग क्षेत्र अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। कई ऐसे काम हैं, जिनके लिए आपको अपने बैंक की उसी शाखा में जाना पड़ता है, जहां से आपका खाता खुला था। अच्छी सेवा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी समावेशन और तकनीकी साक्षरता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि कागज रहित बैंकिंग संभव हो।

इन दिनों पीएसयू सहित बैंक मुख्य रूप से खुदरा अग्रिमों या कॉरपोरेट्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र ज्यादातर एमएसएमई अग्रिमों की अनदेखी करते हैं। यह प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और यहां लगभग आठ करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। भारतीय जीडीपी में इस क्षेत्र का 16 प्रतिशत योगदान है, जिसके 2022 तक 25 प्रतिशत हो जाने की सम्भावना है। लोगों को अच्छी बैंकिंग सुविधा मिलनी ही चाहिए। सवाल यह है क्या सरकारी बैंक इस मोर्चे पर पूरा ध्यान दे रहे हैं? ग्राहकों से लंबे समय तक संबंध बनाए रखने के लिए नवाचार महत्वपूर्ण है। बदलते परिवेश व अन्य उद्योग प्रथाओं के साथ तालमेल रखते हुए बैंकिंग क्षेत्र को नवाचार में निवेश करना चाहिए, जिससे उन्हें ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

यह तथ्य सर्व विदित है विनिवेश की प्रक्रिया 1991 में शुरू की गई थी। वर्ष 2022 के लिए सरकार ने विनिवेश से राजस्व हासिल करने का लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपये रखा है। कोरोना काल सहित संकट के समय में निजी व सरकारी बैंकों ने कैसा प्रदर्शन किया है, यह किसी से छिपा नहीं है। विनिवेश से धन तो जुटाया जा सकता है, पर इसे हर मर्ज की दवा समझना गलत है।

हमारे यहां निजी क्षेत्र के बैंकों की पर्याप्त मौजूदगी है, जो सरकारी बैंकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सरकारी बैंकों की परिचालन व्यवस्था में अभी सुधार की जरूरत है। साथ ही, बैंकिंग सतर्कता आयोग के गठन पर देश के नीति निर्माताओं को विचार करना चाहिए। ■

भाजपा की स्थिति सुधारते पुष्कर धामी

● **अभिषेक सिंह एवं अमित त्यागी**

विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है उत्तराखंड की राजनीति भी दिन प्रतिदिन दिलचस्प होती जा रही है। चाहे वह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस, उठापटक का दौर दोनों तरफ जारी है। कांग्रेस में हरीश रावत के ट्विटर बम को अभी दो दिन भी नहीं बीते थे कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से खबर आने लगी कि उनके कद्दावर मंत्री हरक सिंह रावत नाराज हो गए हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी के लिए और अपनी सरकार के लिए एक संकटमोचक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। सूत्र बताते हैं कि हरक सिंह रावत जैसे ही कैबिनेट बैठक छोड़कर बाहर निकले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तुरंत सक्रिय हो गए और अगले 3 घंटों के भीतर अपने एक विधायक के जरिये उन्होंने नाराज हरक सिंह से संपर्क साध लिया। हरक सिंह की नाराजगी कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर थी अत: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से वार्ता की और उसके बाद हरक सिंह से बात करके यह सुनिश्चित किया कि उनकी मांग पर सरकार समुचित कार्रवाई करने जा रही है। कम विधानसभा सीटों वाले छोटे राज्यों में पार्टियों को राजनैतिक क्राइसिस मैनेजमेंट वाले नेताओं की बहुत आवश्यकता होती है। हरक सिंह की नाराजगी के ठीक 24 घंटे बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री आवास में डिनर टेबल पर साथ बैठे और दोनों के बीच लगभग 3 घंटे तक एकांत वार्ता चली। खास बात यह है कि हरक सिंह रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों ही सैनिक पुत्र हैं और इसके चलते यह राजनैतिक डिनर थोड़ी है देर में व्यक्तिगत डिनर में तब्दील हो गया। इसके बाद देर रात हरक सिंह का मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी मीडिया चैनलों पर चमक रहा था। हरक सिंह प्रकरण के बाद उत्तराखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद और बड़ा हुआ है। उत्तराखंड की जनता में धामी की छवि एक सौम्य, शिष्ट और काम करने वाले नेता की बनी है और जनता को यह भी लग रहा है कि उत्तराखंड को ऐसे ही नेता की आवश्यकता थी जिसे लाने में भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी सी देरी कर दी।

प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और खासकर हरीश रावत की गतिविधियों का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। बीते दिनों एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी के भीतर छिड़े द्वंद को पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया है। दरअसल इस बार का विधानसभा चुनाव हरीश रावत के लिए आर या पार की लड़ाई है और वो इस लड़ाई को किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहते हैं। हरीश रावत की यही अति महत्वाकांक्षा कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ी परेशानी का सबब भी है। हरीश रावत चाहते हैं कि उनकी पार्टी उन्हें प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा

उत्तराखंड कांग्रेस में चेहरे की लड़ाई !

उत्तराखंड में चुनावों से पहले चेहरों की लड़ाई छिड़ गई है। पहले भाजपा ने एक दम नए चेहरे और युवा नेता पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव में उतरने का फैसला किया। और अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, घमासान होता दिख रहा है। इसके संकेत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के दो ट्वीट से साबित हो रहा है।

हरीश रावत ने किया दर्द बयां

पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मैं आह भी भरता हूं तो लोग खफा हो जाते हैं। यदि उत्तराखंड के भाई-बहन मुझसे प्यार जता देते हैं तो लोग उलझन में पड़ जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हम लाख कहें, लोकतंत्र की दुल्हन तो वही होगी जो जनता रूपी पिया के मन भायेगी। मैं तो केवल इतना भर कहना चाहता हूं कि, उत्तराखंड यदि मैं, आपके घर को आपके मान-सम्मान के अनुरूप ठीक से संभाल सकता हूं तो मेरे समर्थन में जुटिये। राजनीति की ...तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिसलन और धक्का देने वाले, दोनों से बचाइये।

पिछले बार चुनावों के पहले हो गई बगावत

साल 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी बगावत हुई थी। उस समय पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में बगावत हो गई थी। और हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई थी। मार्च 2016 में वित्त विधेयक के दौरन 9 विधायकों ने बगावत कर दी थी। उस समय कांग्रेस के पास 36 विधायक थे। हालांकि बाद में उनकी सरकार बच गई थी।

लेकिन इस बार आलाकमान चुनाव के पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा होने देना चाहता है, जिससे पार्टी में गुटबाजी हो। इसलिए वह किसी चेहरे को पेश नहीं करना चाहती है। इसलिए वह नाम पेश करने से बच रही है। इसलिए उसके नेता यह कह रहे हैं कि पार्टी इस बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है।

उत्तराखंड में पार्टी को बड़ी उम्मीद

फरवरी-मार्च में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में सरकार बनने की बड़ी उम्मीद है। ऐसे में वह नहीं चाहती है कि चुनावों के पहले उसके लिए कोई असहज स्थिति पैदा हो और मतदाताओं में गलत संदेश जाय। इस बीच कांग्रेस नेता हरीश रावत की भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात भी सत्ता के गलियारे में चर्चा है। हालांकि मौका त्रिवेंद्र सिंह रावत को जन्मदिन की बधाई का था।

घोषित करके चुनाव में आगे बढ़े और इसके साथ साथ वे टिकट वितरण में भी फ्री हैंड चाहते हैं। हरीश रावत के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो कभी भी एक टीम मैन नहीं रहे और जब भी वे निर्णायक स्थिति में होते हैं। हमेशा अपने निर्णयों को बाकी लोगों पर थोपने के लिये जाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि अक्सर उनके साथ रहे लोग भी उनके खिलाफ हो जाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो किसी भी सूरत में हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव में जाना नहीं चाहता है, फिर चाहे वह नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अथवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत का खेमा हो। यह बात कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के संज्ञान में है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इन सब चीजों को बखूबी समझते हुए उसी लाइन पर चल रहे हैं जिस पर उनके आलाकमान ने उनसे चलने को कहा है। यह सारी बातें और परिस्थितियां इस समय हरीश रावत को बेहद नागवार गुजर रही हैं।

एक के बाद एक ट्वीट के जरिए अपनी बात रख कर हरीश रावत ने दरअसल अपना अंतिम हथियार चल दिया। हरीश रावत राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो ये समझ रहे हैं कि जब चुनाव से पहले टिकट वितरण में उनकी इतनी अनदेखी हो रही है तो चुनाव के बाद अगर पार्टी की सरकार बनने की कोई सूरत बनती भी है तो किसी भी हाल में नेतृत्व की पहली पसंद हरीश रावत तो नहीं ही होंगे। कांग्रेस आलाकमान के नजरिए से अगर देखा जाए तो हरीश रावत उसके लिए वह रास्ता है जिस पर चलना बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस रास्ते पर एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। हरीश प्रकरण को निपटाने के लिए दिल्ली में आलाकमान के साथ प्रदेश के नेताओं की जो बड़ी बैठक हुई उसमें भी यथास्थिति को बनाए ही रखा गया क्योंकि इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई चारा भी नहीं है। कांग्रेस आलाकमान का यही धर्म संकट हरीश रावत के लिए सबसे बड़ी संजीवनी है और इसके बूते वह अपना लक्ष्य साधना चाहते हैं। कांग्रेस में पनप रहे इस बड़े संकट का बीज उसी दिन पड़ गया था जिस दिन भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को नए मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की बागडोर सौंपी थी। धामी युवा हैं, लंबित मामलों को तेजी से निपटाते जा रहे हैं और साथ-साथ राज्य के ताबड़तोड़ दौरे भी कर रहे हैं। उनके दौरों और तेजतर्रार कार्यशैली का परिणाम यह हुआ है कि राज्य में भाजपा के विपरीत जो माहौल बन गया था उसे उन्होंने लगभग समाप्त कर दिया है। हाल ही में किए गए कई सर्वे भी इस बात की ताकीद कर रहे हैं उत्तराखंड में भाजपा एक बार फिर सत्ता में वापसी करने जा रही है। ■

पंजाब चुनाव अंधेरा नहीं, रोशनी के दीप जलाये

● ललित गर्ग

जब-जब चुनाव का माहौल बनता है एवं चुनाव की आहट होती है, हिंसा, द्वेष, नफरत एवं साम्प्रदायिकता की आग सुलगने लगती है, एकाएक शांत एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में ऐसी चिंनगारियों का फूटना एवं स्थितियों का पनपना स्पष्टत: राजनीति के हिंसक एवं अराजक होने का संकेत देता है। पंजाब में माहौल का निरंतर संवेदनशील, हिंसक एवं अराजक होते जाना चिंताजनक है। पिछले दिनों से बेअदबी की घटनाओं को लेकर वैसे ही तनाव है और अब गुरुवार दोपहर लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट ने एक अलग ही चिंता का संचार कर दिया है। विस्फोट में दो लोगों की मौत भी हुई है और करीब पांच घायल हुए हैं। ये घटनाएं निश्चित रूप से पंजाब में होने वाले चुनाव से पहले हिंसा, अशांति एवं द्वेष पैदा करने का प्रयास है। इन घटनाओं का सिलसिला बताता है कि कुछ राष्ट्रविरोधी शक्तियां पंजाब के शांतिपूर्ण माहौल को अचानक भय, आतंक, तनाव एवं कलहपूर्ण कर देना चाहती है। पंजाब एक मजबूत रक्षा-कवच है, पाकिस्तान से होने वाले षडयंत्रों एवं आतंकवादी हमलों से सुरक्षा देने में। अपनी गौरवपूर्ण छवि को कायम रखते हुए पंजाब के लोगों को अपने राष्ट्रप्रेम, एवं देशभक्ति के संस्कारों को बल देते हुए ऐसी घटनाओं के सिलसिले को रोकने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। पंजाब ने भले ही आतंकवाद के गहरे घाव अपने सीने पर झेले हैं, लेकिन शांति एवं अमन के दीप भी उसी ने जलाये हैं, राष्ट्र की एकता एवं साख को उसी ने बढ़ाया है।

निस्संदेह, पंजाब बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, पंजाब की संवेदनशीलता को आहत करने का अर्थ है देश की संवेदनाओं को आहत करना। राज्य में अगले साल के प्रारंभ में होने वाले विधानसभा चुनाव में निहित स्वार्थी तत्वों एवं राष्ट्रविरोधी शक्तियों द्वारा राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बाधित करने, आतंकवाद पनपाने, हिंसा एवं अराजकता फैलाने के कुत्सित प्रयास हो सकते हैं, जिसके चलते राजनीतिक दलों को जिम्मेदाराना व्यवहार करने, आम जनता को जागरूक रहने तथा पुलिस-प्रशासन द्वारा चौकस रहने की आवश्यकता है। इन तमाम हालात को देखते हुए पंजाब सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि कानून-व्यवस्था बनाये रखने को लेकर सतर्क रहे और असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटे। ऐसे संवेदनशील समय में सत्तापक्ष के साथ ही विपक्षी दलों की भी जवाबदेही बनती है कि वे ज्वलनशील मुद्दों को हवा देने से बचें। राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। भीड़ द्वारा हिंसा की घटना पर राजनीतिक दलों का प्रतिक्रिया से परहेज हिंसा की अनदेखी करने के समान ही है। इसमें दो राय नहीं कि देश के विभिन्न राज्यों में भीड़ की हिंसा को रोकने के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति में कमी लगातार सामने आती रही है। कभी कभी तो ऐसी घटनाएं राजनीतिक प्रेरित होने के संकेत भी मिलते रहे हैं। हमें राजनीति को हिंसा नहीं शांति का, तोड़ने नहीं जोड़ने का, नफरत नहीं प्रेम का माध्यम बनाना होगा।

आज देश को जोड़ने वाली सोच, जोड़ने वाली राजनीति चाहिए। पर हमारे राजनेता, जोड़ने वाली बात तो करते हैं, पर राजनीति तोड़ने वाली ही कर रहे हैं। धार्मिक संतुलन की बात करने वाले नेता और जाति के आधार पर वोट बांटने का गणित लगाने वाले चुनावी-रणनीतिकार देश को जोड़ते नहीं, तोड़ते हैं। सच तो यह है कि देश नारों से या स्वार्थी मंत्रों से नहीं जुड़ता, देश के जोड़ने के लिए भारतीयता की पहचान को स्वीकारना होगा। समझना और कहना होगा कि मैं पहले भारतीय हूं, राष्ट्रीयता मेरी पहली प्राथमिकता है, मानवता मेरा आदर्श है।

लेकिन यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई ही है कि आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमारी भारतीयता और मनुष्यता, दोनों, सवालिया निशानों के घेरे में है। धर्म व्यक्ति को जोड़ता है, पर हमने धर्म को राजनीति का हथियार बनाकर तोड़ने का जरिया बना दिया है। जाति मनुष्य के कर्म की पहचान होनी चाहिए, पर हम जाति के नाम पर राजनीतिक पहचान को मजबूत बनाने के नफा-नुकसान का गणित लगाने में लगे हैं। भाषा एक व्यक्ति को दूसरे से जोड़ने का माध्यम होती है, हम आज भाषा के नाम पर राजनीति स्वार्थ की रोटियां सेकते हुए एक-दूसरे से अलग करने का काम

पंजाब में क्रांति की आवश्यकता

पंजाब को जट्ट सिख राजनीति से मुक्ति के साथ साथ धार्मिक क्रांति की भी आवश्यकता है । पंजाब के गांवों में सीखों सनातन धर्म को समाप्त कर दिया है । जिसका लाभ ईसाई मिशनरी उठा रही है । जिन गांवों की हवाओं कभी राम कृष्ण के भजन कानों ने रस घोलते थे वहां अब नीरसता है । राम और कृष्ण भारत की एकात्मता का सूत्र हैं जो पंथ या सम्प्रदाय इन पर कटाक्ष करता उसपर इतना तीव्र प्रहार हो चाहिए कि उनके कानों में से धुआं निकल जाए । पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों को रामायण गीता के ज्ञान और राम कृष्ण के भक्ति रस में डुबोने का उचित समय है क्योंकि पंजाब की धरती पर निराकार की उपासना के नाम पर कई गुरु, पीर फकीर स्वयं ही भगवान बन बैठें हैं। जब तक आशुतोष जी महाराज जीवत थे पंजाब में आशा की किरण दिखती थी। उनके समाधि लेने के उपरांत अब केवल एक ही संस्था से उम्मीद है वह है इस्कॉन। इस्कॉन ही वह संस्था है जो इसाई मशीनरी को काउन्टर कर सकती है। पंजाब की पिच खाली है । अगर इसको जल्द ही भरा नहीं गया तो पंजाब की धरती अगला नागालैंड बन सकती है ।

पंजाब में सिखों का धर्म परिवर्तन को कांग्रेस द्वारा पूरी तरह promote किया जा रहा है । लेकिन सिख इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रहें हैं। अंकुर नरूला द्वारा आयोजित एक धर्मपरिवर्तन कार्यक्रम में कांगेसी उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंघ रंधावा ने शिरकत की ।

पंजाब के जट्ट कैसे सीख बनें ।

क्योंकि सारे गुरु खत्री परिवारों से सम्बंध रखते

थे इसलिये सबसे पहले खत्री परिवार सिख बने । फिर दलित सीख बनें सबसे अंत में जट्ट सिख बने । अधिकतर जट्ट बन्दा वैरागी के समय सीख बनें। जब पंजाब में कुछ समय के लिये बन्दा वैरागी सत्ता में आये तो उन्होंने लोह गढ़ के किले से दो हुक्मनामे जारी किए ।

1. गौ हत्या पर मौत की सजा का हुक्मनामा सबसे पहले जारी किया गया ।
2. जट्ट से पहले भूमि के मालिक मुसलमान थे क्योंकि पंजाब में भारत मे सबसे अधिक लंबे समय तक इस्लाम का राज्य रहा । जट्ट अधिकतर बटाई पर खेती करते थे जिसका अर्थ है कि मालिकाना हक मुसलमानों का था जट्ट उनके मुजारे थे। बन्दा वैरागी ने मुसलमानों से यह जमीन छीन कर जट्ट के नाम कर दी। इससे प्रभावित होकर पंजाब के अधिकतर जट्ट सीख पंथ में परिवर्तित हो गए।

दुःख के बात है पंजाब के जट्ट सीख बन्दा वैरागी का पहला हुक्मनामा भूल गए जिसमे गौ सरक्षण की बात की गई है ।

कांग्रेस स सेकूलर दलों ने हिन्दुओं की परिवार व्यवस्था को नष्ट करने के लिये, Domestic Violence Act, Dowry Act आदि हिन्दू समाज पर लाद दिए । इससे हुआ क्या हिन्दू समाज के परिवार के झगड़े जो समाज द्वारा सुलझा लिए जाते थे वह आदालतों तक पहुंच गए। इस तरह सनातन परिवार व्यवस्था की जड़ों में तेल डाला गया। तांकि परिवार व्यवस्था खत्म होने से हिन्दुओं की आबादी कम हो सके। नालीवादी हमेशा सनातन परिवार व्यवस्था को समाप्त करने के लिये हिन्दू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाते रहतें है। तांकि सनातन परिवार व्यवस्था का आधार नारी का चरित्र पतन हो सके। और सनातन परिवार व्यवस्था को जड़ से खत्म किया जा सके। नालीवादी कभी किसी और धर्म का मजाक नहीं उड़ाते। सनातन भारत मोदी सरकार से अनुरोध करता है कि वह सनातन परिवार व्यवस्था को तोड़ने वाले कानूनों को संशोधित करे। और हिन्दू समाज को अपने पारिवारिक मसले सनातन पंचायत व्यवस्था से हल करने की छूट दे। नालिवादिओं का जमकर मजाक उड़ाया जाना चाहिये।

- राजीव कुमार

कर रहे हैं। बड़ी त्रासदी यह है कि यह सब अनजाने में नहीं हो रहा, हम जानबूझकर यह कर रहे हैं, अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिये कर रहे हैं। सोच-समझ कर, रणनीतियां बना कर राजनीति की शतरंज पर शह-मात का खेल खेला जा रहा है और इस प्रक्रिया में हम लगातार कमजोर हो रहे हैं, हमारी राष्ट्रीयता आहत हो रही है। विडम्बना यह भी है कि हम इसके परिणामों की भयावहता को समझना भी नहीं चाहते।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। समूची दुनिया की नजरे भारतीय लोकतंत्र पर टिकी रहती है, अत: यहां होने वाले चुनाव निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक संचालित हो, यह सुनिश्चित करना सरकार के साथ-साथ राजनीतिक दलों एवं आम मतदाताओं का बड़ा दायित्व है। राष्ट्र में आज ईमानदारी, सौहार्द एवं निष्पक्षता हर क्षेत्र में चाहिए, पर चूंकि अनेक गलत बातों की जड़ चुनाव है इसलिए वहां इसकी शुरूआत होना ज्यादा जरूरी है। पंजाब के इस चुनावी कुंभ में इस प्रकार की शांति, आदेशों की पालना तथा कानूनी कार्यवाही का भय दिखना चाहिए। इन परिस्थितियों में फिर एक बार देश में 'भारत जोड़ो' की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कही है। 'मन की बात' के अपने मासिक-कार्यक्रम में उन्होंने देश का आह्वान किया है कि वह आजादी के अमृत-महोत्सव वाले वर्ष में एक-दूसरे से जुड़ने का संकल्प है। यह बात सुन कर अच्छा लगा, यह भारतीयता का अहसास जगाने का आह्वान है, मनुष्यता को सही अर्थों में समझने की प्रेरणा है, जनता के बीच

बिक्रम मजीठिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई गलत समय में लिया गया सही फैसला क्यों है?

संभव है कि मजीठिया पर लगा आरोप गलत हो, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अकाली दल के शासनकाल में पंजाब में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और हमेशा शक की सुई बादल परिवार के आसपास ही जा कर रुकती थी। जिसमें मजीठिया का नाम सबसे ऊपर होता था।

सी नेता के खिलाफ, वह भी चुनाव के दो महीने पहले प्राथमिकी दर्ज होना राजनीति से प्रेरित कदम ही माना जाता है. पंजाब पुलिस द्वारा पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स के मामले में कल प्राथमिकी दर्ज करने से मजीठिया सिर्फ आरोपी बने हैं, मुजरिम नहीं. इससे मजीठिया को चुनाव लड़ने से भी नही रोका जा सकता है. एक तरीके से यह पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की जीत मानी जा सकती है, क्योंकि सिद्धू और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच खाई बढ़ने का यह एक बड़ा कारण था।

सिद्धू का आरोप था कि अमरिंदर सिंह की बादल परिवार से मिलीभगत है और वह जानबूझकर बादल परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लड़ाई में जीत सिद्धू की हुई और अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के ठीक तीन महीने बाद मजीठिया के खिलाफ सात साल पुराने आरोप की फाइल खुली है। इसके लिए सिद्धू को चन्नी से भी लड़ाई लड़नी पड़ी और सिद्धू के दबाव में ही पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल और एडवोकेट जनरल को हटाना पड़ा, तब जा कर मजीठिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शुरुआत हुई है। सम्भव है कि अगले एक-दो दिनों में मजीठिया से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में भी लिया जाएगा जिससे पंजाब की राजनीति में भूचाल आ सकता है।

क्या अकाली दल को एक लाइफलाइन मिल जाएगी?

मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स के तस्करों को संरक्षण देने का आरोप जब भी लगा था जबकि वह अकाली दल-भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे। पर चूंकि मजीठिया के जीजा सुखबीर सिंह बादल उपमुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल थे, मामले को रफा दफा कर दिया गया था। इस केस की फाइल तब ही खुलनी चाहिए थी जब कि 2017 कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अब जिस तरह से अमरिंदर सिंह खुल कर सामने आए हैं और कहा है कि यह केस राजनीति से प्रेरित है और उन्हें इसकी पूरी जानकारी है, कि यह केस गलत है, सिद्धू का आरोप कि अमरिंदर सिंह और बादल परिवार की मिलीभगत है, साबित करता है।

हो सकता है कि अमरिंदर सिंह सही कह रहे हों कि मजीठिया पर लगा आरोप गलत है, पर मजीठिया के लिए अमरिंदर सिंह का सर्टिफिकेट काफी नहीं है, अब उन्हें अदालत से क्लीनचिट लेना पड़ेगा। यह सम्भव नहीं है कि जांच की कार्रवाई और अदालत में मुकदमा अगले दो महीनों में ख़त्म हो जाए। संभव है कि या तो इसके बाद शिरोमणि अकाली दल जिसके सुखबीर सिंह बादल अध्यक्ष हैं और मजीठिया महासचिव, पूरी तरफ से बर्बाद हो जाएगी या फिर अकाली दल को एक लाइफलाइन मिल जाएगी। जो भी हो, पंजाब सरकार का यह एक सही फैसला है जो गलत समय में लिया गया है, जिसका असर फरवरी के महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव पर साफ दिखेगा।

2007 से 2017 के बीच पंजाब भारत का ड्रग कैपिटल बन गया था

संभव है कि मजीठिया पर लगा आरोप गलत हो, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अकाली दल के शासनकाल में पंजाब में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और हमेशा शक की सुई बादल परिवार के आसपास ही जा कर रुकती थी। जिसमें मजीठिया का नाम सबसे ऊपर होता था। 2007 से 2017 के बीच जबकि पंजाब में बादल सरकार थी, पंजाब भारत का ड्रग कैपिटल बन गया था। पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे की लत लग गई थी। आरोप था कि सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी और वितरण सरकार के बड़े नेताओं के संरक्षण में चल रहा था। बादल परिवार भ्रष्टाचार के दूसरे के पूरक बन गए थे, जिसका खामियाजा अकाली दल को 2017 के चुनाव में हुआ, जबकि अकाली दल 68 सीटों से लुढ़क कर 18 सीटों पर आ गई।

बादल परिवार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे

भ्रष्टाचार भी कई तरीके का होता है. एक होता है कि किसी भी टेंडर को रिश्वत ले कर ही पास किया जाता है। यह सबसे सरल और दिखने वाला भ्रष्टाचार होता है जिसमें अमूमन 10 प्रतिशत की कम से कम राशी दी जाती है। याद हो कि बेनजीर भुट्टो के शासनकाल में पाकिस्तान में भुट्टो के पति आसिफ अली जरदारी को Mr 10 Percent के नाम से जाना जाता था। भ्रष्टाचार का दूसरा तरीका होता है सरकार में बैठे लोग इस तरह का निर्णय लें जिससे उनके स्वयं के व्यापर को लाभ मिले। अकाली दल सरकार के समय पंजाब में केबल टीवी का मामला भी लगातार उछलता रहता था। बादल परिवार भी इस व्यवसाय में था और सरकारी तंत्र द्वारा दूसरी कंपनियों को परेशान किए जाने का आरोप लगता था, ताकि आमजन बादल की कंपनी का कनेक्शन लें।

ऐसा ही कुछ हाल पंजाब से दिल्ली रूट पर बस चलाने का भी था। पंजाब से हजारों लोग प्रतिदिन दिल्ली ह्वाईअड्डा आते और जाते हैं। इस रूट पर सरकारी बसों की संख्या कम कर दी गयी, पुरानी बसों को इस रूट पर लगाया गया और उनकी टाइमिंग ऐसी रखी गयी जो ह्वाई यात्रिकों को सूट नहीं करता था। उसकी जगह बादल परिवार की ट्रांसपोर्ट कम्पनी की आधुनिक बसें चलने लगीं और दूसरे ट्रांसपोर्ट कंपनियों को इस रूट से दूर रखा गया। सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपयों का घाटा होता रहा और बादल परिवार की कंपनी को भारी मुनाफा। बादल परिवार हरेक व्यापर पर मोनोपोली स्थापित करने का आरोप लगा।

गैरकानूनी धंधों में मजीठिया का नाम सबसे ऊपर

पंजाब भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां रेत की कीमत सीमेंट से अधिक होती थी। रेत का कानूनी और गैरकानूनी खुदाई और व्यापर वही कर सकते थे जिसके सिर पर बादल परिवार का हाथ हो। यही हाल कमोबेश शराब के व्यापर का भी था। पंजाबी समुदाय जम कर परिश्रम करने और शाम में थकान मिटने के लिए शराब का सेवन करने के लिए विख्यात हैं।

भारत में सबसे महंगी शराब पंजाब में ही बिकती थी और वह भी न्यूनतम मूल्य से अधिक कीमत पर। शराब व्यापारी कहते थे उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उन्हें सरकार में बड़े लोगों को प्रतिमाह एक मोटी रकम देनी होती थी। अब जब शराब महंगी हो तो लोग देसी शराब पिएंगे खासकर गरीब और मजदूर तबका। पर देसी शराब भी इतनी महंगी की उसे खरीदना भी संभव ना हो. तो फिर अवैध शराब बनता था जिसको पी कर अक्सर लोग मर भी जाते थे। और अवैध शराब बनाने और बेचने के व्यापार को संरक्षण देने का आरोप भी सरकार और सरकारी मंत्रियों पर लगता था। ड्रग्स हो, रेत हो या शराब, सभी के गैरकानूनी धंधे में मजीठिया का नाम सबसे ऊपर रहता था।

बादल परिवार यूं ही नहीं भारत के सबसे धनाढ्य राजनीतिक परिवारों में गिना जाता है। अधिकारिक तौर पर उनकी कुल संपत्ति सैकड़ों करोड़ में है पर असलियत में यह हजारों करोड़ में है। 2003 में पंजाब विजिलेंस कमीशन के एक अनुमान के अनुसार बादल परिवार की कुल संपत्ति 4326 करोड़ थी। उसके बाद 2007 से 10 वर्षों तक लगातार बादल परिवार सत्ता में रहा और यह वह समय था जब पंजाब में भ्रष्टाचार का नंगा तांडव दिख रहा था। अब बादल परिवार की कुल संपत्ति कितनी होगी इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है।

मजीठिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चुनाव में मुद्दा बनेगा

बादल सरकार के दौरान पंजाब कंगाली के कगार पर पहुंच गया था और बादल परिवार की संपत्ति दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। यह आलम पंजाब की जनता ने भी देखा जो भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, जिसका अंजाम हुआ कि ना सिर्फ अकाली दल को सत्ता से हाथ धोना पड़ा बल्कि वह आम आदमी पार्टी से भी कम सीट जीत पायी।

चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में अनुसार अकाली दल के लिए इस बार 18 सीट जीतना ही काफी चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। और शायद यही कारण है कि जब अकाली दल ने कृषि कानून के विरोध में बीजेपी के साथ अपना वर्षों पुराना गठबंधन तोड़ दिया तो बीजेपी विचलित नहीं हुई। अब चूंकि कृषि कानून वापस ले लिया गया है, बीजेपी ने पलट कर भी अकाली दल की तरफ नहीं देखा। बादल परिवार ने जिस तरह से कांग्रेस के बाद भारत की सबसे पुरानी पार्टी पर कब्जा किया और फिर उनकी लोकप्रियता का नाजायज उपयोग धन बटोरने के लिए किया, उसका ही नतीजा है कि पंजाब की राजनीति में अकाली दल की साख कमजोर पड़ती जा रही है। सिद्धू की जिद के आगे सरकार को झुकना पड़ा और मजीठिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चुनाव के ठीक पहले करना किसी जुए से कम नहीं है। यह चुनाव में एक बड़ा मुद्दा तो बनेगा ही, बस देखना यह है कि क्या इससे अकाली दल बर्बाद हो जाएगी या फिर उनकी वापसी होगी।

22 किसान संगठनों ने बनाया नया मोर्चा

पंजाब विधानसभा चुनाव में शनिवार को बड़ा अपडेट सामने आया है। कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करने वाले 22 किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने संगठन का नाम संयुक्त समाज मोर्चा रखा है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हमें व्यवस्था बदलने की जरूरत है और लोगों से इस मोर्चा का समर्थन करने की अपील करना चाहते हैं।

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे पंजाब के 22 किसान संगठनों ने शनिवार को संयुक्त समाज मोर्चा नाम से एक नया राजनीतिक मोर्चा बनाया और घोषणा की कि वे आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस संबंध में निर्णय इन संगठनों के प्रतिनिधियों ने यहां लिया।

किसान नेता हरमीत सिंह कादियान ने कहा कि पंजाब में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संयुक्त समाज मोर्चा का गठन किया गया है। ये 22 किसान संगठन पंजाब के उन 32 किसान संगठनों में से हैं, जिन्होंने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।

मुफ्त की संस्कृति को पनपाने की बजाय राष्ट्रीयता को बल देने का उपक्रम है। जब राष्ट्र मजबूत होता है तो उसके नागरिक भी मजबूत होते हैं, फिर उन्हें किसी भी साधन या सुविधाओं को मुफ्त में लेने की जरूरत नहीं होती।

डर लगता है यह मुफ्त की संस्कृति को पनपाने वाले राजनेताओं से। प्रश्न है कि हमारी राजनीति में इस तरह की प्रवृत्तियों को पनपने क्यों दिया जा रहा है? यह स्वार्थ की राजनीति है और जनतांत्रिक व्यवस्था में इसके लिए कोई स्थान नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पंजाब में इस तरह की घटनाओं का होना हमारे लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। यह हिंसक प्रवृत्ति, स्वार्थ की राजनीति, यह मुफ्त की संस्कृति इसका अर्थ यह नहीं है कि यह पंजाब तक सीमित है। हमने देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग रूप में इस हिंसा एवं अराजकता को पनपते देखा है। कभी यह प्रवृत्ति गौहत्या के नाम पर पीट-पीट कर मार देने में दिखती है और कभी 'बच्चा चोरों' का आतंक दिखा कर किसी को मार दिया जाता है। अब पंजाब में इसकी नयी शक्ल सामने आयी है, इससे सावधान एवं सर्तक रहने की जरूरत है। जनतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की भाषा और प्रवृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह दुर्भाग्य की ही बात है कि हमारा नेतृत्व इस बात की गम्भीरता को समझने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहा। हमारी राजनीति का आधार गोली नहीं, वोट होना चाहिए। स्वार्थ नहीं, स्वावलम्बन होना चाहिए, नफरत-द्वेष नहीं, प्रेम एवं सौहार्द होना चाहिए। इसलिए ऐसी हर कोशिश को नाकामयाब बनाना उस हर नागरिक का कर्तव्य है जो जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है, जो भारत को सशक्त-स्वावलम्बी भारत बनाना चाहता है। हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की हिंसा, अराजकता एवं नफरत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ■

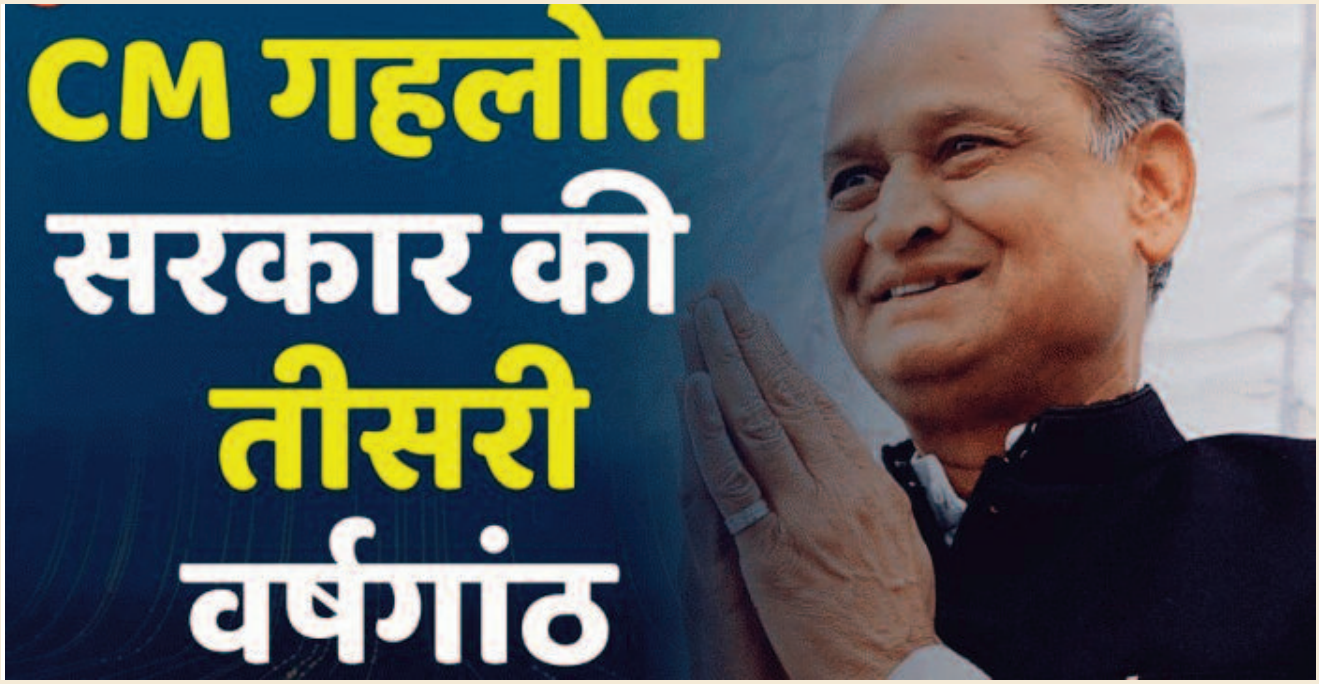

खुद को बचाये रखने की जद्दो जहद

● रामस्वरूप रावतसरे

राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को तीन वर्ष 17 दिसंबर 2021 को पूरे हो गये हैं। तीन वर्ष पूर्ण होने पर गहलोत सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत कर रही है। चुनावी वायदे पूरे करने और विकास के दावे तो हर सरकार करती है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है बताई जा रही है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को तीन वर्ष तक बनाए रखा है।

राजस्थान में दिसंबर 2018 में जब कांग्रेस को सरकार बनाने लायक बहुमत तो मिल गया था, लेकिन मुख्यमंत्री का पद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फंस गया था। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी के आवास के बाहर लोगों ने गहलोत और पायलट को लंबी मंत्रणा करते देखा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही अशोक गहलोत को चुनौती मिल रही थी। लंबी जद्दोजहद के बाद गहलोत ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन गहलोत को पहले ही दिन से सरकार के अस्थिर होने का डर रहा, इसलिए गहलोत ने बड़ी चतुराई से बसपा के सभी 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवा लिया। उस समय सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री होने के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे।

जानकार लोगों का कहना है कि गहलोत ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की सचिन पायलट को भनक तक नहीं लगने दी। रात को अंधेरे में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के समक्ष बसपा के सभी छह विधायकों को प्रस्तुत कर राजस्थान से मायावती की बहुजन समाज पार्टी का निशान ही मिटा दिया। यह अशोक गहलोत की राजनीतिक कुशलता का ही परिणाम था। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहला अवसर होगा, जब किसी प्रदेश के सभी निर्दलीय विधायक सत्तारूढ़ दल के समर्थन खड़े थे।

अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि मध्यप्रदेश की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार गिर जाए। उनका एक मात्र मिशन था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी रहे। सचिन पायलट प्रदेश के मुखिया का ताज उनके सिर पर हो इसके लिए वे ज्योंही दिल्ली गए, इधर गहलोत ने पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद से बर्खास्त कर दिया गया। सचिन पायलट को 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाने का श्रेय जाता है, वह पायलट आज सिर्फ एक विधायक हैं। इन सब स्थितियों के मध्य प्रदेश के विधान सभा उप चुनावों को जीतना तथा आला कमान के लाख कौशिश करने पर भी पायलट को अधिक तवज्जों नहीं देना और मंत्री मंण्डल का विस्तार भी अपने अनुसार ही करना गहलोत की सबसे बड़ी उपलब्धी मानी जा रही है।

लेकिन इन तीन वर्षो में जनता के कितने काम हुए और सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार कितना काम कर पाई है। इस

सम्बन्ध में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां का कहना है कि राज्य सरकार का प्रदर्शन पूरी तरह फीका और अफसोस जनक रहा है। उनके अनुसार सरकार किसान की कर्ज माफी, अपराध की बढती दर और बेरोजगारी के मुद्दे पर बिल्कुल ही विफल रही हैं ।

सतीश पूनियां के अनुसार जब यह सरकार 2018 में चुनी गई थी, तक किसानों में यह भ्रम फैलाया गया था कि कांग्रेस सरकार उनके सभी कर्जे माफ कर देगी। परन्तु राज्य सरकार ने केवल भूमि विकास से जुड़े लोन को माफ किया है जबकि शिड्यूल्ड बैंकों और नैशनलाइज्ड बैंको के कर्ज अभी तक माफ नहीं किये गये है। प्रदेश में करीब 60 लाख किसान है जिन पर कर्जा है और इन पर पूरे कर्ज के कुल एक लाख बीस हजार करोड़ रूपये का कर्जा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सबसे बड़ा वादा खिलाफी अपने ही जन घोषणा पत्र से की है, जिसे स्वयं राहुल गांधी ने अपने भाषणों में बार बार कहा है और स्वयं मुख्यमंत्री ने बार बार उद्धत किया है।

प्रदेश में बढती बेरोजगारी को सतीश पूनियां ने राज्य सरकार की दूसरी सबसे बड़ी विफलता बताया है। उन्होंने कहा कि सैंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी के आंकडे कहते है कि राजस्थान में पूरे देश से सबसे अधिक 27 प्रतिशत बेरोजगारी है। कांग्रेस सरकार जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है इसका उदाहरण है कि प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को अपनी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुचाने के लिए प्रियंका गांधी से मिलने के लिए लखनऊ तक जाना पड़ा। यही नहीं राज्य में जो भी सरकारी पदो के लिए परीक्षाएं हुई है, इनमें कितनी धांधली हुई है, चाहे रीट हो या नीट सभी जगह अभ्यर्थियों के मामले अदालतों में फसे पड़े है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि इस सरकार की युवाओं को रोजगार देने की कोई मंशा नहीं है। दूसरी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रिस्तेदार जब परीक्षाओं में बैठते है तो इन्हें कैसे चुन लिया जाता है किसी से छुपा नहीं है। प्रदेश में बेरोजगारी के मामले में राज्य सरकार ने स्वयं माना है कि उन्होंने अभी तक 1.5 लाख को बेरोजगारी भत्ते दिये है। जबकि सी एम आई ई के सर्वे के अंकड़े कहते हैं कि प्रदेश में करीब 30 लाख बेरोजगार है।

राज्य सरकार के तीन साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था के बारे में पूनियां का कहना है कि राजस्थान को लोग पहले शांतिप्रिय प्रदेश मानते थे। यहां अन्य प्रदेशों से पर्यटक आता था परन्तु इस सरकार के कार्यकाल में 6.5 लाख एफ आई. आर दर्ज हुई है जो स्वयं इस बात का प्रमाण है कि राज्य की कानून किस स्तर पर पहुची हुई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक अखवार में दिये इंटरव्यू में कहा कि वर्ष 2019 में महिलाओं पर हुए अपराधों के संदर्भ रजिस्टर हुई 45.88 प्रतिशत एफ.आई आर फर्जी पाई गई। इसी प्रकार 2020 में 45.23 प्रतिशत और 2021 जून माह तक 47.56 प्रतिशत एफ.आई आर फर्जी पाई गई। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए सतीश पूनियां ने कहा कि किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के ज्यादातर मामले फर्जी हैं। इस प्रदेश की महिलांए, माताएं और बेटियां इस बयान को सत्य नहीं मानेगीं प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की 5000 से अधिक वारदातों की लम्बी फैहरिस्त है। जिसका दर्द केवल प्रदेश की महिला ही समझ सकती है। सतिश पूनियां के अनुसार मुख्यमंत्री के पास ऐसी कौनसी जांच एजेंसी है जिसने यह निर्णायक निर्णय देकर तय किया है कि ज्यादातर मामले फर्जी है। उनका यह बयान गैर जिम्मेदाराना है।

सतीश पूनियां के अनुसार प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सत्ताधारी दल के नेताओं में मतभेद के कारण प्रशासनिक प्रणाली ठप पड़ गई। करोना महामारी के दौरान सत्ताधारी नेताओं को जनता के साथ होना चाहिए था। ये होटलों में बैठे थे। प्रदेश की वास्तविक स्थिति किस प्रकार की है इसको ''ट्रांसपरैंसी इन्टरनैशनल'' ने अपनी रिर्पोट में बताया है। राजस्थान पूरे देश में गैर कानूनी खनन और भ्रष्टाचार के मामलों अव्वल है। उनके अनुसार इस वर्ष विधान सभा सत्र में सरकार ने कृषि उपयोग के लिए अलग से बिजली उपलब्ध कराने के लिए अलग से ग्रिड और उसकी वितरण कंपनी बनाने का वादा किया था, इस पर अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है। बल्कि सर्दी से कई किसान मर गए है, जिन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया है। राज्य सरकार मंहगाई को लेकर केन्द्र सरकार के खिलाफ रैली का आयोजन करती है। लेकिन मंहगाई के मामले में स्वंय कहा है। उसका भी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिये।

वैसे इस समय सत्तधारी दलों से यह उम्मिद रखना कि वे सिर्फ और सिर्फ जनता के ही काम करेगें। ऐसा कुछ भी नहीं है उन्हें अपने आपको बनाएं रखना भी बहुत बड़ा और सबसे पहला काम होता है। वही काम राजस्थान में अशोक गहलोत ने किया है। घोषणा पत्र कितना पूरा हुआ, कितनों को रोजगार दिया गया। कानून व्यवस्था की स्थिति किस प्रकार की है। जनहित के लिए कितने प्रोजेक्ट पूर्ण किये और कितनों की आधार शिला रखी। यह सब चुनाव के समय आंकड़े गिनाने का रहता है। जो समय पर गिना दिये जाते है और यह काम भी सरकारी तन्त्र का है। वैसे तीन साल को लेकर गहलोत सरकार की किस मामले में उपलब्धि स्वरूप पीठ थपथपाई जानी चाहिए प्रदेश की जनता जानती है। ■

मौलिक भारत अभियान

मंदिर संकुल : सनातन संस्कृति व चेतना के केंद्र

● अनुज अग्रवाल, अध्यक्ष, मौलिक भारत

भारत में मंदिर हमेशा सनातन संस्कृति के चेतना केंद्र रहे हैं। धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यकलापों का केंद्र रहे मंदिर धीरे धीरे सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र बनते गए। देश के इतिहास में लंबे समय तक सेकड़ो राज्यों में राजा के महल और किले के साथ साथ प्रमुख मंदिर और उनसे जुड़े शिक्षित , योग्य व विद्वान ऋषि, मुनि, महंत व पुरोहित प्रमुख स्तंभ बनकर उभर गये राजा को हिंदू धर्म ग्रंथो की व्याख्या, पुनर्लेखन व उनके आधार पर राज्य को चलाने की सलाह राजा को देते थे । सनातनी राज व्यवस्था राजसत्ता, धर्मसत्ता, अर्थसत्ता और समाजसत्ता के आपसी समन्वय व संतुलन का अनोखा उदाहरण व भारत के विशिष्ट लोकतंत्र का परिचायक थी। इसीलिए भारत ज्ञान परंपरा आधारित देश बन पाया।सनातन राज व्यवस्था का माडल किलों, महलों व मंदिरो के इर्दगिर्द रचित हुआ। राज्य का संचालन, कानून व्यवस्था व आंतरिक और बाहरी सुरक्षा किलों व महलों से नियंत्रित होती थी और राज्य की जनता व सामान्य जीवन के कार्यकलापो का केंद्र मंदिर होते थे। यह मंदिर एक संकुल का स्वरूप लेते गए। इस मंदिर संकुल में देव स्थान, ध्यान कक्ष, मंत्रणा कक्ष, सभा/प्रवचन कक्ष, महंत आवास ,यात्री विश्राम ग्रह, यज्ञशाला, धार्मिक पुस्तकालय, वाचनालय, गुरुकुल, गौशाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम कक्ष, चिकित्सालय, व्यायामशाला, रसोई व भोजन कक्ष, अन्न कक्ष, तिजोरी कक्ष, बगिया, कौशल विकास केंद्र सब कुछ होता गया। और मंदिर पूजा व उपासना के साथ ही राज्य के सलाहकार, अन्न व संपदा के केंद्र (जिसका प्रयोग राज्य आपात स्थिति में करता था) बन गया। मंदिर संकुल में शिक्षा हेतु गुरुकुल भी था जहां शास्त्र व शस्त्रों की शिक्षा के साथ साथ कला, नृत्य, संगीत, योग, नाटक, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, कौशल विकास, आयुर्वेद, व्यायाम, आत्मरक्षा इत्यादि की शिक्षा व सुविधा दी जाती थी। इस प्रकार भारतीय मंदिर कला, संस्कृति के साथ ही सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र थे। अपनी इस व्यवस्था के कारण भारतीय संस्कृति व सत्ता सम्पूर्ण विश्व में स्थापित हो गयी।

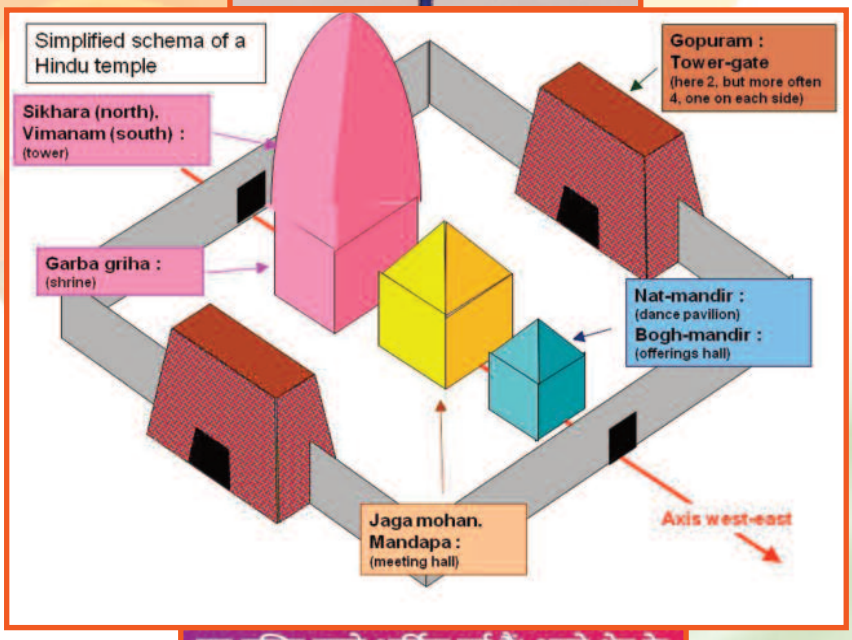

कालांतर में ईसाईयत व इस्लाम ने विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए हिंदू संस्कृति के स्तंभ मंदिरो व गुरुकुलों को नष्ट करने का भरकस प्रयत्न किया। अपनी साम्राज्यवादी नीतियो व सत्ता की व्यवस्था को स्थापित करने के क्रम में राज व्यवस्था की पंथनिरपेक्ष व्यवस्था पूरी दुनिया के देशों पर थोप दी गयी और मंदिर उपेक्षित व महत्वहीन बनाने की हरसंभव कोशिश की गयी। इस कारण भारत की ज्ञान परंपरा कहीं न कहीं दब सी गयी है।

चूंकि सनातन धर्म व संस्कृति सर्वाधिक वैज्ञानिक वेदों ब उपनिषदों पर आधारित है और प्रकृति केंद्रित विकास पर आधारित है इसलिए इसकी शाश्वतता अक्षुन्न है ,इस कारण आम भारतीय हिंदू आज भी इससे जुड़ा है और सनातनी जीवन व्यवस्था से ही

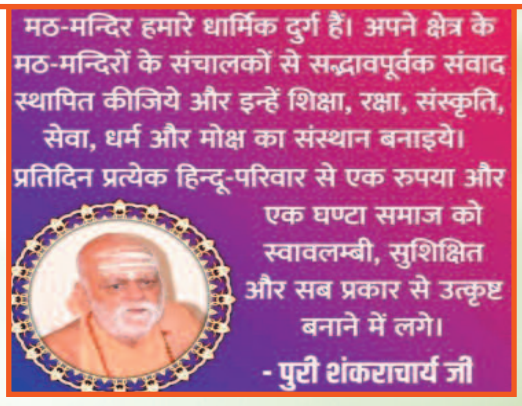
मठ-मन्दिर हमारे धार्मिक दुर्ग हैं। अपने क्षेत्र के मठ-मन्दिरों के संचालकों से सद्भावपूर्वक संवाद स्थापित कीजिये और इन्हें शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान बनाइये।
प्रतिदिन प्रत्येक हिन्दू-परिवार से एक रुपया और एक घण्टा समाज को स्वावलम्बी, सुशिक्षित और सब प्रकार से उत्कृष्ट बनाने में लगे।
- पुरी शंकराचार्य जी

उसका जीवन संचालित होता है। यह कहा जा सकता है कि सरकार व कारपोरेट जगत पश्चिमी माडल से और आम समाज व व्यापारी वर्ग सनातन माडल से संचालित होता है।

जीडीपी आधारित, अत्यधिक केंद्रित व प्रकृति व मानव के अपार शोषण व लालच पर आधारित वर्तमान सेकूलर राज व्यवस्था का माडल अब टूटने व बिखरने के कगार पर है ।वर्तमान समय में अन्य बीमारियों के साथ साथ कोरोना जैसी महामारी और 'जलवायु परिवर्तन' जैसी भयावह चुनौतियां इस विकृत व्यवस्था के कारण उपजी हैं। इस कारण संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व ही संकट में है ।सनातन संस्कृति का परम्परागत माडल ही अब मानव जाति को बचा सकता है। इसके लिए पुन: मंदिरो को उनकी पुरानी भूमिका में आना होगा जो समाज को एक सूत्र में पिरोकर और जागृत कर पुन: राजव्यवस्था के सनातन माडल को स्थापित कर मानव जाति पर आए संकट को दूर करेंगे और ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित कर हर व्यक्ति के समग्र आंतरिक व बाहरी विकास को कर उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए हर जागरूक व संवेदनशील सनातनी के लिए आवश्यक है कि वह अधिक से अधिक रूप में स्वयं , अपनी परिवार, रिश्ते नातेदारो व मित्रों को समग्र रूप से मंदिर से जोड़े ताकि मंदिर और उनके माध्यम से देश पुन: उठ खड़ा हो व दुनिया को अस्तित्व के संकट से निकाल समुन्नति के मार्ग की ओर ले चले।

मंदिर संकुल

वेद काल में न तो मंदिर थे और न ही मूर्ति। वैदिक समाज इकट्ठा होकर एक ही वेदी पर खड़े रहकर ब्रह्म (ईश्वर) के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करते थे। इसके अलावा वे यज्ञ के द्वारा भी ईश्वर और प्रकृति तत्वों का आह्वान और प्रार्थना करते थे। शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। शिवलिंग पूजन के बाद धीरे-धीरे नाग और यक्षों की पूजा का प्रचलन हिन्दू-जैन धर्म में बढ़ने लगा। बौद्ध काल में बुद्ध और महावीर की मूर्तियों को अपार जनसमर्थन मिलने के कारण राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाने लगीं।

माना जाता है कि प्राचीन काल में देवी या देवताओं के पूजा स्थल अलग होते थे और प्रार्थना-ध्यान करने के लिए स्थल अलग होते थे। वैदिक काल में वैदिक ऋषि जंगल के अपने आश्रमों में ध्यान, प्रार्थना और यज्ञ करते थे। हालांकि लोक जीवन में मंदिरों का महत्व उतना नहीं था जितना आत्मचिंतन, मनन और शास्त्रार्थ का था। फिर भी आम जनता इंद्र, विष्णु, लक्ष्मी, शिव और पार्वती के अलावा नगर, ग्राम और स्थान के देवी-देवताओं की प्रार्थना करते थे। बहुत से अन्य समुदायों में शिव और पार्वती के साथ यक्ष, नाग, पितर, ग्रह-नक्षत्र आदि की पूजा का भी प्रचलन था। वैदिक काल में ही चार धाम और दुनियाभर में ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के साथ ही प्रार्थना करने के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। समय-समय पर इनका स्वरूप बदलता रहा और कर्मकांड भी ।समय के साथ मंदिर सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बन एक संकुल का रूप लेते गए इस मंदिर संकुल में देव स्थान, ध्यान कक्ष, मंत्रणा कक्ष, सभा/प्रवचन कक्ष, महंत आवास ,यात्री विश्राम ग्रह, यज्ञशाला, धार्मिक पुस्तकालय, वाचनालय, गुरुकुल, गौशाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम कक्ष, चिकित्सालय, व्यायामशाला, रसोई व भोजन कक्ष, अन्न कक्ष, तिजोरी कक्ष, बगिया, कौशल विकास केंद्र आदि होते हैं व यह क्षेत्र विशेष के सनातन धर्म लंबियो के जीवन व दैनिक गतिविधियों का केंद्र होता है। लंबे समय तक बड़े मंदिर राजसत्ता से भी संतुलन बैठाते रहे और भारत भूमि के राज्य राजसत्ता व धर्मसत्ता के संतुलन का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते रहे।

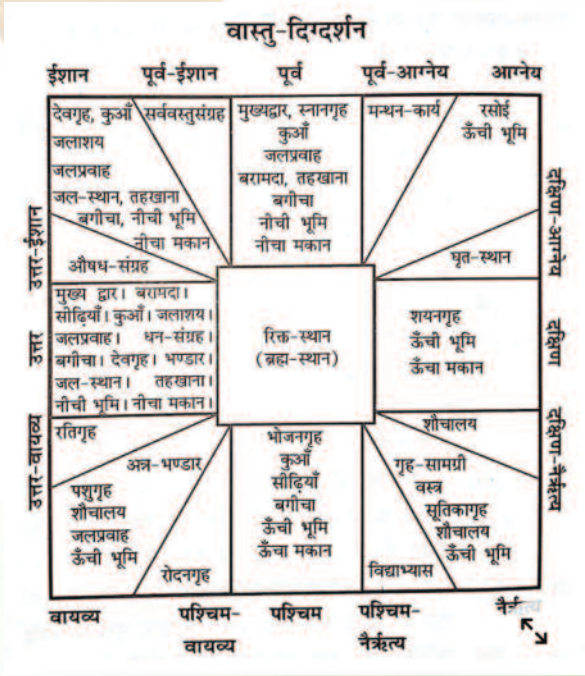

मंदिर का अर्थ होता है-मन से दूर कोई स्थान।

मंदिर का शाब्दिक अर्थ 'घर' है और मंदिर को द्वार भी कहते हैं- जैसे रामद्वारा, गुरुद्वारा आदि।

मंदिर को आलय भी कह सकते हैं जैसे की शिवालय, जिनालय।

लेकिन जब हम कहते हैं कि मन से दूर जो है वह मंदिर तो, उसके मायने बदल जाते हैं।

मंदिर को अंग्रेजी में मंदिर ही कहते हैं टेम्पल नहीं। जो लोग टेम्पल कहते हैं वे मंदिर के विरोधी हो सकते हैं।

मंदिर किसी भगवान, देवता या गुरु का होता है, आलय सिर्फ शिव का होता है और मंदिर या स्तूप सिर्फ ध्यान-प्रार्थना के लिए होते हैं, लेकिन वर्तमान में उक्त सभी स्थान को मंदिर कहा जाता है जिसमें की किसी देव मूर्ति की पूजा होती है।

मन से दूर रहकर निराकार ईश्वर की आराधना या ध्यान करने के स्थान को मंदिर कहते हैं। जिस तरह हम जूते उतारकर मंदिर में प्रवेश करते हैं उसी तरह मन और अहंकार को भी बाहर छोड़ दिया जाता है।

जहां देवताओं की पूजा होती है उसे 'देवरा' या 'देव-स्थल' कहा जाता है। जहां पूजा होती है उसे पूजा स्थल, जहां प्रार्थना होती है उसे प्रार्थनालय कहते हैं।

वेदज्ञ मानते हैं कि भगवान प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं पूजा से नहीं।

मंदिर का महत्व

मंदिर के निर्माण के दौरान, यह वास्तुकारों, कारीगरों, मूर्तिकारों और मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है।

पूरी तरह से निर्मित मंदिर सांसारिक जीवन पर अध्यात्म के महत्व का प्रतीक

वे सात सूत्र जिससे मंदिरो का पुनरुत्थान व समाज का पुनर्जागरण होगा

1) प्रतिदिन मंदिर जाना प्रारंभ कर। हमें घर में मंदिर नहीं बनाना वरन घर को मंदिर जैसा बनाना है। इसलिए अपनी पूजा, आराधना, ध्यान व योग मंदिर में करना प्रारंभ करें।

2) यथासंभव सभी व्रत, त्योहार, शुभ व मांगलिक कार्य, सभी संस्कार आदि मंदिर में ही करना प्रारंभ करें। इससे पूरे परिवार को धर्म का मर्म समझ आएगा व उनकी आंतरिक व बाह्य उन्नति होगी।

3) सेवा का कोई भी कार्य यथा दान, भंडारा, वस्त्रव कंबल वितरण, सेवा प्रकल्पों को मंदिर में माध्यम से ही करें। इससे स्वाभाविक रूप से हर अशक्त व जरूरतमंद व धर्म की मुख्यधारा से कटा व्यक्ति मंदिर व सनातन संस्कृति से जुड़ता जाएगा। यथासंभव टीका, कलावा, शिखा(चोटी) आदि धारण करें व हर लाभार्थी को ईश दर्शन, मांगलिक आरती व सनातन प्रतीकों से जोड़े।

5) इस बात का भरकस प्रयत्न करें कि मंदिर में कीर्तन, कथा, प्रवचन,ध्यान कक्षाओं, शास्त्रीय संगीत व नृत्य का आयोजन व शिक्षा, कौशल विकास की शिक्षा का केंद्र, योगशाला, यज्ञशाला , गौशाला, व्यायामशाला, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, धार्मिक पुस्तकालय, निशक्त हिंदुओं के बच्चों के लिए अनोपचारिक विद्यालय आदि अनेकानेक गतिविधियों का संचालन नियमित रूप से होता रहे। मंदिर से जुड़ा कोई एक परिवार किसी एक गतिविधि की जिम्मेदारी ले सकता है।

6) मंदिर को मिलने वाले दान का सही प्रबंधन व हिंदू समाज के उत्थान व सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में कर।

7) मंदिर से ब उससे जुड़े बड़े आयोजनो, मेलों, कथाओं आदि से गरीब, अशक्त, अनपढ़ व हाशिए पर पड़े हिंदू समाज को जोड़कर , संस्कारी बना व उसे सहायता देकर ।

देश को इसी प्रकार के पांच लाख मंदिर संकुल (हर पंचायत व वार्ड में कम से कम एक एक) जो सनातन संस्कृति व चेतना के केंद्र बन सकें ,की आवश्यकता है जिससे भारत पुनः ज्ञान व अध्यात्म की धरती बन जग का कल्याण कर सके।

है।

मंदिर के भीतर भगवान की छवि लोगों के मन को शांति प्रदान करती है।

मंदिर में संगीत, नृत्य और ललित कला कार्यक्रम कलाकारों को प्रोत्साहन देते हैं ।

मंदिर के अन्न भंडारों में पशु को चारा और भूखों को भोजन कराया जाता है।

प्रख्यात संतों द्वारा धार्मिक प्रवचन आम जनता के लिए ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है।

अन्य देशों में निर्मित मंदिर हिन्दू धर्म की संस्कृति को आगे ले जाने के रूप में कार्य करते हैं। और हिंदू धर्म के बारे में जानने में रुचि रखने वाले भारतीय समुदाय और स्थानीय जनता के लिए आध्यात्मिक और शैक्षिक सेवाओं का प्रसार करते हैं।

मंदिर का अर्थ क्या है?

मंदिर का अर्थ मन से दूर कोई स्थान,मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहा प्रवेश मात्र से ही हम सकारात्मक महसूस करते है क्यूंकि वह मंदिर वास्तु अनुसार बनाया जाता है। और इसे बनाते वक्त भी कही चीजो का ध्यान रखा जाता है। जिससे मंदिर में आनेवाले को सकारात्मक ऊर्जा मिले, जिससे हमे शांति मिलती है।

हिंदू मंदिर की वास्तु रचना

हिन्दू मंदिर की रचना लगभग 10 हजार वर्ष पूर्व हुई थी। उस काल में वैदिक ऋषि जंगल के अपने आश्रमों में ध्यान, प्रार्थना और यज्ञ करते थे। हालांकि लोकजीवन में मंदिरों का महत्व उतना नहीं था जितना आत्मचिंतन, मनन और शास्त्रार्थ का था। फिर भी आम जनता शिव और पार्वती के अलावा नगर, ग्राम और स्थान के देवी-देवताओं की प्रार्थना करते थे।

देश में सबसे प्राचीन शक्तिपीठों और ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है। प्राचीन काल में यक्ष, नाग, शिव, दुर्गा, भैरव, इंद्र और विष्णु की पूजा और प्रार्थना का प्रचलन था। रामायण काल में मंदिर होते थे इसके प्रमाण हैं। राम का काल आज से 7 हजार 200 वर्ष पूर्व था अर्थात 5114 ईस्वी पूर्व।

हिन्दू मंदिरों को खासकर बौद्ध, चाणक्य और गुप्तकाल में भव्यता प्रदान की जाने लगी और जो प्राचीन मंदिर थे उनका पुन:निर्माण किया गया। ये सभी मंदिर ज्योतिष, वास्तु और धर्म के नियमों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। अधिकतर मंदिर कर्क रेखा या नक्षत्रों के ठीक ऊपर बनाए गए थे। उनमें से भी एक ही काल में बनाए गए सभी मंदिर एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। प्राचीन मंदिर ऊर्जा और प्रार्थना के केंद्र थे लेकिन आजकल के मंदिर तो पूजा-आरती के केंद्र हैं।

सबसे प्राचीन मंदिर के प्रमाण

राम के काल में सीता द्वारा गौरी पूजा करना इस बात का सबूत है कि उस काल में देवी-देवताओं की पूजा का महत्व था और उनके घर से अलग पूजा स्थल होते थे। इसी प्रकार महाभारत में दो घटनाओं में कृष्ण के साथ रुक्मणी और अर्जुन के साथ सुभद्रा के भागने के समय दोनों ही नायिकाओं द्वारा देवी पूजा के लिए वन में स्थित गौरी माता (माता पार्वती) के मंदिर की चर्चा है। इसके अलावा युद्ध की शुरुआत के पूर्व भी कृष्ण पांडवों के साथ गौरी माता

के स्थल पर जाकर उनसे विजयी होने की प्रार्थना करते हैं।

देश में सबसे प्राचीन शक्तिपीठों और ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है। इन सभी का समय-समय पर जीर्णोद्धार किया गया। प्राचीनकाल में यक्ष, नाग, शिव, दुर्गा, भैरव, इंद्र और विष्णु की पूजा और प्रार्थना का प्रचलन था। बौद्ध और जैन काल के उत्थान के दौर में मंदिरों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा।

मुंडेश्वरी देवी का मंदिर बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल में पवरा पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी स्थापना 108 ईस्वी में हुविष्क के शासनकाल में हुई थी। यहां शिव और पार्वती की पूजा होती है। प्रमाणों के आधार पर इसे देश का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है।

विश्व का सबसे बड़ा हिन्दू मंदिर अब सिर्फ कंबोडिया के अंकोरवाट में ही बचा हुआ है। अंकोर का पुराना नाम 'यशोधरपुर' था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय (1112-53 ई.) के शासनकाल में हुआ था। यह विष्णु मंदिर है जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्राय: शिव मंदिरों का निर्माण किया था।

साउथ अफ्रीका के सुद्वारा नामक एक गुफा में पुरातत्वविदों को महादेव की 6 हजार वर्ष पुरानी शिवलिंग की मूर्ति मिली जिसे कठोर ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इस शिवलिंग को खोजने वाले पुरातत्ववेत्ता हैरान हैं कि यह शिवलिंग यहां अभी तक सुरक्षित कैसे रहा।

सोमनाथ के मंदिर के होने का ऋग्वेद में भी मिलता है इससे यह सिद्ध होता है भारत में मंदिर परंपरा कितनी पुरानी रही है। इतिहासकार मानते हैं कि ऋग्वेद की रचना 7000 से 1500 ईसा पूर्व हई थी अर्थात आज से 9 हजार वर्ष पूर्व। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ई.पू. की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है।

विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। इसका निर्माण 1003-1010 ई. के बीच चोल शासक राजराज चोल 1 ने करवाया था। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़े से बने हैं। यह भव्य मंदिर राजाराज चोल के राज्य के दौरान केवल

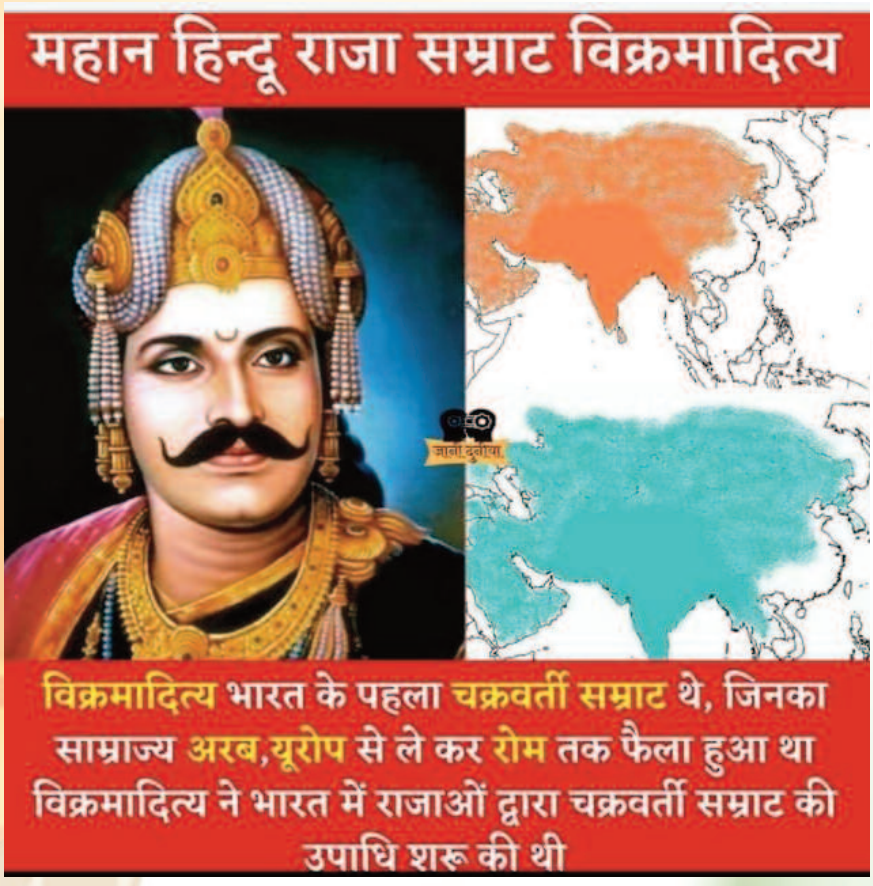
महान हिन्दू राजा सम्राट विक्रमादित्य
विक्रमादित्य भारत के पहला चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका साम्राज्य अरब,यूरोप से ले कर रोम तक फैला हुआ था
विक्रमादित्य ने भारत में राजाओं द्वारा चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि शरू की थी

5 वर्ष की अवधि में (1004 एडी और 1009 एड़ी के दौरान) निर्मित किया गया था।

तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर 10वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक गंतव्य है। रोम या मक्का जैसे धार्मिक स्थलों से भी बड़े इस स्थान पर प्रतिदिन औसतन 30 हजार श्रद्धालु आते हैं और लगभग लाखों रुपए प्रतिदिन चढ़ावा आता है। कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का साया नहीं नजर आता।

विश्व का सबसे पुराना शहर : वाराणसी, जिसे 'बनारस' के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है। भगवान बुद्ध ने 500 बीसी में यहां आगमन किया था और यह आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। इसके बाद अयोध्या और मथुरा का नंबर आता है।

काशी, अयोध्या, मथुरा और आगरा जैसे कई स्थान हैं, जहां पर हिन्दुओं के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाने का प्रमाण मौजूद है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ताजमहल पहले तेजो महालय था जिसमें शिवलिंग स्थापित था।

दक्षिण भारत में ज्यादातर मंदिरों का अस्तित्व बरकरार है। यहां के मंदिरों की स्थापत्य कला और वास्तुशिल्प अद्भुत है। दक्षिण में रामेश्वरम में भगवान राम द्वारा भगवान शिव के मंदिर की स्थापना का जिक्र रामायण में मिलता है।

पिरामिडनुमा होते हैं मंदिर : प्राचीन काल से ही किसी भी धर्म के लोग सामूहिक रूप से एक ऐसे स्थान पर प्रार्थना करते रहे हैं, जहां पूर्ण रूप से ध्यान लगा सकें, मन एकाग्र हो पाए या ईश्वर के प्रति समर्पण भाव व्यक्त किया जाए इसीलिए मंदिर निर्माण में वास्तु का बहुत ध्यान रखा जाता है। यदि हम भारत के प्राचीन मंदिरों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सभी का वास्तुशिल्प बहुत सुदृढ़ था। जहां जाकर आज भी शांति मिलती है। यदि आप प्राचीन काल के

मंदिरों की रचना देखेंगे तो जानेंगे कि सभी कुछ-कुछ पिरामिडनुमा आकार के होते थे। शुरुआत से ही हमारे धर्मवेत्ताओं ने मंदिर की रचना पिरामिड आकार की ही सोची है। ऋषि-मुनियों की कुटिया भी उसी आकार की होती थी। हमारे प्राचीन मकानों की छतें भी कुछ इसी तरह की होती थीं। बाद में रोमन, चीन, अरब और यूनानी वास्तुकला के प्रभाव के चलते मंदिरों के वास्तु में परिवर्तन होता रहा।मंदिर पिरामिडनुमा और पूर्व, उत्तर या ईशान मुखी होता है। कई मंदिर पश्चिम, दक्षिण, आग्नेय या नैऋत्यमुखी भी होते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें मंदिर कह सकते हैं? वे या तो शिवालय होंगे या फिर समाधि स्थल, शक्तिपीठ या अन्य कोई पूजास्थल। मंदिर के मुख्यत: उत्तर या ईशान मुखी होने के पीछे कारण यह है कि ईशान से आने वाली ऊर्जा का प्रभाव ध्यान-प्रार्थना के लिए अति उत्तम माहौल निर्मित करता है। मंदिर पूर्वमुखी भी हो सकता है किंतु फिर उसके द्वार और गुंबद की रचना पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्राचीन मंदिर ध्यान या प्रार्थना के लिए होते थे। उन मंदिर के स्तंभों या दीवारों पर ही मूर्तियां आवेष्टित की जाती थीं। मंदिरों में पूजा-पाठ नहीं होता था। यदि आप खजुराहो, अजंता-एलोरा, कोणार्क या दक्षिण के प्राचीन मंदिरों की रचना देखेंगे तो जान जाएंगे कि मंदिर किस तरह के होते हैं। ध्यान या प्रार्थना करने वाली पूरी जमात जब खत्म हो गई है तो इन जैसे मंदिरों पर पूजा-पाठ का प्रचलन बढ़ा। पूजा-पाठ के प्रचलन से मध्यकाल के अंत में मनमाने मंदिर बने। मनमाने मंदिर से मनमानी पूजा-आरती आदि कर्मकांडों का जन्म हुआ, जो वेदसम्मत नहीं माने जा सकते।

मंदिर की घंटी : मंदिर में घंटी लगाने का प्रचलन भी बहुत प्राचीन काल से शुरू हो चुका था। इसका प्रमाण कई प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां, भित्ति चित्र आदि से ज्ञात हो सकता है। घंटी लगाने के दो कारण थे- पहला घंटी बजाकर सभी को प्रार्थना के लिए बुलाना और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब जो नाद था, घंटी की ध्वनि को उसी नाद का प्रतीक माना जाता है। यही नाद ओंकार के उच्चारण से भी जाग्रत होता है। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है, वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियां हटती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। प्रात: और संध्या को ही घंटी बजाने का नियम है, वह भी लयपूर्ण। घंटी या घंटे को काल का प्रतीक भी माना गया है।

ऊर्जा के केंद्र मंदिर : अनेक प्राचीन मंदिर ऐसे स्थलों या पर्वतों पर बनाए गए हैं, जहां से चुंबकीय तरंगें घनी होकर गुजरती हैं। इस तरह के स्थानों पर बने मंदिरों में प्रतिमाएं ऐसी जगह रखी जाती थीं, जहां चुंबकत्व का प्रभाव ज्यादा हो। यहीं पर तांबे का छत्र और तांबे के पाट रखे होते थे और आज भी कुछ स्थानों पर रखे हैं। तांबा बिजली और चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाकर इस मूर्ति की घड़ी के चलने की दिशा में परिक्रमा करता है, वह इस एनर्जी को अवशोषित कर लेता है। इससे उसको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। हालांकि यह एक धीमी प्रक्रिया मानी जा सकती है लेकिन इससे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगें व ध्वनि तरंगें व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं। ये परावर्तित किरण तरंगें मानव शरीर आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती हैं। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे-धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। पुराने मंदिर सभी धरती के धनात्मक (पॉजिटिव) ऊर्जा के केंद्र हैं। ये मंदिर आकाशीय ऊर्जा के केंद्र में स्थित हैं।

मंदिर-रामायण काल में मंदिर होते थे, इसके प्रमाण हैं। राम का काल आज से 7129 वर्ष पूर्व था अर्थात 5114 ईस्वी पूर्व। राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। इसका मतलब यह कि उनके काल से ही शिवलिंग की पूजा की परंपरा रही है। राम के काल में सीता द्वारा गौरी पूजा करना इस बात का सबूत है कि उस काल में देवी-देवताओं की पूजा का महत्व था और उनके घर से अलग पूजा स्थल होते थे। देश में सबसे प्राचीन शक्तिपीठों और ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है। इन सभी का समय-समय पर जीर्णोद्धार किया गया। प्राचीन काल में यक्ष, नाग, शिव, दुर्गा, भैरव, इंद्र और विष्णु की पूजा और प्रार्थना का प्रचलन था। बौद्ध और जैन काल के उत्थान के दौर में मंदिरों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। विश्व का सबसे बड़ा हिन्दू मंदिर अब सिर्फ कंबोडिया के अंकोरवाट में ही बचा हुआ है। हिन्दू मंदिरों को खासकर बौद्ध, चाणक्य और गुप्तकाल में भव्यता प्रदान की जाने लगी और जो प्राचीन मंदिर थे उनका पुनर्निर्माण किया गया।

मंदिर समय : हिन्दू मंदिर में जाने का समय होता है। सूर्य और तारों से रहित दिन-रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्याकाल माना है। संध्या वंदन को 'संध्योपासना' भी कहते हैं। संधिकाल में ही संध्या वंदना की जाती है। वैसे संधि 5 वक्त (समय) की होती है, लेकिन प्रात:काल और संध्याकाल- उक्त 2 समय की संधि प्रमुख है अर्थात सूर्य उदय और अस्त के समय। इस समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। दोपहर 12 से अपराह्न 4 बजे तक मंदिर में जाना, पूजा, आरती और प्रार्थना आदि करना निषेध माना गया है अर्थात प्रातकाल से 11 बजे के पूर्व मंदिर होकर आ जाएं या फिर अपराह्न काल में 4 बजे के बाद मंदिर जाएं।

भारत में 7वीं सदी के प्रारंभ में मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। यहां उन्होंने सोना-चांदी आदि दौलत लूटने और इस्लामिक शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से आक्रमण किए। 7वीं से लेकर 16वीं सदी तक लगातार हजारों हिन्दू, जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ा और लूटा गया। उनमें से कुछ ऐसे थे, जो कि विशालतम होने के साथ ही भारतीय अस्मिता, पहचान और सम्मान से जुड़े थे। ■

सीएजी रिपोर्ट : नोएडा में जमीन अलॉटमेंट के नाम पर बड़ा खेल

● अनुज अग्रवाल, अध्यक्ष, मौलिक भारत

मौलिक भारत संस्था ने सन 2014-15 में उजागर किया था यह खेल

क्या इतना बड़ा खेल सिर्फ अफसरों नें कर दिया ? पूर्व सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है ? क्या राजनेताओं के कोई साक्ष्य नहीं मिले आडिट में, या फिर यह भी एक राजनीतिक गुगली ही साबित होने वाली है कोयला घोटाला की तरह ?

चुनावी माहौल और सीएजी रिपोर्ट क्या एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते है ? वर्षो के इंतजार के बाद आखिर मौसम ने करवट ली है और सीएजी रिपोर्ट जिसका इंतजार था वह लोगों के सामने है। सीएजी नें 52 हजार करोड़ की मामूली सी हेराफेरी अपनी रिपोर्ट में बताया है। जानकारों का यह भी मानना है कि यह अगर आज के हिसाब से आडिट किया जाता तो लाखो करोड़ का होता। खैर देर आये दुरुस्त आये हम सबको मिलकर इसके लिए सरकार का एहसानमंद होना चाहिए कि चुनाव के समय में सरकार ने ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है। हालांकि जानकार मानते है कि यह एक चुनावी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नही। क्योंकि चुनावी मौसम है और विपक्ष को इस हथियार के माध्यम से कमजोर किये जा सकते है। जैसा कि देखने में भी आया है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता खासकर अखिलेश यादव के करीबियों पर लगातार आयकर विभाग की छापेमारी की जा रही है। हालांकि नेताओं के पास बचने के लिए एक इमोशनल हथियार भी होते है, हर बार जब भी सरकार कारवाई करे उसे चुनावी स्टंट और बताकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का सूर अलापने लगते है। देश भर में हमेशा चुनाव ही चलते रहते है तो क्या नेताओं पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।

एक बार तो ऐसा भी लगता है कि सरकार नींद से जागकर हड़बड़ाहट में कदम उठा रही है या फिर इसी का इंतजार था ? हाल ही में रेरा को पावर दिया गया है। रेरा अब वसूली करने में सक्षम है लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा लेकिन सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत करना चाहिए। हालांकि अभी फिलहाल चुनावी मौसम है और जो कदम सरकार नें आज उठाए है उसे 6 महीने पहले ही करना चाहिए था।

मौलिक भारत हाल ही में एक मौलिक जन संवाद नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें जिला गौतमबुद्धनगर के तीनों प्राधिकरण में 20 लाख करोड़ से ज्यादा की भूमि घोटाला होने का आरोप लगाया। रेरा को दंत विहीन बताते हुए कुछ पावर देने की मांग की गई। भूमि-घोटाले से जुड़े लोगों सख्त कार्यवाही करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। घर खरीदारों को जल्द से जल्द उनका घर देने की मांग किया। लगातार शहर के समाचार पत्रों में मामले सुर्खियों बटोरती रही है लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद अब नोएडा के वरिष्ठ नागरिक अनुज अग्रवाल, अध्यक्ष, मौलिक भारत व अधिवक्ता अनिल के गर्ग नें सरकार से कुछ सवाल पूछे है और सुझाव भी दिये है -

क्या प्रदेश सरकार मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश में है या फिर घोटाले के लिए दोषी राजनेता, अधिकारी, नौकरशाहों पर कोई कार्यवाही करने की मंशा भी रखती है, क्योंकि यह रिपोर्ट ऐसे समय में आये है जिसके कुछ दिनों बाद ही चुनावी आचार संहिता लागू होने जा रही है और सरकार के पास में एक बहाना होगा कि हम कार्यवाही कैसे करे? इसलिए जरूरी है कि कैग रिपोर्ट को माननीय उच्च न्यायालय की एक एसआईटी बनाकर उसके निगरानी में दोषियों पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

सभी अधिकारियों नौकरशाही, राजनेताओं से पिछले 20 वर्षों में अर्जित संपत्ति की घोषणा का शपथ पत्र लेने की सबसे अधिक आवश्यकता है, और उनके परिवारों द्वारा अर्जित सभी संपत्तियां भी। इसके बाद इन अधिकारियों और नौकरशाही और समाचार युवा ईमानदार, समर्पित योग्य पेशेवरों की नियुक्ति के लिए वीआरएस और छंटनी प्रक्रिया की आवश्यकता है जो हमारे रोजगार बाजार में पारिश्रमिक के आधे में उपलब्ध हैं। एनसीएलटी की कार्यवाही के माध्यम से विलफुल डिफॉल्टर बिल्डर्स से सभी परियोजनाओं को तुरंत लेने के लिए निर्दोष गृह खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए भारी भूमि बकाया वसूलने के लिए। डिफॉल्टर बिल्डर्स के खिलाफ सीआईआरपी दाखिल करने के बाद। उत्तर प्रदेश के रुपये की चुकता पूंजी के साथ संकल्प फाइल करने के लिए एक जीबी नगर संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का गठन किया जाना चाहिए। प्रत्येक परियोजना की 'बुनियादी समाधान योजना' प्रस्तुत करने और उसे लेने के लिए 25000 करोड़। अब उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले और अब सीएजी ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों का प्रकाशन, संभवत: केवल एक प्रोपेगैंडा और आई वॉश रणनीति है लेकिन अधिकारियों और सरकार के सामने कोई समाधान नहीं है। क्या किसी राजनीतिक खेल की संभावना है

सीएजी रिपोर्ट संक्षिप्त में

नोएडा फार्म हाउस घोटाला

जब कार्यवाही ही नहीं होती तो सीएजी जांच का क्या मतलब

बड़ी बड़ी मछलियों के नाम सहित नोएडा फार्म हाउस घोटाले को मौलिक भारत संस्था ने सन 2014-15 में उजागर किया था और इसके बाद मौलिक भारत ने लगातार राज्य व केंद्र सरकार से इस घोटाले की जांच कर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की थी। मायावती सरकार के इस घोटाले की जांच अखिलेश सरकार करवाने से बचती रही और योगी सरकार ने सीएजी से नोएडा प्राधिकरण के पिछले 10-15 सालों के अकाउंट ऑडिट करवाए तो हजारों करोड़ की अनियमितता व घोटाले सामने आए और फार्म हाउस घोटाले की बाद भी उसमें सामने आयी है।सीएजी रिपोर्ट के अनुसार इस खेल में सरकार को 2833 करोड़ रुपयों के राजस्व की हानि हुई। मगर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पर सरकार न तो कोई कार्यवाही करती हैं और न ही किसी को सजा मिलती है। तो फिर क्या यह भी आंखों में धूल झोंकने वाली ही मानी जानी चाहिए। मौलिक भारत के अध्यक्ष अनुज अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार सीएजी जांच को आधार बना हाईकोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी बनाए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर सभी आवंटन रद्द करे, दोषी प्राधिकरण कर्मियों, राजनेताओं व आबंटियो के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही कर सख़्त से सख़्त सजा दे व सरकार को हुई राजस्व की हानि को इनसे वसूला जाए।

नोएडा में जमीन अलॉटमेंट के नाम पर अफसरों ने कैसे किया बड़ा खेल

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी ने जनहित और नैतिकता को ताक पर रख दिया। 113 में से 71 हाउजिंग प्रॉजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं मगर बिल्डर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने नोएडा में जमीन की बंदरबांट का खुलासा किया है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों और बिल्डर्स ने मिलीभगत से जमीन अधिग्रहण, आवंटन और मंजूरियों में नियमों की जमकर अनदेखी की। सीएजी का आंकलन है अधिकारियों की करतूतों के चलते नोएडा अथॉरिटी को 52,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने इसे रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए स्वर्ग बना दिया क्योंकि केवल 18% जमीन का इस्तेमाल ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हुआ।

'अधूरे प्रोजेक्ट्स वाले बिल्डर्स पर कोई एक्शन नहीं'

नोएडा में हजारों फ्लैट्स के मालिक पजेशन का इंतजार कर रहे हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रस्तावित 1.3 लाख ग्रुप हाउजिंग फ्लैट्स में से 44% (57,000) के पास ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट्स नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, नोएडा के 113 में से 71 हाउजिंग प्रॉजेक्ट्स भुगतान की अवधि पूरी होने के बावजूद अधूरे पड़े हैं। इनके बिल्डर्स के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की।

सीएजी ने किया 13 सालों का ऑडिट

सीएजी ने दिल्ली से सटे नोएडा का पहला बार परफॉर्मेंस ऑडिट किया है। यह ऑडिट 2005-06 से लेकर 2017-18 की अवधि के बीच का है। अपने ऑडिट में सीएजी ने पाया कि नोएडा ने जमीनों की प्लानिंग, अधिग्रहण, कीमत तय करने और आवंटन में कई गड़बड़ियां कीं। सीएजी ने नोएडा बोर्ड, उसके प्रबंधन और अधिकारियों की नाकामी को उजागर किया है। ग्रेटर नोएडा पर भी सीएजी की ऐसी ही एक रिपोर्ट जल्द विधानसभा में रखी जाएगी।

नोएडा में जमीनों की बंदरबाट का खुलासा करती सीएजी की यह रिपोर्ट अगले साल होने प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले सियासी पारा चढ़ा सकती है। रिपोर्ट में योगी आदित्यनाथ सरकार से पहले की सरकारों के कामकाज का ऑडिट है।

नोएडा अधिकारियों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दीं

मौलिक भारत के सुझाव पर यूपी सरकार ने दी रेरा को न्यायिक शक्तियाँ

मित्रों,जैसा कि आपको मालूम है कि मौलिक भारत की पहल पर नेताओं-सरकारी बाबुओं-बिल्डरों के गठजोड़ के खिलाफ व आम निवेशकों के हित में समस्याओं के समाधान के लिए कुछ रचनात्मक व सकारात्मक उपाय ढूंढने के लिए दिल्ली एनसीआर की प्रमुख संस्थाओं (गौतमबुद्ध नगर सहित दिल्ली एनसीआर के स्ट्रेस प्रोजेक्ट (लटके हुए बिल्डर प्रोजेक्ट) से जुड़े निवेशकों के संगठनों जो बायर्स के हितों के लिए प्रभावी कार्य कर रहीं हैं) व अन्य प्रमुख सामाजिक संस्थाओ के अनुभव व सुझावों को साझा करने व सम्मिलित कार्ययोजना बनाने के लिए 26/9/2021 , रविवार को अग्रसेन भवन, नोएडा में मौलिक जन संवाद का आयोजन किया था। इस जनसंवाद व उसके बाद के मंथन के उपरांत गौतमबुद्ध नगर सहित दिल्ली एनसीआर के स्ट्रेस प्रोजेक्ट (लटके हुए बिल्डर प्रोजेक्ट) की समस्या को सुलझाने के लिए मौलिक भारत ने अनेक सुझाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजे थे। जिनमे सबसे महत्वपूर्ण सुझाव RERA को न्यायिक अधिकार देने का था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे इस सुझाव को यूपी सरकार ने मान लिया है और RERA को कल लखनऊ में आयोजित केबिनेट की बैठक न्यायिक शक्तियां दे दी हैं। संस्था इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की का हार्दिक आभार प्रकट करती है।

मौलिक भारत के सुझाव पर यूपी सरकार ने दी रेरा को न्यायिक शक्तियाँ

मौलिक भारत की पहल पर नेताओं-सरकारी बाबुओं- बिल्डरों के गठजोड़ के खिलाफ व आम निवेशकों के हित में समस्याओं के समाधान के लिए कुछ रचनात्मक व सकारात्मक उपाय ढूंढने के लिए दिल्ली एनसीआर की प्रमुख संस्थाओं (गौतमबुद्ध नगर सहित दिल्ली एनसीआर के स्ट्रेस प्रोजेक्ट (लटके हुए बिल्डर प्रोजेक्ट) से जुड़े निवेशकों के संगठनों जो बायर्स के हितों के लिए प्रभावी कार्य कर रहीं हैं) व अन्य प्रमुख सामाजिक संस्थाओ के अनुभव व सुझावों को साझा करने व सम्मिलित कार्ययोजना बनाने के लिए 26/9/2021 , रविवार को अग्रसेन भवन, नोएडा में *मौलिक जन संवाद*का आयोजन किया था। इस जनसंवाद व उसके बाद के मंथन के उपरांत गौतमबुद्ध नगर सहित दिल्ली एनसीआर के स्ट्रेस प्रोजेक्ट (लटके हुए बिल्डर प्रोजेक्ट) की समस्या को सुलझाने के लिए मौलिक भारत ने अनेक सुझाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजे थे। जिनमे सबसे महत्वपूर्ण सुझाव पश्चप्र को न्यायिक अधिकार देने का था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे इस सुझाव को यूपी सरकार ने मान लिया है और पश्चप्र को कल लखनऊ में आयोजित केबिनेट की बैठक न्यायिक शक्तियाँ दे दी हैं। संस्था इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की का हार्दिक आभार प्रकट करती है।

नोएडा अथॉरिटी ने 'इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट' को वजह बताकर 80% भूमि 'तात्कालिकता खंड' के तहत अधिग्रहित की। अंतिम प्रस्ताव जमा करने में 11 महीने से लेकर चार साल तक की देरी हुई। सीएजी ने केवल जमीनों के आवंटन से ही 14,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट बताती है कि कैसे नोएडा के अधिकारियों ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को तोड़ा-मरोड़ा। बिल्डर्स का बकाया 14,000 करोड़ की अलॉटमेंट वैल्यू के मुकाबले 18,633 करोड़ तक पहुंच गया, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया।

आधार कार्ड को अनिवार्य करने के लिए मौलिक भारत सन 2015 से ही सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग व भारत सरकार को प्रतिवेदन भेज रहा है। आज देश में 99% से अधिक नागरिकों को आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं किंतु फिर भी 'निजता के उल्लंघन' के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को प्रत्येक सेवा व लेन देन में अनिवार्य नहीं होने दे रहा है। इसीलिए भ्रष्टाचारी व कालेधन कमाने वाले मौज कर रहें हैं क्योंकि उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको संरक्षण दे रहा है। मौलिक भारत इस दुरभिसंधि को समाप्त करने की मांग करता है।

वैसे समझ में नहीं आता कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ने में सुप्रीम कोर्ट के मिलार्डस को निजता का हनन होता हुआ कैसे दिखाई पड़ता है ? मिलार्डस क्या स्पष्ट करेंगे कि क्या फर्जी और दोहरा मतदान को आधार से वोटर कार्ड को के जोड़ने से रोकना ऐसे अपराधी की निजता का हनन है ? क्या फर्जी और दोहरे मतदान को रोकना गैरकानूनी है ? बताइए मिलार्डस ?

उधर विपक्षी दलों का इस कार्य का विरोध करना लाजिमी है क्योंकि इनमें से कुछ की सरकार तो बांग्लादेशी और रोहंगिया घुसपैठियों की फर्जी वोटिंग से बनीं हैं ।

केंद्र सरकार ने निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर चुनाव सुधारों को आगे बढ़ाने का फैसला कर एक आवश्यक काम किया है। इनमें सबसे बड़ा सुधार मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने का है।

हालांकि फिलहाल यह स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा, लेकिन उम्मीद की जाती है कि आगे चलकर सभी मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने में सफलता मिलेगी।

अभी ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे निजता के अधिकार में हनन होने की बात कही थी।

उचित होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस दृष्टिकोण पर नए सिरे से विचार करे।

बेहतर होगा कि निर्वाचन आयोग और भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध करें कि वह मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया को निजता के अधिकार में हनन के रूप में न देखे। आखिर जब पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि आधार से जुड़ सकते हैं तो फिर मतदाता पहचान पत्र के साथ भी ऐसा करने में क्या हर्ज है ?

नि:संदेह निजता के अधिकार का अपना महत्व है, लेकिन किसी भी अधिकार की तरह वह भी असीम नहीं हो सकता। विडंबना यह है कि अपने देश में एक समूह ऐसा है, जो हर सुधार का विरोध करता है। ऐसे ही एक समूह ने यह माहौल बना रखा है कि यदि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ा जाता है तो इससे लोगों की निजता का हनन होगा। यह और कुछ नहीं, एक जरूरी सुधार की राह में अड़ंगा लगाने वाला रवैया है।

दुर्भाग्य यह है कि कुछ राजनीतिक दल भी यही रवैया अपनाए हुए हैं। ऐसे दलों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने के जो पायलट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, वे बेहद सफल हैं और उनके जरिये फर्जी एवं दोहरे मतदाता पहचान पत्रों की समस्या से पार पाने में मदद मिली है। इसका अर्थ है कि इन पायलट प्रोजेक्ट में शामिल लोगों को वैसी कोई समस्या नहीं, जिसकी ओर सुप्रीम कोर्ट ने इंगित किया था।

इससे भी कोई अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि देश में फर्जी या दोहरे मतदाता पहचान पत्रों की जो समस्या है, वह चुनावों की निष्पक्षता पर चोट करती है।

यह अच्छा हुआ कि सरकार ने निर्वाचन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी, लेकिन अभी चुनाव सुधारों को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसकी पूर्ति तभी संभव है, जब सत्तापक्ष और विपक्ष में सहमति कायम होगी।

सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कम से कम संगीन किस्म के आपराधिक अतीत वालों को तो चुनाव लड़ने से रोकने पर तो सहमति बननी ही चाहिए। ■

पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर

भारत में गहरा सकता है जल संकट

जलवायु परिवर्तन के चलते जिस असाधारण तेजी से हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके चलते भारत सहित एशिया के कई देशों में जल संकट और गहरा सकता है

हिमालय के ग्लेशियर असाधारण तौर पर पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके चलते भारत सहित एशिया के कई देशों में जल संकट और गहरा सकता है। यह जानकारी हाल ही में लीड्स विश्वविद्यालय द्वारा किए अध्ययन में सामने आई है, जोकि जर्नल साइंटिफिक रिपोर्टस में प्रकाशित हुआ है।

अनुमान है कि जिस तेजी से यह ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके चलते गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के लिए संकट पैदा हो सकता है। इसके कारण इन नदियों पर निर्भर करोड़ों लोगों की समस्याएं पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी।

शोध के मुताबिक हाल के दशकों में हिमालय के ग्लेशियर जिस तेजी से पिघल रहे हैं उसकी रफ्तार 400-700 साल पहले हुई ग्लेशियर विस्तार की घटना जिसे हिमयुग या 'लिटिल आइस एज' कहा जाता है उसके मुकाबले दस गुना ज्यादा है।

इस बारे में जानकारी देते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स और इस शोध से जुड़े शोधकर्ता डॉ जोनाथन कैरविक ने जानकारी दी है कि निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पिछली शताब्दियों की तुलना में हिमालय के ग्लेशियर औसतन 10 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। उनके अनुसार नुकसान की यह दर पिछले कुछ दशकों में काफी बढ़ गई है, जोकि इस बात का सबूत है इसके पीछे हम इंसानों के कारण जलवायु में आ रहा बदलाव जिम्मेवार है।

देखा जाए तो अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद हिमालय के ग्लेशियरों में सबसे ज्यादा बर्फ जमा है। यही वजह है कि इसे अक्सर दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। अपने इस शोध में शोधकर्ताओं ने उपग्रहों से प्राप्त चित्रों और डिजिटल तकनीकों की मदद से आज से करीब 400 से 700 साल पहले हिमालय में मौजूद रहे 14,798 ग्लेशियरों की रुपरेखा तैयार की है।

पहले के मुकाबले 40 फीसदी सिकुड़ चुके हैं ग्लेशियर

साथ ही बर्फ की सतह के मॉडल का पुनर्निर्माण किया है, जिससे उन ग्लेशियरों की लम्बाई और उनमें जमा बर्फ का अनुमान लगाया जा सके और यह जाना जा सके की तब से लेकर अब तक इन ग्लेशियरों से कितनी बर्फ किस रफ़्तार से पिघल चुकी है।

मॉडल से पता चला है कि आज हम जो ग्लेशियर देख रहे हैं, उनका क्षेत्रफल पहले के मुकाबले 40 फीसदी सिकुड़ गया है। जो कभी अपने शिखर पर 28,000 वर्ग किलोमीटर से घटकर 19,600 वर्ग किलोमीटर में सीमित रह गए हैं।

इतना ही नहीं अनुमान है कि इस अवधि के दौरान यह ग्लेशियर 586 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ को खो चुके हैं। यह इतनी बर्फ है जितनी आज मध्य यूरोपीय आल्प्स, काकेशस और स्कैंडिनेविया में संयुक्त रूप से मौजूद है।

ठीक नहीं है, मौसम का मिजाज

उत्तर भारत में पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और ठंडी हवाओं के चलने से शीत लहर का प्रकोप देखने को मिला है। देश के अन्य हिस्सों जम्मू-कश्मीर हो, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, भीषण ठंड से लोग बेजार हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान तीन और पांच सेंटीग्रेड से भी नीचे गिरने से जन-जीवन प्रभावित हुआ है।

इस बार ठंड ने 1965 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसके जनवरी के पहले पखवाड़े तक ऐसे ही रहने का अनुमान है। देश की राजधानी दिल्ली ने तो बीते 15 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया । यहां पारा 4.6 डिग्री पर उतर गया। इस स्थिति का अहम कारण जलवायु परिवर्तन के चलते प्रशांत महासागर में हुए मौसम के बदलाव की वजह से ला नीना का प्रभाव है। दरअसल, मौसम के चक्र में प्रशांत महासागर की भूमिका बेहद अहम है। ईएनएसओ (अल नीनो साउथ ओसिलेशन) प्रशांत महासागर की सतह पर पानी और हवा में असामान्य बदलाव लाता है। इसका असर पूरी दुनिया के वर्षा चक्र, तापमान और वायु संचरण प्रणाली पर पड़ता है।

जहां ला नीना ईएनएसओ के ठंडे प्रभाव का परिचायक है, वहीं अल नीनो भीषण गर्मी के प्रभाव का प्रतीक है। देखा गया है कि दोनों ही प्रभाव प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सामान्य तापमान में असमानता पैदा करते हैं। ला नीना में प्रशांत महासागर की गर्म पानी की सतह पर हवा पश्चिम की ओर बहती है, नतीजतन गर्म पानी में हलचल होने से ठंडा पानी सतह पर आ जाता है, इससे पूर्वी प्रशांत क्षेत्र सामान्य से काफी ठंडा हो जाता है। ला नीना के चलते सर्दियों में तेजी से हवा बहने पर भूमध्य रेखा और उसके आसपास का पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है। इससे महासागर का तापमान समूची दुनिया के मौसम को प्रभावित कर देता है। इसके कारण कहीं भारी बारिश, कहीं बाढ़, तो कहीं सूखे की स्थिति पैदा होती है।

हमारे देश में पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी के चलते कड़ाके की जानलेवा ठंड इसी ला नीना का परिणाम है। मौसम विभाग और दुनिया के वैज्ञानिक भी इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। जहां तक भारत का सवाल है, मैरीलैंड यूनीवर्सिटी अमेरिका के जलवायु वैज्ञानिक रघु मूर्तुगडे की मानें, तो भारत में समूचे उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के पहाड़ी इलाकों में भीषण ठंड का प्रमुख कारण ला नीना ही है।

भारत में ला नीना का असर सर्दी के मौसम में ही होता है। इसके चलते हवाएं उत्तर-पूर्व के हिस्सों की ओर से बहती हैं। इससे पैदा पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर व दक्षिण में निम्न दबाव बनता है, नतीजतन देश में बारिश और बर्फबारी होती है तथा शीतलहर के प्रकोप में वृद्धि होती है।

इस बार शीतलहर के प्रकोप से आनेवाले 15-20 दिनों तक राहत मिलने के आसार कम हैं। जिसके परिणाम स्वरूप शहरों में प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक स्तर में बढ़ा रहेगा। ऐसे में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। भीषण जानलेवा सर्दी से फसलों के बर्बाद होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। इससे किसान काफी भयभीत हैं।

पारा गिरने और पाला पड़ने से रबी की फसल तबाह हो सकती है, और सब्जियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। पौधों की पत्तियां हरी होने की जगह हल्की भूरी पड़ने लग जायेंगी। टमाटर, गोभी, बैंगन और मिर्च की फसल पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। रोजमर्रा की जरूरतों, खासकर भोजन, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं व स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी, ऊर्जा की खपत बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, धीमी आर्थिक प्रगति की दर और बढ़ती मंहगाई आम जनता की जेब पर भारी पड़ेगी। ऐसी हालत में दूसरे साधनों पर निर्भरता और बढ़ेगी इससे खाद्यान्न तो प्रभावित होगा ही, अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव रोका नहीं जा सकेगा। हमें सचेत रहना चाहिए।

शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि इतनी बर्फ पिघल जाए तो उससे दुनिया भर में समुद्र के जलस्तर में करीब 1.38 मिलीमीटर की वृद्धि हो जाएगी।

जलवायु परिवर्तन की भूमिका

शोध में यह भी सामने आया है कि पूर्वी हिमालय में नेपाल और भूटान में मौजूद ग्लेशियर बड़े पैमाने पर तेजी से पिघल रहे हैं। अध्ययन के मुताबिक संभवत: ऐसा पर्वत श्रृंखला के दोनों किनारों पर भौगोलिक विशेषताओं में अंतर और वातावरण के साथ वो कैसे परस्पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं उसके कारण हो रहा है जिससे मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है।

इसी तरह जिन ग्लेशियरों के किनारे झीलों से मिले हुए हैं वो कहीं ज्यादा तेजी से घट रहे हैं। क्योंकि भूमि की तुलना में झीलों पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव ज्यादा होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक जिस तरह से इन झीलों की संख्या और आकार में वृद्धि हो रही है, वो दर्शाता है कि इन ग्लेशियरों को बड़े पैमाने पर, निरंतर तेजी से नुकसान हो रहा है।

इसी तरह जिन ग्लेशियरों में प्राकृतिक तौर पर मलबे की मात्रा ज्यादा है वो भी तेजी से पिघल रहे हैं। अनुमान है कि कुल ग्लेशियरों का केवल 7.5 फीसदी होने के बावजूद उन्होंने ग्लेशियरों को होने वाली कुल हानि में करीब 46.5 फीसदी का योगदान दिया है।

जर्नल द क्रायोस्फीयर में प्रकाशित एक अन्य शोध से पता चला है कि दुनिया भर में जमा बर्फ के पिघलने की रफ्तार तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती जा रही है। 2017 में ग्लेशियरों और अन्य जगहों पर जमा यह बर्फ 1990 की तुलना में 65 फीसदी ज्यादा तेजी से पिघल रही थी। अनुमान है कि 1994 से 2017 के बीच 28 लाख करोड़ टन बर्फ पिघल चुकी है।

इसी तरह अंतराष्ट्रीय जर्नल नेचर में छपे एक शोध के मुताबिक वैश्विक स्तर पर ग्लेशियरों में जमा बर्फ के पिघलने की दर 2015 से 2019 के बीच रिकॉर्ड 29,800 करोड़ टन प्रतिवर्ष पर पहुंच गई थी, जिसका मतलब है कि पिछले 20 वर्षों में बर्फ के खोने की दर में 31.3 फीसदी का इजाफा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तेजी से यह ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसका असर करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ेगा। अनुमान है कि इसके चलते अगले तीन दशकों में करीब 100 करोड़ लोग पीने के पानी और खाद्य की कमी का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे। ■

ललित गर्ग

बच्चों पर आभासी दुनिया के तिलिस्मी संसार का कहर

आजकल ज्यादातर बच्चों को मूड स्विंग की समस्या रहती है, वे असंतुलित मानसिकता से ग्रस्त होते जा रहे हैं। वे पल भर में खुश, तो दूसरे ही पल चिड़चिड़े, तनावग्रस्त व मायूस हो जाते हैं। दरअसल, मूड स्विंग का एक बहुत बड़ा कारण मोबाइल का अधिक इस्तेमाल है। जो बच्चे स्मार्टफोन पर हमेशा अलग-अलग तरह की एप्लिकेशन ट्राई करने में बिजी रहते हैं। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के कारण स्कूली शिक्षा ऑनलाइन हुई तो अभिभावकों ने छोटे-छोटे बच्चों को स्मार्टफोन थमा दिये और वे इंटरनेट की दुनिया एवं इंटरनेट गेमों से जुड़ गये। ये गेम एवं इंटरनेट की बढ़ती लत बच्चों में अनेक विसंगतियों, मानसिक असंतुलन, विकारों एवं अस्वास्थ्य के पनपने का कारण बनी है, यह आदत बच्चों को एकाकीपन की ओर ले जाती है। बच्चे धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई और सामाजिक हकीकत से दूर होकर आभासी दुनिया के तिलिस्मी संसार में रमते जा रहे हैं। यह नये बनते समाज के लिये बहुत ही चिन्ता का विषय है।

इसी चिन्ता के मद्देनजर साइबर मीडिया रिसर्च (सी.एम.आर.) ने 'स्मार्टफोन और मानव संबंध' विषय पर सर्वेक्षण करके एक नई रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बच्चों के जीवन से जुड़े अनेक चौकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। इसमें रेखांकित किया गया है कि स्मार्टफोन पर बिताया जाने वाला औसत समय कोविड के बाद के युग में खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, क्योंकि पूर्व कोविड अवधि से स्मार्टफोन पर बिताए गए समय में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां 85 प्रतिशत माता-पिता महसूस करते हैं कि उनके बच्चों को सामाजिक परिवेश में अन्य बच्चों के साथ घुलना-मिलना मुश्किल है और कुल मिलाकर बाहरी अनुभव कठिन है। मोबाइल पर कुल निर्भरता बढ़ गई है। लोग अपने फोन का इस्तेमाल खाना खाते समय 70 फीसदी, लिविंग रूम में 72 फीसदी और यहां तक कि परिवार के साथ बैठकर 75 फीसदी उपयोग करते हैं। शीर्ष 8 भारतीय शहर जिनमें नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि शामिल हैं, यह सर्वेक्षण किया गया है।

दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बच्चों और परिवार के साथ बिताया जाने वाला समय सामान्य रूप से बढ़ गया है, लेकिन बिताए गए समय की गुणवत्ता बिगड़ गई है। कम से कम अस्सी प्रतिशत स्मार्टफोन उपयोगकर्ता अपने फोन पर तब भी होते हैं, जब वे अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे होते हैं और 75 प्रतिशत अपने स्मार्टफोन से विचलित होने और बच्चों के साथ रहते हुए भी ध्यान नहीं देने की बात स्वीकार करते हैं। कम से कम 69 प्रतिशत माता-पिता का मानना है कि जब वे अपने स्मार्टफोन में डूबे रहते हैं तो वे अपने बच्चों, परिवेश पर ध्यान नहीं देते हैं और 74 प्रतिशत मानते हैं कि जब उनके बच्चे उनसे कुछ पूछते हैं तो वे चिढ़ जाते हैं।

आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जरूरत बन गया है। एक तरफ

जहां इसके काफी फायदे हैं, वहीं इससे कुछ नुकसान भी हैं। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन को घातक बताया जाता है। रोजाना 50 मिनट तक लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करने से दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। जिससे कैंसर एवं ब्रेन ट्यूमर जैसा खतरनाक रोग होने की संभावना रहती है। हालांकि, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी तक किसी भी रिसर्च में यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि किसी व्यक्ति को कैंसर या ब्रेन ट्यूमर या कोई दूसरी घातक बीमारी मोबाइल रेडिएशन के कारण हुई हो।

आजकल स्मार्टफोन तो बच्चों का खिलौना हो गया है, दिनोंदिन हाईटेक होती टेक्नोलॉजी और उसकी आसान उपलब्धता के कारण बच्चों के पढ़ने का तरीका भी बदल गया है। अब वे हमारी और आपकी तरह पढ़ने के लिए दिमाग ज्यादा खर्च नहीं करते, क्योंकि इंटरनेट के कारण एक क्लिक पर ही उन्हें सारी जानकारी मिल जाती है, तो उन्हें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैथ्स के कठिन से कठिन सवाल को मोबाइल, जो अब मिनी कॉम्प्यूटर बन गया है कि मदद से सॉल्व कर देते हैं। अब उन्हें रफ पेपर पर गुणा-भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चे नॉर्मल तरीके से पढ़ना भूल गए हैं। साधारण-सी कैलकुलेशन भी वो बिना कैलकुलेटर के नहीं कर पाते।

बच्चों के हाथ में मोबाइल होने के कारण उनका दिमाग हर समय उसी में लगा रहता है। कभी गेम्स खेलने, कभी सोशल साइट्स, तो कभी कुछ सर्च करने में यानी उनके दिमाग को आराम नहीं मिल पाता। दिमाग को शांति व सुकून न मिल पाने के कारण उनका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। कभी किसी के साथ साधारण बातचीत के दौरान भी वो उग्र व चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे बच्चे किसी दूसरे के साथ जल्दी घुलमिल नहीं पाते, दूसरों का साथ उन्हें असहज कर देता है। बच्चें हमेशा अकेले रहना ही पसंद करते हैं। बच्चों के दिमाग में हमेशा मोबाइल ही घूमता रहता है, जैसे- फलां गेम में नेक्स्ट लेवल तक कैसे पहुंचा जाए ? यदि सोशल साइट पर है, तो नया क्या अपडेट है ? आदि। इस तरह की बातें दिमाग में घूमते रहने के कारण वो अपनी पढ़ाई

पर ध्यान नहीं दे पातें। जाहिर है ऐसे में उन्हें पैरेंट्स व टीचर से डांट सुननी पड़ती है। बार-बार घर व स्कूल में शर्मिंदा किए जाने के कारण वो धीरे-धीरे तनावग्रस्त भी होने लगते हैं। नतीजतन पढ़ाई और बाकी चीजों में वो पिछड़ते चले जाते हैं। आभासी दुनिया में खोए रहने के कारण उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, जो भविष्य में उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।

गतदिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि वह बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत से बचाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने पर गंभीरता से विचार करें। दरअसल, बच्चों के बीच ऑनलाइन गेम खेलने की लत अब एक व्यापक समस्या बनती जा रही है, इसके घातक परिणाम भी सामने आ रहे हैं और लोगों के बीच इसे लेकर चिंता बढ़ रही हैं। आज इंटरनेट का दायरा इतना असीमित है कि अगर उसमें सारी सकारात्मक उपयोग की सामग्री उपलब्ध हैं तो बेहद नुकसानदेह, आपराधिक और सोचने-समझने की प्रक्रिया को बाधित करने वाली गतिविधियां भी बहुतायत में मौजूद हैं। आवश्यक सलाह या निर्देश के अभाव में बच्चे ऑनलाइन गेम या दूसरी इंटरनेट गतिविधियों के तिलिस्मी दुनिया में एक बार जब उलझ जाते हैं तो उससे निकला मुश्किल हो जाता है।

पांच वर्ष से अठारह वर्ष के बच्चों में मोबाइल या टेक्नोलॉजी एडिक्शन की लत बढ़ रही है, जिनमें स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच, टैब, लैपटॉप आदि सभी शामिल हैं। यह समस्या केवल भारत की नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश की है। ऐसे अनेक रोगी बच्चें अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिनमें इस लत के चलते बच्चे बुरी तरह तनावग्रस्त थे। कुछ दोस्त व परिवार से कट गए, कुछ तो ऐसे थे जो मोबाइल न देने पर पेरेंट्स पर हमला तक कर देते थे। बच्चे आज के समय में अपने आप को बहुत जल्दी ही अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा महसूस करने लगे हैं। अपने ऊपर किसी भी पाबंदी को बुरा समझते हैं, चाहे वह उनके हित में ही क्यों ना हो।

इंटरनेट की यह आभासी दुनिया ना जाने और कितने सूरज व छोटे बच्चों को अपनी जाल में फंसाएगी और उनका जीवन तबाह करेगी। बच्चों के इंटरनेट उपयोग पर निगरानी व उन्हें उसके उपयोग की सही दिशा दिखाना बेहद जरूरी है। यदि मोबाइल की स्क्रिन और अंगुलियों के बीच सिमटते बच्चों के बचपन को बचाना है, तो एक बार फिर से उन्हें मिट्टी से जुड़े खेल, दिन भर धमा-चौकड़ी मचाने वाले और शरारतों वाली बचपन की ओर ले जाना होगा। ऐसा करने से उन्हें भी खुशी मिलेगी और वे तथाकथित इंटरनेट से जुड़े खतरों से दूर होते चले जाएंगे। इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग की वजह से साइबर अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है। हमारी सरकार एवं सुरक्षा एजेंसियां इन अपराधों से निपटने में विफल साबित हो रही हैं।

शिक्षित किंतु कमजोर होता समाज

डॉ कामिनी वर्मा

पहले अभाव में खुशियां थी ,
अब संसाधनों में भी अवसाद है ।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री आर. एम. मैकाइवर एवं एच.सी.पेज का कथन है, 'समाज सामाजिक संबंधों का जाल है' अर्थात समाज व्यक्तियों का समूह या झुण्ड न होकर उनमें पाया जाने वाला पारस्परिक अंतर संबंध है। यह संबंध व्यक्ति का व्यक्ति के बीच, व्यक्ति का समूह के बीच तथा समूह का समूह के बीच हो सकता है। इस तरह के अंतर संबंधों से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब अपनी क्रियाओं का आदान प्रदान करता है, तब सामाजिक संबंधों का सृजन होता है। यह सामाजिक संबंध व्यक्ति को न सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से संबल प्रदान करते हैं, बल्कि उसका जीवन पथ भी सुगम बनाते हैं।

गांवों में बसा भारत आज भी अंतर संबंधों की सुगंध बिखेर रहा है। आज लगभग हर किसी के हाथ में फोन और इंटरनेट सेवा है । सूचना का आदान प्रदान बड़ी सरलता से दुनिया के किसी भी कोने में संभव है । दृष्टि डालते हैं कुछ समय पूर्व उस शिक्षित या अर्ध शिक्षित समाज पर जब सूचना संप्रेषण का साधन पत्र हुआ करते थे, और लोग दूर देश में रह रहे अपने प्रिय जनों की कुशलक्षेम जानने के लिए डाकिए बाबू का बड़ी उत्सुकता से इंतजार किया करते थे। पत्र वाहक से पत्र प्राप्त करके गांव में किसी शिक्षित के घर पर लगी चौपाल पर समाचार सुनकर सभी हर्ष की अनुभूति करते थे। किसी के घर में कोई विशिष्ट आयोजन होने पर सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते थे। अपनत्व भरा सहयोग पाकर व्यक्ति दुगने उत्साह से कार्य का निष्पादन करता था। साथ ही एक दूसरे के सुख दुख का साझीदार बन कर उसे सुदृढ़ता प्रदान करता था। हमारा कार्य व्यवहार ही हमारा जीवन दर्शन था।

भारत की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक वैशिष्ट्य व शिक्षा पद्धति एक दूसरे को जोड़ने वाली थी। जिसे देखकर लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद के समक्ष दिए गए उद्बोधन में कहा था मैंने भारत की चतुर्दिक यात्रा की और एक भी ऐसा आदमी नहीं देखा जो भिख मंगा हो या चोर हो, यहां के उच्च नैतिक मूल्य, उच्च क्षमतावान व्यक्ति, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत तथा शिक्षा प्रणाली यहां की रीढ़ की हड्डी है और जब तक हम इसे तोड़ नहीं देते तब तक इस देश को जीत नहीं सकेंगे।

कालक्रम में वही हुआ, हम विदेशी शिक्षा और संस्कृति के दास बन गए हैं। शिक्षा के तीनों स्तंभ अर्थात उचित शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी में जीवन मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। अपनी गौरवमई संस्कृति और उच्च आदर्शो से हम दिन प्रतिदिन विमुख हो रहे हैं । उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर वैज्ञानिक दृष्टि से समुन्नत हो रहे हैं, किंतु सांस्कृतिक और संस्कारित दृष्टि से विपन्न हो रहे है। हम चांद तारों की ऊंचाई और समुद्र की गहराई मापने में सफल हुए हैं, लेकिन मानव मन के भावों को पढ़ने में असफल हैं। हमारा मस्तिष्क पक्ष बड़ा ही उर्वर और समृद्ध है, पर हृदय पक्ष बंजर और विपन्न होता जा रहा है। जिसका परिणाम तनाव, व्यग्रता, भय, कुंठा और अवसाद के रूप में हमारे सामने आ रहा है।

तकनीकी रूप से समृद्ध होकर संपूर्ण विश्व को हमने एक गांव बना लिया है, वही संवेदनाओं से क्षीण होकर अपने गांव, परिवार और समाज से दूरी बन गई है। विकास के उन्माद ने रिश्तो पर घातक प्रहार किया। जहां संयुक्त परिवार अप्रिय परिस्थितियों में मजबूत चट्टान बनकर संबल प्रदान किया करता था। वहीं परिवार के बड़े बुजुर्गों की छत्रछाया में बच्चों का न सिर्फ सम्यक विकास होता था, अपितु उनके प्रेरणादाई वचनों व अनुभव के उद्धरणों से मूल्योन्मुखी शिक्षा बाल्यकाल में अनायास ही मिल जाया करती थी।

आज हम एकाकी परिवार और एकाकी जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जहां भौतिक विकास के बहुत से अवसर हैं, किंतु भावनात्मक विकास शून्य है। व्यक्ति के आसपास बहुत सारे लोग होने के बावजूद भावनात्मक रिश्तो के अभाव में मन में उदासीनता, सूनापन और निराशा है। बौद्धिकता और तार्किकता ने मन के कोमल तंतुओं को नष्ट कर दिया है । वर्तमान संदर्भ में डॉ राधाकृष्णन का कथन सर्वथा समीचीन है, आधुनिक युग आध्यात्मिक खोखलेपन, नैतिक विमूढ़ता तथा सामाजिक अराजकता का युग है। इतना ही नहीं वह तो इसे आर्थिक और बौद्धिक नृशंसता का युग भी कहते हैं।

वर्तमान में जैसे जैसे शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वैसे-वैसे संस्कारों का पतन हो रहा है। दहेज प्रथा, दहेज हत्या, गर्भ में ही लिंग की जांच करवा कर कन्या भ्रूण की निर्ममता से हत्या तथा बलात्कार से मानवता शर्मसार है। उचित संस्कारों के अभाव में उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति समाज की विघटनकारी शक्तियों में संलग्न है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अनुचित साधनों से धनोंपार्जन तथा धनोपार्जन हेतु घर परिवार से दूर जाने से समाज व परिवार कमजोर पड़ रहा है। साथ ही जिन उच्च शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता

अनुसार रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वह भी विद्धवंशक् गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं।

शिक्षा मानव जीवन के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। इसीलिए इसे मनुष्य का तीसरा नेत्र माना गया है। विवेकयुक्त शिक्षा से मनुष्य सभ्य, सुसंस्कृत एवं बुद्धिजीवी होता है। स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा माना है। वही प्लेटो का वक्तव्य है ,शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है, जिसके वह योग्य है। इस प्रकार भारतीय शिक्षा का स्वरूप सर्वथा कल्याणकारी है। वेदांत में भी कहा गया है 'सा विद्या या विमुक्तए' अर्थात शिक्षा वह है जो विमुक्त करें। यह जहां अज्ञानता और स्वार्थपरता से छुटकारा प्रदान करती है तथा सामाजिक रूप से जागरूक इंसान बनाती है ,किंतु यह हमारा मात्र आदर्श है । व्यवहारिक रूप से अन्वेषण करने पर हम पाते हैं, शिक्षित और ज्ञानियों ने भी स्वार्थ वश अनुचित और अमर्यादित कार्य किए हैं।

वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप वृतात्मक है। संस्कारात्मक नहीं। इसका उद्देश्य डिग्री प्रदान करना है। न कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। यह केवल आजीविका प्राप्त करने का साधन है । यह एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने वाली है । इस अशांति, अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति से मुक्ति पाने के लिए आत्मानः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत अर्थात जो कृत्य हमारे लिए प्रतिकूल हो उसे दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। के आदर्श को आत्मसात करना होगा। 'येन केन प्रकारेण' आगे निकलने की होड़ की नीति का परित्याग करना होगा।वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विद्या को समावेशित करने की आवश्यकता है। जो छात्रों को जीवन जीने की कला, जीवन का प्रबंधन करना सिखायेगी। इसी ज्ञान से जीवन की दशा में परिष्कार होगा और जीने की सही राह मिलेगी। जीवन की सम्पूर्ण दृश्य, अदृश्य शक्तियों का विकास करके निर्मित संस्कारी व्यक्तित्व सभी के लिए अनुकरणीय होता है। हृदय पक्ष को पुष्ट करके बुद्धि को उसका अनुगामी बनाकर, संस्कारों से पोषित व्यक्तित्व ,जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है । यही शिक्षा सम्यक शिक्षा हो सकती है जो समाज को मजबूत करेगी।

बदल जाएगा वर्क कल्चर, 4 दिन की नौकरी

● सम्यक अग्रवाल

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि अगले वित्त वर्ष यानी 1अप्रैल 2022 से उनके काम के दिन कम हो सकते हैं

देश में वर्क कल्चर बदल सकता है और कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन छुट्टी मिलेगी। यानी कर्मचारियों की छुट्टी शुक्रवार से रविवार तक रहेगी।

अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार अगले वित्त वर्ष यानी 2022-23 से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। इन लेबर कोड के नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) और व्यवसाय सुरक्षा (Occupation Safety) और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि जैसे 4 लेबर कोड शामिल है।

इससे पहले केंद्र सरकार इन नियमों के इस साल 2021 में अप्रैल से लागू करना चाहती थी लेकिन राज्यो सरकारों के तैयार नहीं होने के कारण लेबर कोड के नियमों को लागू नहीं कर पाई। केंद्र सरकार ने लेबर कोड के नियमों को अंतिम रूप दे दिया है और अब राज्यों को काम करना है। नियमों के मुताबिक लेबर कानून समवर्ती सूची (Concurrent List) यानी राज्यों का विषय है। ये अगले वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2022 से लागू हो सकते हैं।

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर लेबर कोड के ड्राफ्ट रूल्स को अब तक 13 राज्य तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा बाकी 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ड्राफ्ट रूल्स पर काम कर रहे हैं।

श्रम कानून लागू होने से आएंगे ये बदलाव, हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा

श्रम कानून लागू होने से कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा और कंपनियों को ऊंचे पीएफ दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन का स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जानें वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। अगर ऐसा होता है जो आपके घर आने वाली सैलरी घट जाएगी रिटायरमेंट पर मिलने वाला PF और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।

4 दिन की हो जाएगी नौकरी

नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव है। हालांक, 12 घंटे काम करने पर आपको हफ्ते में 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी मिलेगीष कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा।

संसद में हो चुका है पारित

संसद द्वारा इन चार संहिताओं को पारित किया जा चुका है, लेकिन केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है। उसके बाद ही ये नियम राज्यों में लागू हो पाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होने थे लेकिन राज्यों की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इन्हें टाल दिया गया। ■

भारत एक समृद्ध देश था, है और बना रहेगा

सभ्यता अध्ययन केंद्र की सेमिनार का निष्कर्ष, डायलॉग इंडिया बना मीडिया पार्टनर

● **डॉ. सारिका अग्रवाल**

दिल्ली के रफी मार्ग स्थित कांस्टीट्यूशनल क्लब में 19 दिसंबर, 2021 को कोरोना पश्चात वैश्विक व्यवस्था में भारत, संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।

इस कार्यक्रम में बीज वक्तव्य देते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने कहा कि भारत कोरोना पश्चात किस प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है और इनके समाधान के लिए कौन सी दिशा पकड़नी है इसका मंथन करना अब आवश्यक हो गया है। प्रश्न उठता है कि पश्चिमी देशों ने जिस प्रकार की एक व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी है क्या उसके सहारे भारत महान बन पाएगा और अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्स्थापित कर पाएगा।

पश्चिमी देशों की पक्षपात पूर्ण व्यवस्था का सबसे ज्वलंत और सटीक उदाहरण वर्तमान समय की आर्थिक प्रणाली और उसको चलाने के उनके मानदंड का है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को मापने अर्थात जीडीपी के आकलन का एक पैमाना तय किया हुआ है जिसे उन्होंने सार्वभौमिक स्तर पर घोषित कर रखा है और उसी के आधार पर तमाम देशों की जीडीपी को तय कर रहे हैं तथा आर्थिक नीतियों का निर्माण कर रहे हैं। इन्हीं मानदंडों पर विकासशील, विकसित देशों का वर्गीकरण हो रहा है। यहां तक कि इसी चालाकीपूर्ण व्यवस्था के तहत वैश्विक आर्थिक निकायों में गरीब देशों और अमीर देशों की भागीदारी अथवा हिस्सेदारी निर्धारित कर रहे हैं।

कहने का मतलब है कि जिस देश की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी वैश्विक आर्थिक निकायों में उनके पास उतने ही अधिकार होंगे। समझना पड़ेगा कि चाहे वह विश्व व्यापार संगठन हो संयुक्त राष्ट्र अथवा आईएमएफ हो किसी का भी रुचि गरीब देशों को उनकी गरीबी से बाहर लाने में नहीं है और न ही उनका यह उद्देश्य है। उनका उद्देश्य तो यह है कि कैसे इनको थोड़े से लालच देकर उनके संसाधनों पर कब्जा जमाया जाए। चालाकीपूर्ण तरीके से इन्हें अपने भ्रम जाल में फंसा कर और उलझा कर रखा जाए।

जहां तक भारत को वैश्विक व्यवस्था में स्थान दिलाने की बात है तो सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि आज जो वैश्विक व्यवस्था हमें दी गई है अथवा नजर आ रही है जिसकी धूरी अमेरिका और यूरोप अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उससे हजारों वर्ष पूर्व एक व्यवस्थित व्यवस्था चली आ रही थी तो ज्यादा समृद्ध, सुसंगतम, सभ्य और व्यवस्थित थी और जिसकी धूरी भारत रहा है। आज की संगोष्ठी में इसी बात को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

मौजूदा आर्थिक व्यवस्था में देखा जा रहा है कि भारत की जीडीपी लगभग 300000 करोड़ रुपए की है जो कि अमेरिका और यूरोप द्वारा बनाए गए अथवा समर्थित वैश्विक निकायों ने अपने मानदंडों पर गणना करके तैयार की है। अब सवाल उठता है कि भारत कितने लंबे समय तक उनके झूठ और प्रपंच के जाल में फंस कर स्वयं की हीनता बोध से ग्रस्त रहेगा क्योंकि यदि भारत की जीडीपी का आकलन यदि ठीक प्रकार से किया जाए मसलन कितना उत्पादन होता है, कितना खपत होता है, हमारी समृद्धि का पैमाना क्या है, हमारी जीवन शैली का पैमाना क्या है और इन आधारों पर यदि सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 900000 करोड़ रुपए की बैठती है।

जेंटलमैन एग्रीमेंट यानि कि सभ्य लोगों का समझौता के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आज के डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ जैसे वैश्विक आर्थिक तंत्र खड़े किए गए जिनका मूल उद्देश्य युद्ध में अमेरिका और यूरोप को हुई क्षति की भरपाई करना था। जब यह कार्य पूरा हो गया तब इनको भंग किया जाना चाहिए था जबकि इसके इसे गरीब देशों से कमाने का जरिया बनाया गया। यह षड़यंत्र उन्हें गरीबी से उबरने

के नाम पर चल रहा है। इसमें उनका भेदभाव पूर्ण रवैया स्पष्ट तौर पर नजर आता है।

डॉक्टर शैलेंद्र ने भारत के आर्थिक समृद्धि के पैमाने को रेखांकित करते हुए कहा कि हमारे यहां शास्त्रों में व्यापारे वसते लक्ष्मी की बात कही गई है जो स्वत: सिद्ध करती है की व्यापार के स्तर पर हम कितने उन्नत सोच से युक्त रहे हैं और पुन: अपनी जड़ों की ओर लौटने और अपने तरीकों को अपनाने पर ही हम उस गौरव को हासिल कर पाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि मध्य एशिया के जितने देशों के नाम के अंत में स्थान शब्द लगा नजर आ रहा है वह वास्तव में स्थान था जो भारत की सीमा होने का परिचय देते हैं।

समृद्धि के मोर्चे पर बात करें तो भारत के सभी तटीय प्रदेशों पर नजर डालिये। ओडिशा से लेकर गुजरात तक के समृद्ध मंदिर भारत के समृद्धि के प्रतीक के तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके आधार पर भारत के व्यापार के दायरे को समझा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि आर्थिक समृद्धि में पिछड़ने की एक वजह यह भी है कि हमें निज भाषा का गौरव नहीं रहा। जिन देशों में एक भाषा है एक संस्कृति, प्रकृति और जाति के लोग हैं उन्होंने जबरदस्त आर्थिक तरक्की हासिल की है। हमारे यहां विदेशी भाषा, विदेशी तंत्र की नकल और विविधता की जकड़न आर्थिक प्रगति में अड़चन पैदा कर रहे हैं। हमें निज भाषा का गौरव होना चाहिए और निश्चित तौर पर इसी के दम पर हम आर्थिक उन्नति की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे।

हमारे यहां कहा गया है

विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति: परेषां परिपीडनाय।

खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥

जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वह विद्या का उपयोग विवाद खड़ा करने, धन का उपयोग मद के लिए और शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं।

आईटी एवं वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ श्री प्रकाश शर्मा ने कहा कि दुनिया की तमाम आईटी कंपनियों में शीर्ष स्तर पर भारतीय की नियुक्ति हमारे लोगों की मेधा शक्ति का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। सरकार से स्तर पर भी भारत को शशक्त और समृद्ध बनाने के प्रयास जारी हैं। सरकार कारोबार में हस्तक्षेप से बाहर निकल रही है।

प्रसिद्ध इतिहासकार तथा लेखक डॉ आनंदवर्धन ने कहा की भारत शिल्पियों का देश रहा है जिनके कौशल के दम पर दुनिया भर के तमाम देशों में भारतीय उत्पांदों की मांग और व्यापार की धमक थी। आज जब हम कोरोना पश्चात के भारत की संभावना पर बात कर रहे हैं तो इस आपातकाल के दौरान जिस सूझबूझ से भारत ने अपनी उद्यमिता का परिचय दिया है वह अपने आप में एक शशक्त और समृद्ध भारत के लिए आशा जगाने वाला है।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री आभाश कुमार मालदहियार ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को भारत के वाश्तुशाश्त्र की अहमियत समझ आने लगी है। घर के अंदर प्रकाश और सूर्य की रोशनी का महत्व अब लोग फिर से समझने लगे हैं। दुनिया के तमाम देशों में भारत की सांस्कृतिक पहचान की जड़ें नजर आती है। चीन में पांच अंगुलियों की अवधारणा भारत की देन है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव और कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉ पंकज मित्तल ने शिक्षा में हो रहे बदलावों पर रोशनी डालते हुए कहा कि कोरोना काल में हमने शिक्षकों और विद्यार्थियों की तकनीक को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता का परिचय पाया है। आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा जगत में बदलाव लाने का प्रयास चल रहा है।

सभ्यता अध्ययन केंद्र के निदेशक श्री रवि शंकर ने कहा कि आज की वैशिवक व्यवस्था से पहले भी एक विश्व व्यवस्था थी जिसके केंद्र भारत था और यह व्यवस्था सदियों पुरानी थी और विश्व के कल्याण से ओतप्रोत थी। हम इस बात को मजबूती के साथ रखने के लिए एक वैचारिक आंदोलन खड़ा करने की दिशा में बढ़ रहें जिसमे आज का कार्यक्रम महज एक पड़ाव है।

इस कड़ी में देशभर के लगभग 100 विद्वानों की दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सितम्बर माह में किया गया था। उस कार्यशाला में इस विषय के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की गई थी। उस कार्यशाला में यह निश्चित किया गया था कि इस विषय पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाए। इस पुस्तक में अलग अलग विषयों के विद्वान 21वी शताब्दी की वैश्विक व्यवस्था में भारत के दावों की पुष्टि के ऐतिहासिक आधारों तथा राष्ट्र की क्षमताओ पर शोधपूर्ण अध्यायों का लेखन करेंगे। प्रस्तुत संगोष्ठी का आयोजन भी इसी दिशा में एक पड़ाव है। ■

मीना
जी

जय मां शारदे

जय मां शारदे
ऊं ब्रां ब्रीं ब्रों स: बुधाय नम:
प्रणाम संदेश : 2022
शाश्वत सनातन सत्य - वास्तविक धर्म
सत्य - सबसे बड़ी प्रतिरोधक क्षमता

मानव पूर्णरूपेण अपनी अहम्युक्त छवि, ईमेज के प्रति सतर्कता, जोड़तोड़ वाली चतुर मानसिकता और अपने स्वार्थी प्रयोजनों का उत्पाद बनकर रह गया है। जबकि उसे परम बोधि-सुप्रीम इंटेलिजेंस और प्रकृति के मन वाला होना होता है। सांसारिक विज्ञान केवल आचरण के प्रतिरूपों, देखी भाली शारीरिक संरचना, शरीर क्रिया विज्ञान, मानवों कोषाणुओं और वायरसों तक ही पहुंच सकता व उपचार कर सकता है।

लेकिन एक अनदेखी, अदृश्य शरीर संरचना भी होती है। अब ध्यान व सतत साधना द्वारा कोषाणुओं-सेल को डीप्रोग्राम करने की आवश्यकता है। उत्थान के अगले सोपान, त्वरित उछाल-क्वांटम लीप की ओर अग्रसर होने को सुपात्र होने के लिए। एक सत्य-वास्तविक मानव, जैसा कि होना चाहिए- प्रकाशमय मानव- बीईंग ऑफ लाईट बनने के लिए।

छंटनी का समय : ट्रांसिट पीरियड, परिवर्तन के पारगमन काल की यह अवधि, छंटनी का दौर अपना हिसाब कर रहा है। जो कोई भी यह सत्य समझेंगे और समय की पुकार सुनकर सचेतन होकर पुरानी मान्यताओं, अज्ञान व झूठ को काटने की साधना करेंगे उनको इस कठिन समय से पार होने के लिए स्वत: ही संदेश व निर्देश प्राप्त होंगे।

अपना स्वामी स्वयं बनो : अपने में पूर्ण विश्वास रखो और स्वयं निर्णय लो। अपना सत्य जानने समझने और अपनी योग्यताओं व क्षमताओं का सही आकलन करने को अपनी सम्पूर्णता से अपने निर्णय के अनुसार कर्म में जुट जाओ।

कर्म चक्र पूर्ण करो : इसके लिए जीवन में कोई कटघरा ना रखो ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। तर्क कुतर्क , वाद विवाद, सफाई देना, पक्ष विपक्ष में बोलना, दूसरों को अपने बनाए तराजू पर तौलना सब पूर्णतया हटा दो। यह सब हमें कर्म चक्रों में ही घुमाता रहेगा किसी भी परिस्थिति, अच्छी या बुरी से प्रभावित होकर अपने जीवन के प्रवाह को बाधित न होने दो। व्यर्थ के मानसिक वार्तालाप में ऊर्जा व्यय ना करो।

सहज व स्वाभाविक रहो : जीवन को घटित होने दो। इस बिन्दु तक पहुंचने के लिए मस्तिष्क में पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए ना कोई धुंध ना शंका ना दुविधा। पूर्ण आस्था व पूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के सर्वोत्तम विधान के साथ बहो। प्रत्येक परिस्थिति से धैर्य सुगमता शांति व शोभा पूर्वक पार होने तथा कुछ सीखने व उन्नत होने के लिए।

सभी आध्यात्मिकता का अनुसरण करो : यह विकसित, रूपान्तरित होने और क्रमागत रूप से उत्थान का उर्ध्वगामी मार्ग है। यह प्रकृति के नियमों व ब्रह्माण्ड की प्रक्रियाओं के विज्ञान पर आधारित है जो कि परम बोधि द्वारा उत्कृष्टता से शासित और संचालित है। यही शाश्वत नित्य, सनातन सत्य धर्म है। किसी मानव बुद्धि द्वारा रचित तथा वर्गीकृत किया धर्म नहीं। यह अन्तरिक्षीय रचना की प्राकृतिक उत्थान प्रक्रिया के साथ प्रवाहित रहने और प्रगतिशील रहने के लिए है।

इसी शाश्वत सत्य पथ पर चलो

1. ब्रह्माण्डीय शुद्धतम ऊर्जाओं से संयुक्त होने का माध्यम होने हेतु...
2. सम्पूर्ण सृष्टि से एकात्म अनुभव करने के लिए, विश्व बंधुत्व की भावना की ओर...
3. सही भावना से कर्म करने, कोई जुगाड़ बल प्रयोग छल कपट चालाकी आदि न करने के लिए...
4. अपने अंतरतम सत्य, जो कि उस परम तत्व का ही स्फुलिंग है, से संयुक्त होने हेतु...
5. यह बोध हो जाना कि यह आध्यात्म ही आत्मा का वास्तविक धर्म है, आत्मा के गुणों, सत्य प्रेम प्रकाश व आनंद में रहने के लिए...
6. स्वस्थ, विषाक्त तत्वों से मुक्त शरीर व परिपक्व मस्तिष्क हेतु...
7. शरीर मन व आत्मा में संतुलन व समरसता स्थापित करने हेतु...
8. चैतन्य व जागृत होने, नवीन विधाओं का अन्वेषण करने और नवीन वस्तुओं को सीखने के लिए...
9. सृष्टि, मानव अस्तित्व और ब्रह्माण्डीय क्रियाकलापों का उद्देश्य जानकर अपने सत्य में पूर्णतया स्थित रहकर जीवन के कर्तव्य कर्मों और जीवन के लक्ष्यों पर पूर्णतया केन्द्रित रहने के लिए...
10. यही सभी पूजा प्रार्थना आस्था कृतज्ञता और समर्पण है। अपने आप में पूर्णतया शान्त रहने के लिए। सदा इसी आध्यात्म पथ पर चलें जो कि सत्य प्रेम कर्म व प्रकाश पर आधारित है, दोनों संसारों अपरा व परा में संतुलन स्थापित करने हेतु...

व्यक्ति अन्य कर्मों से सेवानिवृत हो सकता है परंतु इस रुचिपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा से कभी नहीं। केवल यही मार्ग जीवन सार्थक करने का व बढ़ती आयु के प्रभावों को न्यून करने का भी है। कहावत है- जिसने प्रेम भरी मुस्कान, बालसुलभ सरलता और नटखटपना अन्त तक बनाए रखा उसने जीवन भरपूर जीया। महामृत्युन्जय मंत्र के सार का औचित्य सिद्ध करते हुए।

महामृत्युंजय मंत्र : ऊं त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

अर्थ : हे तीन आंखों वाले महादेव, हमारे पालनहार, पालनकर्ता, जिस प्रकार पका हुआ खरबूजा बिना किसी यत्न के डाल से अलग हो जाता है, कृपा कर हमें उसी तरह इस दुनिया के मोह एवं माया के बंधनों एवं जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति दीजिए।

प्रकाशमय बनो

Career Magazine

DIALOGUEINDIA

... Dialogue for Change

Consistent Journey of Rating ...

Career Portal : www.dialogueindiaacademia.com

राष्ट्रवादी पत्रकारिता की सतत् यात्रा ...

News Portal : www.dialogueindia.in

राजनीतिक पत्रिका

डायलॉग इंडिया

★★★★★★★★★★★★ परिवर्तन की चाह - संवाद की राह

सफलता के 12 वर्ष

12 Year of Success

GET RANKED AMONGST THE TOP COLLEGES IN INDIA

Participate in the Dialogue India National Ranking & Awards for India's Best Colleges / Universities - 2020

DIALOGUE INDIA National Ranking

DIALOGUE INDIA Academia Awards

DIALOGUE INDIA Academia Conclave

Anuj Agarwal

Group Editor
DIALOGUEINDIA

National President
CAREER PLUS EDUCATIONAL SOCIETY

National President
MAULIK BHARAT

Founder Director
GLOBAL CHAMBER OF SPORTS EDUCATION & CULTURE FOUNDATION

Our Other Initiative

GLOBAL CHAMBER OF SPORTS EDUCATION & CULTURE FOUNDATION

Career Dream — A Leading Institute for Bank / SSC / Railways / LIC / GIC / NDA / CDS / CPF & Other Competitive Exams

Career Plus — A Leading Institute for IAS / PCS — Subject : G.S. • ESSAY • P.A. • HISTORY • GEOGRAPHY • SANSKRIT LITT. • HINDI LITT.

Career Plus SKILLS — Institute of Skill Development — Affiliated to Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Govt. of India

Career Plus — EDUCATIONAL SOCIETY

मौलिक भारत

Head Office : 301/A, 37-38-39, Ansal Building, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-9

dialogueindia.in@gmail.com • dialogueindiaacademia@gmail.com,

Phone/Fax : 011-27654588, Mob. : 9811424443

This issue Published on 1st January, 2022 Postal Registration No. G-3/DL (N)/252/2020-22, Postal dt. 1st & 2nd Every Month

R.N.I. No. - DELHIN/2009/30089

Career Plus People - Born to Lead

2022 IAS/PCS 2023

PRELIMS • MAINS • PRELIMS CUM MAINS

New ONLINE/OFFLINE Batches in English/Hindi Medium

SUBJECTS AVAILABLE

GEN. STUDIES (for Prelims/Mains), CSAT & ESSAY

HISTORY | GEOGRAPHY | SOCIOLOGY

POLITICAL SCIENCE | PUBLIC ADMINISTRATION

SANSKRIT "LITERATURE" | HINDI "LITERATURE"

By Most Renowned & Competent Facilities under the Leadership & Direction of

Mr Anuj Agarwal & Niraj Kushwaha

Silver Jublee Year (Since 1997)

Career Plus

English / हिन्दी Medium Hostel Facility

EDUCATIONAL SOCIETY

A Legacy of 25 Years

Study Material & Test Series

44 SELECTIONS IN IAS 2020

H.O. : 301/A,37,38,39, Ansal Building, Behind Safal Dairy, Mukherjee Nagar, Delhi-9

9891186435, 9811069629, 9015912244, 011-27654588

Website : www.careerplusonline.com / www.careerplusgroup.com